राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 10] चौदहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तीसरा दिवस [संख्या: 03

बुधवार,
07 फरवरी 2018

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, नमस्कार। राम राम सा। वह आपके विधायक आ गये धाकड़जी? मिस्टर विवेक धाकड़। लाइये, आप आइये, इधर आइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): पहले आप हमें विराजने के लिए तो कहें, साहब। आप हमें विराजने के लिए तो कहें अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, पहले हमें विराजने का आदेश तो दें। हम खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। (व्यवधान) ऐसे आज्ञापालक हैं हम, आप जब तक नहीं कहेंगे विराजिये आप, तब तक हम बैठेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

शपथ अथवा प्रतिज्ञान

नवनिर्वाचित सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान

(माननीय सदस्य ने उनके नाम के सम्मुख अंकित भाषा में शपथ ग्रहण की)

श्री अध्यक्ष: आप अंग्रेजी में लेंगे क्या ओथ? मैं आई बोलूंगा, उसके बाद अपना पूरा नाम बोलकर पढ़ देना।

क्र.सं.	सदस्य का नाम	शपथ/प्रतिज्ञान	भाषा
(1)	श्री विवेक धाकड़	शपथ	अंग्रेजी

प्रश्नकाल। श्री सुरेन्द्र पारीक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले ये दस्तखत कर लें। औपचारिकता पूरी हो जाए। आसन पर विराज जाएं नये माननीय सदस्य, उसके बाद आप प्रश्नकाल करें तो ज्यादा अच्छा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुरेन्द्र पारीक।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की योजना

26. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाये जाने की दृष्टि से शहर में विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के माध्यम से बिजली के तारों को अण्डरग्राउण्ड किये जाने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत कार्य किये जा रहे हैं? यदि हां, तो अण्डरग्राउण्ड किये गये व किये जाने वाले कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर शहर में केवल घरेलू विद्युत कनेक्शन की लाइनों को ही अण्डरग्राउण्ड किया जा रहा है जबकि रोड लाइट्स के तारों को अण्डरग्राउण्ड नहीं किया जा रहा है? यदि हां तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि रोड लाइट्स के तारों को अण्डरग्राउण्ड किये जाते समय अब पुन: नई बनाई गई सड़कों को तोड़ा जाएगा, जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की हानि होगी?

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ स्थानों पर हाईटेंशन लाइनों को अण्डरग्राउण्ड कर दिया गया है, जबकि घरेलू कनेक्शन/रोड लाइट्स की लाइनों को अण्डरग्राउण्ड नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) घरेलू कनेक्शनों/हाईटेंशन लाइनों को अण्डरग्राउण्ड किये जाने तथा रोड लाइट्स के तारों को अण्डरग्राउण्ड नहीं किये जाने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

(6) क्या सरकार जयपुर शहर में घरेलू कनेक्शन की लाइनों के साथ ही रोड लाइट्स के तारों को भी अण्डरग्राउण्ड किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): (1) जी हां। जयपुर शहर में चौकड़ी मोदीखाना एवं चौकड़ी विश्वेश्वर में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के आवेदन पर आवश्यक शुल्क जमा कराने के बाद बिजली के तारों को अण्डरग्राउण्ड करने का कार्य किया जा रहा है। कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका या कोई अन्य स्वायतशासी निकाय द्वारा रोड लाइट्स के तारों को अण्डरग्राउण्ड करने का कार्य आवश्यकतानुसार किया जाता है।

(3) जी नहीं। आवश्यकतानुसार रोड लाइट हेतु अण्डरग्राउण्ड केबल मशीन के द्वारा डाली जायेगी एवं जहां छोटी गलियां एवं रोड की चौड़ाई कम है, वहां केबल ट्रे-सिस्टम पर स्थापित की जायेगी। इसलिए राज्य सरकार को इस कार्य के मद में रोड काटने की अतिरिक्त राशि की कोई हानि नहीं होगी।

(4) जी हां। जे.डी.ए. अथवा नगर निगम द्वारा लाइनों को अण्डरग्राउण्ड करने हेतु आवेदन करने एवं नियमानुसार खर्चा वहन करने पर विद्युत लाइनों को अण्डरग्राउण्ड किया गया है।

(5) उपरोक्त बिन्दु संख्या-2 के अनुसार।

(6) उपरोक्त बिन्दु संख्या-2 के अनुसार।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, यह जो इन्होंने जवाब दिया है, यह स्मार्ट सिटी वालों ने जो पैसा दिया है, उसका दिया है। राज्य सरकार ने दो साल पहले बिजली के तार अण्डरग्राउण्ड करने के लिए पैसा इनको दिया था, उसमें इन्होंने

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

बाईफरकेशन करके कि जो घरेलू उपयोग की लाइनें थीं, उनको अण्डरग्राउण्ड कर दिया और जो रोड लाइट्स थीं, उनको अण्डरग्राउण्ड नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा यह की थी कि गलियों में जितने भी वायर लटके हुए हैं, वह सारे अण्डरग्राउण्ड किये जायेंगे तो यह बाईफरकेशन सरकार ने किया था या आरएसईबी ने अपने स्तर पर कर दिया?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण 2015-16 में जयपुर की जो इनर सिटी है, जो हैरिटेज सिटी है, उसके तहत 80 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। जेडीए द्वारा जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को यह पैसा देना था। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 80 करोड़ रुपये की जगह 30 करोड़ रुपये ही हमें दिया, जिसका हमने टेण्डर भी लगा दिया। टेण्डर के तहत काम लगभग पूर्ण हो गया है। इसके तहत हमने लगभग 28 करोड़ रुपये खर्च भी कर लिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें जेडीए ने हमको कहा था कि जितनी भी आपकी 11 केवी लाइन हैं और खासतौर पर हमारी जो एलटी लाइन है, उसको अण्डरग्राउण्ड केबलिंग करनी थी, जिसका कार्य हमने कर लिया है। अगर उन्होंने हमें यह कहा होता कि हमको यह रोड लाइट्स को भी अण्डरग्राउण्ड करना है, अण्डरग्राउण्ड केबलिंग करनी है तो हम उसको भी कर लेते, परन्तु उन्होंने जो एस्टीमेट हमारे पास भेजा, एक संयुक्त टीम है, जिसमें जेडीए के कमिशनर या उसके एस.ई., जो जेडीए के हैं और हमारे एस.ई.(जेसीसी) हैं, उनके साथ मिलकर यह पूरा प्रोग्राम बनाकर, हमने यह एस्टीमेट बनाया। इसके तहत उन्होंने जो चाहा है, वह काम हमने किया है। हमने हमारी मर्जी से ऐसा कोई काम नहीं किया है। फिर भी मैंने पता किया है, जेडीए ने अभी टेण्डर निकाले हैं, जिसमें आलरेडी पहले हमने एलटी लाइन और 11 केवी लाइन को अण्डरग्राउण्ड किया है, उसमें रोड लाइट्स की केबल अभी भी ऊपर लटक रही है, उसको अण्डरग्राउण्ड करने के लिए जेडीए ने टेण्डर निकाला है, उसका काम प्रक्रियाधीन है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल): इसमें जो अण्डरग्राउण्ड किया है, उसके जो बाक्स गलियों में लगाये हैं, वह गलियां तो बहुत छोटी-छोटी हैं, इनके बाक्स गली की साइज से काफी बड़े हैं, उससे सारे रास्ते जाम हो गये हैं तो मैं तो कहना चाहूंगा कि वह जो गली में बाक्स इन्होंने लगाये हैं, उनको छोटा करके अच्छा लगाने की स्थिति में है कि नहीं आरएसईबी वाले?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पक्की गलियां नहीं हैं, वहां उसकी अण्डरग्राउण्ड केबलिंग हम कर नहीं सकते क्योंकि वहां मशीन जा नहीं सकती है, वहां ट्रे-सिस्टम पर, दीवारों पर केबल्स को लगाकर इसको ट्रे-सिस्टम के माध्यम से हम करते हैं। ये जो बाक्स की बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया, कौनसा बाक्स है? ट्रांसफार्मर लग रहा है, उसका कह रहे हैं या आरएमयू के लिए कह रहे हैं, कौनसे बाक्स की आप बात कर रहे हैं जो गलियों में बीच में आ रहा है? या तो जो ट्रांसफार्मर है, जो आग्मेंटेशन करते हैं, या तो वह ट्रांसफार्मर बीच में आ रहे हैं, छोटी गलियों में ट्रांसफार्मर बीच में आ रहे हैं। अगर ऐसी किसी जगह आपको लगता है कि ऐसा कोई ट्रांसफार्मर बीच में आ रहा है तो आप मुझे स्वयं बतायें, आप भी मुझे जगह बता दें, उसको हम वहां से स्थानान्तरित कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक, श्री निर्मल कुमावत।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है स्मार्ट सिटी और स्मार्ट विलेज बनाने के लिए ताकि ये केबल से हमें छुटकारा मिले। कहीं न कहीं डिपार्टमेंट की ओर से मंत्रीजी यह बतायें कि क्या इसकी रेट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन्स हैं? कई बार हमारी स्थानीय एजेंसी चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगरपालिका हो या नगर निगम हो, पैसा देना चाहते हैं डिपार्टमेंट को कि हमारी केबल्स अण्डरग्राउण्ड हो। मगर रेट्स का उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कोई टैक्नोलोजी का फर्क है क्या? हम इसकी दुबारा समीक्षा करना चाहते हैं क्या कि गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या संस्था उसको बड़ा पैसा या फण्ड देना चाहें तो उसके लिए कुछ रियायत हो

(श्री निर्मल कुमावत)

या कोई टैक्नोलोजी में या उसमें कोई मोनोपोली तो नहीं है, कहीं ऐसा कुछ विचार हम रखते हैं क्या, यह बतायें आप।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आवासीय क्षेत्र से 33 केवी की लाइन निकल रही है या आपकी 11 केवी लाइन निकल रही है या एलटी लाइन निकल रही है। अगर वहां की नगरपालिका, नगर परिषद वगैरह उस लाइन की अण्डरग्राउण्ड केबलिंग कराना चाहते हैं तो हमारे पास पूरी एक बीएसआर रेट है, उस रेट के तहत हम मात्र पांच परसेंट सुपरविजन चार्जेज लेते हैं और पाँच परसेंट सुपरविजन चार्जेज लेकर, जो भी आपका निगम है या परिषद है या पालिका है, वह अपने लेवल पर अपना काम कर सकते हैं। हमारा तो खाली पाँच परसेंट सुपरविजन चार्जेज है। हमारी जो बीएसआर रेट है, उस बीएसआर रेट के तहत हम उसका एस्टीमेट बनाते हैं और अगर नगर निगम, नगर परिषद स्वयं काम करना चाहती है तो हम उसको परमिशन देते हैं, हम खाली पाँच परसेंट सुपरविजन चार्जेज लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरक प्रश्न नम्बर दो, श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, शहर में या जहां आबादी है, उसके ऊपर ये 11 केवी या अन्य जो लाइनें जा रही हैं, जिनकी वजह से जन हानि भी हो रही है। उनको हटाने के लिए विभाग पहले कह रहा है कि एमएलए फण्ड से 50 परसेंट पैसे दो तो हम हटायेंगे। वह 50 परसेंट देने के बाद भी नहीं हटती हैं, खुद तो क्या हटायेंगे। क्या मंत्रीजी उन लाइनों को हटायेंगे जहां एमएलए फण्ड के भी 50 परसेंट हम देने को तैयार हैं, हमने दिये भी हैं, फिर भी अभी वह नहीं हट रही हैं।

दूसरा, अण्डरग्राउण्ड केबल जो आप लगा रहे हो, वह इतनी हल्की क्वालिटी की है कि बरसात से वह फाल्ट हो जाती है, उसमें करंट से कई लोग खतम भी हुए हैं, क्या उनकी भी आप जांच कराएंगे मंत्री महोदय?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि कोई भी कॉलोनी के ऊपर से या कोई रहवासी क्षेत्र से लाइन ऊपर से जा रही है, चूंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं जानते हैं कि आबादी का विस्तार होता है और नेटवर्क हमारा पुराना है और नेटवर्क पुराने होने के आधार पर धीरे-धीरे जो आबादी बढ़ती है और लोग उसके बाद अपना मकान उसके नीचे बनाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई रहवासी कॉलोनी है, उसके ऊपर से कोई भी व्यक्ति लाइन डालने देता नहीं है। अगर आबादी का बाद में विस्तार होता है फिर भी हमने डिस्कॉम के माध्यम से यह तय किया है कि ऐसी कोई आबादी है जिसके ऊपर से 11 के.वी. या 33 के.वी. जा रही है और अगर कोई निगम या कोई, जैसे आपने कहा कि विधायक कोटे से हम पचास परसेंट देते हैं तो निश्चित रूप से आपका काम अगर आपने पैसे जमा किये हैं और आपको लगता है कि वो काम अभी तक कंपलीट नहीं हुआ है तो मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। अगर हमारे अधिकारियों द्वारा कोताही बरती गयी है, उसमें अगर ज्यादा टाइम ले लिया है डिमाण्ड जमा कराने के बाद तो हम उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करेंगे। अगर टाइम पर उसका काम पूरा नहीं हुआ है तो और आपने जो बात कही है कि पुराने जो आपके शासन के कार्यकाल में आरएपीडीआरपी का काम हुआ था। उसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में यह आरएपीडीआरपी का काम हुआ था। सिस्टम इम्प्रवूमेंट का काम हुआ था। उसमें लगभग सभी जिला हैडक्वार्टर्स के शहर लिये थे और सिस्टम इम्प्रूवमेंट के तहत नये जीएसएस बनने थे। नये पावर ट्रांसफार्मर्स आग्मेंट करने थे। नये डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर्स लगे और अण्डरग्राउंड केबलिंग हुई। आपने जो बात ध्यान दिलायी है कि वहां आज भी वो अण्डरग्राउंड केबलिंग सही नहीं है, उसमें शॉर्ट होता है, उसमें कोई गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से बाड़मेर की आरएपीडीआरपी की स्कीम के तहत काम हुआ था, उसकी पूरी जांच करवाकर उस पर मैं उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री फूल चंद भिण्डा। नहीं करेंगे? तो फिर आप कर लीजिये श्री मोहन लाल जी गुप्ता।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय मंत्री महोदय, स्मार्ट सिटी के तहत आप चौकड़ी विश्वेश्वर जी और मोदीखाना में काम करवा रहे हैं तो ये काम कब शुरू होगा और कब तक इसको कम्पलीट कर देंगे? इसका टाइम पीरियड और इस पर राशि कितनी व्यय होगी? दूसरा, जब आप खुदाई करेंगे तो साथ ही साथ सड़क बनाने का काम भी यदि आपका डिपार्टमेंट कर दे तो लोगों को असुविधा नहीं होगी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी के तहत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा हमको आवेदन किया गया था और हमने उनको मांग राशि हेतु 12.09.2017 को मांग पत्र भी दे दिया। फर्स्ट फेज का तो 16.81 करोड़ और सैकिंड फेज का 17.9 करोड़, लगभग 33 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी द्वारा विद्युत निगम को दिया गया है। पहला टैण्डर हमने कर भी लिया है और मुझे लगता है कि आने वाले पांच-छह दिनों में एलओआई भी हो जाएगी और सैकिंड टैण्डर भी प्रक्रियाधीन है, लगभग 15 दिनों के अन्दर उसके भी टैण्डर हम इश्यू कर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से आईपीडीएस के तहत 294 करोड़ रुपये पास हुए हैं। लगभग पूरे शहर में 112 करोड़ रुपये तो हमारे सिस्टम इम्प्रूवमेंट के लिए है जिसमें नये जीएसएस बनेंगे। इसके साथ-साथ जीएसएस का आग्मेंटेशन होगा। जहां 5 के.वी. का ट्रांसफार्मर है उसको हम 8 के.वी. का करेंगे और नये ट्रांसफार्मर्स भी लगायेंगे। खास तौर पर मुख्य मंत्रीजी के प्रयासों से पूरे जयपुर शहर के लिए 181 करोड़ रुपये पास हुए हैं तो मैं समझता हूं कि पूरे जयपुर शहर में जो खर्च होगा, खास तौर पर सीडी-5 में सबसे ज्यादा काम होगा जो इनर वॉल सिटी है इसमें जितने भी हमारे 11 के.वी. हैं या एल.टी. लाइन है उसको पूरी हम अण्डरग्राउण्ड केबलिंग करेंगे। इसके लिए नये ट्रांसफार्मर्स लगायेंगे, बड़े ट्रांसफार्मर्स लगायेंगे जिससे हम छोटे ट्रांसफार्मर्स को हटा सकते हैं और खास तौर पर जो हैरिटेज प्लेस हैं जैसे मोती डूंगरी है, बिड़ला टैम्पल है, अल्बर्ट हॉल है, आमेर फोर्ट है, इसके आस-पास जितने भी हैरिटेज प्लेसेज हैं जहां काफी संख्या में टूरिस्ट आते हैं इन प्लेसेज को हमने इसमें सम्मिलित किया है। पूरे शहर में सौन्दरर्यीकरण

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

के लिए मुख्य मंत्रीजी के विशेष प्रयासों से 181 करोड़ रुपये पास हुए हैं, 112 करोड़ रुपये तो ...।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कहां से पास हुए हैं?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): यह हमारा केन्द्र और राज्य का 60:40 का शेयर है। 60 परसेंट तो आईपीडीएस के तहत केन्द्र सरकार देती है और 40 परसेंट राज्य सरकार देती है और अभी जयपुर शहर के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी के विशेष प्रयासों से 15 करोड़ रुपये हमको और दिये गये हैं सिटी के सौन्दर्यीकरण के लिए और ये काम हमने अवार्ड भी कर दिया है। इसकी प्रगति भी है और मुझे विश्वास है कि जुलाई तक हम ये काम पूरा कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष: आ गया। आप मिल लीजिये। जितना उनको देना था, उतना दे दिया उन्होंने। अब विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वो तो आपने तय कर दिया न, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): काम कब तक कम्पलीट हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल पुकार लिया है। आप उनसे मिल लीजिये। माननीय विधायक हैं आप।

प्रदेश में पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध रिश्वत के दर्ज प्रकरण

27. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत चार वर्षों में किस-किस जिले में कितने एवं कौन-कौनसे पुलिस कार्मिक रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) उक्त अवधि में दर्ज ऐसे कितने प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश प्रकरणों में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो, क्यों?

(4) उक्त अवधि में दर्ज कितने प्रकरणों में गिरफ्तारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): माननीय अध्यक्ष महोदय (1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा विगत 4 वर्षों (वर्ष 2014 से 2017) में पुलिस विभाग के कुल 200 अधिकारी/कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) आलोच्य अवधि में पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज कुल 275 प्रकरणों में से 155 प्रकरणों में चालान एवं 6 प्रकरणों में अंतिम प्रतिवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। 114 प्रकरण अनुसंधान की विभिन्न प्रक्रियाओं में लम्बित है। ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंतिम कॉलम में अंकित है।

(3) जी नहीं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रत्येक प्रकरण में विधिसम्मत, कार्यवाही की गई है। विगत 4 वर्षों में 200 पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। 155 प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है।

(4) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विगत 4 वर्षों (वर्ष 2014 से 2017) में पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज 275 प्रकरणों में से 171 प्रकरणों में गिरफ्तारी की गई है। विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: विराजिये। पूरक प्रश्न नंबर- 1.

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं, पूरक प्रश्न बाद में पूछूंगा। इन आंकड़ों में कंट्रोवर्सी है। एक जगह कह रहे हैं कि पुलिस विभाग के कुल

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

200 अधिकारी/कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। आगे और खंडों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में विगत चार वर्षों का जो मैंने पूछा है, उसमें पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध 275 प्रकरणों में से 171 प्रकरणों में गिरफ्तारी और बाकी का इन्होंने दिया है कि इंक्वायरी बकाया है। एक तरफ 200 लोगों की गिरफ्तारी, 275 कुल प्रकरण और एक तरफ 171 की गिरफ्तारी, यह थोड़ा आंकड़ों की संख्या में कंट्रोवर्सी है।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछ लीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): इसके साथ में पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उसमें ज्यादातर कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर और सीआई है। क्या आईपीएस और आरपीएस ने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं इन चार वर्षों में? सिर्फ दो आईपीएस का, अजमेर का और कोटा के आईपीएस का इसमें प्रकरण में गिरफ्तारी का दिया गया है भ्रष्टाचार जांच का। मेरा यह निवेदन है कि सिपाही, हैड कांस्टेबल, एएसआई, थानेदार या सब इंस्पेक्टर है या सीआई है, वह भ्रष्टाचार तब तक नहीं कर सकता जब तक ऊपर के अधिकारी भ्रष्ट नहीं हो। मैं आपको इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि ये पुलिस की जो एसपी के खिलाफ कार्यवाही हुई अजमेर के....

श्री अध्यक्ष: सवाल कीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरा निवेदन है, अजमेर के एसपी ने जो मंथली ली क्या आप हमारे अलवर के एसपी की बदसलूकी, बदव्यवहार, कदाचार और भ्रष्टाचार की जांच करायेंगे माननीय गृह मंत्री महोदय? ...(व्यवधान)...

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): दुर्भाग्य है यह राजस्थान का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप शांति रखिये। आपका काम नहीं है। यह प्रश्न मेरा है, आपका नहीं है, आप उठाते। उनका कदाचार, भ्रष्टाचार, उनकी बदसलूकी, अलवर के एक-एक एमएलए से अलग से गृह मंत्रीजी पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा और आप प्रभारी मंत्री अलवर से पूछें, क्या बदसलूकी हुई। अलवर के एसपी ने जिस तरह से

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

तानाशाही, हिटलरशाही मचा रखी है और थानों से मंथली और वहां अवैध खनन के 15-15 लाख रुपये एक-एक थाने से उनको मंथली पहुंचती है।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): धिक्कार है गृह मंत्रीजी के ऊपर। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हाल है। यह राजस्थान प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है, भ्रष्टाचार का हाल है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बस हो गया आपका नाटक, हो गया।

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): यह क्वेश्चन माननीय सदस्य ने किया है, मंत्रीजी जवाब देंगे, आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप मुझे पूरा पूछने दीजिए। बैठ जाओ। मैं अलवर की धांधली के लिये गृह मंत्रीजी को बता चुका, मैं डीजीपी साहब को बता चुका, मैं आईजी साहब को बता चुका लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई, क्या उनकी बदसलूकी, बदव्यवहार, कदाचार और भ्रष्टाचार की आप जांच करायेंगे?

पूरक प्रश्न संख्या दो, आपके सारे पुलिस वाले भ्रष्ट नहीं हैं...

श्री अध्यक्ष: एक जवाब आ जाने दीजिए फिर दूसरा कर लीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): दूसरा बाद में पूछूं?

श्री अध्यक्ष: हां, यह आपका अधिकार है दूसरा पूछने का।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सूची दी है, आपने जिले के अनुसार सूची मांगी थी कि कितने लोग गिरफ्तार हुए? मैंने प्रत्येक जिले के हिसाब से दिया है। अजमेर में 8, भीलवाड़ा में 10, नागौर में 2, जितने भी अपने जिले हैं, हर जिले में कितने लोग गिरफ्तार हुए, जो आपका पहला प्रश्न था, उसका उत्तर यह था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य सचेतक महोदय माननीय सदस्य को धमका रहे हैं कि आपने ऐसा कैसे कहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की तोहीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की तोहीन है। उप मुख्य सचेतक माननीय सदस्य को धमका रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): ...(व्यवधान)... डोटासरा जी, यह सबको नजर आ रहा है, आप विराजें, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप विराजें। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... तो क्या वहां आहूजा जी से लड्डू लेने गये हैं ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): आप विराजें अपनी सीट पर, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... डोटासरा जी, मंत्रीजी जवाब देने में सक्षम हैं ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... कि आपने ऐसे कैसे पूछा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान)... कांग्रेसियों में पूछने में सक्षम हूं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य कह दे कि मैंने धमकाया है, क्यों अनर्गल बात कर रहे हो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... आपकी मर्जी हो वही आरोप लगा रहे हो ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... आप वहां लड्डू लाने के लिये गये थे क्या? ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... डोटासरा जी, आप बैठिए। आपको क्या अधिकार है ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): ...(व्यवधान)... माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत आरोप लगा रहे हैं। आप माननीय सदस्य से पूछ लो ...(व्यवधान)... मैं यह पूछने के लिये गया था कि आप अभिभाषण पर बोलेंगे क्या। आप पूछिए मैंने केवल अभिभाषण पर बोलने के लिये बात की है। ...(व्यवधान)...

श्री जितेन्द्र कुमार गोठवाल (संसदीय सचिव): माननीय सदस्य क्वेश्चन पूछने में सक्षम हैं, वह अपने आप पूछ लेंगे, मंत्रीजी जवाब दे देंगे। आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सचेतक महोदय, आप कृपा करें। मंत्रीजी जवाब दें रहें हैं और आप लोग चुप रहें, मैं सक्षम हूं। मैं पूछने में, कहने में सक्षम हूं, आप चुप रहें।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): नहीं, मैंने केवल अभिभाषण की बात की है आपसे, इसके अलावा तो नहीं की न? यह क्यों इस प्रकार की गलत बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिए, विराजिए। माननीय गृह मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया कि इस फीगर में कोई अंतर है, वह नहीं है। कुल 275 प्रकरण दर्ज हुए, उसमें 171 में 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसकी मैंने आपको प्रत्येक केस व प्रत्येक जिले के अनुसार सूची दी है। इसके साथ ही मैंने यह भी बताया कि 275 में से चालान पेश कर दिये, थोड़ा आप लोग अगर धैर्यतापूर्वक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमने बहुत कठोरता से कार्यवाही की है। राजस्थान पहला प्रदेश हैं जहां तीन आईपीएस को गिरफ्तार किया है। ...(व्यवधान)...

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ...(व्यवधान)... आपने कौनसा तीर चला दिया, आपके राज में चोर हैं, आपके राज में भ्रष्टाचार हो रहे हैं। आपको 300 गिरफ्तार करने पड़ेंगे। सभी चोरी कर रहे हैं, सभी एक तरह से भ्रष्ट हैं। आप कह रहे हैं कि हमने तीन को गिरफ्तार कर लिया। कौनसा तीर मार दिया, भ्रष्टाचार, चोरी तो आपके राज में हो रही है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, आप बीच में क्यों खडे हो गये, आप बैठिए। आप बीच में कैसे खड़े हो जाते हैं, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय विधायक, माननीय विधायक, जवाब आने दीजिए। गृह मंत्रीजी का जवाब आने दीजिए। डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो हमने 275 प्रकरण दर्ज किये, राजस्थान हिन्दुस्तान में कार्यवाही करने में नंबर वन पर है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिये। मैं आपको डिटेल बता रहा हूं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपने जो प्रकरण दर्ज किये हैं वह छोटी मछलियों के हैं, मगरमच्छों के, आईपीएस और आरपीएस के लिये क्यों नहीं? उनके लिये क्यों नहीं, वह छोटी मछलियों के हैं, मछलियों के नहीं, आईपीएस, आरपीएस भी भ्रष्ट हैं और नीचे वालों को वही भ्रष्ट करते हैं, उनके खिलाफ कितने प्रकरण हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अभी आप जोश से मत बोलो, मैं आपको अभी एक-एक सवाल का उत्तर दूंगा, आप धैर्यता से सुन लीजिए और सुनने के बाद कोई शंका रह जाये तो उसके लिये मैं यहां उपस्थित हूं। मेरी बात को आप शांति से सुन लो, आपके हर सवाल का जवाब दे रहा हूं। 275 प्रकरण जो इन चार सालों में हुए, अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि आज की तारीख में केवल 13 केस पेंडिंग हैं, बाकी सारे केस डिस्पोज किये हैं। मैं आपको बता रहा हूं 275 में केवल जिनकी अभी स्वीकृति लेकर उनके खिलाफ हमको चालान करने हैं, वह इतने ही हैं। मैं आपको बता रहा हूं 155 में हमने चालान कर दिया, 7 में अभी आरोप पत्र तैयार हो रहे हैं। केवल 13 में आरोप पत्र पेश किया जाना शेष है। 6 में अंतिम एफआर लग गई, 66 के लिये मैंने अभी आपको अनुसंधान के लिये बताया, इसमें 12 विभाग को स्वीकृति के लिये भेज दिया जो पूरे हमारी तरफ से फिट केस हैं। विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद कार्यवाही हम कर देंगे। इस तरह से केवल 12+13 जिनमें अभी स्वीकृति आना बाकी है, 275 में से बाकी सारे केसों का निस्तारण कर लिया।

एक आपके मन में शंका है, विशेषकर अभी प्रतिपक्ष की तरफ से माननीय सदस्य बोले थे, मैं आपकी भी पूरी जन्म पत्री लेकर आया हूं। मुझे पता है कि क्या क्या चीजें होंगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2009 से लेकर 2012 तक...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सवाल ही नहीं है ...(व्यवधान)... क्या एसपी के भ्रष्ट आचरण की जांच कराओगे या नहीं कराओगे? ...(व्यवधान)...

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बार-बार बीच में कैसे व्यवधान कर रहे हैं। क्या सवाल है, यह मंत्रीजी का अधिकार है। ...(व्यवधान)... मंत्रीजी बहुत विस्तृत जवाब देंगे ...(व्यवधान)... आपकी जन्म

(श्री मदन राठौड़)

पत्री आ रही है तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं, आपकी जन्म पत्री को आने दीजिए। ...(व्यवधान)... आप उनको सुनने का माद्दा रखिए। ऐसे हंगामा करने से काम नहीं चलेगा। ...(व्यवधान)... आपकी पोल खुलेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य की जो भावना थी, वह मुझे मालूम हैं कि कांस्टेबल से लेकर जो उप निरीक्षक हैं वहां तक हम लोगों ने 202 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। जो इंचार्ज हैं, थाना इंचार्ज से लेकर, सीआई से लेकर डीवाई एसपी, एडिशनल एसपी, एसपी तक के लिये हमने 73 लोगों के खिलाफ, चाहे तो मैं आपको हर साल का दे सकता हूं, मैं 2014 में 24 बड़े अधिकारियों के खिलाफ, 2015 में 9 लोगों के खिलाफ, 2016 में 14 लोगों के खिलाफ और इस साल 26 बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है और तीन एसपी तो गिरफ्तार होकर लंबे समय तक जेल में रहे हैं, राजस्थान शायद पहला आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तार करने वाला प्रदेश होगा। मैं आपकी संतुष्टि के लिये ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिए, कृपया जवाब आने दीजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ से जो माननीय सदस्य आये हैं, 2009 से लेकर 2014 तक, नीचे के कांस्टेबल से लेकर एएसआई तक है, 191 लोगों के खिलाफ केस बने, मेरे टाइम पर 202 लोगों के बने। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: रनिंग कमेंट्री नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): इंचार्ज से लेकर पिछली सरकार के समय केवल 58 लोगों के खिलाफ केस बने थे, मेरे समय में 73 ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह 2008 से 2013 का मामला नहीं पूछ रहे हैं, आप इसको लंबा करना चाह रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप सब लोग भी खड़े हो जाओ तो भी इतना दम तो मेरे में है, मैं आपके सवाल का जवाब दे सकता हूं।

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह बात कही कि हमारे समय में यह नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, मैं इसलिए बता रहा था, मैं जानता था कि यह विषय आयेगा ही आयेगा कि हमने तो तीर मार दिया और आपने नहीं मारा, मैं अब आपका तीर बता रहा हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी, हम कहां पूछ रहे हैं, आपके सदस्य कह रहे हैं कि अलवर का एसपी भ्रष्ट है, प्रताड़ित कर रहा है, जांच कराइए।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आपकी जन्म पत्री भी सुन लो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जोर से मत बोलिए, क्योंकि नीचे सारा गड़बड़ ही गड़बड़ है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यहां से केवल नीचे और ऊपर ही किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है, उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): हमसे लोग नहीं कह रहे हैं गड़बड़ हुआ है, आप से लोग कह रहे हैं गड़बड़ हुआ है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं पूरा बता रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सुन लीजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): वर्ष 2014 में मैंने 7 प्रकरणों में सज़ा दिलायी। 2015 में 9 में, 2016 में 17 में..(व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये सवाल ही नहीं है। यह अलवर का सवाल है। अलवर की बात करें।

श्री अध्यक्ष: डोटासरा जी, बार-बार नहीं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। बार-बार डिस्टर्ब मत कीजिए। पूरक प्रश्न करना हो तो कर लीजिए। लेकिन जो रनिंग जवाब आ रहा है, वह तो सुनना पड़ेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप पढ़े-लिखे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): कहां लिखा है, अलवर इसमें?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, यह नर्सिंग काउंसिल वाला सवाल टालने के लिए..

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार कैसे व्यवधान कर रहे हैं?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं तो जवाब दे रहा हूं। आप अगर संतुष्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छा है। आप संतुष्ट नहीं हो रहे हों तो..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ज्ञानदेव आहूजा जी को करो।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को बता रहा हूं कि हमने इन वर्षों में सज़ा दिलाई है। 2014 में 7 लोगों को, 2015 में 9 को, 2016 में 17 को, 2017 में 47 लोगों को हमने सज़ा दिलायी है और पिछली सरकार के समय में 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में 18.. केवल 18 लोगों को, मैंने 47 लोगों को सज़ा दिलायी है और यह जो भ्रम है कि केवल छोटे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं, ऐसा नहीं है। इन चार वर्षों में सभी स्तर के 73 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है, जिसमें सारे के सारे डीवाईएसपी, एडिशनल एसपी, एसपी और सीआई स्तर तक के हैं। कांस्टेबल स्तर के 202 लोग हैं तो इस तरह मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है। यही नहीं, हमने इसके साथ-साथ विभागीय कार्यवाही की है, जो शायद राजस्थान के सब विभागों को एक तरफ जोड़ लो और पुलिस विभाग के लोगों को एक तरफ। पुलिस, पुलिस के लोगों को पकड़े, इससे ज्यादा शाबासी और क्या दे सकते हो?

श्री अध्यक्ष: गृह मंत्रीजी, चेयर को एड्रेस कीजिए, उनको नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह पहला डिपार्टमेंट है, जिसके बारे में लोगों को संदेह है, लेकिन यह धन्यवाद देना चाहिए कि पुलिस के लोग, पुलिस के लोगों को ट्रेप करके इतनी बड़ी संख्या में सज़ा दिलाते हैं। इसका मतलब हम जिस प्रकार से ईमानदारी से और फेयर कार्यवाही करते हैं, इसके लिए सम्पूर्ण देश में हमारा राज्य सज़ा के परसेंटेज के हिसाब से नंबर वन पर है। राष्ट्रीय सज़ा का परसेंटेज 12 है और हमारा सज़ा का परसेंटेज 47 प्रतिशत है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी उप चुनाव वाली सज़ा की बात कर रहे हैं। परसेंटेज एकदम हाइएस्ट है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): व्यवधान नहीं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में और डिटेल बता देना चाहता हूं। जिनको हमने सज़ा दिलाई है, अभी जो मेरे पास संख्या है, इसमें हमने 44 लोगों को सज़ा दिलायी है। इसमें 27 लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया है। हमने 5 लोगों के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी उनकी पेंशन को रोका है। विभागीय कार्यवाही विचाराधीन और अनिवार्य सेवा में हमने एक व्यक्ति को सजा दी। मतलब हमने 27 लोगों को बर्खास्त किया। ये जो 47 लोगों की सज़ा के बारे में बताया है, उसमें सज़ा की दृष्टि से हमने किसी के साथ कोई रहम नहीं किया है कि भई उनके साथ हमने कोई रहम कर लिया है। मैं सोचता हूं कि यह जो सज़ा का परसेंटेज है। आपको धन्यवाद देना चाहिए, नाराजगी जाहिर नहीं करनी चाहिए कि कम से कम एसीबी एक ऐसा विभाग है, जिसने कलक्टर और कलक्टर के ऊपर के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्रीजी, क्यों लंबा कर रहे हैं? माननीय सदस्य का स्पेसिफिक क्वेश्चन है। उसका उत्तर दें दें, बात खतम।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपने देखा है कि हमारे यहां आईपीएस अधिकारी को..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बीच-बीच में व्यवधान क्यों करते हो?

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो कहते हैं कि जवाब नहीं दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं तो कहते हैं कि लंबा कर रहे हैं। यह क्या मतलब है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, एसपी के खिलाफ कार्यवाही करने में मंत्रीजी सक्षम नहीं हैं, इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप पहले जवाब सुनिए। आपको पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। आपके इसमें काले कारनामे निकल रहे हैं

(श्री कालू लाल गुर्जर)

इसलिए आप बीच में अपनी मर्जी से बोल रहे हो। कभी कहते हो जवाब नहीं देते हैं, कभी कहते हो इतना लंबा कर दिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): क्या है कि जिसको सज़ा देनी है, उसको बिना जांच किए न तो आप के कहने से दूं, न उनके कहने से दूं। अगर गुनाहगार होगा तो सज़ा जरूर दूंगा, लेकिन आपके जोर से बोलने से या यहां हल्ला करने से मैं किसी अधिकारी को सज़ा दे दूं, यह न आज हो सकता है, न कल हो सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप लंबा कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं अलवर एसपी की जांच करवाने के लिए कह रहा हूं। आपको धन्यवाद देता हूं आप ईमानदार गृह मंत्री हैं। आपने इतनी बड़ी कार्यवाही की है। धन्यवाद। धन्यवाद। लॉट ऑफ धन्यवाद। आप ईमानदार गृह मंत्री हैं और आपने इतनी बड़ी कार्यवाही की है। बात यह नहीं है। आँकड़ों के आधार पर मत जायें। माननीय गृह मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि अलवर एसपी के कदाचार, बदसलूकी, बदव्यवहार और भ्रष्टाचार की आप जांच करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, मेरा यही कहना है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य को निमंत्रण दे रहा हूं कि सूचना पाइंटवाइज लिखकर दें। उसकी हंड्रेड परसेंट जांच होगी और दोषी पाया जायेगा तो सज़ा मिलेगी, मेरी यह भी गारंटी है। लेकिन यहां पर बोल देने से, किसी पर आरोप लगा देने से मैं किसी आदमी को कठघरे में खड़ा नहीं कर सकता हूं। ये केवल आप नहीं कहते हो। मैं स्वयं भी चार दिन रहकर आया हूं। जो लॉ एण्ड आर्डर को उसने मेंटेन किया है, वह आपके अलवर जिले का ऐतिहासिक लॉ एण्ड आर्डर है। आप क्या कहना चाहते हो ?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या जांच करायेंगे? अध्यक्ष महोदय, जब प्रमाण-पत्र ही दे दिया तो जांच क्या करायेंगे? ये जांच हो गई ना। गृह मंत्रीजी ने तो जांच कर दी कि उससे बढ़िया कोई अफसर राजस्थान में नहीं है तो फिर अब जांच क्या करायेंगे?

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बार-बार क्यों व्यवधान करते हो?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप लिखकर दो कि ये-ये कमियां हैं, इसकी जांच तो मैं करा सकता हूं, लेकिन बिना जांच करे या आपके हल्ला करने से मैं किसी को दोषी करार दे दूं, यह तो मेरे पद की गरिमा के खिलाफ है। जांच करने के बाद दोषी पाये जायेगा तो मैं इस सदन में वादा करता हूं कि चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसके खिलाफ कार्यवाही सौ परसेंट करूंगा, लेकिन बिना तथ्यों, बिना प्रमाण और बिना जांच के आप किसी को यहाँ पर हल्ला करके उसको सज़ा दिलाना चाहते हो तो यह आज संभव नहीं है, कल भी संभव नहीं है और कभी भी संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न हो गया ना आपका तो?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक और है। मेरा यह कहना है कि सारा पुलिस महकमा, पूरा पुलिस कुनबा भ्रष्ट नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप अपने विषय तक सीमित रहिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरा निवेदन सुनें, जो मैं कहना चाहता हूं। पूरा पुलिस कुनबा भ्रष्ट नहीं है, परंतु जो भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ आपने कार्यवाही की, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने कहा धन्यवाद दो। आप धन्यवाद मांग रहे हैं, मैं धन्यवाद दे रहा हूं और लगातार दे रहा हूं। अब मेरा यह निवेदन है कि कुछ लोग जो भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ.. आप खुद जैन हैं। किसी जैन मुनि, किसी जैन आचार्य, किसी गणाचार्य या सनातन संत के द्वारा कोई अभ्यास वगैरह लगायेंगे कि उनका व्यवहार ठीक हो जाए? कल ही डीग में एक महिला को एक एसआई ने पीटा है। उनका व्यवहार ठीक हो जाए और उनकी ईमानदारी आ जाये, उसके लिए क्या कोई ऐसा धार्मिक अभ्यास आप करेंगे, यह मेरा निवेदन है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने सारे राजस्थान के अपराध को ले लिया। मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि राजस्थान में कहीं अपराध नहीं हो रहा है या कहीं गलती नहीं हो रही है या कोई गलत सलूक नहीं हो रहा है। ऐसी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो तथ्य के साथ शिकायत आयेगी तो मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करता हूं कि अगर तथ्य के साथ चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, मैं उनको

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

विश्वास दिलाता हूं कि अगर वह जांच में प्रमाणित पाया जायेगा तो सौ परसेंट उसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा। कोई लिहाज नहीं होगा, इतना मैं आपको कह सकता हूं। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि कल की तारीख में कहीं भी कोई घटना या दुर्घटना नहीं होगी। कानून के तहत उस महिला को जो मदद दी जा सकती है, वह मदद देंगे। अगर आपको लगता है कि उसको मदद.., जहां अगर जांच चल रही है, वहां अगर नहीं मिल रही है तो मैं दूसरी जगह पर जांच चेंज कर दूंगा। आप जैसा चाहोगे, वैसा होगा लेकिन जांच अधिकारी ही निर्णय देगा कि इसमें दोष है या नहीं है। आपके या मेरे कहने से न तो दोषी बना सकता हूं, न निर्दोष बना सकता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नंबर एक, श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: सवाल की सीमा में ही रहिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): हां हां। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, एसीबी जो कार्यवाही करती है, वह टारगेट बेस कार्यवाही करती है या शिकायत के ऊपर कार्यवाही करती है? जिस भी कर्मचारी के खिलाफ एसीबी के द्वारा कार्यवाही की गई, उसको बहाल करने की क्या प्रक्रिया है? बहाल करने के बाद उसके लिए क्या ये भी मापदण्ड तय हैं कि जहां से उस पर एसीबी ने कार्यवाही की है, उसको फील्ड पर पोस्टिंग पर आप जब तक नहीं लगाओगे, तब तक कि उसकी कोई निर्धारित अवधि तय नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से एसीबी की कार्यवाही में सारे तथ्यों को पहले इकट्ठा करते हैं। आपसी बात को ट्रेप करते हैं। ट्रेप को कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू करते हैं। जहां तक संस्पेंशन का सवाल है तो केंद्र सरकार के जो आईएएस और आईपीएस हैं, उनके संस्पेंशन की जो अधिकतम सीमा है,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

वह दो साल की है। राजस्थान सरकार के जो कर्मचारी हैं, उनकी संस्पेंशन की मैक्सीमम सीमा तीन साल की है। उसके बीच में जो कमेटी बैठती है, वह कमेटी अगर उसे वापस रींस्टेट करती है तो हम रींस्टेट करते हैं। और अगर वह कमेटी नहीं करती तो तीन साल बाद वह अपने आप अधिकार प्राप्त कर लेता है, उसको वापस करना पड़ता है। फिर कोर्ट की सज़ा के आधार पर या कोर्ट के निर्णय के आधार पर ही उसका अंतिम फैसला करते हैं जिसमें हम बर्खास्त भी करते हैं, सेवानिवृति भी देते हैं, उसकी पेंशन भी रोकते हैं, बाकी कार्यवाही करते हैं लेकिन वह कोर्ट के निर्णय के बाद।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न, श्री नन्दकिशोर महरिया।

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): अन्य मामलों में पुलिस के खिलाफ एफआईआर या दर्ज मामले चल रहे हैं उनमें से कितने अधिकारी आज के दिन फील्ड पोस्टिंग में लगे हुए हैं? पहले भी एक आदेश सरकार का निकला हुआ है कि ऐसे अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग पर नहीं लगाया जाए। क्या आप ऐसा आश्वासन देना चाहते हैं कि इस तरह की कार्यवाही, इस तरह के अधिकारी फील्ड पोस्टिंग में राजस्थान प्रदेश में नहीं रहेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा जिसके खिलाफ 16 की कार्यवाही है उसकी फील्ड पोस्टिंग नहीं हो सकती। सामान्यतया कभी-कभी कहीं पर ध्यान में आता है कि 16 की कार्यवाही पैंडिग होने के बाद भी उसको फील्ड में लगाया तो जैसे ही सूचना प्राप्त होती है उसके साथ ही उसको फील्ड से हटाते हैं। 17 की कार्यवाही में फील्ड से नहीं हटाते हैं, वह अपना काम करता रहता है। 17 में जो भी फाइनल होकर उसके खिलाफ, एक वेतन वृद्धि या दो वेतन वृद्धि या जो कुछ भी कार्यवाही करनी होती है, वह कार्यवाही करते हैं पर 16 की ज़िसकी कार्यवाही चल रही है उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं देते हैं। गलती से भी अगर कहीं आदमी लगा रह गया और जानकारी में आता है तो तुरंत हटाते हैं।

श्री अध्यक्ष: तीसरा पूरक प्रश्न, श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विषय है यह वर्तमान सरकार या पूर्व सरकार से संबंधित नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या गृह मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे, पुलिस

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

डिपार्टमेंट में उच्चाधिकारियों से लेकर नीचे कांस्टेबल तक शुचिता के लिए आंतरिक मूल्यांकन का कोई पैमाना है क्या? कोई व्यक्ति केवल शिकायत करे, उसकी शिकायत के आधार पर किसी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही हो, यह पर्याप्त नहीं है। क्या आंतरिक मूल्यांकन की कोई ऐसी प्रणाली भी है? इनके डिपार्टमेंट में इंटर्नल कोई भी ऐसा सिस्टम डवलप कर रखा हो कि जो लोग भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी आंतरिक रूप से जांच करके, आंतरिक रूप से ही उन पर कोई कार्यवाही करने का विभाग काम करता है क्या?

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): निश्चित रूप से, वास्तव में क्या है कि जब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं होती या किसी तफ्तीश में यह लगता है कि तफ्तीश गलत दिशा में हुई है, निर्दोष को फंसाया गया है या दोषी को छोड़ा गया है, उसकी जब जांच होती है तो उसमें कुछ तथ्य निकलकर आते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही करते हैं। एक नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों के खिलाफ जिन्होंने तफ्तीश में हेराफेरी की। एक जांच कह रही है एफ आर लगती है, दूसरी जांच कहती है मुलजिम बनता है, तीसरा और कुछ कहता है, चौथा कुछ, ऐसे केसेज को जरूर इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उस अधिकारी की जांच के आधार पर उसका निर्णय करते हैं कि उसको क्या सज़ा दी जाए, उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाए। सामान्यतया पुलिस विभाग में कोई जिला ऐसा नहीं बचता है जिसमें इस प्रकार की कार्यवाही किसी न किसी के खिलाफ नियमित रूप से नहीं चल रही हो।

श्री अध्यक्ष: अगला सवाल, श्री जोगाराम पटेल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष: नहीं, जवाब आ गया। श्री जोगाराम पटेल।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों की रैंकिंग के मानदण्ड

28. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोगाराम पटेल)

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास विभाग द्‌वारा देश भर में स्थित ग्राम पंचायतों की रैंकिंग का कार्य करवाया जाता है? यदि हां, तो यह कार्य किस कार्यक्रम के तहत किन-किन मानदण्डों के आधार पर करवाया जाता है?

(2) क्या प्रदेश की भी सभी ग्राम पंचायतों की रैंकिंग करवाई गई है? यदि हां, तो कब व उक्त रैंकिंग के दौरान प्रदेश की किन-किन ग्राम पंचायतों को किस-किस आधार पर रैंकिंग प्राप्त हुई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र लूणी, की किसी भी ग्राम पंचायत का नाम देश भर की उन 50 हजार ग्राम पंचायतों में है, जिनकी रैंकिग करवाई जा चुकी है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): (1) जी हां। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की मिशन अन्त्योदय योजना के अंतर्गत देश की चयनित 50,000 ग्राम पंचायतों का निष्पादन तथा परिवारों की खुशहाली की स्थिति के मापन के आधार पर सर्वे किया जाकर मिशन अन्त्योदय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना था। सर्वे का आधार ग्राम पंचायतों का निष्पादन व परिवारों की खुशहाली की स्थिति है जिसके सर्वे प्रपत्र की प्रति पताका 'अ' पर संलग्न है।

(2) इन 50,000 ग्राम पंचायतों में से राजस्थान की 1,959 ग्राम पंचायतों का सर्वे दिनांक 1 से 15 अक्टूबर, 2017 तक मिशन अन्त्योदय एवं स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान किया गया जिसके आधार पर भारत सरकार द्‌वारा प्राप्त सूचना का विश्लेषण कर ऑनलाइन रैंकिंग की गई है जो मिशन अन्त्योदय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

राजस्थान की उन ग्राम पंचायतों की सूची जो मिशन अन्त्योदय के तहत चयनित जिन्हें रैंकिंग प्राप्त हुई है उनकी सूची पताका 'ब' पर संलग्न है।

रैंकिंग का आधार सर्वे रिपोर्ट में उपलब्ध आंकड़ों का भारत सरकार द्‌वारा किया गया विश्लेषण है जिसके सर्वे प्रपत्र की प्रति पताका 'अ' पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री)

(3) विधान सभा क्षेत्र लूणी जिला जोधपुर की 45 ग्राम पंचायतों का सर्वे पूर्ण किया जाकर इन आकड़ों को मिशन अन्त्योदय की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है। प्राप्त रैंकिंग की सूचना पताका 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर एक।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, खण्ड एक में सर्वे का आधार बताया है ग्राम पंचायतों का निष्पादन, निष्पादन से आपका क्या तात्पर्य है? क्योंकि निष्पादन से संबंधित कोई भी मैटीरियल, आधार, नियम-कायदे या परिपत्र आपने संलग्न नहीं किये हैं। दूसरा, आपने आधार दिया है परिवारों की खुशहाली की स्थिति। इसके संबंध में तो परिपत्र आपने संलग्न किया है। मेरा आपसे पहला निवेदन है कि निष्पादन से क्या तात्पर्य है? राजस्थान में 50 हजार ग्राम पंचायतों का सलेक्शन किया गया था, उनका क्या आधार था? कृपया मंत्री महोदय बताने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूरे देश के अंदर प्रति वर्ष तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा राशि ग्रामीण विकास के लिए और विशेष तौर पर गरीबी उन्मूलन के लिए विभिन्न विभागों द्वारा खर्च की जाती है। गरीबी उन्मूलन के लिए जिस प्रकार देश में विभिन्न समय के अंदर सरकारों ने किया उस प्रकार के सार्थक परिणाम नहीं आए। इसलिए 2017-18 के बजट में प्रधान मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि वर्ष 2019, जब महात्मा गांधी जयंती का 150वां वर्ष देश मना रहा होगा, उस समय एक करोड़ परिवार, एक करोड़ जनसंख्या नहीं, एक करोड़ परिवार, उनको गरीबी से निजात दिलाने के लिए एक मिशन अन्त्योदय की घोषणा की गई। देश के अंदर 50 हजार पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने के लिए एक योजना बनी।

अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंदर हमारे विभिन्न विभाग हैं, उन विभागों ने ग्राम पंचायत के अंदर अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से, अलग-अलग राशि के माध्यम से विकास के काम, विकास के साथ-साथ गांव में खुशहाली और पोवर्टी इवेल्युएशन के लिए काम किए उन सबका एक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोर्डिनेंस के रूप में, उनमें क्या-क्या गेप बच गए, गेप एनेलिसिस के लिए एक सर्वे हुआ। यह सर्वे अक्टूबर महीने से प्रारम्भ हुआ, 15 अक्टूबर, 2017 को समाप्त हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य खण्ड एक के लिए पूछ रहे हैं कि खण्ड एक के अंदर जो बात मैंने कही कि ग्राम पंचायतों का निष्पादन, निष्पादन से आपका आशय क्या है। अध्यक्ष महोदय, उसके पीछे यह आशय है कि ग्राम पंचायतों का निष्पादन और परिवारों की खुशहाली की स्थिति क्या है? इसके लिए एक परिपत्र जिसमें 40 इंडीकेटर्स हैं जिसमें गांव की कुल जनसंख्या, गांव में कुल परिवार, गांव में एसएलजी कितने हैं? कुल कितने हैक्टेयर में जमीन है? बोया गया क्षेत्र कितना है, सिंचित कितना है, असिंचित कितना है? इसी प्रकार गांव के अंदर कृषि कार्य में संलग्न लोग कितने हैं, गैर कृषि कार्य-कलाप के साथ कितने लोग जुड़े हैं? क्या गांव में बैंक है? अगर बैंक नहीं है तो गांव का बैंक कितनी दूरी पर स्थित है? गांव के अंदर इंटरनेट कनेक्टीविटी है या नहीं है? गांव में एटीएम है या नहीं है? गांव बारहमासी सड़क से जुड़ा हुआ है या नहीं है? गांव में आंतरिक सड़के है या नहीं है? गांव में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति क्या है, इस तरह का। अध्यक्ष महोदय, गांव में बिजली आती है तो कितने घंटे बिजली आती है उसके अलग-अलग मार्क्स दिए गए हैं। एक से चार घंटे आती है तो दो नम्बर। पाँच से आठ घंटे आती है तो तीन नम्बर। नौ से बारह घंटे आती है तो चार नम्बर। इसी तरह गांव में पीडीएस का सिस्टम कैसा चल रहा है। गांव में बाजार मण्डी है कि नहीं, नियमित बाजार है या नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह केवल इस जवाब को लंबा करके चौथा क्वेश्चन टालना चाह रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): लंबा कैसे कर रहे हैं, मेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। Who are you? मेरे क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। मेरा राइट है। आपका जितना राइट था, मेरा भी राइट है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो मौलिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बुनियाद के साथ सर्वांगीण विकास की दृष्टि से गांवों में रहने वाले लोगों के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने से संबंधित है। जिन लोगों का संबंध कभी इस प्रकार का नहीं रहा। आजादी के बाद 52 वर्ष तक इन लोगों ने केन्द्र में शासन किया, राजस्थान में शासन किया। कभी आपने अन्त्योदय के कंसेप्ट के बारे में भी नहीं सोचा। आप गरीबों को गुमराह करने के लिये अलग-अलग योजना लाते रहे। आप गरीबी उत्थान के नाम पर, 'गरीबी हटाओ' के नाम पर ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भाषण दे रहे हैं, चौथा क्वेशचन, जो स्वास्थ्य मंत्रीजी को कठघरे में खड़ा करता, उनको बचाने के लिये कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप बैठ जाओ। आपमें तो इतनी अक्ल नहीं रही, अन्त्योदय क्या होता है, कभी सोचा नहीं। आप अन्त्योदय के बारे में क्या जानो। ...(व्यवधान)... गरीबों का भला ही नहीं किया, अन्त्योदय शब्द ही नहीं सुना आपने।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये चौथा क्वेशचन जो स्वास्थ्य मंत्रीजी के भ्रष्टाचार को उजागर करता, को बचाने के लिये कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिस अन्त्योदय मिशन के साथ 40 इंडिकेटर्स की चर्चा माननीय सदस्य ने खण्ड-एक में मेरे से पूछी है, उसमें अध्यक्ष महोदय, गांव के अन्दर स्वच्छ इंधन का प्रयोग कितने परिवार कर रहे हैं। यानी उज्ज्वला योजना के बाद में गांव के अन्दर, गांव के जीवन स्तर के अन्दर कितना उठाव आया है, इसके भी उसमें ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो जीवन सुधार किया, जो-जो किया, वह तो देख लिया चार साल में, सवा चार साल में।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): इतना बड़ा उत्तर मांगा गया है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अब माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी से सवाल कर लेने दो। इनके भ्रष्टाचार को उजागर कर लेने दो।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): जिस प्रकार का प्रश्न है, इतना मोटा उत्तर है, इतना मोटा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय डोटासराजी, आपके समझ के बाहर की बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): इसी तरह अध्यक्ष महोदय, उस गांव के अन्दर, जिसके निष्पादन की बात माननीय सदस्य ने खण्ड-एक में कहा है, आपने इतनी विस्तृत बात पूछ ली। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा तो शायद यह सदन महरूम रह जाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं हैं। इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांव के अन्दर कच्ची दीवार ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप इनकी भावना समझ गये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): .... और कच्ची छत वाले परिवारों की संख्या कितनी है, उस गांव में डाकघर, आज भी इस राजस्थान के अन्दर जो एनेलेसिस आई है, उसमें बहुत से गांव ऐसे हैं, जहां पोस्ट आफिस नहीं है। इसी चीज का सर्वे भी हुआ कि गांव में पोस्ट आफिस है कि नहीं है और गांव में पी.एच.सी. और सी.एच.सी. है कि नहीं है। गांव के अन्दर पशु क्लीनिक है कि नहीं है। गांव के अन्दर ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्षजी, न्याय दिलाओ। स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जो अपने विवेक का इस्तेमाल किया, उसको सदन में उजागर करने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मृदा कार्ड केन्द्र, ...(व्यवधान)... बीज केन्द्र, यानी गांव के अन्दर किसानों को कितने मृदा कार्ड दिये गये हैं, वे उपयोग करते हैं कि नहीं, फर्टिलाइजर की दुकान है कि नहीं है। इसके साथ सामुदायिक अपशिष्ट निपटाना ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी के अधिकार में दखल नहीं दे सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, इस देश के अन्दर पहली बार, स्वच्छता का अभियान माननीय प्रधान मंत्रीजी ने चलाया और गांव के अन्दर उस स्वच्छता के मिशन के आधार पर गांव का जो अपशिष्ट है उसके निपटाने के लिये कोई प्रणाली विकसित हुई या नहीं हुई, इस अन्त्योदय मिशन के माध्यम से इस प्रकार की सारी बातों का सर्वे किया गया और ये गांव खुले से शौच मुक्त हैं कि नहीं ...(व्यवधान)... और माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जीती मक्खी निगल रहे हैं मंत्रीजी, स्वास्थ्य मंत्रीजी को बचा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकारों की रक्षा करें। मेरे प्रश्न का जवाब आ रहा है। बार बार ये व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे अधिकारों पर कुठाराघात कर रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 11 महीने बाद दोनों एक जगह ही रहोगे तो वहां पूछ लेना ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भूल जाओ, भूल जाओ। मुंगेरीलाल के हसीन सपने भूल जाओ, पता लग जाएगा दिसम्बर में। ...(व्यवधान)... मेरा जवाब नहीं आ रहा है। बार बार व्यवधान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था करें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात मुझसे पूछी, उन सारे इंडिकेटर्स को, चालीस इंडिकेटर्स हैं, उन इंडिकेटर्स की चर्चा मैंने संक्षेप में की है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ये चालीस इंडिकेटर्स, इसमें आंगनबाड़ी है, गांव में आंगनबाड़ी है तो जीरो से तीन वर्ष तक के बच्चे गांव की आंगनबाड़ी में जाते हैं कि नहीं जाते। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वैसे तो आप सराफ साहब के खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी आज बचा रहे हैं। कौनसी +++ लेकर आये हैं, मुझे पता नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गांव में एस.एच.सी. कितनी हैं, गांव के अन्दर सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने हैं गांव के अन्दर सर्वे हुआ। इन सारी चीजों के आधार पर राजस्थान में एक सर्वे हुआ। यह जो सर्वे था, उस सर्वे के आधार पर, अपने राजस्थान में जो राजस्थान आजीविका मिशन है, उसमें एक अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर, उसमें जो सर्वे किया, उस सर्वे के आधार पर 1959 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। ...(व्यवधान)... इसके अन्दर, ये जो 1959 ग्राम पंचायतें थीं, इसमें 8668 गांव इसमें सम्मिलित हुए। इन गांवों के अन्दर, इन गांवों की खुशहाली को आगे बढ़ाने के लिये किस प्रकार पंचायतों के अन्दर सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर आये और गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका जीवन स्तर कैसे उठे, यह एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जो मिशन अन्त्योदय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने प्रारम्भ किया, "भूतो न भविष्यति", आज तक किसी ने सोचा नहीं, जहां एक ओर उन्होंने कहा कि 2022 तक पूरे हिन्दुस्तान में ऐसा कोई गरीब बचेगा नहीं, जिसके घर पर छत नहीं हो, वहां दूसरी ओर ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्नकाल का महत्व ही खतम कर रहे हैं, मंत्रीजी। संसदीय कार्य मंत्री हो आप, और प्रश्नकाल का महत्व समाप्त कर रहे हो। +++ लेकर आये हो कालीचरण सराफ से, स्वास्थ्य मंत्रीजी से कि मैं आपका क्वेशचन नहीं आने दूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: यह +++ लेने वाला ड्रोप किया जाए... (व्यवधान)... यह +++ लेने वाला ड्रोप किया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): आप मुझे वर्षों से जानते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं न तो इधर-उधर की बात करता, मैं टू द पाइण्ट बात करने वाला आदमी हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो आपका प्रोटेक्शन चाहिए। मेरा जितना समय इन्होंने नष्ट किया है, किसी ने नहीं किया। बार बार मुझे टोक रहे हैं। मैं डिरेल हो रहा हूं, मैं डिरेल्ड हो गया, इसलिये मैं दुबारा यह पढ़कर सुनाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न नम्बर दो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा दूसरा प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है। यह जो आपने खण्ड-ब में मिशन अन्त्योदय के ग्राम पंचायतों की एक लिस्ट दी है, यह एनेक्सचर-2, उसमें एक कॉलम है स्कोर और दूसरा कॉलम है नेशनल रैंक। ज्यों-ज्यों स्कोर बढ़ते हैं, त्यों-त्यों नेशनल रैंक घटती है। जैसे एक नम्बर पर कोटा की ग्राम पंचायत है और उसका स्कोर है 80 और रैंक 12 है। ज्यों-ज्यों आप जाएंगे, ज्यों-ज्यों स्कोर कम होंगे, त्यों-त्यों रैंक बढ़ेगी तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन यह है कि स्कोर ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय माननीय सदस्य को पढ़ा रहे हैं या माननीय सदस्य मंत्री महोदय को पढ़ा रहे हैं? यह तो समझा दो, और तो कोई बात नहीं, चार मिनट और रह गये हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): यह आपके समझ के बाहर की बात है, आप तो सुनते रहो। बैठे रहो चुपचाप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा प्रश्न आप से यह है कि स्कोर ज्यों-ज्यों बढ़ते हैं तो रैंक क्यों घटती है और ज्यों-ज्यों रैंक बढ़ती है तो स्कोर क्यों घटते हैं? इसके पीछे क्या आधार है?

श्री अध्यक्ष: अब आधार तो बढ़ गया। उन्होंने जो पूछा है, आप विस्तार से बताइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो मिशन अंत्योदय, जो भारत सरकार की स्कीम है, भारत सरकार की मंशा एक करोड़ परिवार और 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी से मुक्त करने की रही, इसके लिये जो सर्वे हुआ, उस सर्वे के अन्दर जो 40 इंडिकेटर्स थे, जिसके आधार पर सर्वे एक अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हुआ, उस सर्वे के आधार पर ही यह योजना आगे चल रही है। उस सर्वे के अन्दर जहां-जहां एनेलिसिस के बाद गैप कम है, जिस तरह कोटा, जिसका नाम आपने लिया, सांगोद, कोटा, उसमें आवां का स्कोर 80 है और नेशनल रैंक 12 है, इसका मतलब इसमें 20 प्रतिशत गैप है, उस गैप को अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं समझ गया, बांध दिया, इसलिये क्यों तकलीफ पा रहे हो। ...(व्यवधान)...

श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर): आपकी नजर में गांवों का कोई महत्व नहीं है क्या? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: डिस्टर्ब नहीं करें। मंत्रीजी का भाषण, यस।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि इस गैप एनेलिसिस के बाद में इसकी पूरी योजना बनी। अध्यक्ष महोदय, यह पूरी योजना अलग-अलग योजनाओं, भारत सरकार ने सिर्फ इसको ऐसे ही नहीं बना दिया, इस योजना के अंतर्गत कुछ अलग-अलग जो एजेंसीज हैं, जैसे नेशनल रुरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से जिन ग्राम पंचायतों में फंडिंग होनी है या जो नोडल एजेंसी बनेगी, यानी नोडल एजेंसी बनकर उनकी जिम्मेदारी है, इसमें नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट है इसके अन्दर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसके अन्दर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अरबन मिशन है, इसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना भी शामिल की गई है। इन सबके साथ, जो उद्देश्य था कि इस एनेलिसिस के बाद में जो गैप्स हमारे सामने आयेंगे, उन गैप्स को पूरा करके किस प्रकार हम सारे राजस्थान की 1959 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें किस प्रकार हम गरीबी उन्मूलन करें।

यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की सदारत में एक कमेटी बनी है। अलग-अलग विभाग के मंत्रियों को उसमें शामिल किया गया है। वे सारे मंत्री मिलकर मुख्य मंत्रीजी की सदारत में अपने-अपने डिपार्टमेंट्स में जो गैप इसमें आये हैं, वे गैप को पूरा करने का काम करेंगे।

यही नहीं, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक इम्पावर्ड बोर्ड बना है। यह इम्पावर्ड बोर्ड समय-समय पर बैठेगा और यह इम्पावर्ड बोर्ड इसमें एक्शन-टेकन रिपोर्ट, यानी इस पूरे मामले के अन्दर, विशेष तौर पर जो स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छता, सामाजिक सुरक्षा, कृषि और आजीविका, शिक्षा और कौशल, पंचायत का इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय समावेशन, इसके आधार पर, आप कहें तो वह सूची पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ...(व्यवधान)... एनेलिसिस के अन्दर ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ...(व्यवधान)... मंत्रीजी को बचाने के लिये आपको बहुत-बहुत आभार।

श्री अध्यक्ष: दस सैकण्ड में आपको कुछ कहना हो तो दस सैकण्ड में कह दीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): क्या, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: दस सैकण्ड में कह दीजिये आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय आप कहें तो इसमें आधे घण्टे की चर्चा रखवा लीजिये, अगर कुछ रह गया है तो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री रामनारायण, सदस्य की ओर से अजमेर लोक सभा चुनाव के दौरान आपस में हुई छुटपुट मारपीट व गालीगलौज के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा परेशान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के आलनियावास रोहीसा मेड़ता में अधिकारियों की मिलीभगत से बजरी के अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्रीमती सोनादेवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जे.जे.वाई स्कीम के अंतर्गत शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(4) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किसानों की बिना सहमति मीटर

(श्री अध्यक्ष)

बदलकर गलत बिल वसूलने एवं पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री भँवरसिंह, सदस्य की आर से बीकानेर शहर में पॉलीथिन से आवारा गौ-वंश की हो रही मौतों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(6) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजकीय आवासीय छात्रावासों में घटिया किस्म के गद्दों-तकियों की सप्लाई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्रीमती सोनादेवी, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री भंवरसिंह एवं श्री सुखराम विश्नोई को उनके प्रस्ताव की विषय-वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमानुसार भुगतान किये जाने के संबंध में।

(2) श्रीमती शिमला बावरी, सदस्य की ओर से सरसों की फसल की खरीद समर्थन मूल्य पर किये जाने के संबंध में।

(3) श्री छोटू सिंह, सदस्य की ओर से जैसलमेर जिले के राजस्व गांवों में बारानी भूमि आबंटन की स्वीकृति एवं पूर्व में निरस्त किये गये आवेदन पत्रों को पुनर्जीवित कर बारानी भूमि का आबंटन किये जाने के संबंध में।

(4) श्री जोगाराम पटेल, सदस्य की ओर से तहसील लूणी के काश्तकारों को 2016 की खरीफ की फसल खराबे पर फसल बीमे की राशि का भुगतान किये जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री सुखाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत किये जाने के संबंध में।

(6) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से गंगानगर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाये जाने के संबंध में।

(7) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बानसूर व नारायणपुर सी.एच.सी. पर महिला चिकित्सक की नियुक्ति किये जाने के संबंध में।

(8) मास्टर मामन सिंह यादव, सदस्य की ओर से भिवाड़ी शहर में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में बरती जा रही अनियमितताओं के संबंध में।

(9) श्री कैलाश भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के वार्ड संख्या 35 को हैरिटेज वार्ड बनाये जाने एवं उसका सौन्दरयीकरण किये जाने के संबंध में।

(10) श्री हीरालाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र निवाई में निवाई-कररिया सड़क का पुनर्निर्माण किये जाने के संबंध में।

(11) श्री नन्दकिशोर महरिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

(12) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत किये जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

पर्ची

आज दिनांक 07 फरवरी, 2018 को शून्यकाल में बोलने हेतु 31 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित है:-

(1) श्री तरुण राय कागा- उपखंड मुख्यालय चौहटन पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री हरिसिंह रावत- जिला राजसमंद में खाद्य सुरक्षा योजना का कोटा बढ़ाने एवं राशन डीलरों द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में।

(3) श्री बाबू सिंह- जिला जोधपुर की ग्राम पंचायत सामराउ में उपद्रवियों द्वारा एक युवक की हत्या एवं लूटपाट, छेड़छाड़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री शंकर सिंह- ब्यावर में विद्युत विभाग की लापरवाही से उत्पन्न समस्या के संबंध में।

श्रीमती सोनादेवी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

रायसिंहनगर में जे.जे.वाई. स्कीम के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की उपलब्धता

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाही को रोककर अतिमहत्वपूर्ण लोक महत्व के विषय पर चर्चा करने का समय प्रदान किया, आपकी आभारी हूं, थैंक्स, सर।

सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में पेयजल व्यवस्था की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मेरे रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था जे.जे.वाई. स्कीम से और पी.एच.ई.डी. स्कीम से की जाती है। पिछले टू ईयर्स से मेरे विधान सभा क्षेत्र से रायसिंहनगर व विजयनगर की पी.एच.ई.डी. विभाग द्वारा जीर्णोद्धार के लिये योजना बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित की गयी है जो आज दो वर्ष से लंबित है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये जो योजनाएं प्रेषित की गयी हैं उन पर वित्तीय स्वीकृति जारी करके यह व्यवस्था दी जाए।

दूसरा, मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो जे.जे.वाई. स्कीम है, उसमें कर्मचारियों को पर डे 82 रुपया दिया जाता है। आज के दिन 82 रुपये में कैसे वह पेयजल व्यवस्था की सप्लाई करेगा? एक तो रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में थ्री फेज कनेक्शन, एक हफ़्ता दिन में लाइट और एक हफ़्ता नाइट को तो ऐसे में 82 रुपये के लिए वह कर्मचारी रात को जगकर

(श्रीमती सोनादेवी)

पेयजल व्यवस्था की सप्लाई क्यों करेगा? इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इसी बजट में सरकार यह घोषणा करे कि जे.जे.वाई. के जो भी कर्मचारी पूरे राजस्थान में हैं, उनको स्थाई किया जाएगा, यह मेरा सरकार से अनुरोध है।

इसी में मेरा यह अनुरोध है कि जो प्रस्ताव विभागीय योजना के अन्तर्गत हैं, वे तीन प्रस्ताव पिछले दो साल से लंबित पड़े हैं, जिनकी मैं जानकारी देना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदयजी को कि 26 FF, 62 NP और 72 से 78 RB की योजना लंबित पड़ी है और जनता जल योजना के अन्तर्गत यह लम्बी लिस्ट है, मैं अवश्य ही सरकार को बताना चाहूंगी कि 35 ML, 12NRD, 2LPM, 24PTD, 15PTD, 6FD, 34MP, 1LC, 2NP, 1-4TK, 3NZP बारानी 6LC, 4MK, 20RB, 48NP भोमपुर-बग़ीचा, 6NZPD, 28F राइयावाली बारानी, ये योजनाएं जे.जे.वाई की हैं, ये दो साल से लंबित पड़ी हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि ये जो योजनाएं हैं इन पर ध्यान देकर, इन पर वित्तीय स्वीकृति तुरंत जारी करके रायसिंहनगर में पेयजल व्यवस्था की जाए।

दूसरा, जब भी मैंने क्वेशचन विधान सभा में पेयजल व्यवस्था के लिए लगाया तो चौदहवीं विधान सभा के सत्र फर्स्ट में भी मेरी मांग यही थी कि रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करें। आज दसवां सत्र है, मेरा सरकार से यही अनुरोध है और हाथ जोड़कर अपील करती हूं कि राजस्थान सरकार रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र की शुद्ध पेयजल व्यवस्था के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करे।

एक बजट बी.ए.डी.पी. प्लान का, सीमावर्ती एरिया रायसिंहनगर के अंदर है। सीमावर्ती क्षेत्र में जीरो से टेन किलोमीटर की दूरी में बी.ए.डी.पी. प्लान की योजनाएं 2018-19 की तैयार की जा रही हैं, प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मेरा करबद्ध अनुरोध है कि जीरो से टैन किलोमीटर की दूरी में यह पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता से देकर, वह बजट बी.ए.डी.पी. प्लान का पेयजल में प्राथमिकता देकर लिया जाए ताकि जीरो से टेन किलोमीटर तक रायसिंहनगर में जो ग्राम पंचायतें, जो ग्राम, ढाणियां आती हैं, उनमें शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवायी जाए क्योंकि आज तक 20 साल के लगभग, 20 साल से बी.ए.डी.पी. प्लान का पैसा रायसिंहनगर विधान सभा क्षेत्र में जीरो

(श्रीमती सोनादेवी)

से टैन किलोमीटर में लगता रहा, फिर भी यह स्थिति थी पेयजल व्यवस्था की।

मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि बी.ए.डी.पी. प्लान में जो पैसा लगता है वह भी पेयजल पर लगाया जाए, जे.जे.वाई. स्कीम से भी और विभागीय स्कीम से भी। यह पैसा लगाकर प्रमाण पत्र जारी किया जाए पंचायती राज स्तर पर कि सरपंच के लैटर हैड से यह प्रस्ताव लिया जाए कि इतना पैसा यहां पर पेयजल पर लगा था। हमारी पंचायत में उप सरपंच से भी लिया जाए, वार्ड पंच से भी, प्रत्येक मैम्बर से। प्रत्येक गली- मौहल्ले में पेयजल व्यवस्था स्कीम पूरी हो चुकी है, व्यवस्था हो चुकी है, ऐसा प्रमाण-पत्र पंचायत स्तर से, ग्राम पंचायत से, सरपंच से जब लिखा जाएगा तब जाकर यह पेयजल की व्यवस्था का पूरा रिकार्ड होगा होगा, मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री महोदय। समाधान होगा आपकी समस्या का।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि रायसिंहनगर से आने वाली माननीय सदस्या ने बताया है, इनके 61 जनता जल योजनाएं चल रही है, उनके अंदर पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की थी जनता जल को सुदृढ़ीकरण करने के लिये, उसके अंदर करीब 13 कार्य योजनाएं इनके दो साल में 2016-17 और 2017-18 में स्वीकृत की थीं। उनकी अनुमानित लागत 8 करोड़ 61.70 लाख रुपये हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 13 कार्य योजनाएं स्वीकृत हुई थीं, उनमें से 4 पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं। एक ठेकेदार की धीमी गति के कारण पूर्ण किया जाना लक्षित है और 2017-18 की जो सैंक्शनें हुई थीं, उनमें जैसाकि माननीय सदस्या ने कहा, आर.डब्ल्यू.यू. ऐसे 20 एन.पी. की निविदा 29.01.2018 को प्राप्त कर ली गयी है, जिसका कार्यादेश जारी किया जा रहा है और 2017-18 के तहत दूसरा कार्य आर.डब्ल्यू.यू.एस.एस. ठाकरी की जल संसाधन विभाग से मोगा की स्वीकृति प्रक्रियारत है। इस योजना के लिये भूमि का प्रकरण कलक्टर साहब, गंगानगर के कार्यालय में उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक 82/17.01.2018 से भूमि

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

आबंटन हेतु भिजवायी गयी है। यह दोनों स्वीकृतियां प्राप्त होते ही निविदा करके योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा और शेष जो 6 कार्य हैं, जिनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मुख्य अभियन्ता द्वारा दिनांक 02.02.2018 को जारी कर दी गयी है, आगामी तकनीकी स्वीकृति निविदा कार्यवाही की जा रही है।

अब, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इनकी 15 योजनाएं पैंडिंग हैं, जैसाकि माननीय सदस्या ने कहा, यह 70 आर.बी., पीडीटीबी, 15 टीकेखांटा, 22 आरबी, 20 एनपी और पुनर्गठन कार्यों में ठाकरी, 5 एफडी, 19 एनपी, 36 पीएस, 33 एनपी, 19 पीएस और 34 पीएस यह योजनाएं आयी हुई हैं, जो 14 करोड़ 75 लाख 99 हजार रुपये की हैं। इन पर विचार किया जा रहा है। बजट की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृतियां निकाली जाएंगी।

जैसाकि माननीय सदस्य ने कर्मचारी के लिये कहा तो वह पंचायती राज के अधीन हैं। डी ए डी पी भी पंचायती राज के अधीन है तो पंचायती राज में वह प्रस्ताव भेजें और जो डी ए डी पी की स्वीकृतियां निकालनी हैं, जो चीफ सैक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, वह देखती है। आप प्रस्ताव भेजेंगे तो उनके ऊपर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लीजिये। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, रायसिंहनगर से आने वाली माननीय विधायक महोदय ने यह कहा है कि जनता जल योजना में 83 रुपये रोज मिल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय की सदन में की हुई घोषणा की तरफ आकर्षित करता हूं कि इन्होंने फरमाया था कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से सबको न्यूनतम मजदूरी देने का आदेश हो गया है और आपने कहा है कि मेरे तहत जितने भी जनता जल योजनाएं हैं ग्रामीण विकास की, उनमें यह आदेश कर दिये हैं। माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ साहब, जब आदेश कर दिये तो जनता जल योजना, जो रायसिंहनगर में है, उसमें 83 रुपये रोज कैसे मिल रहे हैं। इस अन्याय को तो आप तत्काल बंद करिये और 201 या 207 रुपये जो भी आज न्यूनतम मजदूरी है, उसके

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आदेश तत्काल, चूंकि आपके ध्यान में आ गया, माननीय अध्यक्षजी के ध्यान में आ गया, विधान सभा में आपकी घोषणा है, इसलिये आप उन आदेशों को आप आज ही जारी करने की कृपा करें।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): यह तो विधान सभा में कल ही कहा था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 16.09.2016 में एक आदेश जारी किया था कि जनता जल योजना के पम्प चालकों को न्यूनतम मजदूरी पर भुगतान किया जाये। इस पर न्यूनतम मजदूरी उनकी 5,382 रुपये प्रतिमाह बनती है। हमने विभागीय आदेश 06.09.2017 को जारी कर दिया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में 5,382 रुपये इनको देय हो। रायसिंहनगर का प्रकरण आया है। मैं माननीय सदस्या, आपसे निवेदन करूंगा कि आप लिखकर दे दें कि आपके यहां कहां-कहां जनता जल योजना के अंदर अब भी 82 रुपये प्रतिदिन दिये जा रहे हैं। इसको हम दुरुस्त करायेंगे और दुबारा मैं आपको यह आश्वस्त कर रहा हूं, कि यह जो आदेश हमने 06.09.2017 को जारी किया था, इसको दुबारा एक बार पुन: सारे बी.डी.ओज.को और सी.ई.ओज. को प्रेषित कर देंगे ताकि इसमें कोई विसंगति नहीं रहे।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा किसानों से गलत बिल की वसूली एवं बिजली उपलब्ध न कराना

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी का किसानों की बहुत ही महती समस्या के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कृपया आप मुझे समय प्रदान करेंगे, ऐसी मुझे पूरी-पूरी आशा है।

श्री अध्यक्ष: अपने आप ही आप सीमित कर दोगे तो मुझे कहने की नौबत नहीं आएगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बिलकुल सर, मैं 100 परसेंट

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो खेती किसान के लिये घाटे का सौदा है। किसान जब बिजली लेता है, तब से लेकर और फिर नाना प्रकार की उसकी समस्याएं आती हैं। बिजली सुधार के नाम से उसकी बिजली काटी जाती है। जो सरकार घोषणाएं करती हैं, वह 24 घंटे की करती है। किसान को 8 घंटे भी बिजली देती नहीं। अगर थोड़ा-सा भी किसान का ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो फिर वह ही अपने साधन से लाएगा, वापस ठीक कराएगा, फिर ले जाएगा। फिर किसान के लिये एक समस्या और खड़ी कर दी। कभी कहते हैं डी.ओ. लगायेंगे, फिर डी.ओ.हटाकर फिर जी.ओ. लगाये। अब जी.ओ. भी हटा रहे हैं। लेकिन अब एक ताजा समस्या हमारे अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जो मेरे ध्यान में आयी है, जो किसानों ने बतायी है, वह यह है कि जब किसान ने एग्रीकल्चर का कनेक्शन लिया तो उसने अपने फ्लेट रेट के ऊपर आवेदन किया, फ्लेट रेट के ऊपर उसको कनेक्शन मिल गया। आपका जो भी मिनिमम-मैक्सिमम चार्जेज होता है, विभाग उसको जो बिल भेजता है, वह बिल बराबर जमा कराता रहा है और अपना जीवन यापन करता है लेकिन अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड पिछले कुछ दिनों से पता नहीं क्या इनके, कहां से वह अदृश्य शक्ति आयी है, कोई आदेश नहीं इस प्रकार का अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का, कि जो किसान फ्लेट रेट पर अपना कृषि का कनेक्शन चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके फ्लेट रेट को हटाकर मीटर लगाये जा रहे हैं और मीटर के आधार पर, वह मीटर की डी.पी. भी पता नहीं कहां लगाते हैं। वह जो बिल किसान का आता था, वह चार गुना, छह गुना और आठ गुना तक बढ़ गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसान के साथ में अन्याय है। एक तो कर्ज से डूबा हुआ किसान आत्महत्या कर रहा है। उसके पास जीने का कोई साधन नहीं है। वह व्यवस्था आपकी सरकार कर नहीं रही है और बिजली के मामले में जिस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है वी.सी.आर. के नाम पर लाखों-लाखों रुपये के मर्जी आये जिसके भर दिये, हस्ताक्षर करने से मना किया, लगा देते हैं, भर देते हैं।

अब मेरे सीकर में 65 हजार से भी ज्यादा एग्रीकल्चर कनेक्शन हैं,

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

जिसमें 24-25 हजार, माननीय मंत्री महोदय, ऐसे कनेक्शन हैं, जो फ्लेट रेट से चल रहे थे। कोई 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से चल रहे हैं। अगले बिल दे रहे हैं जो किसान को आ रहा है। अब आनन-फानन में मीटर लगा रहे हैं। कभी सुपर ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, लेकिन मीटर उसकी बिना अनुमति के लगाकर उससे चौथ वसूली की जा रही है, जिससे किसान का जीना दूभर हो गया है। वह आत्महत्या के लिये मजबूर हो रहा है। वह संघर्ष कर रहा है, आन्दोलन कर रहा है, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जूं अगर नहीं रेंगे तो मैं समझता हूं यह जो परिणाम अभी दिखा है न उप-चुनाव में, यह परिणाम भी आने वाले समय में माननीय मंत्री महोदय, आने वाला है। पूरी सरकार का आने वाला है तो कृपया इससे थोड़ा बहुत बचवाइये। हम जितने आये, उतने तो आने की चेष्टा कीजिये। किसान को आप मार रहे हैं, आपने उसकी मर्जी के बगैर पहले तो उससे सिक्योरिटी राशि के नाम पर वसूल कर लिये। अब आपको धन्यवाद दूंगा कि मंत्री महोदय ने उसको रोका और वापस थोड़ी-बहुत दिलायी भी, वह भी अभी तक पूरी नहीं मिली। लेकिन आज तो महत्वपूर्ण समस्या है, वह यह है कि बिना उसकी अनुमति के फ्लेट रेट के किसान के कनेक्शन को आप क्यों कर रहे हैं मीटर के ऊपर और उससे चौगुनी, आठ गुनी, दस गुनी राशि क्यों वसूलना चाह रहे हैं? यह इतनी-सी बात है। मैं तो आपका शिष्य हूं, आपके आदेश की पालना करता हूं। कृपया आप थोड़ा-सा मंत्रीजी से यह कहलवा दें कि किसान के साथ यह सरकार अब बिजली के मामले में अत्याचार नहीं करेगी और यह वापस फ्लेट रेट के ऊपर, जो फ्लेट रेट से कनेक्शन था, उसी आधार पर बिल लिया जाएगा। यह थोड़ा-सा फरमा दें तो मैं समझता हूं किसान जी लेगा।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है, जो फ्लेट रेट के किसान थे, उनको हम मीटर प्रणाली पर ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से ऊर्जा के मामले में मैं कह सकता हूं कि पिछले चार साल में जो हमने

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

काम किये हैं, और खास तौर पर आम उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए और किसानों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत ही सराहनीय काम किया है। किसानों के बारे में जो भी विपक्ष से सुझाव आये, उनको गहराई से हमने विचार-विमर्श करके, उनके लिये हम जो कुछ कर सकते थे, हमने उनके लिये किया है।

जैसे अभी बताऊं कि नियामक आयोग ने किसानों की दर दो बार बढ़ाई। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस विधान सभा पटल से माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जो कि किसान की हितैषी हैं, किसानों के प्रति सोच अच्छी रखती हैं कि दो बार बढ़े हुए बिजली के बिल को सरकार ने अपने खाते पर लिया। जो बिजली के बिल एक बार 52 पैसे से 55 पैसे तक बढ़ गये थे, सरकार ने उस बढ़े हुए बिल को अपने खाते पर लिया। दूसरी बार 25 पैसे बढे, उसको भी सरकार ने रोल बैक करके अपने खाते पर लिया है। इससे राज्य सरकार पर लगभग 1800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, किसानों के लिए पिछले चार साल में लगभग 27 हजार करोड़ रुपये क्रॉप सब्सिडी के माध्यम से इस सरकार ने दिये। पूर्ववर्ती सरकार की अगर मैं बात कहूं तो उनके पूरे पाँच साल के कार्यकाल में क्रॉप सब्सिडी के माध्यम से दस हजार करोड़ रुपये मात्र डिस्कॉम को दिये। जहां विजिलेंस की बात कर रहे हैं तो आपने स्वयं देखा होगा कि जहां विजिलेंस होती थी, किसान से दो हजार रुपये कम्पांउडिंग लेते थे। उसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घटा कर एक हजार रुपये कम्पांउडिंग की और दस हॉर्स पावर के ऊपर जो भी कम्पांउडिंग थी उसको हमने पाँच सौ रुपये तक लाकर छोड़ा।

अगर हम सिविल लाइबिलिटी की बात करें तो किसान 20 परसेंट जमा करके, विजिलेंस से उसके खिलाफ जो नोटिस निकला है उसको मात्र 20 परसेंट भर कर सैटलमेंट में आ सकता है। जहां उसके खिलाफ हम 12 महीने का चार्जेज लेते थे पैनल्टी, डबल दि प्राइजेज अण्डर ट्वैल्व मन्थ्स, यानी प्रत्येक हॉर्स पावर पर यूनिट, उसको हमने घटाकर दो महीने कर दिया। जहां किसान पाँच एच पी की मोटर पर एक लाख रुपये विजिलेंस भरता था, आज वह किसान मात्र दस हजार रुपये भरकर विजिलेंस से बाहर

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

निकल रहा है तो जहां तक मैं समझता हूं, आपने सिक्योरिटी की बात उठायी थी, उसको मैंने सीरियसली लिया कि जहां हम इण्डस्ट्रीज को कनेक्शन दे रहे हैं, उसमें तो सिक्योरिटी अमाउन्ट 180 रुपये है और किसान से 600 रुपये ले रहे थे। मैंने उसको भी घटाकर 15 रुपये प्रति हॉर्स पावर सिक्योरिटी अमाउन्ट किया है। मैं यह बात मानता हूं। हम भी सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से बंधे हुए हैं। उसमें क्लीयर कट डायरेक्शंस हैं कि प्रत्येक कंज़ूमर को मीटर प्रणाली से जोड़ा जाए। उदय योजना के तहत जो एम.ओ.यू. हुआ है जिसमें सरकार ने, 80-82 हजार करोड़ रुपये का जो लोन है, उसमें 64 हजार करोड़ रुपये सरकार ने अपने खाते पर लिया है। जिसके लिए सरकार ने 06 हजार करोड़ रुपये इंट्रेस्ट के भरना शुरू किया है। उसके तहत भी यह लिखा हुआ है कि राजस्थान में जितने भी एग्रीकल्चर कनेक्शंस हैं, उनको हमको हण्ड्रेड परसेंट मीटरिंग करना पड़ेगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमको लिखकर दिया है कि अगर आपने इसको 100 परसेंट मीटरिंग नहीं किया तो हम आपको कंज़ूमर की क्रॉप सब्सिडी बन्द कर देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आज मीटर प्रणाली भी है तो प्रत्येक यूनिट हम किसान से 90 पैसा लेते हैं, 03 रुपये 85 पैसे सरकार वापस प्रति यूनिट क्रॉप सब्सिडी के माध्यम से हमको देती है। 90 पैसे हम किसान से लेते हैं। जिसके तहत अभी मैंने आपको बताया कि पिछले चार साल में हमारी सरकार ने 27 हजार करोड़ रुपये क्रॉप सब्सिडी के माध्यम से हमको दिये हैं और इनके पाँच साल के कार्यकाल में क्रॉप सब्सिडी के माध्यम से मात्र दस हजार करोड़ रुपये मिले।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत मीटरिंग प्रणाली कम्पलसरी है। उदय योजना के तहत खासतौर पर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उन्होंने भी हमको निर्देश दिये हैं कि प्रत्येक किसान की मीटरिंग करें। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तो हमको सख्त लैटर लिखा है कि अगर आपने मीटरिंग नहीं की तो आपकी जो क्रॉप सब्सिडी है, जो फ्लैट रेट पर है, हम आपको फ्लैट रेट देना बन्द कर देंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं क्योंकि मैं भी स्वयं एक किसान हूं इसलिए मैं किसान की पीड़ा को जानता हूं। निश्चित रूप से

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

आपने जो बात ध्यान में लायी है, इसकी मैं पूरी समीक्षा करूंगा और समीक्षा करके जो मैं इस पर कार्यवाही कर सकता हूं ....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): घोषणा करो किसान के बेटे हो। किसान से जबरदस्ती सीकर जिले में 24031 फ्लैट रेट वालों को मीटर में बदल दिया जानबूझ कर बिना उसकी अनुमति के।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरी संख्या है। जयपुर डिस्कॉम में साढ़े चार लाख कृषि कनेक्शन हैं। इसमें मात्र 22 हजार कनेक्शन फ्लैट रेट के हैं और 1.52 लाख कनेक्शन वह हैं जिनमें कभी न कभी हमें मीटर लगाना है। फिर अजमेर डिस्कॉम में 4.2 लाख कनेक्शन हैं, फ्लैट रेट से जो कनेक्शन दिये हुए हैं वह मात्र 36 हजार हैं, पूरे अजमेर डिस्कॉम के। जोधपुर डिस्कॉम में 2.83 लाख कनेक्शन हैं और 36 हजार कनेक्शन ऐसे हैं जो फ्लैट रेट प्रणाली से दिये हुए हैं। दूसरे साढ़े चार लाख कनेक्शंस हैं जो मीटर प्रणाली से दिये हैं। मीटर जलने के कारण उसको हम फ्लैट रेट देते हैं। पूरे राजस्थान में आफिशियल जो कनेक्शंस हैं तीनों डिस्कॉम के मिलाकर, वह मात्र 94 हजार कनेक्शन हैं, जो फ्लैट रेट कनेक्शन हैं। जो फ्लैट रेट प्रणाली में हैं उन्होंने एप्लाई किया है और एप्लाई करके वे फ्लैट रेट चला रहे हैं। पर चूंकि किसी किसान का मीटर जल जाता है तो हम टाइम पर बदल नहीं सकते तो उसको हम फ्लैट रेट पर कन्वर्ट करके उनसे फ्लैट रेट के पैसे वसूल करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं मेरे अधिकारियों से बात करूंगा, मीटिंग करके जो भी किसानों को अच्छा फायदा हो सकेगा, वह मैं निश्चित रूप से करूंगा। आप मेरे ऊपर विश्वास करें। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री भँवरसिंह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरा इतना ही निवेदन है कि जो वर्षों से फ्लैट रेट पर चल रहे थे, उनको अभी दो महीने, छह महीने में ही मीटर प्रणाली से कर रहे हो। उनको तो कम से कम वापस कराओ। आगे रोको इसको।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया। जवाब आ गया। श्री भँवरसिंह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जवाब तो आ गया लेकिन जवाब आया ही नहीं न। आया ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, मीटर प्रणाली से दस गुना बढ़ा दिया आपने, किसान का बिल और किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। आप यह घोषणा ही नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा? आप किसानों के हितैषी होने की बात कर रहे हो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, रेगुलेटरी कमीशन ने दो बार कृषि पर रेट्स बढ़ाये, पर आज भी वही रेट हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में वर्ष 2000 में जो रेट बढ़े थे, वर्ष 2017-18 में भी वही रेट चल रहे हैं। हमने कोई नया रेट किसानों के ऊपर बढ़ाये नहीं हैं। जो भी बढ़ी हुई रेट्स थी, वह सरकार ने अपने खाते पर ले लिया है और किसानों का भार सरकार ने अपने ऊपर लिया है। किसान को तो 90 पैसे प्रति यूनिट ही बिजली दे रहे हैं। यह मैं आपको निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मानिकजी, आप कुछ पूछ रहे हैं? ...(व्यवधान)... नहीं, अब नहीं। मैंने मानिकजी को इजाजत दी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): वह मीटर लगाकर दस गुना चार्ज ले रहे हैं। वह मार रहे हैं न।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का फरमाना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में यह मजबूरी है कि हर कनेक्शन को मीटर कनेक्शन करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्षजी, जहां तक कानून का सवाल है, आप सही कह रहे हैं। पर आप गृह मंत्रीजी से तो कुछ सीखिए विद्युत मंत्रीजी। इन्होंने जाप्ता फौजदारी जो देश में लागू है, उसका राजस्थान संशोधन लाये हैं और वह प्रवर समिति से पास होकर सदन में आ चुका है। आप इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का राजस्थान संशोधन लाइये और उस संशोधन में यह कहिए आज जिसका फ्लैट रेट है वह फ्लैट रेट बदला नहीं जायेगा। यह वित्त विभाग कौन होता है जो आपको कह रहा है। वित्त विभाग का मतलब समझिए एक मिनट। वित्त विभाग का मतलब है माननीय मुख्य मंत्री महोदया। डी. बी. गुप्ता साहब जो भी आपको कहते हैं न, कोई जरूरी नहीं है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी भी वही बात कह रही हैं। मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाइये। यदि हमने 94 हजार फ्लैट रेट को मीटर रेट कर दिया तो एक भी वोट उन परिवारों का अपने को नहीं पड़ना है और यदि आपको

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वोट लेने ही नहीं हैं अगले चुनावों में, तो वह आपका फैसला है। उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि आप विद्युत एक्ट का राजस्थान संशोधन लायें और आज जो फ्लैट रेट पर हैं, उनको फ्लैट रेट पर रहने दें। यह राजस्थान और किसानों के हित में है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): अध्यक्ष महोदय, लूणकरणसर और लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो बात रखी है, मैंने यही कहा है कि निश्चित रूप से इसकी जांच करके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने यही कहा है।

श्री अध्यक्ष: रास्ता निकालेंगे आप?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): मैं इस चीज को समझता हूं। मैं स्वयं खेती पर निर्भर हूं। खेती पर ही मेरा परिवार चलता है तो मैं समझता हूं कि किसानों की पीड़ा क्या होती है। मीटर प्रणाली से क्या पीड़ा होती है और फ्लैट रेट की उसकी क्या आवश्यकता है। मैं आपको विश्वास देता हूं कि मैं निश्चित रूप से इस पर विचार-विमर्श करके किसानों के हित में कोई न कोई काम करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री भँवरसिंह।

बीकानेर शहर में पोलीथीन से आवारा गौवंश की मौत

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बीकानेर शहर में जो आवारा-बेसहारा गौवंश हैं, उनकी वजह से बीकानेर के आम नागरिकों को समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है। इसके साथ-साथ पोलीथिन पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध होने के बावजूद बीकानेर में धड़ल्ले से पोलीथिन की बिक्री हो रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा गौवंश हैं जिनकी वजह से बीकानेर शहर में जो आवारा और बेसहारा गौवंश हैं, उसकी एक बहुत गम्भीर समस्या पैदा हो गयी है। करीब दस से पन्द्रह हजार बेसहारा गौवंश हैं, जो शहर में गलियों और सड़कों पर घूमते रहते हैं जिसकी वजह से पिछले दो सालों में कई बार दुर्घटना हुई है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, गत एक महीने में दो लोगों की मौत सांडों के लड़ने की वजह से मोटर साइकिल से टकराने से हो गयी।

(श्री भंवरसिंह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ पोलीथिन पर जो प्रतिबंध है, वो पिछले काफी समय से पूरे प्रदेश में लागू है लेकिन पोलीथिन का उपयोग पूरे प्रदेश में और विशेषकर बीकानेर जिले में खुलेआम हो रहा है, सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है और उसकी वजह से पोलीथिन खाकर के हमारी जो गायें हैं वो, हमारा जो गौवंश हैं वो मृत हो रहा है, हर वर्ष हजारों गायें मर रही हैं। एक-एक मृत गाय के पेट से 20 से 40 किलो पोलीथिन निकल रही है। यह जो पशुपालन विभाग के आंकड़े हैं उसमें भी आया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि भा.ज.पा. का जो सरकार का घोषणा पत्र था, उसमें बाकायदा लिखा गया है कि हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नंदी गौशाला खोली जायेगी। तीन वर्ष पूरे होने पर सरकार का जो बीकानेर में जश्न मनाया गया, पूरी सरकार वहां पहुंची और उस समय बीकानेर में नंदी गौशाला खोलने की घोषणा की गयी थी। आज चार साल पूरे होने जा रहे हैं लेकिन बीकानेर में नंदी गौशाला अभी तक नहीं खोली गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में बीकानेर संभाग मुख्यालय एक मात्र ऐसा है जहां नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई गौशाला संचालित नहीं की जा रही है और जिसकी वजह से गौवंश की और हमारे जो आवारा और बेसहारा गौ-धन है, उसकी संख्या 10 से 15 हजार के करीब हो गयी है। अध्यक्ष महोदय, बीकानेर शहर के आसपास करीब 42 हजार गोचर भूमि स्टेट के समय से उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से हमारे यू.डी.एच. मिनिस्टर और गोपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले डेढ़ साल से बीकानेर में आवारा और बेसहारा गौवंश की समस्या का स्थाई समाधान करने की मांग को लेकर आन्दोलन चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। आपने अपना बिंदु रख दिया। समाप्त कीजिए।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): एक मिनट में मैं अपनी बात कन्क्लूड करूंगा।

जो आन्दोलन चल रहा है, पूरी बीकानेर की जनता के द्वारा किया जा रहा है। तीन-चार महीने पहले बीकानेर बंद भी करवाया गया और 17

(श्री भंवरसिंह)
जनवरी से आज तक, बीकानेर शहर में गौवंश के लिए स्थाई समाधान, बीकानेर में गौशाला की मांग को लेकर और बीकानेर में पोलीथिन पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर लगातार धरना चल रहा है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय मंत्री श्री कृपलानीजी। जवाब आ रहा है। जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन रहेगा कि गाय के नाम यह सरकार, वर्तमान में जो सरकार आयी है, वो गाय के नाम पर आयी है और यह सरकार गाय को भूल गयी और जिसकी बद्दुआ या जिसकी सज़ा भी इस सरकार को मिली है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आप किसके नाम पर आये थे?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, आज बीकानेर की जनता सड़कों पर है, बीकानेर की जनता धरना दे रही है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। आप अपना पाइंट बोल चुके हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, गाय का मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: हां तो वो जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, गाय और राम के नाम पर जो सरकार आज अस्तित्व में है और जो सरकार गाय को भूल जाए अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उसको किसी भी प्रकार से राज करने का अधिकार नहीं है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस वाले, सुन तो लो।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहूंगा मंत्री महोदय से कि इस गम्भीर मुद्दे पर वो बीकानेर की जनता को जवाब देकर आश्वस्त करें।

श्री अध्यक्ष: वो बोल रहे हैं। वो आपको जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आभार।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपको धन्यवाद, आप गाय की बड़ी चिंता कर रहे हो, मैं समझता हूं यह कांग्रेस के लिए भी ...(व्यवधान)...

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आप देख कर रहे हैं इसीलिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बात उठायी है, मैं उसका जवाब देने में यही कहूंगा कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी, 55 साल तक इनका राज रहा, गाय की चिंता इन्होंने नहीं की। गाय की चिंता अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, चाहे वो केन्द्र की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो।

स्वच्छ भारत अभियान भी हमने चलाया, शौचालय भी हम ही बना रहे हैं, गौशालाओं का भी निर्माण हमने ही कराया है, पहले भी कराया भैरोंसिंह जी के राज में, वसुन्धराजी के राज में, अब भी हम ही करा रहे हैं। इसलिए आप चिंता मत करो आपकी बात का पूरा ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा है, मेरा उसमें ...(व्यवधान)... क्या बोल रहे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: शकुन्तलाजी, बैठिये। डिस्टर्ब मत कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): आपकी योजनाएं बड़ी अच्छी थीं इसलिए आपकी 21 सीटें रह गयीं। ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): कितनी मर रही हैं, हिंगोनिया गौशाला में कितनी गायें मर रही हैं, कौनसी हमदर्दी दिखायी?

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हिंगोनिया में अभी जाकर देख लो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या किया आपने उनके लिए? क्या नया बजट दे दिया? सारी गायें गौशालाओं में भूखी मर रही हैं।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अभी आप हिंगोनिया में जाकर देखो।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): देख लिया जाकर।

श्री अध्यक्ष: शकुन्तलाजी, बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): हिंगोनिया जैसी गौशाला पूरे हिन्दुस्तान में ही नहीं है। पूरा नक्शा बदल दिया हिंगोनिया का हमने, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने। ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, जो गौशालाएं जन सहयोग से चल रही हैं उनकी जमीन ही गौशालाओं के नाम कर दें तो हम इनको मान जाएं, कुछ नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे रहे हैं। आप उसको सुनिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं यही निवेदन करूंगा कि हमने सबसे पहले एक दल का गठन किया है। प्रतिबंधित पोलीथिन को जब्त करने के लिए निगम द्वारा स्थाई रूप से स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, राजस्व निरीक्षकों का दल गठित किया है। दल द्वारा 8 दिसम्बर, 2014 से 30 जनवरी, 2018 तक 3752.14 किलोग्राम पोलीथिन थैलियां आपके यहां जब्त की जा चुकी हैं। इससे पूर्व पोलीथिन विनिर्माण, उपयोग एवं भण्डारण करने वाली 27 फर्मों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में इस्तगासे दायर करवाये गये। वर्तमान में नियमित रूप से प्रतिबंधित पोलीथिन को जब्त करने की कार्यवाही लगातार जारी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिबंधित पोलीथिन का उपयोग नहीं करने के लिए हम जागरुकता के लिए भी समय-समय पर कार्यक्रम चलाते रहते हैं और सिर्फ बीकानेर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी मुख्य मंत्रीजी को जो लगातार इस स्वच्छता के मामले में, माननीय भँवरसिंहजी साहब, आपको ध्यान होगा कि अभी हमने जो लोगों की घरेलू गाय हैं, जो लोग सुबह दूध निकालते हैं और गाय को चरने के लिए बाजार में भेज देते हैं, हमने उन पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। पहली बार हुआ होगा, इसकी वजह से कई जगह उस पर रोक भी लगी है। साथ ही प्रतिबंधित पोलीथिन के उपयोग को निरुत्साहित करने के लिए नगर निगम अपने निरीक्षकों, जमादारों, सफाई कर्मचारियों के माध्यम से जागरूकता का कार्य निरन्तर कर रहा है।

प्रतिबंधित पोलीथिन का उपयोग नहीं करने हेतु वाल पेंटिंग का कार्य नगरीय क्षेत्र में आपके यहां 120 स्थानों पर कराया गया? आपने देखा होगा बीकानेर में? देखा है? मैं बीकानेर की पूछ रहा हूं। बीकानेर में 120 जगह वाल पेंटिंग देखी की नहीं देखी आपने?

श्री भंवरसिंह (कोलायत): आप बताइये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): बताइये, आपने देखी ही नहीं, फिर आप सवाल उठा रहे हो। कितना हम वहां पर जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। विकल्प के रूप में निगम स्वयंसेवी संस्थाओं आदि द्वारा कपड़े के थैले आम जन के मध्य व्यस्त बाजारों और सब्जी मण्डी में लोगों का जन सहयोग लेकर वितरित कर रहे हैं सब जगह। इसके साथ ही समाचार-पत्रों, स्वच्छ भारत मिशन के तहत, नुक्कड़, नाटक आदि में पोलीथिन का उपयोग नहीं करने हेतु आम जन को जागरूक करने का हम प्रयास कर रहे हैं और यह बीकानेर में भी हमारा बहुत गम्भीरता से प्रयास चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय, अभी आपने एक बात कही थी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): पूरे राजस्थान में चल रहा है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): पूरे राजस्थान में ही चल रहा है, वो तो सही है। अध्यक्ष महोदय, ग्राम सुजानदेसर की 34.42 हैक्टेयर भूमि में आवारा व अनाथ पशुओं को रखने के लिए, जो बीकानेर में ही है, कांजी हाउस एवं गौशाला हेतु नगर निगम, बीकानेर द्वारा चिह्नित कर लिया गया है। इस भूमि का आबंटन कराये जाने के प्रयास प्रक्रियाधीन हैं।

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें। वक्ता जो बोल रहे हैं उसके सामने वाली टेबल, किरणजी, किरणजी, वो वक्ता बोल रहे हैं, डिस्टर्ब होता है, आप बात मत कीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो आप?

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए बहुत शीघ्र ही कांजी हाउस खोलने का,

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

गौशाला खोलने का हमने प्रस्ताव ले लिया है, जमीन हमने आइडेंटिफाई कर दी है और मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही बीकानेर में और पूरे राजस्थान में पोलीथिन की समस्या का समाधान हम कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखराम विश्नोई। ...(व्यवधान)... नहीं। श्री सुखराम विश्नोई, मैंने आपको पुकारा है। नहीं, आप बैठिये, जवाब आ गया। ...(व्यवधान)... अब जवाब आ गया।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, यह बहस नहीं खोल सकता मैं। मैं बहस नहीं खोल सकता। आप बैठिये। श्री सुखरामजी।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: मैंने कहा बैठिये आप। ...(व्यवधान)... मिस्टर भँवरसिंहजी, बैठिये, आपका जवाब आ गया। श्री सुखराम विश्नोई।

श्री भंवरसिंह (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गौशालाओं पर अनुदान बंद कर दिया ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: आप उनसे और बात कर लेना। श्री सुखराम विश्नोई।

राजकीय आवासीय छात्रावासों में गद्दे-तकियों की घटिया सप्लाई

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीमराव अम्बेडकर छात्रावास टोंक; देवनारायण छात्रावास बारां; अम्बेडकर छात्रावास बारां; देवनारायण आदर्श बालिका छात्रावास मित्रपुरा, दौसा; देवनारायण बालिका छात्रावास कोटा और कोटा छावनी के बारे में मैंने स्वयं वहां के अधीक्षकों और मेरे कार्यकर्ताओं से फोन करके पूछा। वहां 1.72 करोड़ रुपये के गद्दे और तकिये सप्लाई किए गए। उन गद्दों और तकियों में लुगदी मिली या कचरा मिला।

अध्यक्ष महोदय, होस्टलों के खाने के बारे में बार-बार शिकायतें तो मिलती ही मिलती हैं कि वहां तेल घटिया खरीद रहे हैं, सब्जी घटिया ला रहे हैं, गेहूं घटिया खरीद रहे हैं या आटा घटिया ला रहे हैं। लेकिन जो ओढ़ने-बिछाने का है, चादर, ऊपर की जो बैडशीट है, वह धोकर वापस लड़के

(श्री सुखराम विश्नोई)

ने पलंग के ऊपर बिछाई तो वह 2 बाई 2 फुट की रह गई। यह जो 6 होस्टल हैं, इन सभी के वार्डनों को पूछा गया। मैंने स्वयं टेलीफोन करके पूछा तो वह कह रहे हैं कि ऊपर से आई हैं। कई कह रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा कि आपने ली तब देखना चाहिए था। कहा कि हमारी हिम्मत नहीं है कि हम इनके खिलाफ में बोलें।

अध्यक्ष महोदय, यह एक आधा करोड़ का नहीं, 1.72 करोड़ रुपये का घोटाला है। यह बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, जो वहां छात्रावास के अंदर रह रहे हैं, उनके ओढ़ने-बिछाने के कपड़े सही नहीं हैं। यह जो घोटाला हुआ है इसकी क्या जांच की गई है? यहां जयपुर के स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं इनकी और जो ऊपर से सहमति लेते हैं उन अधिकारियों के बिना यह घोटाला नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसमें किस तरह की जांच की गई? आज क्या स्थिति है? वह जो गद्दे, तकिये फटे हुए थे वे बदले कि नहीं बदले? पूरे राजस्थान में इनकी कहां-कहां सप्लाई की? इसका पूरा विस्तृत जवाब चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: आज संबंधित मंत्री नहीं हैं, इसलिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसका जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 6 छात्रावासों में निम्न स्तर के गद्दे और चद्दर सप्लाई होने की बात कही है। समाचार-पत्रों में भी यह समाचार प्रकाशित हुए। जिस दिन समाचार प्रकाशित हुए, राज्य सरकार ने उसी दिन ही इसकी वस्तु स्थिति की रिपोर्ट मंगाने और इसमें आवश्यक कार्यवाही करने का काम प्रारंभ कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, यह जिससे सप्लाई की बात कर रहे हैं, यह बात को वहां ले जाना चाहते हैं जैसे बहुत बड़ा घपला हो गया हो। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को सप्लाई जिसने की है वह नेशनल टैक्सटाइल कॉरपोरेशन भारत सरकार का उपक्रम है।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): भारत सरकार का कहकर ये अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं? यह कोई जवाब है?

श्री अध्यक्ष: आप पूरा सुनिए। पूरा सुनिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आप संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा।

श्री अध्यक्ष: वह पूरा जवाब देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कह रहा था 27.07.2016 को 4 करोड़ 24 लाख रुपए का भारत सरकार के उपक्रम नेशनल टैक्सटाइल कॉरपोरेशन को 8 आइटम का क्रय आदेश दिया। इस क्रय आदेश के लिए भी एक क्रय समिति बनी। समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग के एडिशनल डायरेक्टर की सदारत में एक क्रय समिति बनी। उस क्रय समिति ने यह सारे आदेश दिए। इस क्रय समिति ने आदेश देने से पहले जो नेशनल टैक्सटाइल कॉरपोरेशन का शो रूम है, उससे सैम्पल लिए और उसके आधार पर ही सारा क्रय आदेश दिया।

अध्यक्ष महोदय, यह जो आदेश है, वह जो आरटीपीपी एक्ट 2013 बना है, उसके नियम 32 और 38 के अंदर यह अधिकार दे रखा है कि अगर कोई भी सरकार की आइडेंटिटी है, कोई पब्लिक अंडरटेकिंग सरकार की है तो उसको सीधा आदेश दिया जा सकता है। यह डेढ़ वर्ष पहले के आदेश हैं। डेढ़ वर्ष में गद्दे हों, तकिये हों, उनका उपयोग भी होता है। उनके धागे भी टूट जाते हैं। वह गंदे भी हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसके बावजूद भी जब यह सारी बात सामने आई, राज्य सरकार किसी चीज को छिपाना भी नहीं चाहती। विभागीय स्तर पर एक 3 सदस्यीय कमेटी और बनाई गई कि इसमें जहां-जहां से शिकायत आ रही हैं, वह क्या शिकायतें हैं। राजस्थान सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए हमारे निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव की अध्यक्षता में एक जांच दल बनाया है जिसमें अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता और प्रशासन, वित्तीय सलाहकार, उप निदेशक राइस और उप निदेशक छात्रावास सदस्य रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इसमें सामग्री क्रय करने में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2013 है उसके रुल 38 में लिखा है कि केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग, बोर्ड या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित कोई माल या उपलब्ध कराई गई कोई विशिष्ट सेवाएं, इसमें सीधा क्रय करने का इस एक्ट में लिखा हुआ है।

मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आपने बताया, न केवल इन 6 छात्रावासों में जो कि आपने कहा कि मैंने इन छात्रावासों के अधीक्षकों से बात की, बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर जो यह 2016-17 के अंदर, 27.07.2016 को जो 4 करोड़ 24 लाख रुपये का क्रय हुआ है उसकी पूरी जांच करवाएंगे। इस जांच के आंधार पर कोई भी अगर दोषी होगा तो सरकार निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी।

अध्यक्ष महोदय, सरकार खुद संवेदनशील है। गरीब बच्चों के छात्रावासों में यह सारी चीजें सप्लाई की गई हैं। अगर वास्तविकता में चद्दर छोटी हो गई या गद्दों के अंदर कोई लुगदी और कचरा मिला है तो इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

एक मिनट, महानुभाव आप भी यूं ही अख़बार में पढ़कर आ गए। अगर आपके पास में कोई सूचनाएं हैं कि कौन- कौनसा छात्रावास, कितने गद्दे और उसमें क्या-क्या शिकायतें हैं तो मुझे अभी दे दो, मैं अभी जांच के लिए जांच कमेटी को भेज देता हूं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, जांच से कोई मतलब नहीं है। एसीडी में मुकदमा दर्ज करवाया जाए तब पता चलेगा। आइंदा कोई अधिकारी बेईमानी नहीं करेगा। जांच से क्या होगा? जांच के बाद तो बैठे रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: जांच के बाद जो भी स्थिति बनेगी, जो भी होगा तो कार्यवाही की जाएगी।

295 के अंतर्गत प्राप्त सूचनाएं। श्री अर्जुन लाल जीनगर। (अनुपस्थित।)

एक माननीय सदस्य: हैं।

श्री अध्यक्ष: हैं तो बोलें।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

चित्तौड़गढ़ में स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों के संविदा कर्मचारियों का नियमानुसार भुगतान

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित सभी स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से पीटीआई कम योगा इंस्ट्रक्टर, वर्क एक्सप्रेस इंस्ट्रक्टर, ड्राइविंग एंड पेंटिंग इंस्ट्रक्टर व म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के पदों पर सरकार के द्वारा तय वेतन के आधार पर पदस्थापन किया गया है। सेवा प्रदाता एजेंसी ने सर्विस चार्ज के आधार पर विभाग से अनुबंध किया है। चित्तौड़गढ़ जिले में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा उक्त पदों पर संविदाकर्मियों को विभाग द्वारा तय मानदेय के आधार पर लगाया है लेकिन सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा लगाए गए संविदाकर्मियों को तय मानदंड के अनुसार भुगतान नहीं दिया जा रहा है और न ही पीएफ काटा जा रहा है।

सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा कार्यरत संविदाकर्मियों का वेतन बैंकिंग प्रणाली से भी नहीं किया जाता है। सेवा प्रदाता एजेंसी द्वारा तय मानदेय के अनुसार भुगतान नहीं करके संविदाकर्मियों का शोषण किया जा रहा है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सेवा प्रदाता एजेंसी की उच्च स्तरीय जांच करवा कर संविदाकर्मियों को पिछले महीनों में कम दिया गया वेतन दिलवाने के लिए पाबंद कराएं तथा दोषी सेवा प्रदाता एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करवाने की कार्यवाही कराने का निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शिमला बावरी।

सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 295 के तहत बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि वर्तमान में किसानों के खेतों में सरसों की बंपर फसल खड़ी है और फरवरी माह के अंत तक किसान बेचने के लिए बाजार में लाएंगे।

गत वर्ष सरकार द्वारा सरसों की सरकारी खरीद नहीं की गई थी

(श्रीमती शिमला बावरी)

जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। राजस्थान के कई जिलों में सरसों की भारी मात्रा में फसल होती है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कई जिले शामिल हैं। किसानों द्वारा वर्तमान में बार-बार मांग की जा रही है कि सरकार सरसों की खरीद समर्थन मूल्य पर करें। अत: किसानों की आर्थिक स्थिति व मांग को देखते हुए सरकार को ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वर्तमान में सरसों की खरीद समर्थन मूल्य पर करें ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटू सिंह।

जैसलमेर जिले के राजस्व गांवों में बारानी भूमि का आवंटन

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं जैसलमेर जिले के राजस्व गांवों में बारानी भूमि आवंटन की स्वीकृति एवं पूर्व में निरस्त किए गए आवेदन पत्रों को पुनर्जीवित कर बारानी भूमि आवंटन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

जिस वक्त जैसलमेर जिले के निवासियों को पानी के लिए भी मोहताज होना पड़ता था, उस समय यहां के स्थानीय लोगों ने जिले की भूमि को सुरक्षित रखा। इस जिले के भूमिहीन लोगों को केवल 1970 और 1975 में थोड़ी बहुत बारानी जमीन का अलाटमेंट किया गया था। उसके बाद भूमि उपलब्ध होते हुए भी 35 से 40 वर्ष बीत जाने के बावजूद जिले के स्थानीय निवासियों को एक बार भी बारानी भूमि का आवंटन नहीं किया गया। जिले के लोगों द्वारा बार-बार मांग करने पर भी पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा नहरी क्षेत्र में बारानी भूमि अलाटमेंट पर रोक लगाए रखी गई तथा वर्ष 2003 की भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जिले के भूमिहीन किसानों से आवेदन पत्र लेकर उन्हें राजस्व क्षेत्र में बारानी भूमि आवंटन करने के लिए आवंटन शुरू करने का प्रयास किया था जिस पर कांग्रेस सरकार के आते ही नहरी क्षेत्र में रोक लगा दी। पिछली कांग्रेस सरकार के राजस्व उपनिवेशन विभाग के पत्र क्रमांक 3(25)उप/91 दिनांक 11.03.2010 द्वारा सरकार ने बारानी भूमि आवंटन के लिए जिलेवासियों के वर्ष 2004 में भरे गए सभी 26335 आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया। सरकार तेल कंपनियों को जमीन

(श्री छोटू सिंह)

दे रही है, पवन ऊर्जा के पंखों, सोलर ऊर्जा के लिए कंपनियों को जमीन दे रही है तो दूसरी तरफ लाखों बीघा जमीन डीएनपी में चली गई। लाखों बीघा जमीन सेना को दे दी गई। हम बिजली उत्पादन के विरोधी नहीं हैं, तेल और गैस उत्पादन के विरोधी नहीं हैं, जीव संरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। उनके लिए कोई आजीविका का वैकल्पिक मुख्य साधन के रूप में भूमि उपलब्ध होते हुए भी बारानी भूमि आवंटन नहीं किया जाना एवं सरकार द्वारा कृषि भूमि सोलर व पवन ऊर्जा को लीज पर देने के लिए भू रूपांतरण की छूट प्रदान की है एवं बारानी क्षेत्र के स्थानीय लोग कृषि कार्यों से भी वंचित रह गए हैं। जैसलमेर की जनता में इस समय बारानी भूमि आवंटन न होने से आक्रोश है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह मांग है कि राजस्व गांवों में बारानी भूमि आवंटन की स्वीकृति देते हुए पूर्व में निरस्त किए गए 26335 आवेदन पत्रों को पुनर्जीवित कर तथा नए आवेदन पत्र प्राप्त कर बारानी भूमि का आवंटन किया जाए ताकि स्थानीय जनता में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ सके।

(12.52 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

लूणी तहसील के काश्तकारों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से भुगतान

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत तहसील लूणी, जिला जोधपुर, राजस्थान के काश्तकारों को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीद, 2016 की फसल खराबे पर फसल बीमा की राशि का भुगतान दिलवाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, खरीफ, 2016 के लिए तहसील लूणी, जिला जोधपुर के करीब 26,611 काश्तकारों ने अपनी 38,493,3694? हैक्टेयर भूमि के लिए अपनी होने वाली कृषि उपज का बीमा करवाया था, जो कुल 24,611 काश्तकारों ने उपरोक्त वर्णित एरिया

(श्री जोगाराम पटेल)
के लिए सम एश्योर्ड 44,81,29,457.1 रुपये का बीमा करवाया था और काश्तकारों के द्वारा व काश्तकारों के लिए सरकार की ओर से कुल 16,01,61,710.07 रुपये का अंशदान, ग्रोस प्रीमियम बीमा कंपनियों के पास जमा करवाया था। कुल प्रीमियम की राशि जमा होने पर काश्तकारों को 44,81,29,457.1 रुपये की राशि फसल का बीमा होने के कारण फसल के खराबे पर मिलने वाली थी परंतु उनके स्थान पर बीमा कम्पनियों की मिलावट से मात्र 6,277 काश्तकारों को ही 6,62,88,828.63 की राशि का भुगतान किया गया है। तहसील लूणी में गत वर्ष (खरीफ 2016) अकाल पड़ने के कारण खरीफ फसल पूर्ण रूप से खराब हो गई थी/नष्ट हो गई थी और इस आधार पर ही राजस्थान सरकार ने तहसील लूणी को पूर्ण रूप से अकालग्रस्त/अभावग्रस्त घोषित किया था और इसी आधार पर राजस्थान सरकार ने काश्तकारों को फसल मुआवजे की राशि भी अदा करने की कार्यवाही की है। जब तहसील लूणी पूर्ण रूप से अकालग्रस्त/अभावग्रस्त है तो इस तहसील के समस्त काश्तकारों को उनकी फसल खराबे पर फसल बीमा की राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है क्योंकि फसल बीमा के क्लेम सम्बन्धी कार्यवाही करने का दायित्व कम्पनी और सरकार का है। इसमें काश्तकारों की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। बीमा कम्पनी की मिलावट से या अन्य कारणों से इस तहसील के मात्र कुछ ही राजस्व ग्रामों में फसल बीमा की राशि प्राप्त हुई है जबकि पूरी तहसील के बीमा करवाए गए सभी काश्तकारों को फसल खराबे पर बीमित राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। चूंकि पूरी तहसील ही अकालग्रस्त है तो उक्त पत्र दिनांक 16.05.2017 के संदर्भ में व प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु XI.3(D) के अनुसार उच्चतम तहसील स्तर के औसत उत्पादकता समंक लेकर फसल बीमा क्लेम का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

इस अतिसंवेदनशील जन हित व तुरंत आवश्यकता व आम जन के हित के विषय को आपके मार्फत सदन में रखने की अनुमति प्रदान कराएं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुखाराम।

मेड़ता शहर के राजकीय चिकित्सालय का क्रमोन्नयन

श्री सुखाराम (मेड़ता): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं मेड़ता शहर के राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता शहर बहुत बड़ा है, जो कि 200-300 गांवों से जुड़ा हुआ है। वहां पर रोजाना इन गांवों से हजारों की संख्या में लोगों का आना-जाना रहता है। भारी मात्रा में लोगों के जुड़ाव व इस शहर में आम जन की सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है।

मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मेड़ता शहर का राजकीय चिकित्सालय, जो कि मेड़ता शहर से बाहर नागौर रोड़ पर स्थित है। मेड़ता जैसे बड़े शहर में यह सिर्फ 40 बैड का अस्पताल है जो कि बहुत ही छोटा है। शहर व इससे जुड़े गांवों की आवश्यकता को देखते हुए, मरीजों की सुविधाओं हेतु इस अस्पताल को क्रमोन्नत किया जाना बहुत ही आवश्यक है। आए दिन ग्रामीण लोगों द्वारा इस अस्पताल को क्रमोन्नत करने की मांग रखी जाती है। इतने बड़े गांवों से जुड़े मेड़ता शहर में इस सिर्फ 40 बैड के अस्पताल से पर्याप्त सुविधाजनक सभी लोगों का इलाज होना काफी कठिन हो गया है।

अत: आपसे निवेदन है कि मेड़तावासियों की भावनाओं को देखते हुए इस सरकारी अस्पताल को 40 बैड से 100 बैड में क्रमोन्नत करने का श्रम कराएं ताकि मरीजों को इलाज में सुविधा मिल सके और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार से लोगों को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल (अनुपस्थित)।

श्रीमती शकुन्तला रावत।

(13.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार 295 में जो अनुपस्थित रहते थे उनके सम्बन्ध में आसन का रवैया बड़ा सख्त था। आसन ने जो एक बार अनुपस्थित रहे उनका नाम पुकारा तो फिर आप उनको दो बार सख्त था।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आसन ने जो एक बार अनुपस्थित रहे उनका नाम पुकारा तो फिर आप उनको दो बार मौका नहीं दिया करते थे। इस बार आसन इतना उदारमना कैसे है?

श्री उपाध्यक्ष: एक बार विराज जाएं। संसदीय कार्य मंत्री महोदय, यह प्रश्न अगर आप मुझसे कल पूछते तो उसका आसन जवाब देता। कल आपके ऐसे भी सम्माननीय सदस्य थे और सत्ता पक्ष के थे जो 295 के समय अनुपस्थित थे और बाद में उपस्थित थे। इसलिए अगर आसन से आप अपेक्षा करते हैं तो फिर दोनों के प्रति हमको उदारता का रवैया अपनाना पड़ेगा।

बानसूर में महिला चिकित्सकों का पदस्थापन

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जब विपक्ष पर उदार होते हैं तो ही इनको थोड़ा-सा खटकता है।

सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि विधान सभा क्षेत्र बानसूर में स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं महिला चिकित्सक नहीं हैं। बानसूर व नारायणपुर सीएचसी, पीएचसी पर एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक नहीं है। मेरे द्वारा बार-बार यह मामला विधान सभा में उठाने के बाद भी आज तक महिला चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं की गई और इस सम्बन्ध में मात्र आश्वासन ही दिये जाते रहे हैं। बानसूर विधान सभा क्षेत्र में गरीब व मजदूर वर्ग की महिलाओं को प्रसूती के सम्बन्ध में बहरोड़, कोटपूतली तथा अलवर आदि के अस्पतालों में जाना पड़ता है और संसाधनों के अभाव में कई बार कोटपूतली व अलवर अस्पतालों में पहुंचने में देरी होने के कारण जच्चा-बच्चा की रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूं कि जल्दी से जल्दी बानसूर व नारायणपुर सीएचसी पर स्त्री रोग विशेषज्ञ व महिला चिकित्सक लगाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मामन सिंह।

भिवाड़ी में बहुमंजिला इमारतों का अनियमित निर्माण

मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): उपाध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी में बहुमंजिला इमारतों की अनियमितताओं पर प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के सम्बन्ध में निवेदन है कि भिवाड़ी शहर की अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान है और यहां की आबादी भी 3 लाख के लगभग है। यहां विश्व प्रसिद्ध कम्पनियां संचालित हैं जिनके कारण यहां लगातार आबादी बढ़ती जा रही है। यहां पर बहुत से बिल्डरों ने बहुमंजिला इमारतें बनाई और काफी इमारतें निर्माणाधीन हैं। इनमें से काफी बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की स्थिति से बचने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। कई बिल्डरों ने बहुमंजिला इमारतों का लोगों को आबंटन कर दिया लेकिन नगर विकास न्यास, भिवाड़ी से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया है। साथ ही बहुमंजिला इमारतों का निर्माण भी नगर विकास न्यास, भिवाड़ी से पास किये नक्शे के अनुरूप व मानदंडों के अनुसार नहीं हुआ है व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उचित प्रबन्ध भी सोसाइटी के पास नहीं है। बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों से भारी भरकम ईडीसी लेने के बाद भी सुविधाएं न के बराबर है।

अत: माननीय शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की सभी बहुमंजिला इमारतों में अनियमितताओं की जांच कराई जाए और दोषी बिल्डरों व नगर विकास न्यास के अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाए ताकि आवास करने वाले आमजन को राहत (न्याय) मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री कैलाश भंसाली। (अनुपस्थित) श्री हीरालाल। (अनुपस्थित) श्री नन्दकिशोर महरिया।

फतेहपुर में राजकीय महाविद्यालय की मांग

श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा फतेहपुर उपखण्ड पर सरकारी महाविद्यालय स्वीकृत करने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

फतेहपुर उपखण्ड में सरकारी कॉलेज नहीं है। एक लाख से अधिक की आबादी के फतेहपुर शहर व आस-पास के 30-40 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गांवों में पढ़ने वाले बच्चे 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस क्षेत्र में 78 सीनियर सैकण्डरी स्कूल हैं और हजारों की संख्या में बच्चे 12वीं पास आउट होते हैं जिससे आगे पढ़ने वाले बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां पर सरकारी कॉलेज न होने के कारण बहुत से गरीब परिवारों के बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कई बच्चे अन्यत्र जैसे सीकर, चूरू व झुन्झुनूं जाकर मकान किराये पर लेकर पढ़ाई करते हैं जिससे इनके परिवारों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है व समय की बर्बादी होती है। फतेहपुर एक फसली क्षेत्र है और ऐसे में आय का साधन सिर्फ शिक्षा से ही सम्भव है। अगर इस क्षेत्र में सरकारी कॉलेज खुल जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, विद्यार्थियों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार होगा और उन्हें अध्ययन करने अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा संचालन प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों की रिपेयर करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

मैं आपका ध्यान अत्यन्त ही जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में डामर की सड़कों के हालात सबसे बुरे हैं। जगह-जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं और सरकार इसको लेकर गम्भीर नहीं है। विधान सभा क्षेत्र में करीबन 20 से ज्यादा सड़कें तो बहुत ही क्षतिग्रस्त हैं जिनके कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सरकार को कई बार अवगत कराने के बावजूद इन सड़कों की रिपेयरिंग नहीं की जा रही है। अगर इन सड़कों को अभी पेच रिपेयर करके ठीक नहीं किया गया तो ये सारी सड़कें बिखर जाएंगी और नोन पेचेबल हो जाएंगी जिन्हें पुन: बनाने में सरकार को बहुत ही ज्यादा धन खर्च करना पड़ेगा। जो सड़के पिछड़े दो वर्षों से बिलकुल

(श्री मेवाराम जैन)

ही क्षतिग्रस्त हैं उनमें पूनियों की हौदी से भूरटिया, कवास से वाया भूरटिया सिणधरी तक, कुड़ला से सरली, मंगला टर्मिनल रोड से सरकार पार, कवास से काउ खेड़ा, कगाउ से लेगों की ढाणी स्कूल, डूगेरों का तला से कगाउ, बख्से का तला से नोख, विशाला से बोथिया, बान्दरा से चन्दाणियों की ढाणी, दुदाबेरी से बालेबा हरसाणी, होमगार्ड से एन.एच. 68 तक, बाड़मेर से हरचन्द की प्याऊ, भाड़खा से खारिया तला, रावतसर से आदर्श चवा बाईपास, सनावड़ा से मेघवालों का तला, नांद से कोटड़ा, भादरेश से बोला, चामुण्डा चौराहा से रीको मेघवाल छात्रावास सिणधरी तक की सड़कें बिलकुल टूटी हुई हैं। उपरोक्त सड़कें अत्यंत ही जन हित की हैं अत: आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरी विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर की ऊपर वर्णित इन क्षतिग्रस्त सड़कों की रिपेयर कराएं ताकि आम जनता को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय। श्री तरुण राय कागा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

चौहटन मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन की व्यवस्था

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सम्बन्धित मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चौहटन जो तीन तहसीलों और तीन पंचायत समितियों में विभाजित है लेकिन जिला हैडक्वार्टर से 150-200 किलोमीटर दूरी पर सारे गांव बसे हुए हैं। हमारे वहां लोगों की जो रिहायश है उसमें वो गांव और ढाणियों में रहते हैं जो छितराई हुई हैं। वहां पर आये दिन, कोई ऐसा हफ़्ता नहीं होगा जब आगजनी की कोई घटना नहीं हो। बाड़मेर जिला हैडक्वार्टर की 150-200 किलोमीटर दूरी होने की वजह से आगजनी की वहां सूचना दी जाती है तो फायर बिग्रेड, अग्निशमन वाहन जब तक आता है तब तक वहां गरीबों के सारे जान-माल का नुकसान हो जाता है। मैं बार-बार, चार साल से लगातार इस बारे में प्रयास कर रहा हूं कि हमारे चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा वहां मुआवजा भी

(श्री तरुण राय कागा)
निर्धारित है, लिमिटेड है जिसके कारण से लोगों को लाखों का नुकसान हो जाता है, कई बार जान का भी नुकसान हुआ है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो इसके नोर्म्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी की जाए तथा सबसे पहले हमारे चौहटन उपखण्ड मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराया जाए ताकि वहां पर सुविधा मिले।

"हादसात से टकराना मेरी फितरत नहीं है और नाकामियों पर आंसू बहाना मेरे बस में नहीं है" मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सरकार इस संबंध में पूरा प्रयास करके और जहां जिस इलाके की, यह पशुपालन का इलाका है, ढाणियों का इलाका है, वहां लोग ढाणियों में रहते हैं, घास-फूस के झोंपड़े बनाकर रहते हैं। वहां अगर इस तरह से एक बार हवा का झोंका आया और कई बार ऐसे हादसे हो गये, उनकी अगर जांच करवाई जाये तो इतना नुकसान हुआ है। कई बार तो हमारे पूरे गांव के गांव नष्ट हो गये तो इसलिए वहां सख्त जरूरत है। मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, सरकार इस बारे में गम्भीर हो और हमारे वहां अग्निशमन वाहन की उपलब्धता करायें ताकि आम जनता को उसका लाभ मिल सके। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2016-17 के बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि 15,000 की आबादी के जो भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, उनमें अग्नि सेवा वाहन के लिए सरकार अनुदान देगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चूंकि ग्राम पंचायत मुख्यालय है। इसके रखरखाव, वाहन को चलाने के लिए वाहन चालक का वेतन, यह सारा ग्राम पंचायतों के द्वारा इसको व्यय किया जाना था परन्तु अथक प्रयास के पश्चात् भी किसी भी ग्राम पंचायत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। अग्निशमन वाहन तो मिल जायेगा, पर उसके रखरखाव, संचालन के लिए जो भी पैसा लगेगा, उस पर उनकी अनुमति नहीं मिली, इसलिए इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। चूंकि चौहटन भी ग्राम पंचायत मुख्यालय है, अगर माननीय सदस्य ग्राम पंचायत से प्रस्ताव लेकर, यह प्रस्ताव देते हैं कि ग्राम पंचायत अपनी खुद की आय से, आपको पता है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद, चाहे वह केन्द्र

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार की अनुदान राशि हो और चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन से आने वाला पैसा हो, चाहे सेन्ट्रल फाइनेंस कमीशन से आने वाला पैसा हो, सारा लगभग-लगभग ग्राम पंचायतों को, सीधा उनके खाते में जाता है। हम अनुमत कर देंगे। ये प्रस्ताव ले आयें। हम उनको स्टेट फाइनेंस कमीशन से मिलने वाले पैसे में या फिफ्थ सेन्ट्रल कमीशन का पैसा है, उसके अन्दर अनुमत्त कर देंगे पर ग्राम पंचायत इसकी जिम्मेदारी ले कि इसके रखरखाव और ड्राइवर की तनख्वाह का इंतजाम ग्राम पंचायत करे।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति चौहटन द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके भिजवाया जा चुका है। पंचायती राज विभाग के मंत्रीजी भी हैं, वे उस प्रस्ताव को वहां मंगवायें। वह प्रस्ताव पास करके वहां भिजवाया गया है। कई दिनों से विचाराधीन पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप मंत्री महोदय से विचार-विमर्श कर लीजिये। प्रिंसिपली कमिटमेंट तो है ही। प्रिंसिपली तो कमिटेड हैं ही।

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): ...इसलिए उस प्रस्ताव को मंगाकर आज ही उसकी घोषणा करें। वहां प्रस्ताव भिजवाया हुआ है। यहां इस तरह से नहीं। प्रस्ताव को मंगाकर, पंचायत समिति में वहां आन रिकार्ड है, इसलिए मेरा निवेदन है कि उस प्रस्ताव को मंगाकर...., और वैसे भी ग्राम पंचायत उसके लिए तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराज जाओ। मंत्रीजी दुबारा रिएक्ट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं। प्रस्ताव आता है सिर्फ इसका कि अग्निशमन वाहन को हमें खरीदने की अनुमति दे दें। वह चलेगा कैसे? उसकी मेंटीनेंस कौन करेगा? अगर यह सब लिखकर दे दें ये तो हम उसको, मैं निवेदन कर रहा हूं सदन में कि हम एसएफसी या टीएफसी में, जिस किसी में भी अनुमत करके, इस प्रकार की सेवाएं दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

राजसमन्द में खाद्य सुरक्षा योजना में व्याप्त अनियमितताएं

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला राजसमन्द में गत माह हमारे खाद्य मंत्रीजी पधारे थे और हमारी उन्होंने एक मीटिंग ली थी। उसमें हमने इनसे निवेदन किया था कि खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में बहुत ही विकट समस्या से हमारे क्षेत्र के वासी जूझ रहे हैं तो इनसे हमने निवेदन किया था कि खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत कुछ कोटा बढ़ाया जाये और उसके साथ-साथ ही इनसे यह भी निवेदन किया था कि कुछ हमारे यहां कई पीढ़ी दर पीढ़ी से ऐसे राशन डीलर हैं, जिन्होंने अपना खानदानी पेशा बना रखा है और इस संबंध में भी मैंने आपसे यह निवेदन किया था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि खा़द्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आपने वादा किया था कि मैं जयपुर जाते ही कोटा बढ़ाऊंगा, तो एक तो आप कोटा बढ़ायें।

दूसरा, कुछ हमारे भ्रष्ट राशन डीलर हैं जो जनता को गुमराह करते रहते हैं। गुमराह करने के कई कारण हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। इसमें एक तो पोस मशीन है। पोस मशीन के माध्यम से कई ऐसे हमारे मजदूर तबके के लोग हैं, जिनकी अंगूठा निशानी नहीं आती, कोई फिंगर प्रिंट्स नहीं आते जिससे राशन डीलर गुमराह करता है और उनको राशन नहीं देता है।

तीसरा, हमारे वहां पर वाई-फाई या नेट कनेक्टिविटी हमारे कई अटल सेवा केन्द्रों पर नहीं होने या हमारी उस ग्राम पंचायत पर नहीं होने की वजह से भी, हमारी यह पोस मशीन नहीं चलने की वजह से भी यह राशन डीलर गुमराह करते हैं और ये राशन डीलर कहीं पहाड़ पर चढ़कर या कहीं बड़े ऊंचे भवन पर चढ़कर, यह जो भी राशन जिनका होता है, वह पोस मशीन के माध्यम से वह इनकी चिट्ठियां निकाल देते हैं और आकर बाद में बोलते हैं कि साहब, हमारे पास तो राशन नहीं है तो बड़े बे-आबरू होकर वे जाते हैं और कई बार तो डांग क्षेत्र के लोग हैं जो दो-दो, तीन-तीन, दस-दस किलोमीटर से पैदल जाते हैं और जब जाते हैं तो वहां राशन नहीं मिलता है और बड़े मायूस होते हैं तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक तो ये पोस मशीन से या जहां नेट कनेक्टिविटी नहीं है, वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर

(श्री हरिसिंह रावत)

भी ऐसे प्रावधान रखे, जिससे गरीब तबके के लोग जो खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत आते हैं, उनको राशन समय पर मिले और कुछ जो भ्रष्ट टाइप के राशन डीलर हैं जो दो-दो, तीन-तीन पीढ़ी से चले आ रहे हैं, उनकी भी हमने कई बार कम्प्लेंट की है। जैसे लगेदखेड़ा है, बार है, सारोठ है, लसाड़िया है, इस प्रकार के पाँच-छह लोग ऐसे परिवार के हैं, उन पर थोड़ा या तो अंकुश लगाये, या उनकी जांच करें ताकि ऐसे भ्रष्टों को थोड़ा सबक मिले ताकि गरीब का जो राशन ये लोग कालाबाजारी में बेच रहे हैं, उन पर अंकुश लग सके। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इसमें कोई सेटिस्फाई निर्णय निकालेंगे और जवाब देंगे। धन्यवाद।

श्री बाबूलाल वर्मा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां बताया है। मैंने भी राजसमन्द का दौरा किया था, तब मैंने मीटिंग ली थी तो राशन हेतु खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम बढ़ाने की बात है, जिस प्रकार नाम जोड़े जा रहे थे, उन लोगों का राशन बढ़ाने की बात कही थी। वर्तमान में राजसमन्द में अन्त्योदय परिवार के लाभार्थी 20,004 की संख्या है जिनको 35 किलो पर फैमिली के हिसाब से हम लोग राशन देते हैं और एनएफएसए, पीएचएच की सूची है, उसमें 7,32,635 लाभार्थी हैं जिनको पाँच किलो पर यूनिट के हिसाब से हम लोग दो रुपये किलो के हिसाब के राशन देते हैं। इनके हिसाब से राजसमन्द में टोटल जो आबंटन बनता है, मैंने उसको चैक कराया है। 700 मैट्रिक टन तो अन्त्योदय का बनता है और 3,663 पीएचएच का बनता है, 4,363 आज की तारीख में राजसमन्द जिले की जो निर्धारित मात्रा है, उसके हिसाब से राशन का कोटा बनता है और उसके लिए हमने आगामी माह में बढ़ने के आदेश कर दिये हैं और आज की तारीख में जितना उसका लक्ष्य है, उसके हिसाब से कोटा यहां से जारी कर दिया गया है।

दूसरी बात, माननीय सदस्य ने जो बात बताई है कि कुछ भ्रष्ट डीलर हैं जिनकी शिकायतें दी हैं। वह शिकायत मेरे सामने भी आई थी। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से यहां से एक उच्चस्तरीय कमेटी बनाकर और जो नाम माननीय

(श्री बाबूलाल वर्मा)

सदस्य मुझे बतायेंगे, उन चारों-पांचों डीलर्स के लिए मैं एक कमेटी बनाकर, वहां जाकर उसकी जांच करवा लूंगा और मैं कार्यवाही पूरी करूंगा। मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करता हूं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): इस बार आपने एक्शन लिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबू सिंहजी।

जोधपुर की ग्राम पंचायत सामराउ में कानून-व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अजमेर और अलवर के चुनाव की चर्चा थोड़ी बंद हो जाए। तो मैं मेरी बात कर लूं। (व्यवधान) यही चल रही है, मैं सुन रहा हूं पीछे बैठे-बैठे। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले में आजकल हम लोग यह देख रहे हैं कि काले शीशे की गाड़ियां कहीं यूटिलिटी हैं, कहीं कैम्पर है, कहीं गेटवे है। ऐसी गाड़ियां बेखौफ घूमती हुई नजर आती हैं और उन गाड़ियों में अवैध शस्त्र होते हैं। पुलिस पीछा करने में संकोच करती है और वहां पर ऐसे गैंगस्टर पनप गये हैं जो पूरे जिले में स्मैक ला रहे हैं, हेरोइन ला रहे हैं, अवैध शराब ला रहे हैं। अवैध शराब का यह अड्डा बन चुका है और इसी की परिणति यह होती है कि वहां पर जो अपराधी लोग हैं, पहले तो उनकी आपस में पार्टनरशिप होती है और पार्टनरशिप बिगड़ने के बाद अनबन होती है, रंजिश होती है और रंजिश की परिणति हत्या के रूप में सामने आती है। हमारे जोधपुर जिले के सामराउ गांव में 14 अप्रैल को दो अपराधी गुटों की आपसी रंजिश हुई और रंजिश के कारण एक की हत्या हुई और हत्या के बाद में वहां उपद्रवियों ने ऐसा तांडव मचाया कि देखते ही देखते हत्या के बाद शाम के समय सामराउ गांव में नौ दुकानें जलाई गईं... और उसके बाद रात को भी तांडव मचाया गया। 15 तारीख को सवेरे बहुत बड़ी संख्या में अड़ौस-पड़ौस के पता नहीं कहां-कहां के लोग वहां पर जुटते हैं। बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है। राजनेता भी वहां पहुंचते हैं और उसके अन्दर भड़काऊ भाषण भी दिये जाते हैं और पुलिस पहुंचती है। पुलिस के एसपी

(श्री बाबू सिंह)
वहां मौजूद हैं, पुलिस के उप अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, 6 एसएचओ सहित पुलिस खड़ी है और पुलिस मूकदर्शक होकर देख रही है और उनके सामने ही सामराउ गांव का जो साढ़े पाँच सौ वर्ष पुराना रावलाकोट है उसमें आग लगाई जाती है और उसके बाद में वहां से जब वो आग लगती है तो पीछे गरीब परिवार जो तीन बीपीएल हैं वहां वो भीड़ दौड़ती हुई जाती है और जाकर सूरज कंवर पत्नी श्री मोहन सिंह को बाहर निकालते हैं और बड़ी मुश्किल से सूरज कंवर अपने विकलांग बच्चे को सास-ससुर के साथ भाग करके अपनी जान बचाती है। वहीं पर एक सोहन सिंहजी हैं। सोहन सिंहजी की बिटिया की शादी अभी 6 मार्च को होनी थी और परबत सिंह जी की बिटिया की शादी अभी फरवरी में 3 तारीख को होनी थी तो वो सामान लेने के लिए बाहर गये हुए होते हैं और वहां पर पूरा जो उनका सामान वर्षों से बिटिया की शादी के लिए उन्होंने जो गहने बनवाये हैं, कपड़े खरीदे हैं, सामान खरीदा है दहेज का सामान खरीदा है। उनके साथ में लग्गे हैं, आग लगाने का सामान है पेट्रोल है, डीजल है, वहां रसायन है, वो सारा साथ लेकर पहुंचते हैं और लग्गों से उनकी आलमारी को तोड़ते हैं। सारा सोना जो अन्दर है उसको पेटियों से बाहर निकाल कर उनकी पोटली बांधते हैं और जो सामान उनको पसंद है वो लेकर जाते हैं और बाकी आग के हवाले करते हैं।

ये ही नहीं वहां पर गांव के अन्दर ऐसे कई शोरूम और दुकानें हैं जो एक चन्द्र सिंह, भाग सिंह है, एक और भाग सिंह है उन्होंने अपनी जमीन बेच करके चालीस-पचास लाख रुपये का सामान लाकर के शोरूम बनाया, दुकान खरीदी और व्यवसाय शुरू किया, वहां से वो अपना सामान भी ले जाते हैं और सामान ले जाने के बाद में जो बचा हुआ सामान है उसको आग के हवाले करते हैं। ऐसा तांडव वहां मचाया गया कि वास्तव में न तो कभी इतिहास में ऐसा देखा, यह पहली बार हुआ कि मानवता और इंसानियत हमारे जिले में, उस गांव में शर्मसार हुई।

ये ही नहीं हुआ वहां जब दमकल गाड़ी पहुंचती है तो उस गाड़ी को भी आग के हवाले करते हैं और दो कर्मचारी होते हैं, उनके पीछे दौड़ते हैं बीस किलोमीटर पैदल जाकर लोहड़ता में वो अपनी जान बचाते हैं। अब यहीं से

(श्री बाबू सिंह)
नहीं, वो चार बजे खुले आम 15 तारीख को तांडव मचा रहे हैं, चार बजे से लगा कर रात को एक बजे तक। पड़ौस के जो गांव हैं सामराऊ में, भेहड़ में, भाकरी में, एनएस नगर में, चामूं गांव में पुलिस की गाड़ी को जलाते हैं, पुलिस चौकी को जलाते हैं। वहां पर फैक्ट्रियों में आग लगाते हैं। अड़ौस-पड़ौस में इस प्रकार का तांडव करते हैं और पुलिस मूकदर्शक होकर देखती है। ये हालात वहां पर हुए हैं।

ये ही नहीं, आप देखोगे कि वर्षों से जिन्होंने अपने खून-पसीने से अपना आशियाना बसाया, उन्होंने अपना घर बसाया, अपना व्यवसाय किया, वो उनकी आंखों के सामने उनकी दुर्दशा का मंजर वे अपनी आंखों से देखते हैं और बच्चियां, माताएं, एक तो वहां वृद्ध जो 95 साल के हैं श्री करण सिंहजी, वो अपने हॉल में सो रहे होते हैं और पीछे से खिड़की में से आग लगाते हैं। बड़ी मुश्किल से रेंगते-रेंगते वो अपनी जान बचाते हैं। ये मंजर यही बंद नहीं किया, पशुओं का जो बाड़ा है उसमें बकरियों के बाड़े में गायों के लिए जो चारे का गोदाम है उसमें सबमें आग लगाई है और उसमें तो एक बच्चा झुलस गया। बकरियों के दो बच्चे झुलस गये। इतने हालात उन्होंने कर दिये और इस प्रकार का उपद्रव फैलाया कि दहशत का माहौल फैल गया और वास्तव में जब ये सारा मंजर उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा तो गरीब महिलाओं के केवल अपने तन के कपड़े बचे, बाकी सारा जो वर्षों से उन्होंने अपना आशियाना बसाया था, उनकी आंखों के सामने उनकी गृहस्थी तिल-तिल करके बर्बाद हुई है, उन्होंने देखी है। ये हालात हुए हैं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वास्तव में आज यहां विराजमान हैं आदरणीय गृह मंत्री महोदय, इनको भी हमने आग्रह किया और मुख्य मंत्रीजी से आग्रह किया। आपने तो स्वयं ने जाकर, डीजीपी और गृह मंत्रीजी ने वहां के हालात का जायजा लिया। वहां स्थिति देखी है और देखने के बाद में वास्तव में ऐसे हालात हमने तो कहीं नहीं देखे।

ये ही नहीं, कोई आतंकवादी भी ऐसा नहीं करते हैं। आश्चर्य इस बात का है कि जो हत्या हुई है वो हत्या करने वाला और हत्या जिसकी हुई है उन दोनों का सामराउ गांव से कोई लेना-देना नहीं है। वो निर्दोष लोग हैं, उनके घर जलाये गये हैं। एक हत्या जिनकी हुई है वो भेहड़ के हैं। हत्या

(श्री बाबू सिंह)
करने वाले सुखमड़ला और लोहड़ता के हैं जबकि सामराउ का उसमें कोई लेना-देना नहीं है। केवल मात्र लोकेशन की दुकान लोहड़ता में जगह-जगह पूरे हमारे जोधपुर जिले में लोकेशन की दुकान एक होती है और सब जगह अवैध ब्रांचें हैं कि ये हमारा इलाका है यह हमारी पेरीफेरी इलाका है और जगह-जगह शराब की अवैध दुकानें खोली हुई हैं, ब्रांचें खोली हुई हैं। अवैध शराब आती है और जितनी ब्रांचें वहां लगी हुई हैं, कई बार विधान सभा में भी मामला उठा। प्रभारी मंत्रियों के सामने मामला उठा, जिले की कानून-व्यवस्था का मामला उठा। हमने कई बार कहा कि ये अवैध ब्रांचें आप बंद करा दो और यहां वातावरण खराब हो रहा है। हमारे नौजवान बच्चे सड़कों पर डोलते हुए मिलेंगे। चरस पी रहे हैं और चरस का जब पैसा नहीं मिलता है तो वो इस प्रकार से अपराध जगत की ओर जा रहे हैं, उनके सदस्य बन रहे हैं। वो अपराधी बन रहे हैं, इन अपराधियों को रोकना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है और पुलिस कानून-व्यवस्था को बनाये नहीं रख सके और पुलिस के सामने, पुलिस के टाइगर वहां बैठे हैं और मीटिंग चल रही है और उनके सामने भीड़ जाकर के घरों में आग लगा रही है और पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करे। पुलिस के ऊपर पथराव करे और पुलिस सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज नहीं करे, वो तो गृह मंत्रीजी गये, उनके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। यह सारा तांडव इस प्रकार से चलता है तो हम किससे सुरक्षा की उम्मीद करें। गृह मंत्री महोदय, अपनी आत्मरक्षा के लिए या तो पुलिस खड़ी हो और अगर वो हमारी सुरक्षा नहीं कर सके तो आप हमें बता दो कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। बाड़मेर जिले में, जैसलमेर जिले में अवैध हथियार आ रहे हैं और कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर अवैध हथियार मिल जाएंगे। जितने भी अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, उनकी काले शीशों की गाड़ियों में आपको अवैध हथियार मिल जाएंगे और यह जो परिणति हुई है इसके अन्दर भी अवैध हथियार थे और उन्होंने आपस में गोलियां चलाई हैं। श्री दलपत सिंह के गोलियां लगी हैं और पिस्तौल भी उस बोलेरो गाड़ी में फंसी हुई मिली है तो खुला है कि जितने अपराधी घूम रहे हैं उनके पास में अवैध हथियार हैं। इस प्रकार का

(श्री बाबू सिंह)

दहशत का माहौल बनाया है तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूंगा कि आखिर हम अपनी रक्षा कैसे करें। मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि कम से कम इस प्रकार के जब हालात होते हैं और हम अपने-आपको बचा नहीं सकते लोगों को बचा नहीं सकते हैं तो उनको अगर कोई एप्लीकेशन दे तो लाइसेंस दिलवा दो उनको हथियारों के जिससे अगर पुलिस नाकामयाब हो जाए तो हम अपने हथियार उठायें और अपनी रक्षा तो करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये हालात यहां हो रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हमने यह मांग की है कि जिन लोगों ने सोची-समझी चाल के तहत वहां पर उपद्रव फैलाया है, तांडव फैलाया है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए। 14 अप्रैल की बात है और आज एक महीना होने को आ गया और जो पुलिस उप अधीक्षक मौके पर थे उनकी आंखों के सामने हुआ और अब वो ही जांच कर रहे हैं। हम मांग यह कर रहे हैं कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की एक टीम बने और वो निष्पक्ष होकर के जांच करे। अब वो ही थानेदार और डीवाईएसपी कर रहे हैं। पचास तरीके के मुकदमे वहां होते हैं। यह 14 अप्रैल नहीं 14 जनवरी की बात है, एक महीना होने को आया और उनको कई काम रहते हैं। इसमें जांच ढीली पड़ गई। मैं तो कह रहा हूं कि करीबन 300 की वहां नफरी थी और जलाने वाले भी खूब लोग थे। आज दिन कह रहे हैं कि 29 मुल्जिम पकड़े गये हैं। मैं यह चाहूंगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। इस प्रकार की हमें न्याय की उम्मीद है, इसलिए हमने मांग की है कि आदरणीय गृह मंत्री महोदय, इसकी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अलग से एक टीम बना करके जांच करे जिससे शीघ्र ही इसमें न्याय मिले और ऐसी पुनरावृत्ति करने से लोग हिचके और उनमें कम से कम पुलिस का जो भय होना चाहिए वो इन लोगों में है नहीं और वास्तव में मैं तो समझता हूं कि थानों में अगर अवैध शराब, चरस-तस्करी में अगर पुलिस की मिलीभगत हो जाए तो फिर हमारा रखवाला कौन होगा? इसलिए मैं खास तौर से कहना चाहूंगा, एक तो इन मुल्जिमों की गिरफ्तारी हो। दूसरा, हम चाहते हैं कि प्रशासन की मौजूदगी में, पुलिस की मौजूदगी में

(श्री बाबू सिंह)

ऐसे हालात हुए, कानून-व्यवस्था बिगड़ी तो उसकी एक प्रशासनिक जांच होनी चाहिए और प्रशासनिक जांच में भी हमारे प्रमुख शासन सचिव या शासन सचिव स्तर के अधिकारी की कमेटी जाकर के जांच करे कि कानून-व्यवस्था क्यों बिगड़ी, कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी थी उसके लिए माकूल बंदोबस्त उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया इसलिए हम इसमें चाहेंगे कि जिस प्रकार के ये हालात हुए हैं सामराउ गांव में, हमारे पूरे इलाके में एकदम सामाजिक सौहार्द वर्षों से है। साथ में उठते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन इसको भी आप देखिये, जातीय हिंसा का रूप वहां दिया और भड़काया गया। खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने वहां जितनी मीटिंग थी, एक तरफ तो लाश पड़ी थी और वह वहां पर लाश के ऊपर राजनीति कर रहे थे। आप उनका वीडियो में भाषण सुनेंगे तो देखेंगे कि तीसरे मोर्चे की सरकार आयेगी, हम मुख्य मंत्री बनेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। लाश के ऊपर क्या राजनीति करते हो और खुले आम भड़का रहे हो कि बताओ आप सबका क्या मूड है, और किसी के घर फूंकने हैं क्या? इस प्रकार से भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके सामने घर जलते हैं। और भी कई राजनेता वहां मौजूद होते हैं और उनके भड़काऊ भाषण आप सुनोगे तो मैं तो यह महसूस करता हूं कि यह जातीय जहर घोलकर इस प्रकार से राजनीति करने वाले लोग आज हैं, कल चले जायेंगे लेकिन आपस में फूट डालकर लोगों में जो आपस में भाईचारा है, उसको दूर करेंगे। आज भड़का कर चले गये, उनके ऊपर मुकदमे बन गये। वह तो मुलजिम बन रहे हैं, अब उनको बचाने के लिये कौन आ रहा है। वह इस तरह से भड़का कर राजस्थान में जातीय राजनीति करना चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि राजस्थान का माहौल बिगड़े नहीं, सामाजिक सौहार्द्र बने, इसके लिये सरकार को वापस पहल करनी चाहिये। यह कोई जातीय हिंसा नहीं। मरने वाले जाट, मारने वाले और, चार राजपूत, दो जाट, पाँच गिरफ्तार हो गये। मैं तो कह रहा हूं उसमें 6 मुलजिम है और हत्या करने वाला एक मुलजिम अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, वह भी होना चाहिये। सरकार न्याय करे। मैं आपसे खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जितना भी सामान चोरी हुआ है, गहने ले गये, सारा सामान ले गये, सारे घर को जला दिया, कोर्ट में जो

(श्री बाबू सिंह)
पुराना इतिहास था, उस इतिहास को जला दिया। उस कोर्ट में जितना पुराना सामान था, वह ले गये। हैरिटेज लुक को बिगाड़ा, वहां की संस्कृति को बिगाड़ा, उसमें पूरा न्याय मिले। इसमें हमारी मांग है मुलजिम तुरंत गिरफ्तार हों और जो सरकार ने पैकेज दिया है, इसके लिये मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि वास्तव में जिनकी मानसिक क्षति हुई है और जिनको दर्द और पीड़ा हुई, उसकी कीमत तो हम चुका नहीं सकते लेकिन फिर भी जो वहां मौके पर क्षति हुई, उस क्षति का आकलन करके सरकार ने आर्थिक पैकेज दिया है, इसके लिये तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे लेकिन आर्थिक पैकेज से उनकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जिससे राजस्थान में यह मैसेज जाये कि इस प्रकार के कृत्य करने वालों के सरकार सख्त खिलाफ हैं और सख्त कानूनी कार्यवाही करती है। एक तो मेरा यह निवेदन है कि जो बात हमारी हुई है, उसके अनुसार कार्यवाही हो। नहीं तो जैसलमेर में चतुर सिंह हत्याकांड में सीबीआई की बात हुई, सावरदा में सहमति बनी कि जो झूठे मुकदमे हुए हैं, उनमें झूठे लोगों को फंसाया गया है, वह मुकदमे वापस लेंगे, निष्पक्ष जांच होगी। मैं सरकार से चाह रहा हूं कि जहां सहमति बनाकर बात करते हैं वहां दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिये। मैं खास तौर से कहना चाहूंगा कि इसमें जो भी दोषी है, चाहे पुलिस अधिकारी हैं, चाहे प्रशासन के अधिकारी हैं, जिन्होने भी यह कायराना हरकत की है, उनको सज़ा मिले। इन्हीं शब्दों के साथ गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसमें आप स्पष्टीकरण फर्माएं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह मैंने वहां स्वयं ने जाकर भी आँख से देखी है। बहुत कुछ जो इन्होंने कहा है, वह सच है और इसलिए बहुत अधिक इसको तूल देने की बनिस्पत अभियुक्त गिरफ्तार हों, यह मेरी पहली प्रायोरिटी है, इसको मैं हर हालत में करूंगा। फुटेज देखने के साथ 29 लोग तो गिरफ्तार हैं, लेकिन और भी लोग हैं। वास्तव में जो प्रोपर्टी का नुकसान किया, उसका तो थोड़ा-बहुत अपन ने भरपाई करने का प्रयास किया है। लोगों के घरों में जो कुछ भी तोड़-फोड़ हुई है, लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपया तो उन लोगों को

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

दिया है और सार्वजनिक संपत्ति को जो नुकसान हुआ है, ढ़ाई करोड़ उसमें भी दिया है। आर्थिक पैकेज की दृष्टि से तो जो कुछ मदद मुख्य मंत्रीजी कर सकती थीं, वह उन्होंने जरूर की है। लेकिन यह बात सच है कि जिस प्रकार का नंगा नृत्य हुआ और पुलिस की उपस्थिति में हुआ, सबसे बड़ा दु:खद विषय जो इसका है वह यह है। यद्यपि हमने दोनों एसपी और एडिशनल एसपी को तुरंत हटाया है, और भी जिन लोगों को हटाना होगा, वह निश्चित हटायेंगे। मेरा स्वयं का भी मानना है कि मेरे होम सैक्रेटरी और एक एडीजी, दो लोगों की टीम बनाकर इस सारे प्रकरण की जांच करके एक महीने में, जिनका भी जो दोष बनता है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि यह जो सामाजिक विद्वेष फैलाकर जिस प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयत्न हुआ है, यह भविष्य में न हो, इसके लिये भी हम सब जनप्रतिनिधियों को भी अपना दिल और दिमाग साफ बनाना पड़ेगा क्योंकि आप और मैं तो वहां जाकर आ जायेंगे लेकिन जो लोग वहां रह रहे हैं, वह तो पीढ़ियों से रह रहे हैं और पीढ़ियों तक और रहेंगे। उनके मन में यह विद्वेष पैदा करने से विषय की परिणति इतनी खतरनाक होगी, मैं सोचता हूं उस पर भी रोक लगाने की दृष्टि से हम सब जनप्रतिनिधि भी ईमानदारी से सहयोग करें और जो गलत है, उसको गलत कह कर उसके खिलाफ कार्यवाही करें। रिपोर्ट एक महीने में आयेगी, उसके आधार पर जो प्रशासनिक कमियां रही हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। जो लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाये हैं, फुटेज देखकर उन्हें गिरफ्तार करेंगे और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, दोनों समाजों में बैठकर वापस कोई सुलह-समझौता होकर, बातचीत होकर एक सामान्य जन जीवन कैसे बने, इसके लिये भी आप और हम सब और प्रयत्न करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की दु:खद घटना न हो। मैं सोचता हूं कि जो माननीय सदस्य ने कहा, वह मैंने अपनी स्वयं की आँख से देखा है, इसलिए मुझे कोई तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता महसूस नहीं है। मैं आपकी भावना का सम्मान करते हुए भविष्य में इस प्रकार की घटना न घटे और मेरे विभाग के जिसकी भी मौजूदगी में यह कमी रही है, उसकी निश्चित रूप से जांच करके उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब यह पकड़े जायेंगे तो सबसे ज्यादा अपराधी और असामाजिक तत्व इसमें आयेंगे। हम चाहते हैं कि इन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ आप कड़ी कार्यवाही करें और सामान की बरामदगी भी हो।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंहजी।

ब्यावर में विद्युत विभाग की लापरवाही

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शहरी गौरव पथ सब जगह बन रहे हैं और ब्यावर में भी लगभग एक वर्ष से कार्य शुरू हो रखा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से आज तक भी वह कार्य पूरा नहीं हो पाया। रोड चारों तरफ से खोदी हुई पड़ी है। पीडब्ल्यूडी वाले काम करने को तत्पर हैं लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों के द्वारा वह खंभे नहीं हटाये जा रहे, लाइन नहीं हटाई जा रही है। उनकी शिफ्टिंग का चार्ज भी डेढ़ करोड़ रुपये का बनाकर दे रखा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप भी वहां पधारे थे और उस समय आपने खुद ने मौका देखकर हम सबको आश्वस्त भी किया था कि 7 दिन में यह लाइन शिफ्ट हो जायेगी लेकिन वह आज तक भी शिफ्ट नहीं हुई है, 7 महीने से ऊपर हो गये हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां से निकलने वाले लोगों को वह सज़ा क्यों मिले? मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हम उस लाइन शिफ्टिंग का चार्ज भरने को तैयार हैं। वह नई लाइन लगी हुई है, दो तीन वर्ष पहले ही वह लाइन लगी है, बिजली के खंबे भी वही काम आ जायेंगे, लाइन भी वही काम आ जायेगी और ट्रांसफार्मर भी वही काम आ जायेंगे, शिफ्टिंग का चार्ज हम भरने के लिये तैयार हैं। आप एस्टीमेट बनवा दें तो निश्चित तौर पर वह कार्य भी हो जायेगा और वहां से निकलने वाले लोगों को यह सज़ा नहीं मिलेगी। इतना मेरा आपसे आग्रह है कि यह काम बिलकुल सुविधा से हो सकता है। आप फरमाएं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है कि ऊर्जा विभाग के अधिकारी के कारण ये बिजली के पोल शिफ्ट नहीं हो रहे हैं। आज से चार-

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

पांच महीने पहले आपके ब्यावर में मैं जन सुनवाई के माध्यम से आपके बीच में आया था और यह बात आपने मेरे सामने रखी थी। उपाध्यक्ष महोदय, जो सामान शिफ्टिंग के तहत हम काम में ले रहे है, उसका पैसा हमने डिमांड में जोड़ा भी नहीं है और जो नई लाइन खड़ी हो रही है, उसका 1 करोड़ 19 लाख रुपये का हमने इनको एस्टीमेट दिया है। मैंने इनको कहा भी है कि अगर आपको लगता है कि हमारे विभाग के द्वारा डिमांड ज्यादा है तो हम तो केवल आपसे 5 परसेंट सुपरविजन चार्जेज लेंगे, आप भले ही पीडब्ल्यूडी से करा दो, नगर परिषद अपने टेंडर निकालकर कर दें, हमको तो केवल आप 5 परसेंट सुपरविजन चार्जेज दे दें, उसके तहत हमारा आदमी काम को देख लेगा। यह बात भी मैं आपके एक्सईएन को, एसई को, सबको कहकर आया हूं। अभी आपने उसमें तय नहीं किया कि करना क्या है? या तो नगर परिषद इसका टेंडर निकाल दे। टेंडर निकाल कर उसके ठेकेदार को काम दे दें और हमारे विभाग को तो मात्र 5 परसेंट सुपरविजन चार्जेज दे दें। इसमें मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जो कहना चाह रहे हो कि जो सामान काम में आ रहा है, उसको हमने एस्टीमेट में जोड़ा ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट का जो काम आ रहा है, उसे हमने एस्टीमेट में जोड़ा ही नहीं है। यह तो जो एडिशनल सामान लग रहा है, उसी की कोस्ट ओवरहैड चार्जेज मिलाकर 1 करोड़ 19 लाख रुपये है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि गौरव पथ की पूरे ढ़ाई करोड़ की सड़क है। उसमें अगर 1 करोड़ 19 लाख रुपए हमको दे देंगे तो फिर सड़क क्या बनेगी? मैं भी इस बात को समझता हूं। फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि नगर परिषद स्वयं टेण्डर निकाल दे और टेण्डर निकाल कर, हमको सिर्फ 5 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज दे दे, पीडब्ल्यूडी दे दे तो आपका काम पूर्ण हो जाएगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक लाइन और पूछूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: वैसे तो आप विराज जाओ। कल आसन की तरफ से इस बात का स्पष्टीकरण हो गया था कि पर्ची के माध्यम से हम इसको वाद-विवाद का विषय नहीं बना सकते। वैसे तो मैं मंत्रीजी को बाध्य भी नहीं कर सकता कि आप इस विषय पर जवाब दें। वे अपने स्वयं के विवेक से जवाब

(श्री उपाध्यक्ष)

दे देते हैं अन्यथा तो जवाब देना उनके लिए अभी आवश्यक है नहीं या उसी वक्त है नहीं। अगर आपको और कुछ पूछना है तो व्यक्तिगत रूप से जाकर आप कोई बात हो तो कर लें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजपाल सिंह शेखावत।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 19 एवं आबकारी विभाग की 5 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-158 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान माल एवं सेवा कर नियम, 2017 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-159 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 के देरी से फाईल करने पर देय विलम्ब शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-160 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-5 के देरी से फाईल करने पर देय विलम्ब शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-161 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा. फॉर्म जीएसटीआर-5-ए के देरी से फाईल करने पर देय विलम्ब शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-162 दिनांक 23.1.2018 जिसके द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-6 के देरी से फाईल करने पर देय विलम्ब शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-पार्ट-IV-163 दिनांक

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

23.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(46)वित्त/कर/2017-32 दिनांक 22.6.2017 को अतिष्ठित करते हुए ई-वे बिल वेबसाईट www.gst.gov.in को अधिसूचित किया गया है;

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.2(88)वित्त/कर/2010-164 दिनांक 24.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड़ द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के पक्ष में जारी किये जाने वाले शेयर सर्टिफिकेट पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है।

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.2(31)वित्त/कर/2017-165 दिनांक 24.1.2018 जिसके द्वारा राष्ट्रीय हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निष्पादित रियायती करार पर देय स्टाम्प ड्यूटी पर छूट प्रदान की गई है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-166 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017पार्ट-I-49 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-167 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017--पार्ट-I-50 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-168 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-51 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-169 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा सेवाओं की आपूर्ति के लिये पंजीकृत व्यवहारी हेतु कर के भुगतान के संबंध में विशिष्ट प्रणाली अधिसूचित की गई है;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-170 दिनांक

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

25.1.2018 जिसके द्वारा राज्य कर से पैट्रोलियम प्रोफिट केन्द्रीय सरकार के अंश से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-171 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-40 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-172 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-I-41 दिनांक 29.6.2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

(16) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-173 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा निश्चित वस्तुओं की अन्त: राज्य आपूर्ति पर राज्य कर से सशर्त छूट प्रदान की गई है;

(17) अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-II-174 दिनांक 25.1.2018 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-पार्ट-III-136 दिनांक 14.11.2017 में संशोधन किया गया है;

(18) अधिसूचना संख्या: एफ.2 (6 0)वित्त/कर/2 0 1 2 /पार्ट-1 7 5 दिनांक 30.1.2018 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा आबंटित या बेची गई भूमि के संबंध में जारी किये गये पट्टों पर देय स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान की गई है; एवं

(19) अधिसूचना संख्या: एफ.2 (6 0)वित्त/कर/2 0 1 2 /पार्ट-1 7 6 दिनांक 30.1.2018 जिसके द्वारा स्थानीय निकायों द्वारा भूमि के नियमितीकरण हेतु जारी किये गये पट्टों पर देय स्टाम्प शुल्क पर छूट प्रदान की गई है।

आबकारी विभाग

(1) अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 17.11.2017 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम-68 के

अन्तर्गत वाईन के निर्माण की लाइसेंस फीस में संशोधन किया गया हैं;

(2) अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 17.11.2017 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या:एफ.4(62)वित्त/आब/96 दिनांक 31.3.97 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया हैं;

(3) अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2016/पार्ट-1 दिनांक 18.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान एक्साईज (ग्रांट ऑफ होटल बार/क्लब बार लाइसेन्सेज) रूल्स, 1973 में संशोधन किया गया हैं।

(4) अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 18.1.2018 जिसके द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया हैं; एवं

(5) अधिसूचना संख्या:एफ.4(1)वित्त/आब/2017पार्ट-1 दिनांक 18.1.2018 जिसके द्वारा मासिक पूर्ति से अधिक उठाव पर दिये जाने वाले आबकारी शुल्क में सशर्त छूट प्रदान की गई हैं।

श्री उपाध्यक्ष: वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, श्री राजेन्द्र राठौड़।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड का 7वां प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395(1) के अंतर्गत राजकॉम्प इंफो सर्विसेज लिमिटेड का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राजपाल सिंह शेखावत।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अंतर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का पांचवां प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017; एवं

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 52वां प्रतिवेदन वर्ष 2016-17.

सांभर साल्ट्स लिमिटेड का 52वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभू लाल सैनी।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 59वां प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

दी वेयर हाउसिंग कॉरपोरशन एक्ट, 1962 की धारा 31(2) के अंतर्गत राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम का 59वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17; एवं

राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 39वां प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-394 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का 39वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017.

श्री उपाध्यक्ष: श्री श्रीचन्द कृपलानी।

जयपुर मैट्रो रेल लिमिटेड का 8वां प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

श्री श्रीचन्द कृपलानी (स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 के अंतर्गत जयपुर मैट्रो रेल लिमिटेड का 8वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अजय सिंह जी।

राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का 26वां प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-17

श्री अजय सिंह (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 की धारा-54(14) के अन्तर्गत राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड, जयपुर का 26वां वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद। श्रीमती अलका सिंह।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आभारी हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण किसी भी सरकार के, जो हमारी सरकार ने पिछले चार साल में काम किये हैं, उसकी समीक्षा है और जो बचा हुआ एक साल है, उसमें सरकार ने विकास का क्या रोड मैप बनाया है, क्या कार्य योजना बनायी है, उसका यह प्रस्तुतीकरण है।

हमारा राजस्थान विविधताओं को लिया हुआ राज्य है। यहां पर कहीं पानी है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पहाड़ है। इन सबके विकास के लिए सरकार ने बहुत से काम किये हैं और इन्हीं कामों को इस अभिभाषण में समाहित किया है। मैं बहुत फख्र के साथ कहना चाहूंगी कि हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने सुराज संकल्प यात्रा के समय जो राजस्थान में सुराज और गुड गवर्नेंस का सपना देखा था, उसी के अनुरूप हमारा घोषणा-पत्र बना और उसी के अनुरूप कार्य करते हुए इन चार सालों में 78 परसेंट तक वे काम आज पूर्ण हो चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि वह गांव, किसान, मजदूर की पार्टी है। मैं थोड़ा-सा आईना इन्हें दिखाना चाहूंगी कि ग्रामीण विकास की जो बात की जाती

(श्रीमती अलका सिंह)

है। कांग्रेस के समय ग्रामीण विकास का मतलब नरेगा था। नरेगा कांग्रेस की विफलता का जीता-जागता उदाहरण है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री महोदय कह चुके हैं। इस पर कांग्रेस के लोग बार-बार एतराज करते हैं कि नरेगा हमने क्यों चालू रखी? हमने इस नरेगा के अंतर्गत पक्के कामों को जोड़ा और इसके अतिरिक्त इसको कृषि से जोड़ा। मैं जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि संसद में अप्रैल, 2013 में सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। मैं आँकड़ों के हिसाब से अपनी बात कहना चाहूंगी। उसमें बताया गया कि 4 साल के अंदर 13 हजार करोड़ रुपए का घोटाला कांग्रेस की सरकार ने इस नरेगा के अंतर्गत किया। इसीलिए ग्रामीण विकास का मतलब नरेगा। इनके समय में नरेगा का मतलब था गड्ढे खोदो, गड्ढे भरो और पैसा उठा लो। योजना आयोग के सदस्य मेहर शाह ने उस वक्त भी कहा था कि नरेगा की उपयोगिता तब तक नहीं है, जब तक इसके अंदर पक्के कामों को नहीं जोड़ा जाता है और परिसम्पत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी जाती। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आने के बाद इस चीज को स्वीकार किया और अब कृषक इसमें अपनी मेड़बंदी करा सकता है, इसके अंतर्गत पक्के काम हो सकते हैं और इसके मार्फत परिसम्पत्तियों का निर्माण हो रहा है और देश के पैसे का सही उपयोग हो रहा है, जनता के पैसे का सही उपयोग हो रहा है। नरेगा में पहले क्या होता था कि मजदूरों के नाम लिस्ट में लिख लिये जाते थे। सरपंच साहब, सरपंच साहब के परिवार, कहीं विधायक महोदय, कहीं गांव के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनकी भी लिस्ट हुआ करती है और उनके नाम से पेमेंट उठा लिया जाता था। मोनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार आने के बाद ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की है और आज यह रिकॉर्ड में है कि किस मजदूर ने, किस श्रमिक ने कितना काम किया है? उसको कितना भुगतान किया गया है? हमारी सरकार आने के बाद लीकेज को रोका गया। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि गैस सब्सिडी और नरेगा में भ्रष्टाचार को रोकने और ऑनलाइन करने के बाद पूरे देश में एक वर्ष में 56 हजार करोड़ रुपए बचे हैं। यह बहुत बड़ी राशि है। यह जनता का पैसा है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। मुझे यह कहते हुए कोई आपत्ति नहीं है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। हर क्षेत्र में

(श्रीमती अलका सिंह)

इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। सिस्टम को भ्रष्ट बनाकर रख दिया। आज यह स्थिति है कि नरेगा में ये जितना खर्चा करते थे, उससे दुगुना व्यय हम आज नरेगा में कर रहे हैं। उससे परिसम्पत्तियों का निर्माण हो रहा है और गाँवों का वास्तव में जो विकास होना चाहिए था, वह विकास हो रहा है।

नरेगा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राजस्थान के ग्रामीण विकास विभाग को पाँच अवार्ड मिले हैं। मैं उनको नहीं दोहराना चाहूंगी, क्योंकि मेरे से पूर्व के वक्ता इन अवार्डों के बारे में बता चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की पहले यह परिभाषा होती थी कि पहले हम गांव में जाते थे। जहां से गड्ढे चालू हो जायें, जहां से सड़कें खराब दिखनी लगे, वहीं लगता था कि अब गांव आ गये हैं लेकिन हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने हमारी सरकार आने के बाद गाँवों को ग्रामीण गौरव-पथ दिया। गांवों के विकास के लिए, गांव वाले भी गौरवान्वित होकर कह सके कि हां, अब शहर जैसी सड़कें, शहर जैसी सुविधाएं हमारे यहां पर हैं।

स्मार्ट विलेज की परिकल्पना हमारी मुख्य मंत्री महोदया का बहुत बड़ा सपना है, जिसमें हर गांव हर सुविधा से परिपूर्ण होगा। पानी, बिजली, सड़क और इसके अतिरिक्त वाई-फाई सुविधा, शिक्षा, हर चीज उसके अंदर होगी। आज गांव में निवास करने वाजा व्यक्ति भी बड़े सम्मान के साथ अपना मुंह ऊपर करके कह सकेगा कि हां, हम राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। आज ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का व्यय पूर्ववर्ती सरकार से हमारी सरकार ने ढाई गुना कर दिया है। पहले के समय में छोटे-मोटे झगड़े होते थे, उससे विवाद हो जाता था। हमारी सरकार बांटने की नहीं, जोड़ने की राजनीति करती है। सबको साथ लेकर सबका विकास करने का जो स्वप्न हमारी माननीया मुख्य मंत्री महोदया ने देखा है और उसका उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है 'अंत्योदय', 'पथ है अंत्योदय और प्रण है अंत्योदय'। उसके अंतर्गत 'न्याय आपके द्वार' स्कीम चालू की और उसमें 95 लाख से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों के जो छोटे-मोटे आपसी मनमुटाव थे, आपसी मुक़दमे थे, उनका निस्तारण हुआ है। गांवों में सबका साथ, सबका विकास' स्वप्न के अनुरूप सर्व समाज को साथ लेकर चलने की परिकल्पना हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है।

(श्रीमती अलका सिंह)

दूसरा बड़ा कदम ग्रामीण विकास के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जन कल्याणकारी शिविर लगाए गए हैं जिसमें 14 विभागों के अधिकारी, 240 सेवाएं, ग्रामीण क्षेत्र में जाकर पंचायत स्तर पर यह कैम्प लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कहीं भी इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी विभागों से रिलेटेड काम उनके गांव में जाकर वहीं के वहीं हो रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में कार्यों का निस्तारण हुआ है।

अब किसानों की बात करें। कांग्रेस के लोग बहुत गाल बजाते हैं, किसान-किसान। 60 साल तक देश और प्रदेश में राज करने वाली पार्टी किसानों की बहबूदी के लिए कुछ भी नहीं कर पाई है। आज भी किसान वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। आपकी सूचना के लिए बता दूं कि वर्ष 2010 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का 41 परसेंट किसान कर्ज में डूबा हुआ था। आपने 65 हजार कृषि कनेक्शन का वादा किया था, आपने पाँच साल में 30 हजार कृषि कनेक्शन दिए। कितना किसानों का हित आप सोचते हैं। यूपीए के समय संसद में सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई थी। उसमें 52 हजार करोड़ रुपये की कर्ज माफी योजना में भ्रष्टाचार था, मतलब किसानों को आपने नहीं छोड़ा। जो कर्ज माफी थी उसमें आपने लोचा कर दिया, उसमें भी आपने भ्रष्टाचार की सीमा को लांघ दिया। सीएजी रिपोर्ट का जब अध्ययन किया गया 90576 खातों का, तो उसमें 20242 खातों में जबरदस्त घोटाला था। 22.34 परसेंट मामलों में घोर अनियमितता। किसानों के साथ धोखा। ग्रामीण विकास में धोखा। जनता को लूटने में आपने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भारतीय राज्य फार्म्स निगम लिमिटेड की ओर से वर्ष 2010-11 में गेहूं और चने के बीज 58 हजार और 50 हजार क्विंटल उत्पादन के लिए एक योजना बनाई गई थी, उसमें भी कांग्रेस की सरकार ने मृत व्यक्तियों के नाम पर सब्सिडी उठा ली। अगर आप चाहें तो यह भी सदन की पटल पर पूरी रिपोर्ट है। हमने किसानों की बहबूदी के लिए ग्राम का आयोजन किया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, माननीय सदस्या फरमा रही है, कौन-कौन से कांग्रेस के

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

व्यक्ति हैं जिन्होंने यह फर्जी सब्सिडी उठाई, नाम बताओ। नहीं तो आपके लोग कौन-कौन भ्रष्टाचार कर रहे हैं मैं नाम बता दूं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): विराजें, मैं जब यह बोल लूं, उसके बाद आप मुझसे मिल लीजिएगा, मेरे पास पूरा रिकार्ड है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मेरी मिलने की आदत नहीं है। मैं तो इतना ही निवेदन कर रहा हूं, मैं ऐसे नहीं मिलता। ...(व्यवधान)...

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मुख्य सचेतक महोदय, पूरा रिकार्ड है ...(व्यवधान)... मैं ऑन रिकार्ड बोलती हूं, बिना रिकार्ड के नहीं बोलती हूं। पूरा रिकार्ड है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप बोल रहे हैं तो बोलो न, नाम बताओ।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): इतनी लंबी लिस्ट है, मैं बोलना चालू करूंगी तो मेरा आधा घंटा आपके घोटालों में ही निकल जाएगा। ...(व्यवधान)...

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको नाम जानना है तो माननीय सदस्या से बाद में मिल लेना आप। बाद में मिल लेना नाम जानने के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मेरा आधा घंटा आपके घोटाले गिनाने में ही निकल जाएगा। आप मिल लेना, मैं विद रिकार्ड बोलती हूं, बिना रिकार्ड कुछ नहीं बोलती हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बच्चों की शादी करोगे और बुलाओगे तो आऊंगा बहन जी, नहीं मिलना-विलना नहीं है। आप तो यहीं बता दो जो बताना है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): यहीं बता दूंगी। आपकी लॉबी में ही आ जाऊंगी, मेरे पास सारा है, मैं आ जाऊंगी आपको आने की जरूरत नहीं लेकिन मेरा आधा घंटा आपके घोटालों की भेंट मत चढ़ाओ।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप जानकर क्या करोगे?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या पता इनके काम आ जाए अगर टिकट-विकट कट रहा हो तो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप यूं ही जबरदस्ती, आपको नाम बताए, उससे क्या कर लेंगे आप?

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): भारतीय राज्य फार्म्स निगम लिमिटेड की ओर से 2010-11 में यह बता चुकी हूं। हमने किसानों की बहबूदी के लिए ग्राम का आयोजन जयपुर, कोटा, उदयपुर में किया। यह उद्देश्य था कि किसानों को नई तकनीक बताई जाए कि उनके विकास के लिए किस तरह की कार्य योजना सरकार बना रही है। उसमें उन किसानों को भी बुलाया गया जो जैविक खेती में एक्सपर्ट हैं या जिन्होंने नवाचार किया है। इसके अंतर्गत 5957 करोड़ रुपयों के 78 एमओयूज हुए। निश्चित रूप से किसानों की बहबूदी के लिए इससे बड़ा आयोजन आज तक नहीं किया गया है।

राज्य की मण्डियों का कम्प्यूटराइजेशन कर दिया गया है। अब सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, किसानों को स्थिरता देने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर हमारी सरकार को पुरस्कार मिला है, हमारे कृषि विभाग को पुरस्कार मिला है। कृषि सोइल हैल्थ कार्ड, किसान कॉल सेंटर, किसान क्रेडिट कार्ड, ये बहुत बड़ी योजनाएं हमारी सरकारी की हैं। ऊंट को राष्ट्रीय पशु हमारी सरकार ने घोषित किया ताकि उसका वध नहीं हो सके। आज ऊंट बहुत उपयोगी पशु है। हमारी पूर्ववर्ती सरकार को इसकी जानकारी होते हुए भी उन्होंने इसके बचाव के लिए कुछ नहीं किया। किसानों को ऋण वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से हुआ है। मैं सहकारी मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि बीजेपी के शासन में, चार वर्षों में 77 हजार करोड़ रुपये का ऋण दिया है जबकि कांग्रेस ने पाँच वर्षों में 56 हजार करोड़ रुपये का, कितना बड़ा अंतर है। किसानों की सहानुभूति लेने वाले लोग हैं, उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि लिप पब्लिसिटी और सिर्फ सहानुभूति लेना अलग बात है, धरातल पर काम करना दूसरी बात है। हम गुड गवर्नेंस का सपना लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य हर वर्ग को साथ लेकर उसका विकास करना है।

श्रमिकों की बात यह कहते हैं। यह मज़दूरों की पार्टी बनती है। मैं पूछना चाहूंगी कि मजदूरों के लिए इन्होंने क्या किया? हमने कुशल और

(श्रीमती अलका सिंह)

अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई, 207 और 277 रुपये। श्रमिक कल्याण कार्ड, टी टी साहब यहां उपस्थित नहीं है, मैं उनकों धन्यवाद देना चाहूंगी। बहुत मेहनत से उन्होंने श्रमिक कल्याण कार्ड की योजना बनाई थी। श्रमिक कल्याण कार्ड के अंतर्गत अकुशल क्षेत्र का श्रमिक जिसकी कोई रिकगनेशन नहीं थी, जिसके लिए कोई योजना नहीं थी, अगर परिवार के कमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो कोई व्यवस्था उसके परिवार के लिए नहीं थी। हमारी सरकार ने, हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसके लिए भी सोचा और श्रमिक कल्याण कार्ड की स्थापना की। इसके अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी बच्चियों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए 55 हजार रुपये तक दिया जाता है।

श्रमिक पंजीकरण की बात करें। बीजेपी के चार साल में 15 लाख 24 हजार श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। मजदूरों की हितैषी बताने वाली पार्टी ने पांच साल में सिर्फ 03 लाख, 19 हजार श्रमिक पंजीकृत किए। श्रमिक कल्याण पर खर्चे की बात भी आपको बता दूं। बीजेपी के चार साल में 690 करोड़ रुपये खर्च हुए। कांग्रेस ने पांच साल में 22 रुपये करोड़ खर्च किए। यह थी आपकी किसान और मजदूरों की हितैषी पार्टी। हम नारों पर नहीं धरातल पर योजना बनाने में विचार करते हैं।

कल कांग्रेस के मुख्य सचेतक महोदय बहुत बढ़-बढ़कर बेरोजगारी के बारे में बोल रहे थे। बेरोजगारी निश्चित रूप से बहुत गंभीर विषय है। 70 साल इस प्रदेश और देश पर राज करने वाले लोग इस तरह की फालतू सहानुभूति जीत कर अगर बेरोज़गारों को अपने पक्ष में करना चाहे तो वह सही नहीं है। आप अपने गिरहबान में झांककर देखिए। इंडिया में 64 परसेंट युवा हैं। युवाओं के लिए कांग्रेस की सरकार ने कोई कार्य योजना नहीं बनाई। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सरकारी नौकरियां नहीं दे सकती। सरकारी नौकरियों की सीमा होती है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट विराज जाइये। Now I won't allow any

(श्री उपाध्यक्ष)

intervention. No intervention will be allowed. Once in a while it is alright but don't make it a habit.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बहुत जोरदार बात है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, जोरदार बात है तो बाद में बता दीजिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह बेरोजगारी की बात बहुत कर रहे थे। बहुत गाल बजा रहे थे बेरोजगार-बेरोजगार। 70 साल हो गए, आपने क्या किया? मैं दावे के साथ कह सकती हूं कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कोई भी सरकार सरकारी नौकरियां पूरी युवाओं के लिए नहीं दे सकती। सरकारी नौकरियों की एक सीमा होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह की योजना बनाई जाए ताकि युवा अपने पैरों पर खड़ा हो सके और आगे बढ़कर स्वाभिमान की जिंदगी जी सके। ...(व्यवधान)... मैं सारी बात सुन लूंगी, मुझे दो मिनट बोल लेने दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 000

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): आप पकौड़े बेचने वाले का अपमान नहीं कर सकते हैं। आज चाय बेचने वाला हमारा प्रधान मंत्री है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन की बिना अनुमति के अगर कोई भी माननीय सदस्य बोला है तो अंकित नहीं होगा। आप जो भी इस प्रकार के व्यंजन की बात करना चाहते हैं बाहर जाकर करिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। लगता है आज इन्होंने लंच नहीं लिया है।

मैं सरकारी नौकरियों की बात कर रही थी। हमारे यहां मैकाले की शिक्षा पद्धति थी। उस शिक्षा पद्धति में सुधार का कांग्रेस द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। यही कारण था कि युवा दिग्भ्रमित होता रहा और युवा एक क्लास बनती गई बाबुओं की। कभी इस बारे में नहीं सोचा गया कि युवाओं के लिए कोई कार्य योजना बनाई जाए। इसलिए बार-बार कहा जाता था कि अंग्रेज चले गए लेकिन काले अँग्रेज़ों का राज रह गया। धन्यवाद है देश और प्रदेश की जनता को कि इस काले अँग्रेज़ों के राज से

(श्रीमती अलका सिंह)

मुक्ति मिली है। अब एक ऐसी सरकार आई है जो युवाओं के बारे में, बेरोज़गारों के बारे में सोचने वाली सरकार है।

(14.00 बजे)

हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया और हमारे माननीय मोदीजी ने आजीविका मिशन और उद्यमिता विभाग का गठन किया और इस तरह की व्यवस्था की कि जैसे पुराने समय में सैल्फ डिपेंडेंट गांव हुआ करते थे, सारी स्किल्स और सारे काम गांव के अंदर ही होते थे और उसके अंदर युवाओं और परिवार के परिवार को रोजगार मिलता था। इस आजीविका मिशन के अंतर्गत अभी तक 13 लाख युवाओं को स्किल डवलपमेंट की ट्रैनिंग राजस्थान की सरकार दे चुकी है और सरकारी नौकरियों की अगर बात करें तो 1 लाख 18 हजार सरकारी नौकरियां राजस्थान में दी जा चुकी हैं और 95 हजार के करीब दिसंबर तक और हो जाएंगी। राजस्थान देश में ऐसा पहला राज्य है जहां कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है ताकि कुशल और अर्धकुशल युवा तैयार हो सकें, जो उद्योगों में काम कर सकें, ग्रामीण विकास में काम कर सकें, कृषि के क्षेत्र में काम कर सकें, सहकारिता के क्षेत्र में काम कर सकें और जो आगे बढ़कर बड़े स्वाभिमान के साथ अपना जीविकोपार्जन कर सकें। कौशल विकास के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए हमारी सरकार को एसोचेम ने 2014-15 और 2015-16 में गोल्डन ट्रोफी दी है। प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत हमारे प्रदेश में 2 लाख 21 हजार युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। कांग्रेस का मैं बताना चाहूंगी, चार वर्ष में 28 विभागों में एक भी भर्ती कांग्रेस के द्वारा नहीं की गई थी। सारे विभाग संविदा पर चल रहे थे और 1200 डॉक्टर्स ने इनके समय पर वीआरएस मांगा था।

हमारी सरकार ने निवेश के लिए भी कार्यक्रम चालू किया था, क्योंकि हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का सोचना है कि निवेश होगा तो रोजगार होगा, निवेश होगा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप होगा। पिछली बार भी 2007 में हमारे यहां निवेश के लिए आयोजन किया गया था, लेकिन चूंकि 2008 में सरकार बदल गई और इनकी कोई सीरिनैस नहीं होने की वजह से वे सारे एमओयू मूर्त रूप में नहीं हो पाए। इनके समय में भी एनआरआई सम्मेलन

(श्रीमती अलका सिंह)

हुआ था। मैं हमेशा बताती हूं कि उसमें क्या हुआ था। इनके तीन मंत्री वहां गए थे। इनके जो पर्यटन विभाग की सचिव थीं, वे सीडी ले जाना भूल गई थीं। कोई प्रजेंटेशन वहां नहीं दिया गया और जो एनआरआई आए थे, वे बहुत नाराज होकर गए और उस समय हमारे देश के माननीय प्रधान मंत्री मोदीजी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और राजस्थान की धरती पर राजस्थान के खर्चे से जो एनआरआई सम्मेलन हुआ था, उसका पूरा का पूरा जो भी इन्वेस्टमेंट होना था, वह सारा गुजरात में चला गया, क्योंकि यहां कोई सीरियसनैस नहीं थी। रिसर्जेंट राजस्थान होने के बाद अबकी बार 3 लाख 38 हजार करोड़ रुपये के निवेश हुए जिसके 470 एमओयू हो चुके हैं, 61 परियोजनाएं क्रियान्वित हो चुकी हैं और 120 प्रगति पर हैं। स्टार्ट-अप पॉलिसी घोषित हो चुकी है, एमएसएमई पॉलिसी घोषित हो चुकी है। यह है मजदूर, किसान और ग्रामीण विकास के बारे में सोचने वाली कांग्रेस पार्टी का हाल।

अब महिलाओं के बारे मैं कहना चाहूंगी। मैं महिला हूं तो महिलाओं के बारे में जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि आधी आबादी को सम्मान देने का काम हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने किया है। 2008 में भामाशाह योजना हमारी सरकार ने चालू की थी, लेकिन कांग्रेस का कोई विजन नहीं था, कोई सोच नहीं थी। महिलाओं को सम्मान देने के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा, इसलिए इन्होंने उस योजना को समाप्त कर दिया। हमारी सरकार के आने के बाद फिर भामाशाह योजना को चालू किया गया और 1 करोड़ 51 लाख परिवारों के 5 करोड़ 55 लाख रुपये से अधिक नगद लाभ अब परिवार की जो प्रमुख महिला है, उसके खाते में सीधे जमा हो रहे हैं और यह एक तरह से महिलाओं को सम्मान देने का हमारी सरकार द्वारा सोचा गया बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा कदम है।

बच्चियों के लिए मुख्य मंत्री राजश्री योजना हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चालू की है, जिसमें बच्ची के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक इन्स्टॉलमेंट्स में पैसा देकर 50 हजार रुपए तक की सहायता की जाती है। बच्चियों की एजुकेशन फ्री है, क्योंकि आधी आबादी जब तक शिक्षित नहीं होंगी, तब तक समाज के विकास के बारे में और समाज को आगे ले जाने

(श्रीमती अलका सिंह)
के बारे में सोचना बिलकुल बेमानी है।

हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने मुख्य मंत्री सक्षम बालिका योजना चालू की है, क्योंकि आज समाज जिस चौराहे पर खड़ा है, वहां जब तक बच्चियां स्वरक्षा और आत्मरक्षा के बारे में ट्रेंड नहीं होंगी, तब तक थोड़ी परेशानी माता-पिता को आती है। बच्चियां आज हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। कोई-सा भी क्षेत्र हो, रात-बेरात इधर-उधर जाना पड़ता है। यह एक सामाजिक समस्या है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आत्मरक्षा का गुर बालिकाओं को आए। इसके लिए 5 लाख बालिकाओं को मुख्य मंत्री सक्षम बालिका योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत बड़ी योजना है। इसमें झुंझुनूं अभी सम्मानित हुआ है। प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 24.30 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी राज्य का विकास उसके इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट से परिलक्षित होता है। हमारी सरकार ने सड़क, पानी, बिजली, सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किए हैं। सड़क के क्षेत्र में मैं अगर कहूं कि सड़क हमारी सरकार की यूएसपी है तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। अभूतपूर्व कार्यों के लिए सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी। अभी जो माननीय नितिन गडकरी जी दौसा पधारे थे तो दौसा से लेकर मथुरा तक स्टेट हाईवे की उन्होंने घोषणा की थी और उसमें से 28 किलोमीटर सड़क मेरे विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरती है। मैं उसके लिए उन्हें बहुत-बहुत आभार देना चाहूंगी। हमारी सरकार आने के बाद 14 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रतिदिन हो रहा है। 17 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो रहा है और पांच नए गांव हर दिन सड़कों से जोड़े जा रहे हैं। अगर नवीन राजमार्गों की मैं बात करूं तो कांग्रेस ने 5 साल में 74 किलोमीटर नवीन राजमार्ग बनाए थे। हमारी सरकार ने आने के बाद सिर्फ चार साल में 5262 किलोमीटर बनाए। देखिए आप अंतर।

अगर चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात की जाए तो भामाशाह योजना के बिना बात बिलकुल अधूरी रह जाएगी। इसके बारे में पूर्ववर्ती वक्ता काफी

(श्रीमती अलका सिंह)

बता चुके हैं। 30 हजार से 3 लाख लाख तक की मुफ्त जांच। गत सरकार ने 5 साल में 530 हॉस्पिटल्स खोले थे। इसमें यूपीएचसी, सीएचसी, पीएचसी सभी हैं। हमने 4 साल में 1967 खोले। कांग्रेस का हाल यह है कि योजना आयोग की अध्यक्षा सदस्या सईदा हमीद ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे खराब हालत राजस्थान में है। यह उन्होंने 23 जनवरी, 2012 को कहा था। कांग्रेस को 108 एंबुलेंस का घोटाला याद दिलाना चाहूंगी। स्वाइन फ्लू की कल आप बात कर रहे थे। स्वाइन फ्लू के बारे में हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की। आपने तो आखिर तक जब तक मौतें नहीं हो गईं, तब तक कुछ नहीं किया था। जोधपुर में जो नकली ग्लूकोज से प्रसूताओं की मौत हुई थी, उसकी जांच के बाद कुछ रिजल्ट नहीं निकला। मुफ्त दवाओं के बारे में ज्यादातर ढिंढोरा पीटा जाता है कि मुफ्त दवा, नि:शुल्क दवा योजना हमने चालू की। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि नि:शुल्क दवा का आप बजट देख लीजिए कि आपके समय में क्या था और आज हमारे समय में क्या है। नि:शुल्क जांच को हमने इसमें जोड़ा और जितनी दवाइयां आपके समय में आती थीं, उससे दुगुनी दवाइयां आज नि:शुल्क दवा योजना के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उस समय का एक वाकया बताना चाहूंगी। मेरी कान्स्टीट्यूएंसी का एक व्यक्ति जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको ठीक होना है तो बाहर से दवाई लीजिए। कारण यह था कि नि:शुल्क दवा का ठेका जिसके पास था और जो उसके पार्टनर थे, अगर इसकी पूरी जांच करा ली जाए तो सारी पोल खुल जाएगी।

कानून-व्यवस्था के बारे में कल मुख्य सचेतक महोदय बहुत बोल रहे थे। उनको भी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट बताना चाहूंगी। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड में 2011-12 में राजस्थान सैकिण्ड नंबर पर था। महिला अत्याचार में राजस्थान थर्ड नंबर पर था। दलित अत्याचार देश में 2.9 परसेंट था और राजस्थान में 7.5 परसेंट, जो कि सबसे ज्यादा था। यही कारण है कि जब आम चुनाव हुए थे, एस.सी. का एक भी व्यक्ति आपका चुनकर नहीं आया था। 2011 की जो क्राइम रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि राजस्थान देश का सबसे असुरक्षित राज्य है। यह है आपकी कानून-व्यवस्था की स्थिति। सूरवाल काण्ड को याद कर लीजिये, भंवरी देवी काण्ड को याद कर लीजिये। जोधपुर

(श्रीमती अलका सिंह)

जेलर की हत्या भी आप ही के समय पर हुई थी। आज स्थिति यह है कि अपराध में 5.8 परसेंट गिरावट आई है। 2234 गांव अपराध मुक्त हो चुके हैं। सरकार ने पुलिस के आधुनिकीकरण के लिये 10 करोड़ रुपये खर्च किये हैं, जो कि आपके समय में कभी नहीं किये गये। डिजिटल एफ.आई.आर. की व्यवस्था की है। आपके समय में रिकार्ड इसलिये भी नहीं होता था, क्योंकि रिकार्डेड कुछ नहीं था। अब बिलकुल पारदर्शी तरीके से सारी व्यवस्था की गई है ताकि अपराधी भी नहीं बच सकें और यदि कोई गलत है तो उसके खिलाफ भी कोई कार्यवाही नहीं हो। पारदर्शिता लाने के लिये नीति और सिद्धांतों को प्राथमिकता के लिये, भ्रष्टाचार रोकने के लिये और सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिये हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने डिजिटाइजेशन किया। आपके पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था, एक रुपया भेजता हूं, 15 पैसे मिलते हैं। हमने ऐसी फुलप्रूफ व्यवस्था की कि एक रुपये भेजा जाये तो वह पूरा का पूरा एक रुपया ही उस व्यक्ति के खाते में जाये, जिसके लिये वह बना है। इसी डिजिटाइजेशन का ही यह नतीजा है कि आज सारी पेंशन, आज भामाशाह योजना के अंतर्गत हो, पालनहार योजना में हो, जननी सुरक्षा में हो या किसी भी तरह की कोई भी सरकारी सहायता हो, वह सीधे खाते में जाती है। बिचौलियों का काम बंद हो गया है और जो बीच में भ्रष्टाचार होता था, वह करीब-करीब समाप्त हो चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक चीज और कहना चाहूंगी, कांग्रेस के समय का नारा था। हम नारों पर नहीं टिके, नीति की बात करते हैं। हम सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। कांग्रेस के समय नारा था, 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ' तो इनके 'पानी बचाओ' पर मैं थोड़ा-सा बताना चाहूंगी, कितना पानी इन्होंने बचाया। वह तो कल सदन की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उसके अन्दर ही आपने देख लिया कि जो डिस्कशन का स्तर है, उसको कितने निचले स्तर पर ये ले गये थे। हमारे जो युग पुरुष हैं, माननीय दीनदयालजी, उनके बारे में जिस भाषा का उपयोग इस सदन में किया गया था, निश्चित रूप से बहुत गम्भीर विषय है, उसके लिये इनको शर्मिन्दा होना चाहिए।

वर्ष 2012-13 में केन्द्र सरकार की रिपोर्ट है। उस समय केन्द्र सरकार

(श्रीमती अलका सिंह)

आप ही की थी, कांग्रेस की ही थी। राज्य की कोई ठोस योजना नहीं है और राज्य आठवें पायदान पर है। गत सरकार की तुलना में हमने चार वर्ष में 6 हजार करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किये हैं पानी के लिये। 7698 गांव-ढाणी में पानी पहुंचाया है, 23 शहर लाभान्वित हुए हैं। यह आंकड़ा पूर्ववर्ती सरकार से तीन गुना ज्यादा है।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और काल, गांव में कहा जाता है कि कांग्रेस और काल एक ही राशि है। जब-जब कांग्रेस का शासन आता है तब-तब प्रदेश में अकाल पड़ता है। यह 100 परसेंट है, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार ने 60 वर्ष तक शासन करने के बाद भी, इस बारे में कोई गम्भीर प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनकी कोई सोच नहीं थी, कोई विजन नहीं है। हर जगह सिर्फ भ्रष्टाचार, घोटाला। उसके आगे कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा। हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बहुत संवदेनशीलता से इस विषय को उठाया और मुख्य मंत्री जलस्वावलम्बन अभियान की शुरुआत की। उपाध्यक्ष महोदय, इसको अभियान का रूप इसलिये दिया, ताकि आम जनता का जुड़ाव इसके साथ हो। आज राजस्थान में 294 ब्लाक्स ऐसे हैं जो सूखे हैं, और बहुत जरूरी है कि आम जनता का जुड़ाव जब तक इस अभियान के साथ नहीं होगा, तब तक अकेली सरकार के भरोसे इस तरह के जो अभियान हैं और जो पानी की प्रोब्लम है, उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस अभियान में आम जनता को जोड़ा। जो श्रम देना चाहता था, जो पैसा देना चाहता था उससे पैसा लिया तथा जो अपना साधन देना चाहता था, उससे साधन लिया और इसके बारे में भी कांग्रेस, क्योंकि इनकी आदत है हर जगह भ्रष्टाचार को देखने की, क्योंकि इन्होंने हर जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है, तो मैं बताना चाहूंगी, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, एक साइट का एड्रेस दूंगी, आप उस पर देख लीजिये, कब, कहां से, कितना पैसा आया है। एक-एक पैसे का हिसाब उसके अन्दर है लेकिन इस जल स्वावलम्बन अभियान के बाद 50 ब्लाक पानी की कमी से बाहर निकले हैं। इस स्कीम के तहत 80 लाख पौधे लगाये गये हैं ताकि पौधे लगने से हमारी जलवायु का साइकिल कम्प्लीट हो, जिससे बारिश अच्छी हो। 21 हजार गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाने के

(श्रीमती अलका सिंह)

लिये यह जल स्वावलम्बन अभियान अभी चालू किया गया है। तीसरा चरण अभी इसका ग्रामीण क्षेत्र में और द्‌वितीय अभी शहरी क्षेत्र में आया है और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है।

सैकण्ड पाइण्ट इनका नारा था, 'बिजली बचाओ', अब बिजली कैसी बची है, वह आप सबको ज्ञात है। 80 हजार करोड़ रुपये का घाटा, फीडर रिनोवेशन की कोई योजना नहीं, छीजत रोकने का कोई प्लान नहीं, बार-बार रेट बढ़ा दी, किसानों के हितों के लिये कोई सोचने वाला नहीं, लेकिन नारा दे दिया, बिजली बचाओ। कहां बचा रहे थे, खुद को बचा रहे थे कि बिजली बचा रहे थे? बिजली कम्पनियों की रेटिंग हुई, केन्द्र सरकार की रिपोर्ट, राजस्थान निचले पायदान पर, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। फीडर रिनोवेशन की ठोस कार्य योजना नहीं बनाई।

हमारी माननीय मुख्य मंत्री जब सत्ता में आयीं तो उनके सामने चैलेंज था कि या तो इस सिस्टम को क्रेश हो जाने दें, या इस चैलेंज को स्वीकार करें। हमारी माननीय मुख्य मंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए जनता के हित में, इस 'उदय योजना' के अन्तर्गत 64 हजार करोड़ रुपये का कर्जा अपने ऊपर लिया, छीजत कम की। छीजत 4.8 परसेंट थी, वह मार्च में 3.08 परसेंट हो गयी। फीडर रिनोवेशन का प्रोग्राम चालू किया, जिससे हर वर्ष बिजली के क्षेत्र में होने वाला घाटा कम हो गया है। आपके समय में हालत यह थी कि 23 मार्च, 2011, कोट करना चाहूंगी, संसद में सी.ए.जी. की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उसमें कहा गया कि बिजली उत्पादन में देरी के कारण राजस्थान को 113 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, मतलब कोढ़ में खाज। विकास तो आप कुछ कर नहीं रहे थे, बिजली का ढांचा और बिजली तंत्र में सुधार के लिये तो आपने कोई प्रयास नहीं किये, बल्कि उसको डुबोने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी, क्योंकि कोई सोच नहीं थी, कोई विजन आपका नहीं था, कोई संवेदनशीलता आप में नहीं थी। आज स्थिति यह है कि राजस्थान को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 2018 में फर्स्ट अवार्ड मिला है, क्योंकि फीडर रिनोवशन हुआ है, घाटा हमने कम किया है।

इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहला पुरस्कार राजस्थान को मिला है, क्योंकि अल्टरनेटिव एनर्जीज के बारे में सोचना राजस्थान के लिये

(श्रीमती अलका सिंह)

बहुत जरूरी है। राजस्थान के जो सीमांत इलाके हैं, वहां काफी गर्मी और तेज धूप है। अगर वहां पर सोलर प्लाण्ट्स लगा दिये जाएं तो इस बारे में सोचने वाली भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी माननीय मुख्य मंत्री महोदया हैं।

अब 'सबको पढ़ाओ', पर लाना चाहूंगी। नारा दे दिया, सबको पढ़ाओ। लेकिन कैसे पढ़ाओ, इसकी कोई व्यवस्था आपने नहीं की थी। वर्ष 2012 की योजना आयोग की रिपोर्ट आपको बताना चाहूंगी, आपको आईना दिखाना चाहूंगी। बालिका शिक्षा और ड्रोपआउट वे, राजस्थान फिसड्डी, यह योजना आयोग की रिपोर्ट है क्योंकि आपने शिक्षा के क्षेत्र में कोई नया कदम नहीं उठाया, कोई नवाचार नहीं किया। धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय शिक्षा मंत्रीजी को, माननीय मुख्य मंत्री महोदया को, 17 साल बाद शिक्षा के क्षेत्र में प्रमोशंस हुए। पहली बार, जो ऐसे विद्यालय थे, जो दूरी पर थे, उनका एकीकरण करके शिक्षा के स्तर में सुधार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ने किया है। राजस्थान शिक्षा के सूचकांक में आपके समय में 22वें पायदान पर था। हमने 5300 स्कूल क्रमोन्नत किये, आपने 1311 ही क्रमोन्नत किये। आज हमारी मुख्य मंत्रीजी का सपना है कि हर पंचायत हैड-क्वार्टर पर एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो, और उसका मेन उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में, आप और हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में यह है कि बच्चियों की एजुकेशन के लिये सरकारी स्कूलों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों को तो लोग फिर भी प्राइवेट स्कूल्स में भेज देते हैं, बच्चियों के लिये सरकारी स्कूल हर पंचायत लेवल पर होना बहुत जरूरी है। यह हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी का ही सपना है कि हर पंचायत स्तर पर एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल हो और उसी का परिणाम है, शिक्षा के स्तर को सुधारने के कारण आज सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ा है। एक एन.जी.ओ., 'असर' है, जिसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि 47 परसेंट स्टूडेंट निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में स्विच-ओवर हुए हैं। परिणाम अगर देखा जाये तो निजी स्कूलों का जहां 88 परसेंट रहा है, राजस्थान के सरकारी स्कूलों का 91 परसेंट हुआ है, क्योंकि बहुत सुधारात्मक कार्य शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार ने किया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में राजस्थान को अभी फर्स्ट

(श्रीमती अलका सिंह)

अवार्ड मिला है। हमने अभी फेस्टिवल ऑफ एजुकेशन किया। उसका उद्देश्य यह था कि बच्चों को आप्शन दिये जाये कि वे किस तरह की शिक्षा, कहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्या-क्या रोजगार के लिए, क्योंकि कांग्रेस के समय में मैकाले से आगे शिक्षा पद्धत्ति नहीं बढ़ी। हमने शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को आरम्भ किया। आज डिजिटाइजेशन का जमाना है, कम्प्यूटर लिट्रेसी प्रोग्राम 716 स्कूलों में शुरू करने वाली भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार है।

साइकिल वितरण की जाती थी, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते थे, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को साइकिल वितरण की और आज तीन गुना ज्यादा साइकिल का वितरण हो रहा है।

"शाला दर्पण" पोर्टल की शुरुआत की, जिसमें हर स्कूल का कम्प्लीट रिकार्ड रहता है और यहां बैठकर आफिसर्स, मंत्री महोदय और कोई और भी देखना चाहे तो अपने स्कूल की प्रगति को देख सकता है। बस, समाप्त कर रही हूं। इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, किसानों के लिए हमारी सरकार ने जितना काम किया, उतना कांग्रेस की सरकार ने 70 साल राज में रहने के बाद भी नहीं किया है।

"सम्पर्क पोर्टल", हमारी पारदर्शी, संवेदनशील, प्रशासनकारी और गुड गवर्नेंस का ही परिचायक है कि 17 लाख अभी तक इसमें आई हैं एप्लीकेशंस, उनमें से 15 लाख का निस्तारण हो चुका है।

'अपना जिला अपनी सरकार' यह संवेदनशील हमारी माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं जो 48 डिग्री टेम्प्रेचर में भी हर जिले में गई हैं और हर जिले के आम जो नागरिक हैं उनसे रूबरू हुई हैं।

अन्नपूर्णा रसोई योजना, काफी वक्ता पूर्व में बोल चुके हैं, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ग्रामीणों के बारे में, गरीब व्यक्ति के बारे में सोचने के लिए, जहां 5 और 8 रुपए में खाना और नाश्ता मिल जाता है।

'वृद्धजन तीर्थ यात्रा योजना', युवाओं के बारे में ही नहीं, बुजुर्गों के बारे में सोचने वाली संवेदनशील हमारी माननीय मुख्य मंत्री हैं और यही है कि वृद्धजन तीर्थ यात्रा योजना अभी चालू की है।

अब मैं बताना चाहूंगी, अभी ये बार-बार कहते हैं तीन सीट आ गई, तीन सीट आ गई। आपकी सूखी घास पर तीन बूंद गिरी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 3 नहीं है, 17 हार गये हैं।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): डे ड्रीमिंग मत करिये। दीये की लौ जब बुझती है न उसके पहले एक बार तेज उजाला करती है और बाद में फुस्स होकर बुझ जाती है, इसलिए शान्ति रखिये। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का भविष्य है राजस्थान में। जनता हमें प्यार करती है, इसलिए...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पीछे तो एक भी नहीं है। एक बाड़मेर बोर्डर है सिर्फ और कुछ नहीं, आगे तो सिर्फ पाकिस्तान है। देख लो, पीछे देख लो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपका दल कहां गया, कोई है ही नहीं, अकेले ही सब कुछ बोल रहे हो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, ये सवा चार साल से इतने ही थे, लेकिन फिर भी 17-0 हो गये आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पीछे देखो तो सही एक बार, एक बार देख तो लो हमारे कहने से।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपको छोड़ गये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): मुख्य सचेतक महोदय, जनता ने हमको सतर्क किया है क्योंकि जनता हमें प्यार करती है, उनको डर है कि वापस आप नहीं आ जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्या, ये सिर्फ सचेतक हैं, मुख्य तो अपने पास है।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): सोरी, चलिये अच्छा हुआ आपने करेक्शन कर दिया, मैं जबर्दस्ती गलतफहमी में इनको मुख्य बनाई हुई थी तो ये आम चुनाव से पहले हमें सतर्क किया है कि आप अपनी जो....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, अगले समय के लिए कह रहे हैं अगले समय के लिए।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): थोड़ी-बहुत इधर-उधर की बातों को सुधार लें, नहीं तो वापस वे आ जाएंगे और फिर ग्रामीणों को लूटेंगे, किसानों को

(श्रीमती अलका सिंह)

लूटेंगे, जनता को लूटेंगे। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार लाएंगे और पता नहीं कहां-कहां भ्रष्टाचार लायेंगे, इसलिए जनता ने सिर्फ हमें वॉर्निंग दी है, ज्यादा डे ड्रीमिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री शंकर सिंह जी। श्री कैलाश चौधरी।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसलिए आपका बहुत-बहुत आभार। महामहिम राज्यपाल द्वारा जो अभिभाषण दिया, वह सरकार का पिछले 4 साल का जो कार्यकाल था, उसके अन्दर जो काम किये और आने वाला एक वर्ष जो है उसके अन्दर हमें जो विकास के कार्यों को करना है, उसे लेकर जो अभिभाषण था, उस अभिभाषण को सुनने के बाद, उस समय विपक्ष में बैठे, जो प्रतिपक्ष में हैं, उन्होंने उसे सुना भी नहीं और वो जिस तरह से उस समय से ही यह जाहिर हो गया कि इनका मकसद क्या है और सरकार का जो विकास है, जो विकास कर रही है सरकार, उसको सुनाना नहीं है और सिर्फ हंगामा करना उनका मकसद है और उसी के तहत यहां पर जैसे जीतने के बाद में आये तो आकर जो ये पंक्ति यहां पर लिखी है उसको भी पढ़ा और आपने भी इसको पढ़ा होगा। सत्य बोलना चाहिए लेकिन विपक्ष हमेशा झूठ या जो असत्य बात होती है, उसको रखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय जी, कि सरकार का वास्तव में काम करने का जो तरीका होता है और विकास कराना जो उनका मकसद होता है, वह विकास किस तरीके से होता है। जैसे पहले कोई व्यक्ति होता था तो आपको पता होगा कि हमारी सरकार ने ऐसी-ऐसी योजनाएं बनाई, जिसमें सबसे पहले तो जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, उस भ्रष्टाचार का हम अन्त कैसे करें और हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से भामाशाह योजना को प्रारम्भ किया, पहले एक रुपया भी अगर आपके प्रधान मंत्रीजी ने पहले कहा, आप भी कहते थे, हम भी जब जाते थे, आपसे बात करते थे तो यही कहा करते थे कि हम तो पैसे भेजते हैं ऊपर से, लेकिन बीच में पैसा बिचौलिए खा जाते हैं और नीचे तक 15 रुपये ही पहुंचते हैं लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने ऐसी योजना को

(श्री कैलाश चौधरी)

प्रारम्भ किया और भामाशाह योजना जिसको प्रारम्भ किया। उस योजना के अन्दर सीधे उनके खाते खोले गये और खाते के अन्दर आज 55 लाख व्यक्तियों को उनके नाम से सीधे खाते खोलकर और 13 हजार दो सौ अस्सी करोड़ रुपये उनके सीधे खातों में, लाभार्थियों के खाते में डाले गये। पहले अगर नरेगा हो या चाहे किसी भी काम के अन्दर होता था तो उस समय, जब जाते थे तो उसमें जो व्यक्ति काम करता था, चाहे वह महिला हो, चाहे पुरुष हों तो उनको काम करने वाले को तो पैसा मिलता नहीं था लेकिन जो उनके पति होते थे या उनका जो भाई होता था वो पैसा ले जाता था लेकिन उसके बाद, वे सिर्फ यह कहते हैं कि तगारी ही पांती आती थी, उसका पैसा बीच में खा जाते थे, लेकिन ऐसी एक महत्वपूर्ण योजना प्रारम्भ करके, यह साफ इससे जाहिर होता है कि हमारी सरकार की सोच क्या है। हमारी सरकार की सोच यही है कि हमें सबसे पहले इस राज्य से और इस देश से भ्रष्टाचार को खतम करना है।

इसी तरह से भ्रष्टाचार के लिए भामाशाह योजना बनाई, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना बनाई और भामाशाह स्वास्थ्य योजना के अन्दर पहले जहां पर सरकार के अन्दर ये कहते हैं कि हमने नि:शुल्क दवा योजना प्रारम्भ की। उनके अन्दर बहुत कम मात्रा में बजट आपका होता था, लेकिन उसके बाद हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उसके अन्दर ये संशोधन किया कि एक गरीब व्यक्ति है, कई बार वे सारी सुविधाएं सरकारी अस्पताल में नहीं मिलती हैं तो वह प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर जाता था तो उसको लगता था कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मेरा इलाज हो जायेगा तो उसको वह जब हॉस्पिटल के अन्दर कई बार ऐसे धनाढ्य लोग होते थे, उनको देखकर सोचता था, वहां मेरा भी इलाज हो जाए। मैं अगर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाऊं तो हो सकता है तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जैसे भामाशाह योजना के अन्दर 30 हजार से लेकर 3 लाख रुपये तक एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अन्दर जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, वहां पर उस गरीब व्यक्ति का इलाज कराने का अगर काम किया तो हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने ऐसी एक योजना बनाई, जिसके अन्दर गरीब को यह लगे कि मेरा भी वास्तव में इलाज हो सकता है और अच्छी तरीके से इलाज हो सकता है।

(श्री कैलाश चौधरी)

इसी तरह से आदर्श पी.एच.सीज. हैं, आदर्श पी.एच.सी. बनाई। आदर्श पी.एच.सी के अन्दर आज 518 ऐसी पी.एच.सीज. हैं जो आदर्श पी.एच.सीज. हैं और साथ ही 413 पी.एच.सीज. हैं, उन पी.एच.सीज. के अन्दर हम आदर्श करने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से वहां पर वे सारी दवाइयां भी अवेलेबल रहती हैं, वहां पर पूरा स्टॉफ भी है। गांवों के अन्दर पहले हम जाते थे तो उस समय गांव के अन्दर, एक गांव के अन्दर बड़ी मुश्किल से ए.एन.एम. भी नहीं होती थी लेकिन आज हमारे गांवों के अन्दर ए.एन.एम भी है और डॉक्टर की जहां पर आवश्यकता है वहां पर डॉक्टर भी है और निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के अन्दर जो हमारी मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व के अन्दर काम हुए हैं, वे बहुत ही सराहनीय कार्य हुए हैं। उसी के साथ में अगर देखें, मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से गांवों के अंदर हम जाते थे, पहले पानी की जो समस्या थी, पानी बहुत गहरा हुआ करता था और गहरे पानी को निकालने के लिए वहां पर ऐसी स्थिति थी कि डार्कजोन हुआ करते थे तो उन डार्कजोन के अंदर किसान को कनेक्शन तक नहीं दिया जाता था तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बहुत दूर की सोची कि हमारे यहां पर ऐसी एक व्यवस्था करें कि जिससे वहां पर पानी का स्तर ऊपर उठ सकें तो उन्होंने 'मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान' प्रारंभ किया। उसको एक अभियान के रूप में लिया। एक योजना नहीं बनायी, उसको एक अभियान के रूप में लिया और उसमें जनता का भी सहयोग लिया गया। जनता का सहयोग लेकर मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान प्रारंभ किया, जिसकी वजह से आज प्रदेश के अंदर हमारा जलस्तर ऊपर उठा है।

ऐसे कई एनीकट थे, जहां से पानी बहकर समुद्र के अंदर चला जाता था तो आज उन एनीकट्स की वजह से वहां पर जलस्तर, वहां पर पानी रुकता है और जिसकी वजह से हमारा जलस्तर ऊपर उठा है और ऐसे कई विधान सभा क्षेत्रों के अंदर मेरा भी जाना किसानों के बीच में हुआ तो वहां पर वास्तव में पहले जहां पर बिलकुल खेती ही नहीं हुआ करती थी लेकिन वर्तमान में उन स्थानों पर खेती होती है और उनका जलस्तर ऊपर हुआ है। उसका सीधा अगर कोई कारण है तो हमारी मुख्य मंत्रीजी की वह सोच है

(श्री कैलाश चौधरी)

कि हमारे को जलस्तर ऊपर उठाना है और उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और आज भी इस काम को और गति देने के साथ में हम आगे बढ़ रहें हैं।

इसी के साथ में गांवों के अंदर हमारे कई ऐसे भाई थे जो आपस में भाई-भाई के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहे थे। गांवों के अंदर किसी न किसी बात को लेकर आपस में पड़ौसी का विवाद चल रहा था, वर्षों से विवाद चल रहे थे। उनको कोई यह पूछने वाला नहीं था कि तुम्हारे कोई समझौता कर रहा है या किस तरह से इसका निपटारा हो सके लेकिन हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि ऐसे हमारे सरकार के जो अधिकारी हैं उन किसानों को वहां पर जाना नहीं पड़े, बार बार परेशान नहीं होना पड़े तो प्रशासन को वहां भेजा गांव के अंदर और 'न्याय आपके द्वार' अभियान के तहत लगभग 96 हजार प्रकरणों का वहां गांव के अंदर जाकर निस्तारण करना, यह कोई छोटी बात नहीं है। जिनके 30-30 साल से लोग परेशान हो रहे थे, उनको 30-30 साल या 40-40 साल हो गये, कइयों की पीढ़ियां चली गयीं, उन लोगों को यह एहसास होता है कि वास्तव में हमारे काम हुए है।

इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि चाहे वह 'न्याय आपके द्वार' हो, चाहे 'मुख्य मंत्री जल स्वावलंबन अभियान' हो, 'अन्नपूर्णा भंडार' हो, अन्नपूर्णा भंडार के माध्यम से गांवों के अंदर ऐसी दुकानें जो खोली गयी हैं, जिनके अंदर मल्टी-ब्रांड की दुकानें हैं उनके 6161 अन्नपूर्णा भंडार सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। यह अन्नपूर्णा भंडार, जब शहर के अंदर जाते थे तो वहां पर उनको मल्टी-ब्रांड की वस्तुएं मिलती थीं लेकिन आज गांव के अंदर और उचित मूल्य, जो एक मूल्य होता है उससे भी कम मूल्य पर, बाजार भाव से भी कम मूल्य पर अगर उसको वहां पर मिलती है तो उसको भी लगता है कि मैं आज गांव में बैठा हूं लेकिन मेरे पास में शहर की वह सारी सुविधाएं हैं और वहां से भी सस्ती दर पर उसको मिल रही है।

इसी तरह से खाद्य सुरक्षा की बात करें। जो पोस-मशीन के अंदर, अपन सब जानते हैं, जब गांव के अंदर जाते थे माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री कैलाश चौधरी)
तो यह विषय हमेशा उठता था कि हमारे गेहूं हमें नहीं मिले, हमारे को शक्कर नहीं मिली और जिसकी वजह से वहां पर लोग परेशान होते थे। एक गरीब व्यक्ति था जिसको यह उम्मीद होती थी कि साल के अंत होते-होते, महीने का अंत होते-होते मुझे वहां पर गेहूं मिलेगा लेकिन जब वह गेहूं के लिये जाता था तो उस समय उसको कहते थे कि तुम्हारा गेहूं तो अगले महीने में आएगा। वह अगले महीने जाता तो उसको कहते कि और अगले महीने आएगा तो पाँच-पाँच महीने तक उसको गेहूं नहीं मिलता था, वह अपनी आंखों के आंसू से रोता था लेकिन उसको वह नहीं मिलते थे। हमारी मुख्य मंत्रीजी ने ऐसी पोस-मशीन के द्वारा कहा कि आप वहां पर अंगूठे के द्वारा, जब आप अंगूठा लगाओगे तो आपको ही गेहूं मिलेगा और यही नहीं, उसके बाद में उसके मोबाइल पर मैसेज भी आता है, यह सुविधाएं अगर की हैं तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने की है। अगर यह काम आपने पहले कर लिये होते तो आज आपको बता दूं कि यह जो 21 पर आप आकर बैठे हो, वह स्थिति आपकी नहीं होती। लेकिन हंसने से कुछ नहीं होता, मंद-मंद मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। हम काम करने में विश्वास रखते हैं और हमने काम करके दिखाये हैं।

इसी तरह से श्रमिकों की बात करें। श्रमिक कार्ड आपके भी उस समय में थे लेकिन आपने उनको लाभ देने का काम नहीं किया। मजदूर को इनाम देने की बात की गयी। मजदूरों के लिए कहा गया कि हम मजदूर हितैषी हैं लेकिन मजदूर हितैषी होकर आपने मजदूरों के लिए ऐसा कौनसा काम किया? मुझे आज कहते हुए खुशी होती है कि हमारी सरकार ने वह योजना बनायी उस मजदूर के लिए, उस मजदूर को यह लगता है कि यदि कल मेरे कुछ भी हो गया तो उसके पीछे परिवार को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज उसकी बेटी है, अगर तो उसकी शादी होती है तो उसको यह चिंता नहीं है कि शादी होगी तो उस समय उसको 55 हजार रुपये शादी के खर्चे के रूप तौर पर देना। अगर वह बच्ची पढ़ती है तो उसको पढ़ने के लिए खर्चा दिया जाता है और जब वह बच्ची जन्म लेती है एक मजदूर की तो उस बच्ची के जन्म पर 21 हजार रुपये और लड़के के जन्म पर 20 हजार रुपये दिये जाते हैं। इस तरह से उनकी अगर एक्सीडेंट

(श्री कैलाश चौधरी)

के कारण से किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस मजदूर के पीछे उस परिवार को वहां पर 6 लाख रुपये और इस तरह से उनको देकर उसके परिवार को संबल बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने किया है। हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी के नेतृत्व के अंदर यह काम हुए हैं।

मैं यह कह सकता हूं कि विगत चार वर्षों के अंदर चाहे अपन किसी भी क्षेत्र में, विद्युत के अंदर देखें तो विद्युत के अंदर भी चाहे कृषि कनेक्शन हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, उनके अंदर हमने काम किये हैं। अगर ये कृषि कनेक्शन की बात करें तो 2008 के अंदर जब हमारी सरकार दुर्भाग्य से चली गयी तो उस समय हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो विद्युत कृषि कनेक्शन की पेंडेंसी थी, वह खतम कर दी थी। लेकिन पांच के अंदर आपका जो शासन रहा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब इनका शासन रहा तो इन्होंने कृषि कनेक्शन के नाम पर एक भी कृषि कनेक्शन नहीं करवाया, जिसकी वजह से किसानों के कृषि कनेक्शन नहीं हुए लेकिन मुझे आज यह कहते हुए खुशी होती है कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने उस ओर ध्यान दिया और आज सरकार में आते ही कृषि कनेक्शन वापस करवाये गये और जिसकी वजह से आज किसानों को यह लगता है कि हमारे यहां पर कृषि कनेक्शन हुए हैं। लगभग 75 हजार कृषि कनेक्शन किये गये। यह सोच हमारी है, हमारी मुख्य मंत्रीजी की सोच है। उन्होंने सिर्फ कृषि कनेक्शन ही नहीं, उस विद्युत के उत्पादन को भी बढ़ाया। जहां विद्युत आप घाटे के अंदर छोड़कर गये थे, उसको भी उठाने का काम हमारी सरकार ने किया और विगत चार वर्षों के अंदर अगर विद्युत उत्पादन की बात करें तो 12820 मेगावाट से बढ़ाकर हमने 19536 मेगावाट करने का काम किया है। मैं यह कहता हूं कि विद्युत में हमने किसानों को सिर्फ कृषि कनेक्शन ही नहीं दिये, हमारी विद्युत के मेगावाट को बढ़ाकर किसान तक विद्युत पहुंचाने का काम भी किया और साथ ही, उसको जो 24 घंटे का हमने वादा किया कि घरेलू कनेक्शन पर 24 घंटे लाइट देना तो उस वादे के ऊपर हम पूरा काम कर रहे हैं। कृषि लाइट विद्युत है, उस किसान को भी हमने वादा किया था कि हम सात घंटे लाइट देंगे तो वह सात घंटे लाइट आज भी उन

(श्री कैलाश चौधरी)
किसान को मिलती है तो उसको लगता है कि वास्तव में मेरे, आज किसान को यह महसूस होता है कि वास्तव में सरकार हमारे साथ में खड़ी है। ऊर्जा के क्षेत्र में हो, चाहे नए कृषि कनेक्शन हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसान केहित में योजनाएं बनायी गयी हैं।

आज मैं अगर शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा के अंदर गांवों के अंदर एक विद्यालय के लिए, यह नेता अभी विपक्ष में बैठे हैं, उनके पास में जाते थे, घूमते थे, चक्कर काटते थे, दस-दस चक्कर काटते, गांव का गांव पूरा आ जाता था और कहते थे कि हमारे एक हायर सैकण्डरी स्कूल खोल दो। वह सिर्फ आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं देते थे।

मैं एक छोटा-सा उदाहरण मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही बताता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर मैं यहां पर 14वां विधायक हूं। मेरे से पहले 13 विधायक बने और उन 13 विधायकों ने मिलकर 13 हायर सैकण्डरी स्कूल्स खोलीं यानी कि एक विधायक के कार्यकाल के अंदर उसको एक हायर सैकण्डरी स्कूल मिली होगी लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि मेरे एक कार्यकाल के अंदर 56 हायर सैकण्डरी स्कूलें बायतू विधान सभा क्षेत्र के अंदर खुली हैं। इस तरह से मैं यह कह सकता हूं कि जहां पर पूरे राजस्थान के अंदर, जहां पर भारत आजाद होने के बाद में 3600 हायर सैकण्डरी स्कूल्स थीं, उनकी जगह इन पिछले तीन-चार साल के अंदर हमारी सरकार ने 6300 नई हायर सैकण्डरी स्कूल्स खोली हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर सिर्फ हमने हायर सैकण्डरी स्कूल्स ही नहीं खोलीं, बल्कि हमने अध्यापकों की भी व्यवस्था की। आदर्श हायर सैकण्डरी स्कूल्स खोले। उन आदर्श हायर सैकण्डरी स्कूल्स के अंदर पूरे अध्यापकों की व्यवस्था की और जिसकी वजह से आज देखें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां इनके कार्यकाल के अंदर 2013-14 के अंदर हायर सैकण्डरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 5 लाख थी, उसको बढ़ाकर आज राजस्थान के अंदर हायर सैकण्डरी स्कूलों के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है, वह छात्रों की संख्या 12 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। आज उस बहन को कितना एहसास होता होगा जो बहन दसवीं करके स्कूल छोड़ दिया करती थी। शहर के अंदर रहने वालों को क्या पता उनकी तो व्यवस्था

(श्री कैलाश चौधरी)
हो जाती है लेकिन गांव के अंदर हम कई बार जाते हैं, देखते हैं और पूछते है, अभी भी कई जगह मैं जाता हूं तो कहते हैं कि हमारे बाकी कुछ हो या न हो हमारे यहां स्कूल खोल दो। हमारे सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल की आवश्यकता है तो उसको खोलो। मुझे कहते हुए फख्र होता है और हमारी मुख्य मंत्रीजी पर हमें बहुत गर्व है कि उन्होंने पिछली बार जब वह सरकार में आई थीं, तब उन्होंने प्रत्येक पंचायत के ऊपर सैकण्डरी स्कूल खोली और इस बार जब वह सरकार में आईं तो उन्होंने प्रत्येक पंचायत के ऊपर हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का काम किया है, जिस वजह से जो बहन स्कूल छोड़ दिया करती थी उसको स्कूल के अंदर पढ़ने का मौका मिल गया। हो सकता है वह बहन उस समय अगर सीनियर तक नहीं पहुंचती उसके भाग्य के अंदर क्या था, क्या पता? हो सकता है वह आरएएस बनती, आईएएस बनती, किसी अन्य पोस्ट पर पहुंचती किसी भी क्षेत्र के अंदर लेकिन उसका जीवन वहीं पर, उस गांव के अंदर ही उसका अंत हो जाता था। उसके भाग्य में क्या लिखा है, वह वहीं पर खतम हो जाता था लेकिन उन बहन के भाग्य को जगाने का काम किया है हमारी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने। शिक्षा को बढ़ावा देकर और अध्यापकों की पूर्ण रूप से व्यवस्था करके और प्रत्येक पंचायत पर स्कूल खोलकर एक बहुत सराहनीय कार्य किया है।

शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही गांवों में हमारी पंचायतों का पुनर्गठन हुआ। हमारी पंचायतें बहुत दूर-दूर हुआ करती थीं। हमारी पंचायत समितियां बहुत दूर हुआ करती थीं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर मेरी पंचायत समितियों का जो क्षेत्रफल था, उस क्षेत्र के अंदर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए 100 किलोमीटर तक जाना पड़ता था तब व्यक्ति पंचायत समिति पहुंचता था लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को कि उन्होंने पिछली बार पुनर्गठन किया और उसके बाद में इन्होंने कोई पुनर्गठन नहीं किया। उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ ये बातें करते रहे, इन्होंने पंचायतों के पुनर्गठन की चर्चा भी की लेकिन पंचायतों का पुनर्गठन नहीं किया, सिर्फ लड़ाने का काम जरूर किया। उसके बाद में हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी जब इस बार सरकार के अंदर आई तो सबसे पहले उन्होंने पारदर्शिता के साथ में पंचायतों का पुनर्गठन किया और उस समय जो हमारे

(श्री कैलाश चौधरी)
मंत्री थे गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने जिस पारदर्शिता के साथ में काम किया, जिसकी वजह से आज राजस्थान के अंदर 47 नई पंचायत समितियां बनीं और उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा बाड़मेर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है। उस बाड़मेर जिले के अंदर आजादी के समय में मात्र 8 पंचायत समितियां थीं, लेकिन इस पुनर्गठन की वजह से हमारे 8 की जगह अब 17 पंचायत समितियां हो गई हैं। इससे हमारे वहां के लोगों को कितनी राहत मिली है, ये वहां के लोग जानते हैं। इस तरह से पंचायत समितियों पुनर्गठन किया। एक हजार से अधिक पंचायतों का पुनर्गठन किया गया और इस तरह से गांव के अंदर विकास बढ़ा क्योंकि जब पंचायत समिति होती है या पंचायत होती है तो उसके अंदर पैसा भी ज्यादा आने लगा और जिसकी वजह से आज गांव के अंदर चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, काम हो रहा है।

गांव के अंदर सड़कों को देखें, गौरव पथ। गांव के अंदर कोई व्यक्ति यह नहीं सोचता था पहले, जब हम भी चुनाव के अंदर भरतपुर गए थे, दूसरी जगह भी गए थे, हमारे वहां तो रेगिस्तान है, लेकिन यहां ऐसी स्थितियां थीं कि बरसात के समय में गांव के अंदर पानी पड़ा रहता था, कीचड़ पड़ा रहता था और उसके अंदर आदमी का चलना दूभर हो जाता था और मुझे पता है वहां पर गाड़ी जब फंस जाती थी तो व्यक्ति नीचे उतरता था, उसके पैर पूरे कीचड़ के अंदर होते थे। ऐसे क्षेत्र थे, जहां पर हम गए तो हमें कहा गया कि हमारे तो यहां पर गांव के अंदर एक सीमेंट की सड़क बन जाए तो हमारे भी गांव का गौरव जगे तो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने प्रत्येक गांव के अंदर गौरव पथ की स्थापना की। गांव के अंदर गौरव पथ के तहत शहर के अंदर भी गौरव पथ है। गांव के अंदर से कई शहरों के अंदर भी जाना होता है तो शहरों के अंदर पहले जहां सड़कें टूटी पड़ी थीं, आज वहां पर बहुत शानदार गौरव पथ बनाए जा रहे हैं।

एलईडी की व्यवस्था की गई। विद्युत को बचाने का काम हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इस तरह से अगर देखे तो आज गांव के अंदर बैठा कोई व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है, वह व्यक्ति यह महसूस करता है कि

(श्री कैलाश चौधरी)

शहर में जितनी सुविधाएं हैं, वह सुविधाएं मेरे पास भी हों। उस व्यक्ति के मन में यह कहीं न कहीं आता है तो उस व्यक्ति के लिए जैसा काम हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जिस तरह से किया है, आज लाल बहादुर शास्त्री जी का, आप सबको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार कहा था इस देश के अंदर हमें एक दिन का उपवास करना चाहिए ताकि जो अन्न बचेगा वह देश के गरीब व्यक्ति के काम आएगा। इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा काम उस समय किया और उसके बाद में अगर किसी ने काम किया है तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

जो गैस का कनेक्शन है उस गैस के कनेक्शन के अंदर उपाध्यक्ष महोदय आपको पता होगा कि गैस के कनेक्शन के अंदर कई ऐसे लोग थे जो सब्सिडी छोड़ना चाहते थे, जो धनाढ्य थे वो सब्सिडी ले रहे थे, उनसे आग्रह किया गया उन्होंने और कहा कि आप सब्सिडी छोड़ें और उन्होंने सब्सिडी छोड़ी और सब्सिडी छोड़ने के बाद में, और जिस तरह से उस समय 1 करोड़ 30 लाख लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और जिसका पैसा उन्होंने किसी और दूसरे मद में नहीं डाला। उन्होंने गरीब व्यक्ति को वहां पर गैस का कनेक्शन देने का काम किया और उस गैस के कनेक्शन के अंदर चाहे मैं हूं, मेरी मां थी वो भी, जब मैं छोटा था उस समय मैं देखता था कि वह लकड़ी से खाना बनाती थी। बरसात के अंदर उन्होंने मेरे को कई बार कहा कि लकड़ी गीली है फिर भी खाना बनाना था तो वो बनाती थी, उनकी आंखों में आंसू आते थे और हर मां का यही हाल था। उस मां की किसी ने चिंता नहीं की। इनकी सरकारों ने ये राजनीति जरूर करते हैं लेकिन उस बहन की चिंता, उस गरीब मां की चिंता अगर किसी ने की है तो हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने की है। निःशुल्क गैस कनेक्शन गांवों के अंदर गरीब परिवार को देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और इतना ही नहीं जो गैस के कनेक्शन दिए गए, उन गैस के कनेक्शन के अंदर 30 प्रतिशत तो एससी वर्ग को कनेक्शन दिए गए और 13 प्रतिशत एसटी वर्ग को कनेक्शन दिये गये। उस बहन को कितनी खुशी होती होगी जब उसको गैस का कनेक्शन मिला। ये बातें छोटी-छोटी लगती है। एक गैस के कनेक्शन के लिए सांसद

(श्री कैलाश चौधरी)

से या किसी और से सिफारिश कराते, तब गैस का कनेक्शन मिलता और महीनों-महीनों तक नंबर नहीं आता था। आज गांवों के अंदर कनेक्शन के लिए गैस की एजेंसी वाले घूमते हैं कि टंकी ले लो, टंकी ले लो और गैस का कनेक्शन करा दो।

इस तरह अगर गांव में बैठी उस महिला का अगर सम्मान बढ़ाया है, उसकी व्यवस्था, सुविधा की है तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने की है। इसी के साथ में उस बहन की चिंता की और शौचालय बनाए और शौचालय का नाम भी बदल कर कहा "इज्जत घर।" आज इज्जत घर उसका नाम दिया गया। हम गांव के अंदर जाते थे, कई बार उस बहन को ऐसी स्थिति होती थी कि गांव के अंदर आबादी बहुत ज्यादा होती थी। आबादी जहां ज्यादा होती है वहां बहन के घर शौचालय नहीं होता था तो उसको बाहर जाना पड़ता था। कोई व्यक्ति आता था तो शर्म के मारे कई बार वह नीचे झुकती, बैठती, उसको देखने में शर्म आती। इस तरह से उस समय उसकी क्या स्थिति होगी, यह कल्पना करने की बात है। उस बहन की चिंता अगर किसी ने की तो हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने चिंता की और उन्होंने शौचालय के लिए 12 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए और उन्होंने कहा कि 2022 के अंदर ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जिसके अंदर शौचालय नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई ऐसी सोच रख सकता है तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने उस बात पर ध्यान दिया और शौचालय की बात हो, चाहे मैं प्रधान मंत्री आवास की बात करूं। भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए।

अभी यहां पर चौहटन से आए विधायक बोल रहे थे हमारे घर के अंदर आग लग जाती है। उसकी वजह से हमारे यहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाओ। निश्चित रूप से फायर ब्रिगेड की बात की उन्होंने। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए।

(14.50 बजे)

(श्री ज्ञानचन्द पारख, सभापति, पदासीन)

ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों को पता है कि हमारी ढाणियों के अंदर रहने वाला व्यक्ति, अगर उसके आग लग जाती थी तो उसका सब

(श्री कैलाश चौधरी)

कुछ जलकर स्वाहा हो जाता है और जब उसका सब कुछ जलकर स्वाहा हो जाता था तब वह अपने हाल के ऊपर रोता था, लेकिन हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह वादा किया उस गरीब से कि 2022 तक देश का ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसके कच्ची छत होगी।

पक्का मकान बनाने का काम आज गांवों के अंदर किया जा रहा है और यही नहीं, आप तो इंदिरा आवास के तहत कहते थे कि हम देते हैं 48 हजार रुपये, पहले तो 25 हजार देते थे, फिर बाद में 48 हजार रुपये किये। उसमें भी कांटा-बांटा कर लेते थे बीच में बिचौलिये, लेकिन हमारे प्रधान मंत्रीजी ने 1 लाख 48 हजार रुपये देकर पक्का मकान बनाने का गांव के अंदर व्यक्ति को किया है। इससे आज गांवों के अंदर पक्के मकान बनाये जा रहे हैं और एक-एक पंचायत के अंदर 500-500 और 700-700 मकान बनाये जा रहे हैं। यह काम आपके एक इंदिरा आवास में पूरी पंचायत के अंदर कभी एक चलता था, या दो चलते थे और वह भी 48 हजार रुपये तक। क्या सोच थी आपकी? यह सोच देश को आगे बढ़ाने की नहीं थी। देश को आगे बढ़ाने की अगर किसी की सोच है तो हमारी मुख्य मंत्री और हमारे प्रधान मंत्रीजी की सोच है। प्रधान मंत्री आवास के तहत इतने मकान बनाये जा रहे हैं।

चाहे विद्युत के क्षेत्र में हो, आज बिजली के कनेक्शन की बात करें तो इस देश की अगर मैं पूरी बात करूं तो इस देश के अंदर कृषि कनेक्शन, भारत आजाद होने के बाद भी इस देश में 18 हजार गांव ऐसे थे जिन गांवों के अंदर लाइट नहीं थी। लाइट क्या, तार भी नहीं था, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने 16 हजार गांवों के अंदर लाइट की व्यवस्था की। वहां पर गांव के अंदर लाइट पहुंच चुकी है और आने वाले 2022 तक यही नहीं, 4 करोड़ लोगों को कनेक्शन कर दिये गये हैं और 16 हजार करोड़ रुपये की लागत से 4 करोड़ कनेक्शन किये गये और 2018 पूरा होते-होते इस देश का ऐसा कोई घर नहीं होगा, जिस घर के अंदर लाइट नहीं होगी। लाइट से ही सारा विकास शुरू होता है। पढ़ाई के लिये भी लाइट की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने सिर्फ मेरा कौन, पराया कौन, उसके स्कूल खोल दो, यह हमारा वोट बैंक है।

(श्री कैलाश चौधरी)

सभापति महोदय, इन्होंने सिर्फ यही कहा कि यह हमारा वोट बैंक है, इनके कनेक्शन करवा दो। इन्होंने वोट बैंक की राजनीति की, लेकिन हमारी सोच है कि 'सबका साथ सबका विकास' और सभी के साथ में कृषि कनेक्शन, बिजली कनेक्शन करने का काम, घरेलू कनेक्शन करने का काम हम कर रहे हैं। अगर कृषि की बात करें तो कृषि के क्षेत्र के अंदर आज हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीजी ने, हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी का जो सपना था, जो उन्होंने नदियों से नदियां जोड़ने की बात कही थी, उस काम को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र जी मोदी कर रहे हैं। आज 30 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर नदियों से नदियां जोड़ने का काम प्रारम्भ कर दिया गया है और निश्चित रूप से आज आपने दस साल के अंदर उस फाइल को कभी देखा भी नहीं, लेकिन प्रधान मंत्रीजी की सोच को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने किसान को ऊपर उठाने के लिये यह चिन्ता की। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से यही कहा कि मेरे देश के किसान की आमदनी 2022 तक मुझे दुगुनी करनी है। उन्होंने किसान की चिन्ता की, गरीब की चिन्ता की।

किसान के लिये आज फसल बीमा नीति को सबसे पहले तो हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने प्रारम्भ किया और उसके बाद में आपने उसमें कोई संशोधन भी नहीं किया। लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि कृषि की आमदनी दुगुनी करने के लिये, किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिये तरह-तरह की उनकी योजनाएं बनायी गयीं। आज किसान की आमदनी दुगुनी करने के लिये जो क्लेम था, जहां पर पहले 50 परसेंट खराबे के ऊपर क्लेम दिया जाता था, उसको कम करके अब 33 परसेंट खराबे के ऊपर किसान को मुआवजा दिया जाता है, जिसकी वजह से गांव के अंदर बैठे हुए व्यक्ति का अगर मुआवजा है तो उसकी वजह से आज किसान को मुआवजा मिल रहा है। उसको डेढ़ गुना किया गया और उसी के साथ में क्षेत्रफल को भी दुगुना किया गया।

ई-मंडी के माध्यम से किसान को आज उसकी फसल का उचित मूल्य मिलता है। जहां अच्छी रेट मिलती है, वहां पर वह किसान जाकर अपनी फसल को बेच सकता है।

(श्री कैलाश चौधरी)

इसी के साथ में यूरिया के लिये लाइनें लगती थीं। आप याद करो वह दिन, यूरिया की जिस तरह से लाइन लगती थी, कालाबाजारी होती थी, व्यापारी ले जाते थे। यूरिया के लिये लाइन लगती थी तो किसान रोता था, वह तिल-तिलकर रोता था। उसको यूरिया नहीं मिलता था, सुबह से शाम खड़ा होता, रात को आंसू बहाता हुआ घर जाता था। वह लाइनें आप याद करो। हमारे प्रधान मंत्रीजी ने नीमकोटेड यूरिया प्रारम्भ किया। उसके अंदर नीम को डालने के बाद अब वह ब्लैक में नहीं बिकता और किसान को लाइन के अंदर खड़ा नहीं रहना पड़ता। किसान के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किये हैं।

मुझे कहते हुए फख्र होता है कि हमारे प्रधान मंत्रीजी ने बजट के अंदर घोषणा की है किसानों के लिये कि किसान की फसल की जो दर है, जो किसान का समर्थन मूल्य है, उसकी लागत का डेढ़ गुना किसान को मिलेगा, लागत का डेढ़ गुना। आपने कभी किसान के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का सोचा भी नहीं। आपने सिर्फ किसान के नाम पर राजनीति की है। पहले किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। मुझे अब कहते हुए खुशी होती है, बाड़मेर जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में पिछले तीन साल के अंदर 3 हजार करोड़ रुपये किसानों को मुआवजे के रूप में मिले और पहले के आंकड़े देख लो, एक रुपया भी कोई मुआवजा नहीं दिया गया था।

इस तरह से किसानों के जीवन को ऊपर उठाने का अगर किसी ने काम किया है, चाहे वह सोइल हैल्थ कार्ड के माध्यम से किसानों की जमीन को टैस्ट करने का काम किया ताकि किसान वहां पर किस तरह की फसल, कौनसी फसल बोयें, जिससे किसानों का भला हो सके।

आज जैतून की खेती की बात करें तो राजस्थान के अंदर जैतून की खेती को प्रारम्भ किया गया। आज बाड़मेर जैसे रेगिस्तान के धोरों के अंदर अनार की खेती होती है। यह माननीय सदस्य सामने बैठे हैं, आप पूछ लें। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है, पड़ौस में ही पूछें आप। बाड़मेर के अंदर अनार की खेती होती है, खजूर की खेती होती है। इस राजस्थान में रेगिस्तान के धोरों के अंदर खजूर की खेती होती है, तब किसान को गर्व

(श्री कैलाश चौधरी)

होता है कि मैं आज इस रेगिस्तान के अंदर रहता हूं, लेकिन मैं भी आज उन सबसे, जहां पानी की व्यवस्था है, चाहे अच्छे प्रदेश हैं, उनसे मैं कहीं पीछे नहीं हूं। रेगिस्तान के बाड़मेर जिले में खजूर की, अनार की और उत्तम किस्म की खेती होती है। इस तरह से हम तो काम करने में विश्वास रखते हैं। हम फैसले लेते हैं, वह हमेशा लोगों को अच्छे लगे। ऐसे फैसले नहीं लेते। हम वह फैसले लेते हैं जो लोगों के लिये अच्छे हो, वह फैसले लेकर हमारी सरकार चल रही है।

आप सिर्फ ऐसी बातें, जीत गये 18, यह तीन चुनाव हो गये। इन तीन से आपने वाहवाही कर ली, क्या बात है, हमने क्या कर लिया। हम जनता के जनादेश को मानते हैं। जनता ने जो जनादेश दिया, वह हमें स्वीकार है, लेकिन आप वह दिन याद करो, आप हरियाणा को याद करो। आपने पिछले चार साल के अंदर कितने प्रदेश खोये हैं, आपकी सरकारें कितने प्रदेशों से चली गयी हैं, वह याद करो। आपके हाथ से हरियाणा छूट गया। हरियाणा आपके हाथ से निकल गया, महाराष्ट्र आपके हाथ से निकल गया, आज झारखण्ड आपके हाथ से निकल गया, जम्मू-कश्मीर आपके हाथ से निकल गया, आसाम आपके हाथ से निकल गया और मणिपुर आपके हाथ से निकल गया। अब बिहार और दिल्ली की बात करें तो उसमें भी हम वोट परसेंट के अंदर बढ़े हैं, वहां भी घटे नहीं हैं। अगर उत्तराखण्ड की बात करें, तो वहां से भी आप निकल चुके हैं। आपका उत्तर प्रदेश, जहां आपका साथ में था, वहां से भी आप साफ हो चुके हैं। आज गोवा हमारा। आज गुजरात के अंदर लगातार 22 साल से छठी बार सरकार अगर कोई बनी है तो वह आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के शासन की सरकार बनी है और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं कि हमने विकास कराये हैं, यह जनता निश्चित रूप से विकास को प्राथमिकता देगी और आने वाले समय के अंदर आपकी बातें, बातें ही रह जाएंगी और हम प्रचण्ड बहुमत के साथ में जीतकर और राजस्थान में सरकार बनायेंगे और केन्द्र में भी सरकार हम बनायेंगे। आप सिर्फ बातें करते रहो, हम काम पर विश्वास रखते हैं, हम काम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

मेरा तो इतना ही कहना है यहां पर जो अभिभाषण पेश किया गया,

(श्री कैलाश चौधरी)
यह अभिभाषण वास्तव में बहुत ही सराहनीय अभिभाषण पेश किया गया। अभी लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बैठे थे सभापति महोदयजी, किस तरह से युवा के साथ में मजाक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पकौड़ा बेचने वाले, युवा तो पकौड़ा बेच रहा है। वह पकौड़ा बेचकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो आपको दु:ख हो रहा है क्या? वह स्वाभिमान के साथ में, कहीं भीख तो नहीं मांग रहा, किसी के सामने हाथ तो नहीं फैला रहा है। वह युवा वहां पर पकौड़ा बेचता है। पहले प्रधान मंत्रीजी के लिये कहा कि चाय बेचने वाला व्यक्ति है, वह अगर प्रधान मंत्री बन सकते हैं तो पकौड़ा बेचने वाला भी कभी आगे बढ़ सकता है। उसको भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। आपको पहले चाय वालों ने साफ कर दिया, अब पकौड़े वाले भी साफ कर देंगे, चिन्ता मत करो।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि काम में विश्वास रखकर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है और निश्चित रूप से जो अभिभाषण हमारे महामहिम साहब ने पेश किया, उसमें हमारी सरकार का जो विजन प्रस्तुत किया गया है, वह बहुत सराहनीय है और प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। 'सबका साथ और सबका विकास' लेकर हम प्रदेश और देश को आगे बढ़ायेंगे, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिन्द, जय भारत।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो आपने मुझे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। सभापति महोदय, जिस प्रकार महामहिम महोदय ने अभिभाषण दिया, मैं उसके लिए उनको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जितनी प्रशंसा की जाए, वह कम है।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार अभी विपक्ष में बैठे हुए भाई राजस्थान में हुए तीन सीटों के ऊपर चुनाव के लिए, कहते हैं 'सोंठ का गांठिया लेकर पंसारी नहीं बनना चाहिए' इस प्रकार फैल रहे हैं, जैसे बस, विधान सभा सत्र शुरू होते ही, इनके मन में इतना आक्रोश है, मैं इनको तसल्ली दिला कर निश्चित तौर पर हमारी सरकार के जो कार्य हैं, मैं इनको

(श्री शंकर सिंह)

गिनाना चाहता हूं। आप भी अपनी सरकार के कार्यों को पहले देखें कि पिछले कार्यकाल में क्या हुआ था।

पीने के पानी के मामले में आपकी सरकार ने 8338 करोड़ रुपये के काम किये आपने चार साल के अन्दर और पाँच साल में आपने किये 12225 करोड़ रुपये के। हमारी सरकार को अभी चार साल ही हुए हैं, हम 18071 करोड़ रुपये के काम कर चुके हैं। इसलिए आप कभी भी इस प्रकार की तुलना नहीं करें कि हमारी सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी के हाथों के अन्दर जो सरकार चल रही है, ऐसी सरकार आपने कभी देखी नहीं होगी।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कार्य अभी हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अन्दर आप लोगों की सरकार ने, पिछले कार्यकाल में 15018 करोड़ रुपये की चार वर्षों में सड़कें बनायीं 74 हजार किलोमीटर। हमारी सरकार को अभी चार साल हुए हैं और चार साल में 66053 करोड़ रुपये का कार्य अभी तक कर चुके हैं। जिस प्रकार राजस्थान की सरकार ने गांवों के अन्दर गौरव पथ बनवाये हैं, आपके टाइम में मुझे भी सदन में रहने का मौका मिला, जब हम सड़कों के निर्माण की बात करते तो गांधीवादी सरकार के कानों में जूं तक भी नहीं रेंगती थी और हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के पूरे राजस्थान में सबको अच्छी सड़कें और काम देने का जो कार्य कर रही है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां विराजमान हैं। हमारी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में जितने जो काम किये हैं उसकी तुलना में आपकी सरकार ने 40 परसेंट भी नहीं किये। 132 करोड़ रुपये के काम आपकी सरकार ने चार साल में पूरे किये और हमारी सरकार ने चार सालों में 986 करोड़ रुपये के कार्य कर दिये हैं। हमारी सरकार स्वास्थ्य के ऊपर इतना खर्च कर चुकी है।

शिक्षा के अन्दर आपकी सरकार के टाइम पहली से आठवीं क्लास तक के लिए, आप बिना पढ़े ही पास कर रहे थे। जब हम आकर कह रहे थे कि स्कूल्स के अन्दर टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स की कमी थी, बिना टीचर के आपके स्कूल चल रही थीं। आज हमारी सरकार में कम से कम ऐसी स्थिति तो

(श्री शंकर सिंह)

नहीं है। आपके टाइम में जब बच्चे अपने घर जाते तो मां-बाप उनसे पूछते तो वे कहते थे कि बहुत अच्छा पढ़कर आये हैं और सामने से अगर मास्टर साहब मिल जाते तो मास्टर साहब को नमस्ते करते समय पूछते कि मास्टरजी, मेरा बच्चा फेल तो नहीं हो जायेगा। मास्टरजी उनको गारन्टी देते कि नहीं, नहीं, जब तक मैं स्कूल में बैठा हूं तब तक आपके बच्चे को फेल नहीं होने दूंगा, इस बात की गारन्टी है क्योंकि वह पढ़ाता ही नहीं है। आठवीं क्लास तक तो आपकी सरकार की मेहरबानी से पास कर रहे थे। ऐसे काले कानून को अगर किसी ने समाप्त करने का काम किया है तो राजस्थान की हमारी सरकार, वसुन्धरा राजेजी ने किया है इसलिए आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि शिक्षा के अन्दर सुधार करने के लिए जो कार्य हमारे राजस्थान की मुख्य मंत्री महोदया और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने जो मिल कर किया है, यह बहुत ही सराहनीय है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। जब से शिक्षा विभाग शुरू हुआ तब से, कहीं ऐसी कोई योजना नहीं बनी कि एक सीनियर स्कूल कराने के लिए, कभी एक वर्ष में एक हो जाती, कभी दो हो जाती लेकिन इस कार्यकाल के अन्दर, मैं ब्यावर से आता हूं, ब्यावर के अन्दर 19 सीनियर सेकण्डरी स्कूल एक ही कार्यकाल में रेज हुई हैं तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी प्रकार पूरे राजस्थान में जितने भी पंचायत मुख्यालय हैं, एक भी पंचायत मुख्यालय को नहीं छोड़ा कि वहां पर शिक्षा विभाग का सीनियर स्कूल नहीं बनाया हो। ...(व्यवधान)... अगर कोई नई पंचायत रेज हुई होगी तो उसमें हो सकता है....

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पुरानी-पुरानी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अगर वह है तो वह भी खोल देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप धैर्य रखें। हमारी सरकार में पूरी तरह से पारदर्शिता रहती है। बेईमानी का काम माननीय मुख्य मंत्री महोदया कभी नहीं करना चाहती हैं। ...(व्यवधान)... हम करवायेंगे।

श्रम विभाग के लिए, आप लोगों की सरकार यह कहती थी, हमारी गांधीवादी सरकार आयेगी तो गरीबी मिटायेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने गरीबी नहीं मिटाई, गरीबों को मिटाया है। यह जरूर काम

(श्री शंकर सिंह)

किया है। हमारी सरकार ने गरीबी मिटाने के लिए, गरीब की तरफ अगर किसी ने काम किया है तो राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धराजी ने किया है। उसका ताजा उदाहरण मैं दे रहा हूं। गरीब की जेब में पैसा नहीं होता। उसको बैंक वाले बाहर खड़े हुए को भगा देता है कि इसको भगाओ यहां से, कहीं जेबकतरा तो नहीं खड़ा है यह। उस गरीब को भी जीरो बैलेंस के ऊपर, बैंक वाले को मजबूर करके गरीब का खाता खुलवाने का काम किया है तो राजस्थान की हमारी सरकार ने किया है, भारतीय पार्टी जनता की सरकार ने किया है।

दूसरा, जिसके पास में पैसा नहीं है, उसका बीमा कौन करायेगा। उसका भी एक रुपया एक महीने की बचत के हिसाब से, उस गरीब का बारह महीने के बारह रुपये का बीमा कराने का जो कार्य किया है, वह भी राजस्थान की सरकार ने किया है।

श्रमिक योजना के अन्दर मैं तत्कालीन श्रम मंत्री महोदय आदरणीय टीटी साहब को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, टीटी साहब ने ऐसी योजना बनायी कि जिसके कारण जितने भी मजदूरी करने वाले लोग हैं वह 90 दिन तक मजदूरी करने के बाद उस श्रम कार्यालय में जायेंगे और वहां श्रम कार्ड बन जायेगा और जब उस श्रमिक/मजदूर के लड़का पैदा होगा तो राजस्थान की सरकार उसको 20 हजार रुपया देगी और लड़की पैदा हो गयी तो 21 हजार रुपया देंगे। जब तक लड़का और लड़की पढ़ेंगे, उनको भी पैसे मिलेंगे और जब वह लड़की 18 साल की हों जायेगी तब उसकी शादी पर 55 हजार रुपये उसके खाते में भेजेंगे। इससे बड़ी योजना और क्या हो सकती है। यदि श्रमिक कार्डधारी की कहीं अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो 09 लाख 70 हजार रुपये उसके खाते में भेजने का काम राजस्थान की सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। यह राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने किया है इसलिए जितना धन्यवाद उनको दिया जाना चाहिए, वह कम है।

आपको सुनने में तकलीफ होती होगी, लेकिन आप मेरी बात धैर्य से सुनें। ...(व्यवधान)... इनको तकलीफ इसलिए होती है साहब, सुना नहीं जाता है कि हमारे काम की आलोचना क्यों हो रही है।

(श्री शंकर सिंह)

पंचायती राज के माननीय मंत्री महोदय विराजे हुए हैं, पंचायतों के अन्दर जितने कार्य इस सरकार में हुए हैं, वह आपकी सरकार में नहीं हुए। आपकी सरकार के समय चार वर्षों में 85228 करोड़ रुपये खर्च हुए और पाँच साल में 151431 करोड़ रुपया आप खर्च कर पाये और हमारे चार साल के अन्दर 317406 करोड़ रुपये अभी तक खर्च हो चुके हैं। इतने लोगों को यहां पर कार्य दिये गये हैं और पंचायती राज के अन्दर जितना सुधार हुआ है, एक-एक गांव के अन्दर, जिस प्रकार कैम्प लगाकर, लोग केसों में उलझ कर भटकते रहते हैं, न्यायालय के अन्दर भटकते रहते हैं, उनको भी "न्याय आपके द्वार" लगाकर हर ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर लोगों को न्याय दिलाने का जो काम किया, वह भी हमारी सरकार ने किया है। जिस प्रकार हर जगह पर, किसी भी क्षेत्र के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कार्य किये हैं ऐसे आपकी सरकार कभी कर नहीं सकती है। हमारे शासन चलाने की अगर आप कहीं तुलनात्मक बात करेंगे तो देश में हमारे प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जिस प्रकार शासन संभाला है, उसको देख लीजिए और आपके शासन को भी देख लीजिए। एक प्रधान मंत्री जी वो थे जो हमारे हिन्दुस्तानियों की गर्दनें काट कर पाकिस्तान ले जाते, तभी भी वो गिड़गिड़ा करके उनके सामने कहते कि साहब, हम पाकिस्तान से वार्तालाप करेंगे। यह जवाब आपके प्रधान मंत्री का मिलता था और हमारे प्रधान मंत्री को देख लीजिए, 56 इंच का सीना और पाकिस्तान को सामने खड़े होकर बोले हैं। जिस प्रकार कहीं हिम्मत नहीं हो कि कोई वहां से गोली चले और गोली चलने के बाद में यहां सर्जिकल स्ट्राइक होकर, आज युद्ध करने का नाम भूल गये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हीरालाल जी, झुन्झुनूं जिले और सीकर जिले के लोगों को पूछो जिनके कितने लाल गये हैं। आपको क्या मालूम, कोने में बैठे हो। आपको मालूम है क्या? शंकर सिंह जी ने कह दिया 56 इंच का सीना, जाकिट पहननी है क्या जो 56 इंच का सीना। ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): मैं शहीद की नहीं कह रहा हूं। युद्ध में लड़ाई के अन्दर लड्डू थोड़े बंटते हैं। वहां तो शहीद होना है और शहीद होने के लिए वहां जाते हैं। आज पूरे विश्व के अन्दर कहीं अगर सम्मान बढ़ा है

(श्री शंकर सिंह)

हिन्दुस्तान का तो माननीय नरेन्द्र मोदी जी की वजह से हुआ और उनकी वजह से देश के कोने-कोने से बच्चा आज देखता है कि यह हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं। ऐसे प्रधान मंत्री हमारे होने चाहिए। जिस प्रकार आज दूसरे देश भी, जिस देश में जाते हैं, जो अमेरिका कभी वीजा नहीं देता था, आज अमेरिका उनके लिए पलक-पावड़े बिछाकर सामने खड़े रहते हैं, पधारो साहब, हिन्दुस्तान के नवाज, पधारिये। इस प्रकार की वहां पर उनकी तारीफ होती है और आपके प्रधान मंत्री को कभी वो एयरपोर्ट पर ही रोक लिया करते थे कि, भई, तलाशी दीजिए, अन्दर कैसे जा रहे हो तो निश्चित तौर पर इसमें यह अन्तर है। पाकिस्तान कभी आंख दिखाता था आज वो आंख दिखाना तो भूल गया। वो कह रहे हैं कि साहब, कश्मीर हमारा है, कश्मीर नहीं लेकिन लाहौर मत ले लेना। अब वो इस नीति पर आये हुए हैं। आप देख नहीं रहे हो, टीवी, रेडियो सब देख लीजिए। इसलिए ऐसे 56 इंच के सीने वाले प्रधान मंत्री हमारे देश में हमेशा बने रहने चाहिए। हर भारतीय के मन में ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। इसलिए आप निश्चित रहें कि जिस प्रकार से हमारी इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किये हैं, आपकी कांग्रेस की सरकार कभी नहीं कर सकती है।

आप तुलनात्मक बात करें। आज हमारी सरकार के ऊपर चाहे देश में, भारत में देख लीजिए, कहीं पर भी हमारे किसी मंत्री के ऊपर कोई किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का ऐसा आरोप नहीं लगा और आपके कार्यकाल में कांग्रेस सरकार के टाइम देख लीजिए, लाइन लगी हुई थी। आज हमारे देश का सिर ऊंचा किया है तो यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी जी की वजह से पूरे देश का सिर ऊंचा हुआ है। ...(व्यवधान)... निश्चित, वो भी भारतीय जनता पार्टी की हैं और ...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मोदी जी ने सब कुछ किया, वसुन्धरा जी ने क्या किया, वो बताओ। ...(व्यवधान)... एक का ही नाम लेते रहोगे क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजो, आप विराजो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): आज श्रवण जी को परेशानी हो रही है, ऐसा लग रहा है। यह इनका भी दायित्व निभा रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मोदी मोदी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ऐसा है, मोदी जी हमारे नेता हैं और हमारे देश के प्रधान मंत्री हैं तो उनको क्यों याद नहीं करेंगे। ...(व्यवधान)... इसलिए आप कभी मोदी जी के नाम पर चिड़चिड़ाहट नहीं करें।

राजस्थान के लिए भी अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप कहीं तीन चुनाव को देखकर अपने आप में आपा नहीं खोएं। गांव में कहते हैं न, आला देख के काला नहीं होना चाहिए। इसलिए आप यह मानकर चलें कि राजस्थान के अन्दर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयेगी और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री आदरणीय वसुन्धरा जी बनेंगी। यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): घनश्याम जी को और म्हाने तो मरनो ही पड़ेगो ...(व्यवधान)...

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अब आप सबको मनाना चाहें, वो सब को तो नहीं हो पायेगा। यह देख लीजिए, यहां तो कुछ भी आप करवा सकते हैं लेकिन राजस्थान की जनता अपने-अपने घरों में टुकुर-टुकुर देखकर वो देख रही है कि हमारे राजस्थान की लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदया ने जिस प्रकार का शासन चलाने के लिए और जिस जनता के प्रति, गरीबों के प्रति काम करने की योजना बनायी है वह तारीफ योग्य हैं। आप तारीफ करें या नहीं करें, आप तो हमेशा आलोचना ही आलोचना करेंगे लेकिन वो अपने घरों के अन्दर बैठे-बैठे टुकुर-टुकुर हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम यहां सच्चाई बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इसलिए आप देख लीजिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर वापस बनेगी। ऐसा सपना आप भूल जाओ कि साहब, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे। यही सरकार आयेगी और भारतीय जनता पार्टी की आयेगी और वसुन्धरा राजे ही आयेंगी, यह मैं आपको बताऊं। धन्यवाद।

एक माननीय सदस्य: दिल्ली में मोदी जी आयेंगे।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): और दिल्ली के अन्दर मोदी जी आएंगे, वो तो दिख ही रहा है न, साहब। आपने अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद साहब।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है। सत्ता पक्ष के सभी माननीय सदस्य तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इन चार सालों में सब कुछ हो गया, कोई समस्याएं नहीं रहीं। चाहे किसानों की बात करें, किसान खुश है, युवाओं की बात करें, उनको पन्द्रह लाख नौकरियां मिल गयीं, महिलाओं की बात करें तो आज बहुत सुरक्षित हैं, सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की बात करें तो वो तो बिलकुल संतुष्ट ही हैं, कभी हड़ताल पर जा ही नहीं रहे हैं, एस.सी., एस.टी. की बात करें, व्यापारियों की बात करें, चाहे अल्पसंख्यक की बात करें, हर वर्ग की बात करें तो आपके हिसाब से मेरे ख्याल से सभी खुश हैं, राम राज चल रहा है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हालात देख रहे हैं, किसानों के हालात क्या हैं? किसानों को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रही है, समय पर बिजली नहीं मिल रही है और किसान आन्दोलन पर हैं। उनके कर्ज माफ के लिए आपकी सरकार ने वादा किया, सुराज संकल्प के अन्दर भी आपने साढ़े छह सौ के करीबन घोषणाएं कीं, इन किसानों का कम से कम वो कर्ज माफी का मामला है, उसको तो आप कर दो। खाली आश्वासन और बातों से कुछ नहीं होगा, यह किसान राज़ी होने वाले नहीं हैं।

युवाओं की बात कर रहे थे, 15 लाख युवाओं को हम नौकरी दे देंगे, दे दी क्या? क्या हाल हो रहे हैं? युवा आत्महत्या कर रहे हैं। आज बेरोजगार युवाओं के हालात क्या हैं? संविदा पर जो विद्यार्थी मित्र लगे थे, विद्यार्थी सहयोगी, अन्य कम्प्यूटर वाले, चाहे संविदा पर जितने भी लगे हुए हैं उनके हालात क्या हैं? आप स्वयं देख लें कि बेरोजगारी के हालात क्या हैं। आज सरकारी कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के लिए तरस रहे हैं और जगह-जगह हड़ताल कर रहे हैं और आपने अभी वाट्स एप पर भी मैसेज देखा था कि कर्मचारी आपके बारे में, सरकार के बारे में क्या-क्या कमेंट्स लिख रहे थे इसलिए मजबूरी में आपको एक वो आदेश जारी करना पड़ा।

आपने काम जरूर किया, करीबन दो-ढ़ाई साल में तो आपने भामाशाह योजना, भामाशाह स्वास्थ्य योजना, आधार कार्ड जन-धन योजना और ऐसी-ऐसी योजनाएं, इसमें आपने दो-ढ़ाई साल सभी लोगों को उलझा कर रखा। हर पंचायत में जाओ, वहां भामाशाह कार्ड बनाओ, आधार कार्ड बनाओ,

(श्री मेवाराम जैन)

स्वास्थ्य बीमा वाले लाइनों में लगे रहे और उनको दो साल तक तो आपको कुछ याद नहीं आया, सिर्फ उसी में उलझे रहे और लोग देखे कि यह खाता खुला दें और हमारे खातों में पैसे आ जायेंगे। बाहर से मोदी जी ला रहे हैं, एक-एक खाते में 15-15 लाख रुपये जमा हो जायेंगे और महिला और बहनें जा-जाकर दो-दो दिन, तीन-तीन दिन वहां बैठी रहीं और उन्होंने खाते खुलाये और आज वो क्या कह रही हैं। यह हालात तो आपने अभी इन चुनावों में देखे होंगे, 17 विधान सभाओं में चुनावों में क्या हालात हुए। खुश होने की जरूरत नहीं है, सोचो, अन्दर में झांको और देखो कि धरातल पर क्या हो रहा है। खाली आप यहां बोल रहे हो। सिर्फ गुणगान करने से आने वाले चुनावों में आपको फायदा होने वाला नहीं है। आपकी योजनाओं का हाल क्या है? धरातल पर इन योजनाओं के हालात क्या हैं? इन पर आप सोचो, विचार करो। अभी भी सुधार करोगे तो थोड़े-बहुत आप सुधरोगे। नहीं तो, हम तो मिनी बस में आए थे और आपको टाटा नेनो में आना पड़ेगा।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज रिफाइनरी की बात कर रहे हैं। उसका श्रेय लेने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस सदन में इनका यह पांचवां बजट है। कई बार चर्चा हुई। यहां हमारे बाड़मेर जिले के माननीय सदस्य ने और यहां सदन की नेता ने, सबने कहा कि रिफाइनरी वायबल नहीं है। रिफाइनरी वहां क्या लगेगी? वहां तेल ही नहीं है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): किसने कहा?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): यह आप प्रोसीडिंग लाकर के देखो, उसके बाद बात करना। पहले वह पढ़ो कि प्रोसीडिंग में क्या है और क्या आप बोले थे। आप पढ़िये पहले।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आपके सांसद तो हड़ताल पर गए थे।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): वह आप पहले पढ़ लीजिए प्रोसीडिंग। आपके यहां ही बोले थे कि यह रिफाइनरी लग नहीं सकती है। अब आप यही कह रहे हो कि रिफाइनरी बहुत बढ़िया है। अच्छी बात है। हम तो कह रहे थे कि रिफाइनरी लगनी चाहिए। यह कोई केवल बाड़मेर का ही नहीं, राजस्थान के विकास का हमारा मुद्दा था।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आपने जो एमओयू तय किया था उसमें घाटा था। लेकिन अब 40 हजार करोड़ रुपए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बचाए हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): चेंज नहीं किया। कुछ उसमें नया किया हो तो बताओ। उसमें क्या नया चेंज किया?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): 40 हजार करोड़ रुपए बचाए ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वैसे का वैसा ही है। वही एमओयू है ...(व्यवधान)... इनको शायद ज्ञान नहीं है इतना। पढ़कर देखो उसको। वही एमओयू है वही ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): 40 हजार करोड़ रुपए बचाए हैं हमारी मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)... आपने 56 हजार में एमओयू किया। हमने 16 हजार में एमओयू तय किया ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): वही एमओयू है ...(व्यवधान)... 4 साल के अंदर इतना नुकसान हुआ है। 4 साल पहले रिफाइनरी लगती तो ज्यादा फायदा होता राजस्थान की जनता को ...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): कैलाश जी, मैं आपको बताता हूं। आप सुनने का माद्दा तो रखो ...(व्यवधान)... आप सुनो तो सही ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): 40 हजार करोड़ रुपए हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बचाए हैं और हमने तो काम शुरू किया है। आपने तो सिर्फ पत्थर लगाकर शिलान्यास किया था। आपने काम प्रारंभ नहीं किया था।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं आपके बीच में बोला? आप सुनो ना।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, हमारे सदस्य को डिस्टर्ब कर रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप सुनने का माद्दा रखो न। आप बोल देना न फिर।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 4 साल में इतना लाभ होता। 4 साल तो लगा ही नहीं सके।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप बैठो। आप बात कर रहे हो कि इतने पैसे लगे। 37 हजार के 43 हजार करोड़ रुपए, आपकी 6 हजार की कोस्ट ज्यादा लगी या नहीं लगी? नंबर एक।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): वह नई टैक्नोलोजी पर है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सुनते जाओ। एक मिनट, नई टैक्नोलनोजी मैं बताता हूं। आप सुन तो लो ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): यह नई टैक्नोनोजी की रिफाइनरी है। आज हिन्दुस्तान में सबसे नई टैक्नोलोजी की रिफाइनरी लग रही है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप सुन लो।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आप तो ऐसी रिफाइनरी लगा रहे थे, हमने नई तकनीक की लगाई है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, यह आधा घंटे तक बोलते रहे बाड़मेर के सदस्य।

श्री सभापति: नहीं, आप किसके निर्देश से बोल रहे हो?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं अपनी सीट से बोल रहा हूं। आप बोलने ही नहीं दोगे। मैं यह बोल रहा हूं कि वह किस हैसियत से बोल रहे हैं?

श्री सभापति: विराजो आप। विराजो आप।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बोलने नहीं दे रहे हो हमको। बोलने नहीं दे रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारी और उनकी हैसियत अलग है क्या ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। आप बोलें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): बीच में बार-बार बोल रहे हैं तो बोलें क्या। आप बोलने दो न फिर आप मर्जी पड़े जो करो ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): बोलो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था यह रिफाइनरी की बात, 43100 करोड़ रुपये में इन्होंने एमओयू किया है। पहले से 6 हजार करोड़ ज्यादा इसमें वृद्धि हुई है। हिस्सेदारी वह की वह, 26 परसेंट की 26 परसेंट ही रही। जब हमने एमओयू किया उस समय साढ़े 4 एमएमटीपी का जो क्रूड ऑयल था, वह कम था।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य, यह एमएमटीपी क्या होता है? ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): इनको समझाना पड़ेगा डिटेल से। अगर क्लास लेनी हो तो दुबारा से मेवाराम जी के पास आ जाएं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य कुछ जानकारी चाहते हैं। जानकारी नहीं है इसलिए ले रहे हैं। इसमें दिक्कत कहां है? आपको जानकारी है तो आप जानकारी दे दो। बहुत सिंपल-सी बात है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): मंत्री क्यों बन गए? जानकारी नहीं है तो मंत्री क्यों हैं?

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप क्यों बोल रहे हो? सभापति महोदय, आप क्यों बोल रहे हो?

श्री सभापति: आप विराजो।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): हाउस को पता तो चले।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अब उसकी डबल केपेसिटी करने की वजह से और क्रूड ऑयल ज्यादा होने की वजह से उसके एक कंडीशन थी कि जैसे ही क्रूड ऑयल की मात्रा ज्यादा-कम होगी, उसी हिसाब से जो लोन सरकार दे रही थी, वह कम या ज्यादा होगा। यह उसमें कंडीशन थी। प्रदेश का प्रतिवर्ष 12 हजार करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हुआ। यह 4 साल में कितना नुकसान हुआ इस बात को भी आप देख लो।

सभापति महोदय, हमें तो खुशी होती इस बात की कि रिफाइनरी लगाते। कोई बात नहीं, पत्थर हमारा लगा हुआ था, उसको आप हटा देते। मैंने तो उसी समय कहा था। अगर काम शुरू होता तो आज की तारीख में रिफाइनरी पूरी हो जाती और आप उसका उद्घाटन कराते ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने लीलाला के अंदर जमीन अवाप्ति की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी...(व्यवधान)...

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं आपको धन्यवाद देता कि यह रिफाइनरी आज पूरी हो गई है।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आपने 5 साल किसका इंतजार किया? ...(व्यवधान)... लीलाला के अंदर मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे जी ने स्थापित

(श्री कैलाश चौधरी)

करने की बात कर दी थी। वहां सारा हो गया था, फिर आपने 5 साल किसका इंतजार किया ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय सदस्य बीच-बीच में बोल रहे हैं। ऐसे कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं ...(व्यवधान)... सभापति महोदय, इन्होंने 4 साल क्या किया?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): आपने कितने करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान किया? आपने 5 साल खराब किए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, अब यह हर बात के बीच में बोल रहे हैं। इनको पता नहीं है कि जब तेल निकला तो कुओं का आपके समय में नामकरण भी सदन की नेता ने किया था। कहा था कि हम रिफाइनरी लगा रहे हैं। उस समय तगाराम जी भी एमएलए थे। बाड़मेर में रेलवे स्टेशन पर उनके स्वागत में ढोल और नगाड़े बजे थे। उस समय आप रिफाइनरी लगा देते तो कौन मना कर रहा था? आपने क्यों नहीं लगाई?

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): यही तो पूछ रहा हूं कि 5 साल आपने क्या किया? ...(व्यवधान)... जब तगाराम जी विधायक थे, मैं आपकी ही बात को कह रहा हूं कि 5 साल आप कहां थे ...(व्यवधान)... आपने आचार संहिता से 2 दिन पहले ...(व्यवधान)...

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): 4 साल कहां थे? आप कहां थे 4 साल? आप जवाब दो ...(व्यवधान)... किसके लिए बैठे हो।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अब भी आचार संहिता लगेगी ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): काम शुरू करवा दिया है। वहां मौके पर काम चल रहा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): चारदीवारी के टेंडर किए हैं और वह भी 35 परसेंट बिलो हैं। ठेकेदार भाग गया। आज की तारीख में काम क्या हो रहा है वहां पर। देखो ना आप। काम कराओ। हम तो चाहते हैं कि काम हो।

श्री सभापति: आप विराजो। आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं तो बैठ जाऊंगा लेकिन यह हाउस है क्या?

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हाउस कंट्रोल में ही नहीं है। यह बोलने क्यों नहीं देते हो आप लोग।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं तो विराज जाऊंगा लेकिन यह क्या कर रहे हैं?

श्री सभापति: आसन रोक देगा इनको। आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं तो बैठ जाऊंगा। यह क्या हो रहा है?

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हाउस को कंट्रोल करो आप ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, हम योजनाओं की बात करें। पानी की योजनाओं की बात करें। मैं कहना चाहूंगा कि 5 साल पहले हमने योजनाएं स्वीकृत कीं, टेंडर किए और वह योजनाएं आज वहीं की वहीं हैं। पाइप हमारे लाए हुए वहीं पड़े हैं। ठेकेदार भाग गया। अब कह रहे हैं कि हम वापस उसको री-टेंडर करेंगे। 4 साल आपने किसका इंतजार किया? 4 साल में वह कम्प्लीट हो जाता। लोगों को पानी मिल जाता।

सभापति महोदय, आज हालात क्या हैं? पीएचईडी के अंदर देखो, जनता जल योजना का हाल देखो। पीएचईडी के अंदर हैंड पंप ठीक कराने की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि नट-बोल्ट नहीं हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं है। एक-एक महीना, दो-दो महीना हैंड पंप ठीक नहीं हो रहे हैं। जनता जल योजना की मोटरें खराब हैं। मोटर को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास कर्मचारी नहीं हैं। अब तो गर्मी आने वाली है तो हालात क्या होंगे?

सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्थिति को सुधारना पड़ेगा। नहीं तो आने वाले दिनों में पानी की स्थिति खराब होगी। जितनी भी स्कीमें पड़ी हैं, उनका काम तुरंत शुरू कराओ। जितनी भी कागजों में योजनाएं हैं, उनको धरातल पर लाने का प्रयास करो। मैं इसमें राजनीति की बात नहीं करना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं कि यह काम हो। जनता को पानी मिले।

(श्री मेवाराम जैन)

सभापति महोदय, आज बिजली की बात कर रहे हैं। आपने कितने वादे किए? बिजली 24 घंटे ग्रामीण एरिये में हम दे देंगे, 8 घंटे किसानों को दे देंगे। गांवों में आप पूछो कि किसानों को बिजली कितने घंटे मिल रही है। पता करो, 4-4 घंटे, 3-3 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। गांवों में और शहरों में 24 घंटे की बजाय 20-20 घंटे, 18 घंटे भी नहीं मिल रही है। बिजली के अंदर जिस तरह से आपकी वीसीआर भरी जा रही हैं, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से मीटर लगे हैं, उससे किसानों की क्या हालत है। यह आप देखोगे। आपको अभी पता नहीं पड़ रहा है। आप सिर्फ गुणगान में लगे हो, हकीकत में नहीं जा रहे हो। आप जब हकीकत पर जाओगे तो आपको पता लगेगा किसान की हालत क्या हो रही है।

विद्युतीकरण की बात आप कर रहे हैं कि हम 2018 तक सबको कनेक्शन देंगे। आपने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का नाम चेंज करके दीनदयाल ज्योति विद्युतीकरण योजना कर दिया, कोई बात नहीं। आपने राजीव गांधी सेवा केन्द्र का नाम बदल कर अटल सेवा केन्द्र कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने आपके निर्णय को बदला, आपको वापस वह नाम चेंज करना पड़ा। यह नाम बदल कर जो यह दीनदयाल ज्योति विद्युतीकरण योजना में 2018 तक सबको बिजली देने की बात कर रहे हो, आज धरातल पर क्या है? वहां हालात क्या है? चार साल तक आप टेंडर नहीं कर सके। अब टेंडर किया है, टेंडर तो किया है लेकिन अभी तक आपका काम कहीं भी शुरू नहीं हुआ है। एक-एक पार्टी कहीं कोई भेजी है। 5 साल अगर इस गति से काम चला तो यह काम नहीं होगा, मैं यह आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं। हकीकत में माननीय मंत्रीजी अभी बाड़मेर में आए थे, उस समय भी मैंने यही कहा कि आप देखो, अभी भी आप जनता को कनेक्शन देने की बात कर रहे हो, वह नहीं मिल रहे हैं।

पीपीपी मोड की बात करें तो आप अच्छी स्कूलें पीपीपी मोड पर दे दो। अच्छी स्कूलें, बढ़िया स्कूलें जहां अच्छी स्ट्रेंथ, अच्छा भवन, उस स्कूल को दे दो पीपीपी मोड पर। हॉस्पिटल जो अच्छा चल रहा हो, उसको दे दो पीपीपी मोड पर, आपके रोडवेज उसको दे दो पीपीपी मोड पर। आपके

(श्री मेवाराम जैन)

बिजली के स्टेशंस को दे दो पीपीपी मोड पर। होटलें, दूसरी जो सरकारी सम्पत्तियां हैं उनको दे दो पीपीपी मोड पर। आखिर यह आप क्या करना चाहते हैं? सरकारी सम्पत्तियों को पीपीपी मोड पर देकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आखिर आपको सोचना पड़ेगा, भविष्य में यह खतरा रहेगा। पछताओगे इस बात के लिए कि हम अपनी सम्पत्तियों को बेच रहे हैं, अपने राज्य के साथ कुठाराघात होगा, अभी भी संभल जाओ।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को आप पीपीपी मोड पर दे रहे हो? 22 हजार ...(व्यवधान)... इनके समझ में अभी तक भी नहीं आया, अभी तक भी यह हवा में हैं। एक तारीख को जो समझाया जनता ने वह समझो। समझते तो आज ये ऐसे बोलते नहीं, बीच में बोलते नहीं, बात समझते कि वास्तव में हम कह रहे हैं वह सही है या गलत है। इसको देखो, इसमें सुधार कैसे होगा, सुधार की बात करो। अपन मिल बैठकर कैसे सुधार करें, इस पर बात करनी चाहिए, उस पर मंथन करना चाहिए। खाली आप कह रहे हो कि हम तो वापस आएंगे, अच्छी बात है, आ जाना। हम तो यह कह रहे हैं कि आपको यदि बात सही नहीं लग रही है, आपने एक साथ बीस हजार से ज्यादा स्कूलें बंद की और कह रहे हैं कि वहां स्कूलों में बच्चे नहीं थे। बच्चों की तो बंद की जो की, बच्चियों की स्कूलों को भी मर्ज किया। ...(व्यवधान)...

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सदस्य, मेवारामजी, वापस आएगी सरकार।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): वापस आएगी तो अच्छी बात है, अपन यहीं बैठे हैं। आप कहां बैठोगे उसमें, मैं भी देखूंगा आप यह भी देख लेना।

श्री हीरालाल (निवाई): मैं भी आऊंगा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आप आओगे, यह भी अच्छी बात है। ...(व्यवधान)... पर आप सुनो, सुनने का माद्दा रखो, जो स्कूलों की बात कर रहा हूं, ये स्कूलें अगर बंद नहीं करते और प्रयास यह करते कि उनमें नामांकन कैसे बढ़े। ...(व्यवधान)... वहां पर अध्यापक लगाते तो वह स्कूलें बंद नहीं होती। वहां पर करोड़ों रुपए के भवन जो बने पड़े हैं, उनके दरवाजे उतार कर ले जा रहे हैं, वहां पर क्या-क्या हो रहा है, लोग उन पर

(श्री मेवाराम जैन)

अतिक्रमण कर रहे हैं, वह आज नहीं होता अगर मंत्रीजी इसको अच्छी तरह से देखते। नामांकन बढ़ाने का काम करते तो आज जिस तरह से शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है उसके तहत दो किलोमीटर से ज्यादा बच्चे को स्कूल पैदल न जाने का अधिकार।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आज शिक्षा का अधिकार कानून का पूरा पालन हो रहा है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): नहीं हो रहा है।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): मैं चैलेंज करता हूं, आप आ जाओ।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): मैं बता दूंगा आपको। बता दूंगा, कई स्कूलें ऐसी हैं जहां...

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपके समय पर जीरो नामांकन पर स्कूल चल रहे थे, वहां न अध्यापक था न विद्यार्थी था।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपके जहां मास्टर नहीं तो नामांकन होंगे कहां से? अध्यापक तो वहां लगाए ही नहीं तो नामांकन कैसे होगा? आप अध्यापक लगाते, तो बात आप नामांकन की भी करते।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय मंत्रीजी, दो ही तो अध्यापक हैं और दो ही बच्चे हैं, ऐसी स्कूलें हैं और जहां चालीस बच्चे थे उनको तोड़ दिया और दो बच्चे वाली स्कूल आज भी हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपके जमाने में तो एक भी नहीं था, हमने दो तो भेजे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): दो जो भेजे हैं वह आपने ही तो भेजे हैं न।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): और भेजेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक अलवर से आया है और एक अजमेर से आया है।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): आपने आदर्श स्कूल घोषित कर दी, बढ़िया बात है। उसमें पूरे शिक्षक लगाओ, जितने सब्जैक्ट हैं उनके भी अध्यापक लगाओ। वहां बैठने के लिए एक स्कूल में सारे ही डाल दिए बच्चे, बारह

(श्री मेवाराम जैन)

तक की कक्षाओं में वहां बैठेंगे कहां पर बच्चे? वहां भवन तो बनाओ। वहां भवन का पता नहीं, बाहर बैठ रहे हैं। 'आदर्श' का नाम दे दिया आपने। आप कम से कम यह तो तैयारी करते और फिर बंद करते और कम से कम बच्चियों को तो बख्शते। बच्चियों की जितनी स्कूलें थीं उनको तो आप बंद नहीं करते। आज जगह-जगह आवश्यकता है, पंचायत मुख्यालय पर तो एक तो बच्चियों की आठवीं की स्कूल और जहां तहसील मुख्यालय है वहां पर कम से कम एक कॉलेज बच्चियों की खोलते तो बच्चियां आपको दुआ देतीं, नहीं तो बच्चों के साथ में आज लोग अपनी बच्चियों को नहीं भेज रहे हैं, आपको कोस रहे हैं, आपको समय बताएगा कि स्कूल बंद करने का खामियाजा कितना भुगतना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, दवाइयों की बात करूं। मुफ्त दवाइयों की बात चल रही है, आज दवाइयों के अंदर आपको शायद पता नहीं है, हॉस्पिटल में पधारो और जाकर देखो कि मुफ्त दवाइयां हमारे समय में जो मिलती थीं, वह आज प्राइवेट दुकानों पर देखो भीड़ मिलेगी। जितनी दवाइयां आप लिख रहे हैं उनमें से आप 80 प्रतिशत मार्केट से ला रहे हैं, 20 प्रतिशत भी हॉस्पिटल में नहीं मिल रही है। यह आप पता करो, वहां जाकर असलियत का पता करो तो हकीकत आपके सामने आएगी। अभी अपने यहां बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। पूरे चिकित्सा क्षेत्र में जहां आपके पीएचसी और सीएचसी थीं, वहां भी आपने उसको उत्कृष्ट पीएचसी कर दी, आप कर दो पर क्या आपके वहां पर आपके डॉक्टर लग गए? क्या आपके वहां पर पूरे इंस्ट्रूमेंट्स लग गए? क्या आप वहां शो करना चाह रहे हैं, हमारे यह समझ से बाहर है, यह आपको जनता ही समझा सकती है। मेरे ख्याल से आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, चाहे आप पंचायती राज की बात करें। पंचायती राज के पास पांच विभाग थे। आज पंचायती राज की हालत क्या है? प्रधान, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, डेलीगेट्स इनका पूछो, इनके पास कुछ बचा है? कुछ है उनके पास पावर नाम की चीज? उनके चैक पर हस्ताक्षर करने के पावर भी आपने ले लिए कि डाइरेक्ट खाते में जाएगा। एक अध्यापक या एक एएनएम या कोई एक मात्र भी ट्रांसफर भी करने की

(श्री मेवाराम जैन)

पावर उनके पास है? इस तरह से पांच विभागों में उनको पंगु बना दिया। पंचायती राज विभाग इतना पंगु कर दिया जितना आज से पहले कभी नहीं था। आने वाला समय बताएगा कि पंचायती राज के क्या हालात हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज नगर निकाय की बात करें। मैं तो बाड़मेर की बात करना चाहता था। तीन साल में तेरह तो ईओ बदल दिए, आज ईओ की पोस्ट खाली हैं। तीन साल से मेरे ख्याल से एक पट्टा दिया नहीं, किसी को इजाजत दी नहीं, कोई लोन ले तो उसको एनओसी दें नहीं। भूमाफिया सक्रिय, दलाल बैठे हैं। दलाल बैठे हैं, वही काम कर रहे हैं कि भाई, आप अतिक्रमण करो, आप किसी को निर्माण की इजाजत दो नहीं, पट्टा दो नहीं, तीन-तीन साल से अगर ऐसे हालात, रहे तो फिर बताओ जनता क्या तीन साल से अगर इस ढंग से परेशान होगी तो वह क्या करेगी?

माननीय सभापति महोदय, आज इस तरह के हालात हैं कि आप सुन नहीं पाएंगे। वहां क्या हाल हैं, शहर के अंदर सड़कों पर गड्ढे पड़े हैं, आवारा पशुओं की भरमार पड़ी है, आवारा पशुओं से कई लोगों की वहां मृत्यु भी हो चुकी है और कोई सुनने वाला ही नहीं। किसको कहें, कोई सुनने वाला नहीं, पर आखिर जनता सुनाएगी आपको, जरा सोचो, समझो इसको, अपन हालात कैसे ठीक कर सके, इस पर मनन करो। खाली वाहवाही करने से कोई फायदा नहीं होगा। कैसे ही भाषण अच्छे दो, राज़ी करने के लिए कुछ भी करो, हकीकत में जाओ, धरातल पर जाओगे तब आपको वास्तविकता का पता लगेगा कि जनता आपसे नाराज क्यों थी? क्यों निकाला आपको, इस पर सोचो और मनन करो तो ही आपके समझ में आएगी।

हमारे माननीय सदस्य, लादूरामजी पीछे बैठे हैं। इनको पता है, मीटिंगों में मैं इनके साथ में रहता हूं, क्या बोलते हैं और मन में क्या इनके पीड़ा होती है, वहां मीटिंगों में महसूस होती है इनको। अभी आज बोल नहीं रहे हैं, मेरे से पहले आपके सदस्य बोल रहे थे, शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य भी बोल रहे थे अपनी पीड़ा, पहले अलवर से आने वाले माननीय सदस्य भी बोल रहे थे तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हालात किस तरह के हैं माननीय सभापति महोदय, हमें उनको ठीक करने की आवश्यकता है।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय सभापति महोदय, "स्वच्छ भारत योजना", बहुत अच्छी योजना है, हम भी चाहते हैं कि योजना अच्छी हो पर इसका आपने धरातल पर पता लगाया क्या कि क्या हो रहा है? सर्वे किया उसमें? 25 प्रतिशत तो उस पंचायत के नाम ही छोड़ दिये। आप हण्डरेड परसेंट का कह रहे हो पर 25 परसेंट तो उस पंचायत में नाम ही छूट गये। दूसरा, जिसका बनाया है उसको पूछो कि कम्प्लीट बना है या नहीं। टॉयलेट बना तो उसके पीछे सोक-पिट नहीं होगा या जुड़ा नहीं होगा, पेमेंट कब मिला, पेमेंट का अता-पता नहीं है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय मेरे सामने विराजमान हैं, इनसे मैं निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करिये कि हकीकत में क्या हो रहा है। यह आपकी योजना है, यह अच्छी योजना है, इसमें कोई दो राय नहीं, परन्तु आपका जहां टॉयलेट बन रहा है उस घर के दो किलोमीटर नजदीक में पानी ही नहीं है तो बताओ कि वो टॉयलेट क्या काम आएगा? पानी की व्यवस्था जरूरी है या नहीं? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बगैर पानी टॉयलेट काम आएगा? सभापति महोदय, यह हकीकत है, आप समझ लें। हमारे एरिया में गांवों में, ढाणियों में लोग बसते हैं और वहां पीने को ही पानी नहीं है तो ये टॉयलेट किस काम के हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टॉयलेट के साथ में पानी की भी व्यवस्था करो।

आज चाहें पानी के लिए सोलर पम्प की बात करें, आर.ओ. प्लांट की बात करें तो आर.ओ. प्लांट और सोलर पम्प कितने लगे होगे पर बाड़मेर जिले में पता करो तो वो सारे बन्द पड़े हैं। उन पर कितने पैसे खर्च हुए होंगे यह भी पता कर लो। उन पर करोड़ों रुपये खर्च हुए, क्या उनका उपयोग हो रहा है? यह सिर्फ कागजों में खोलने से इनका कोई फायदा होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, सड़कों और गौरव पथ की यहां बहुत बड़ी-बड़ी बात हो रही थी और बहुत प्रशंसा कर रहे थे। मैं तो कह रहा हूं कि मेरे वहां इस साल में दो गौरव पथ दिये और एक मिसिंग लिंक सड़क नहीं दी। अभी मैं पहले नियम 295 पर बोला था और 20 सड़कों का उदाहरण दिया था। मैंने कहा कि और कुछ नहीं, हमारे उनमें गड्ढे भर दो। आप नई सड़क मत बनाओ, रिपेयर नहीं हो तो कोई बात

(श्री मेवाराम जैन)

नहीं, आपके पास पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं पर आप उनके गड्ढे भर दो तो इससे भी जनता राज़ी हो जाएगी कि कम से कम इन्होंने गड्ढे तो भरे। सड़कों की आप कुछ भी प्रशंसा करते जाओ, करो, उसमें कोई मनाही नहीं है। हां, रोड बनी हैं मगर टोल की बनी है। वो जरूर बनी है और उसमें हम यह नहीं कहेंगे कि नहीं बनी। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, सब टोल की बनी है और बगैर टोल की कोई रोड बनी है तो वो हमें बताओ। जनता को उसमें कितना टोल देना पड़ेगा। हमारे कहने से, भेदभाव करने से सड़कें बन रही हैं। आज मिसिंग लिंक है या गौरव पथ है तो कम से कम जहां आवश्यकता थी सबको देते। इसमें तो राजनीति नहीं करते पर इसमें भी राजनीति और भेदभाव के साथ।

आज उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कीम है। गरीब महिला के पास घर में जलाने के लिए ईंधन नहीं था और आपने उनको सिलेण्डर दे दिया। क्या आपने यह पता किया कि गैस के सिलेण्डर की रेट क्या बढ़ाई, कितने पैसे लग रहे हैं? अब वो एक बार आया उसको वापस खरीद सकेगी क्या? उनके पास पैसे इतने हैं? यह आपने कभी सोचा कि हम गैस की रेट बढ़ा रहे हैं, तेल की, पैट्रोल की बात करें तो क्या रेट है? हमारे समय में क्रूड के भाव क्या थे और उस समय डीजल की क्या दरें थीं और आज क्रूड के भाव क्या हैं और डीजल, पैट्रोल की क्या दरें हैं, यह भी आप सोचो और मनन करो कि किसानों के साथ यह क्या हो रहा है।

नोटबन्दी की बात कर रहे हैं, जी.एस.टी. की बात कर रहे हैं। नोटबन्दी में सारा काला धन आ जाएगा, लोगों के खातों में चला जाएगा, आ गया नोटबन्दी में काला धन? लोग कतारों में थे, वहां बैंक नहीं थी, बैंकों में आते, दो-दो, तीन-तीन दिन पड़े सड़ते और उन कतारों में आखिर कितने लोग मरे होंगे, यह भी आपको पता है? फिर इस नोटबन्दी से क्या फायदा हुआ? जी.एस.टी., में पूरे व्यापारियों को चौपट कर दिया। अब आप मन में तो कुछ भी कहें पर इस जी.एस.टी. की वजह से व्यापारियों की हालत क्या है? कई को तो आत्महत्या करनी पड़ रही है। फिर इस जी.एस.टी. के आने से कौनसी महंगाई कम हुई, क्या फायदा हुआ? समझ में नहीं आया और रात को 12 बजे निर्णय हुआ। अब ऐसे निर्णयों से जनता अपने-आप

(श्री मेवाराम जैन)

बतायेगी कि इन निर्णयों से फायदा है या नुकसान है, यह तो आप आने वाले दिनों में खुद ही समझ पाओगे।

बजरी की बात करें तो आज बजरी बन्द है और बजरी की वजह से राजस्थान का पूरा विकास रुका हुआ है। भू-माफिया, माइनिंग और पुलिस इसमें मिलकर और जो मिले हुए हैं उससे वो बजरी जा भी रही है पर कितनी महंगी हो गई है यह आपको सोचना पड़ेगा। या तो आप वहां सुप्रीम कोर्ट या कहीं से जो इस पर बैन है इसको हटाओ, इसकी कोई व्यवस्था कराओ नहीं तो यह बजरी आपको ले डूबेगी, यह भी मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। सोचो, अभी भी वक्त है, इसका भी कोई उपाय हो तो करना चाहिए।

कल ही बात की थी कि बच्चियों को आप साइकिलें बांट रहे हो, लैपटॉप बांट रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी योजना है। सभापति महोदय, मंत्री जी सामने विराजमान हैं, उन साइकिलों की कंडीशन आपने देखी? बढ़िया है तो आप चलो, जाकर देखो कि घर लेकर गया और टूट गई। ऐसी कंडीशन है, आप जांच कराओ। मैं बाड़मेर की बात कर रहा हूं, मैं लिखकर भी दे दूंगा और लिखकर क्या, मैं बोल रहा हूं न और यह भाषण लिख ही तो रहे हैं, यों ही थोड़े है, आप इसकी जांच कराइये कि उनकी क्या हालत है। आपने एटलस की दी है तो उसकी क्वालिटी कैसी है यह पता तो कर लो जिससे आपको पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। आप इसकी जांच कराओ। आज भी आपने अखबारों में देखा होगा कि आपके जो छात्रावास हैं उनमें किस तरह की सामग्री आई है। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो तो भ्रष्टाचार बढ़ा है या घटा है? यह अन्दर आप सब जान रहे हो कि हालात क्या हैं और लोग डेली, हमेशा ट्रेप क्यों हो रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार घटा होता तो डेली के ट्रेप नहीं होते। भ्रष्टाचार बढ़ा है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ, वहां बगैर पैसे काम नहीं हो रहा है। यह जनता कह रही है और अपन सुन नहीं रहे हैं। अपन तो कह रहे हैं कि रामराज आ गया, यह अभी आप सोच लेना, इसका समय अभी आएगा। अगर अभी भी अपन विचार करके, मन्थन करके कुछ भला करने की सोचेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर वो ही सपने देखना कि हम तो जीतकर आ जाएंगे तो अच्छी बात है। चलते जाओ, जैसे चलना है वैसे चलो।

(श्री मेवाराम जैन)

मेडिकल कॉलेज की अभी बहुत बढ़िया बात चल रही थी। कॉलेज खुले हैं बहुत बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूं कि 5 साल पहले मेडिकल कॉलेज हमारे बाड़मेर में खुली और दूसरी जगह भी खुले पर उन कॉलेज को अभी तक आप शुरू नहीं करा पाये। अभी भी निर्माण कार्य पूरा होने में एक साल लगेगा तब तक तो पता नहीं आप रहोगे या जाओगे तो फिर कैसे शुरू करा पाओगे। मेडिकल कॉलेजेज की यह हालत है। हास्पिटल में स्टाफ की क्या हालत है यह भी आपको पता है। स्टाफ कहां है? एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह कर रहे हो, दूसरे का तीसरी जगह कर रहे हो तो ऐसा करने से कोई जनता को फायदा होने वाला नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि मेडिकल कॉलेज जल्दी शुरू हो जिससे वहां के लोगों को, वहां की जनता को फायदा मिले, यह भी मैं कहना चाह रहा हूं। अब मेडिकल में क्या हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आपने हाउस में ही देखा होगा कि एक प्रश्न को आधे घंटे तक टाला। सभापति महोदय, आपको पता ही है, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूं कि क्या कारण था, किस कारण से आधे घंटे तक उस प्रश्न को न आने के लिए लटका कर रखा, यह आपके सामने नमूना है।

भ्रष्टाचार चरमसीमा पर है और इस भ्रष्टाचार को अभी भी खत्म करने के प्रयास करें। जनता के काम की जितनी भी ये योजनाएं हैं इन योजनाओं पर अपन मन्थन करें, जनता तक पहुंचें, यही मेरा आपसे निवेदन है। आप उस घमण्ड में मत रहो और जनता के भले के लिए काम करो, नहीं तो अभी रिजल्ट आपके सामने आया है वो ही रिजल्ट आने वाले समय में जनता आपको बतायेगी। अगर आप नहीं सुधरे, इसी हालत में अपन चलते गये तो आप देखना। आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री हीरालाल।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू): सभापति महोदय, एक जिज्ञासा है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य विद्वान हैं, बहुत अच्छा बोले हैं और इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, एमएमटीपी, यह शब्द मैंने कई सदस्यों से पूछा था और मेरे समझ में नहीं आया तो आप समझा दें।

श्री सभापति: आप यह जानकारी इनसे व्यक्तिगत मिलकर ले लें। बैठें आप। श्री हीरालाल।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आज महामहिम साहब के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले महामहिम महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसका मैं समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा एक अनुरोध है कि जब भी कोई सदस्य बोले तो माननीय सदस्यों को टोकाटोकी नहीं करनी चाहिए। यह तो खैर आपका काम है लेकिन उन्हें बोलने देना चाहिए। जो वह बोले, वह अपने आप बोले। बीच में क्यों टोकते हैं। मेरी तो यह करबद्ध प्रार्थना है सभापति महोदय, आपसे।

राजस्थान में सबसे पहले गैर कांग्रेस की सरकार बनी, उसके मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री भैरोंसिंह जी शेखावत बने। उन्होंने एक योजना चलाई "अन्त्योदय योजना" ताकि यह जो गांवों में अंत में बैठा हुआ आदमी है, उस आदमी को लाभ मिले। यह योजना कार्ल मार्क्स ने "अन टू द लास्ट" उस आधार पर यह योजना थी। कांग्रेस ने बरसों पंचायतों के चुनाव नहीं कराये थे, माननीय शेखावत साहब ने आने के बाद वह पंचायती राज के चुनाव कराये। हालांकि पंचायती राज की नींव सबसे पहले राजस्थान में माननीय स्वर्गीय श्री पंडित नेहरूजी ने दो अक्टूबर, 1957 को डाली थी... (व्यवधान) 1959 में है, मैं करेक्ट कर लेता हूं। आपको ज्यादा अनुभव है। 1959 में डाली थी। आप बता रहे हैं जो। वह नींव डालने के बाद, सबसे पहले यह श्रेय गैर कांग्रेसी सरकार को जाता है कि पंचायतों को किसने मजबूत किया? जो बरसों चुनाव नहीं हो रहे थे, 10-10, 12-12 साल से चुनाव नहीं हो रहे थे, वह चुनाव उन्होंने कराये और यह भी एक आरक्षण किया। जो बरसों एक सरपंच बन रहा था, एक प्रधान बन रहा था, एक प्रमुख बन रहा था, वही बन रहे थे। उन्होंने एक रोटेशन प्रणाली चालू की जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला वर्ग, तो यह आरक्षण भी माननीय भैरोंसिंहजी के समय में हुआ। उसके बाद यह पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई और देखा जाये तो राजस्थान वीरों की भूमि है। अगर कहीं सीमा पर जवान सबसे ज्यादा शहीद होते हैं तो हमारे राजस्थान के होते हैं। देश की रक्षा करते हैं हमारे शहीद, तो हिन्दुस्तान की

(श्री हीरालाल)

रक्षा करने में सबसे पहले राजस्थान के लोगों का, शहीदों में नाम आता है। वह राजस्थान के रण-बांकुरे हैं।

माननीय प्रधान मंत्रीजी ने सत्ता संभालने के बाद लाल किले से कहा, गांवों में, देहात में जो बैठा है, जनधन योजना के तहत उसका खाता खोला जाये और वह खाता भी जीरो बैलेंस पर खोला जाये। पहले बैंकर अगर खाता खोलने के लिए जाता था तो 1,000-500 रुपये, दो आदमियों की जमानत, इस तरह की व्यवस्था थी। माननीय मोदीजी ने प्रधान मंत्री बनते ही लाल किले की प्राचीर से यह कहा कि मैं सारे बैंकर्स से निवेदन करता हूं कि गांव के, ठेठ देहात में आदमी बैठे हैं, उनका खाता जीरो बैलेंस पर खोलो और उसकी जमानत देश का प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी देता है और 28 करोड़ खाते खुले। आज गांव का आदमी, हमारे देहात का आदमी, उसका बैंकिंग व्यवस्था से साक्षात्कार हुआ, उसको ज्ञान हुआ कि बैंक में क्या व्यवस्था है। मोदीजी देश को भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं और उस ओर कदम भी बढ़ा रहे हैं। यह खाता खोलने का उद्देश्य मोदीजी का यही था कि बिचौलिये नहीं रहे। पहले बैंक में पेंशन जमा नहीं होती थी। आज यह खाता खुलने के बाद सारी उसकी सहायता, सब्सिडी, उज्ज्वला योजना, जो पैसा सब्सिडी का है, उस ग्रामीण के खाते में आता है। इससे पहले उसकी पेंशन डाकिया लेकर आता था। छह महीने की पेंशन लाया, दो महीने की जेब में रख ली, चार महीने का अंगूठा लगाकर दे दी। उस गांव के आदमी को क्या पता, क्या हो रहा है। वह तो यह समझ रहा था कि मेरी चार महीने की पेंशन आई है। इस तरह की व्यवस्था थी। बिचौलियों की व्यवस्था थी। भ्रष्टाचार की व्यवस्था को खत्म करने के लिए यह जनधन योजना बनाई।

हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया के सत्ता संभालने के बाद 2003 से 2008 तक यहां के कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेना पड़ता था। यह व्यवस्था माननीया वसुन्धराजी ने समाप्त की। आज बैंकों से ऋण लेने की जरूरत नहीं है तो यह काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीया वसुन्धराजी ने किया। जो राजस्थान बीमारू था, वह आप तो यह चाह रहे थे कि देश की गरीबी मिटाओ। कांग्रेस का नारा था, गरीबी मिटाओ तो आप लोग तो गरीबों

(श्री हीरालाल)

को मिटाने में लग रहे थे। यह काम गरीबों को उठाने का, भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेन्द्र भाई मोदी ने किया, माननीया वसुन्धराजी ने किया। आज इस तरह की व्यवस्था है।

एक भामाशाह योजना माननीया वसुन्धराजी ने चलाई 2003 में, जिसमें नरेगा में हमारी महिलाओं को साड़ी भी बांटीं। एक तरह से महिला को मजबूत करने का काम किया। यह खाता उसके नाम खोला और 2008 में आपकी सरकार बनी। मैं ज्यादा आलोचना-समालोचना में नहीं पड़ना चाहता। आपने उस योजना को बंद कर दिया। इससे यह जाहिर होता है कि आप महिला को मजबूत नहीं करना चाहते हैं। आपने योजना क्यों बंद की?

अभी साइकिल की बात कर रहे थे। वह टूटी हुई है तो टूटी हुई साइकिलें देते हैं क्या? माननीय सदस्य बोलने में इतना तो ध्यान रखें कि कोई टूटी हुई या पुरानी साइकिल खरीदेंगे क्या? आपको किसने मना किया था कि आप साइकिल बांटो? किसने मना किया था कि आप लेपटोप बांटो? किसने मना किया था, गार्गी पुरस्कार दो? किसने मना किया था, स्कूलें क्रमोन्नत मत करो? आपने स्कूलें क्रमोन्नत नहीं की। माननीया वसुन्धराजी ने आने के बाद हर पंचायत मुख्यालय पर बिना किसी भेदभाव के, यह नहीं देखा कि यह पंचायत किसकी है, कांग्रेस की है या बीजेपी की विचारधारा का सरपंच है, सब जगह स्कूलें खोल दीं। यह एक ऐतिहासिक काम हमारी माननीया वसुन्धराजी ने किया और उनके नेतृत्व में आज राजस्थान विकास की ओर उन्मुख है।

माननीय नरेन्द्र भाई मोदी ने एक योजना चलाई "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ"। एक योजना चलाई "स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत"। यह सही है, आप भले ही आलोचना करें। अगर आदमी स्वच्छ नहीं रहेगा तो स्वस्थ नहीं रहेगा। स्वस्थ नहीं रहेगा तो बीमार होगा और बीमार आदमी देश के लिए क्या काम करेगा? अपने गांव के लिए क्या काम करेगा? प्रदेश के लिए क्या काम करेगा?

माननीय चरण सिंहजी ने भी एक कल्पना की थी। पूर्व प्रधान मंत्री चरण सिंहजी ने भी एक कल्पना की थी कि हमारी बहन-बेटियां रात का

(श्री हीरालाल)
इंतजार करती हैं और सड़क के किनारे शौच को जाती है। उनका एक प्रयास था, वह प्रयास माननीय मोदीजी ने पूरा किया। हर गांव में नि:शुल्क शौचालय बने, जिनमें सरकार की ओर से 12,000 रुपये उसको दिये जाते हैं। आज पंचायतों को शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये मिलते हैं, उसमें शौचालय बने हैं।

(16.00 बजे)

आज बीमार आदमी है, महिला है तो ये बनने से कई तरह की कमी भी आई है, नहीं तो रात को महिला बाहर जाती थी तो आप भी जानते हैं कि कई इस तरह के अपराधी तत्व होते हैं तो उनसे सुरक्षा हुई है। इससे अपराधों में कमी भी आई है। शौचालय मुक्त होने पर जो पंचायत ओडीएफ हैं, उसको सरकार पच्चीस लाख रुपये देती है। पच्चीस लाख रुपये को वहां का सरपंच अपने वार्ड पंचों के साथ बैठकर उस गांव में क्या विकास होना चाहिए, उस विकास के खर्चे के लिए सरकार बीस लाख रुपये का अनुदान देती है। क्या आपने कभी सोचा था कांग्रेस के राज में? क्या कभी कांग्रेस वालों ने सोचा था कि इस तरह की योजना आएगी? यह भारतीय जनता पार्टी की कल्पना है गांवों को स्वच्छ बनाना, किसानों को मजबूत बनाना, किसानों को फायदा दिलाना। यह भारतीय जनता पार्टी का काम है। वह खाली नारा नहीं लगाती है, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो कहती है भारतीय जनता पार्टी, वो करके दिखाती है और दिखा दिया। आज पूरे हिन्दुस्तान में मोदी जी का परचम है। पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा है और जहां मोदी जी जाते हैं विश्व में मोदी-मोदी के नारे लगते हैं। वहां अमेरिका में चुनाव हुआ तो हमारे भारतीय मूल के बहुत लोग वहां रहते हैं, उन्होंने मोदी जी का स्वागत किया। ट्रंप ने टीवी पर देखा कि मोदी जी का इस तरह का स्वागत और अमेरिका में उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी के पदचिन्हों पर काम करूंगा और ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गये। यह है मोदी।

अटल जी जब प्रधान मंत्री थे, जब हमारा सैनिक, हमारे देश का रक्षक सीमा पर अपने प्राण त्याग देता था। सीमा पर लड़ते हुए न्यौछावर हो जाता था, शहीद हो जाता था तो आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया उनके लिए।

(श्री हीरालाल)

कभी सोचने का मौका ही नहीं मिला। अटल जी ने यह सोचा कि देश का जवान देश के लिए शहीद हो गया तो इसकी जो लाश है उसके परिवार में, उसकी पत्नी, मां को मुंह देखने के लिए क्यों नहीं भेजा जाए और आज राजकीय सम्मान से वो उसकी अंतिम यात्रा हम देखते हैं, उससे शहीद का जो सम्मान होता है, दाह संस्कार होता है सम्मान के साथ। राजकीय सम्मान के साथ होता है और जनता उमड़ पड़ती है। अभी हाल ही में झुंझुनूं का, एक अलवर का शहीद देखा है। यह तो मैंने पहले ही बता दिया कि राजस्थान वीरों की भूमि है। राजस्थान का जवान देश पर मरने के लिए और शहीद होने में उसके परिवार के लोग गौरव महसूस करते हैं। अभी एक परिवार में एक ही बच्चा था वो शहीद हो गया। उसके छोटा बच्चा था। उसके दादा ने कहा कि जब जवान होगा तो मैं इसको फौज में भेजूंगा, देश की रक्षा के लिए भेजूंगा तो यह सोच भारतीय जनता पार्टी की सोच है, जनता की सोच है किस तरह से उनका मान-सम्मान किया जाता है। उनको जमीन दी जाती है। उनकी विधवाओं को पेंशन दी जाती है। उनको सम्मान दिया जाता है। आपको किसने मना किया था कि आप देह को उनके गांव में मत भेजें?

साथ ही मोदी जी ने देश की रक्षा नीति हो चाहे आर्थिक नीति हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, सबके लिए इस तरह की सोच उनकी है। दिन-रात यही काम मोदी जी को है। अट्ठारह घंटे काम करते हैं और देश के प्रधान मंत्री को करना भी चाहिए। वो यह कहते हैं कि मैं न खाऊंगा, न खाने दूंगा। वो यह कहते हैं न मैं सोऊंगा, न सोने दूंगा। अब उनका तीसरा नारा है कि मैं न बैठूंगा, न बैठने दूंगा। यह सोच भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री की हो सकती है। आपके यहां कांग्रेस के शासन में परम्परागत, वंशानुगत जैसे राजा बनते हैं, आज +++ बन गये, आज माननीय +++ बन गईं, आज +++ बन गये और अब और भी नहीं तो +++ बनने को तैयार हो गईं। मैं कलाम साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज इस दुनिया में नहीं हैं। कलाम साहब, उन्होंने कहा कि +++ आपके पास बहुमत है, आप नेता हैं, ज्यादा बढ़िया है कि आप नेता ही बनी रहें क्योंकि देश में खून-खराबा हो जाएगा। आप यहां की मूल निवासी नहीं हैं, विदेशी मूल की हैं। +++ ने समझा और ये कह रहे हैं कि बहुत त्याग की मूर्ति है। क्या त्याग किया? उन्होंने शादी

(श्री हीरालाल)

होने के बारह वर्ष बाद भारत की नागरिकता ली। इटली की भी नागरिकता थी। भारत की भी नागरिकता थी। क्यों ली बारह वर्ष के बाद? जब 1965 की लड़ाई हुई तो +++ 1971 की लड़ाई हुई तो +++ बहुत त्याग की मूर्ति हैं, बहुत बढ़िया बात है। आपका वंशानुगत शासन चलाओ। भारतीय जनता पार्टी में यह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो काम करेगा, जो गरीब होगा, काम करेगा वो देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगा।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, सदन की यह परम्परा है कि जो यहां का सदस्य नहीं है उस पर आप नाम लेकर चर्चा नहीं कर सकते।

श्री हीरालाल (निवाई): आप बीच में बोलते हैं, टोकते हो, यह सही नहीं है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): तो माननीय सदस्य को कृपया आप निर्देश दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जो इस सदन का सदस्य नहीं हैं उनके बारे में कोई टिप्पणी आप नहीं करें। आप अपनी बात करें।

श्री हीरालाल (निवाई): ठीक है, साहब। थैंक यू।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): ये तो रेफरेंस है।

श्री सभापति: कोई टिप्पणी की है तो उसको डिलीट कर दें।

श्री हीरालाल (निवाई): चलो ठीक है।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): इसको कार्यवाही से हटवाएं, माननीय सभापति जी।

श्री सभापति: हटा दिया।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): यह तो रेफरेंस है कोई एलीगेशन थोड़े ही लगाया है।

श्री हीरालाल (निवाई): जो टिप्पणी की है उसके लिए सभापति जी ने टोक दिया है।

डा. रामप्रताप (जल संसाधन मंत्री): रेफरेंस ही तो दिया है, माननीय सदस्य ने एलीगेशन तो नहीं लगाया।

श्री हीरालाल (निवाई): एलीगेशन नहीं लगाया।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): एलीगेशन आपने लगा दिया कि 1965 में वो चली गई +++ 1965 में तो उनकी शादी ही नहीं हुई थी।

श्री हीरालाल (निवाई): यह फैक्ट है। नो डाउट, इट्स ए फैक्ट। रिकार्ड देख लीजिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): 1965 में तो शादी ही नहीं हुई थी उनकी, कहां बोल रहे हो। यह कोई राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस हो रही है क्या, माननीय राठौड़ साहब? अपने सदस्यों को कृपया कुछ ज्ञान तो दें।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय ओला साहब, मुझे व्यवधान मत करो, बोलने दो।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): और मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि नया-नया मुल्ला ज्यादा अजान लगाता है। आप युवक कांग्रेस के सदस्य रहे हैं।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, आज टीटी जी अभी सदन में नहीं है। माननीय वसुन्धरा जी ने एक ऐसी श्रमिक योजना चलाई श्रमिक हितकारी योजना। किसने मना किया कांग्रेस की सरकार को कि मत चलाओ ऐसी योजना? लड़की होने पर 21 हजार और लड़का होने पर 20 हजार रुपये। जब शादी की उम्र हो तो 51-51 हजार रुपये उनकी शादी के लिए। यह है। ...(व्यवधान)... पहले 51 थे टीटी साहब के समय, अब टीटी साहब मंत्री नहीं हैं, डॉ. जसवन्त सिंह जी मंत्री हैं, 55 कर दिये होंगे देट्स ऑल राइट। तो ऐसी एक योजना सरकार ने चलाई। आपको किसने मना किया था और एक इंदिरा आवास योजना चलती थी, फिर आप यह कहोगे कि इंदिरा जी का नाम ले लिया जो इस सदन की सदस्य नहीं है। नहीं लूं इंदिरा आवास योजना का नाम, बोलो, क्या योजना बोलूं? इंदिरा आवास योजना चलाई ...(व्यवधान)... बैठ जाओ। आप मत बोलो। इंदिरा आवास योजना नहीं है क्या? बैठ जाइये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप पहले कांग्रेस के नेता थे, ऐसी बातें आपको शोभा नहीं देती और आप इस तरह की बात कर रहे हो सदन में। आप कहां की बात कहां कर रहे हो।

श्री हीरालाल (निवाई): बैठिये आप, पहले सुन लो। जब आपका नम्बर तब बोलना।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वार्ता करें। इस तरह की अनर्गल बात हाउस में न करें। माननीय सभापति महोदय, आप माननीय सदस्य को इस बात के लिए आगाह करें कि इस तरह की अनर्गल बात हाउस में नहीं करें।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य को बैठाइये। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इंदिरा आवास योजना।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप पहले खुद कांग्रेसी रहे हैं। रहे हैं न?

श्री हीरालाल (निवाई): बैठो न आप।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इस तरह की बात आपको शोभा देती है क्या?

श्री हीरालाल (निवाई): सभापति महोदय, आप आसन पर विराज रहे हैं। ये व्यवधान कर रहे हैं।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप संसदीय भाषा में बात करें। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बात करें।

श्री हीरालाल (निवाई): एक इंदिरा आवास योजना चलाई उसमें...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट। माननीय सभापति महोदय, आप जब बैठते हो और आपके सामने अगर इस तरह की भाषा कोई बोलता है तो आपको खुद को महसूस करना पड़ेगा। यदि कोई यह कहे, हम लोग कहें कि +++ तो आप खुश हो जाओगे क्या? +++ और वो अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री न खायेगा न खाने देगा तो वो कल न ये कह देंगे कि +++ तो यह कोई सवाल थोड़े है तो आप लोगों की यह कोई बात है क्या?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): आप अच्छी भाषा बोलिये। संसदीय भाषा में कहिये। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): आपकी संसदीय भाषा है क्या ये? आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तकलीफ हुई क्या आपको?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): +++ आपको जानकारी है क्या?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या हो गया?

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): आप कैसे बोले इस बात को?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको तो भेजना पड़ेगा।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़बास): बैठ जाओ। बहुत देख लिया।

श्री हीरालाल (निवाई): इंदिरा आवास योजना में कई सिफारिशें आती थीं। प्रधान के पास जाते, एमएलए के पास जाते, मंत्रीजी के पास भी जाते। माननीय टीटी साहब ने एक ऐसी योजना चलाई, वह सदन में नहीं हैं, जो व्यक्ति श्रमिक कार्ड बना ले, 90 दिन काम कर ले, उसका पंजीयन हो जाये, उसको डेढ़ लाख रुपये आवास के लिये। माननीय प्रधान मंत्रीजी की भी योजना है उसमें भी डेढ़ लाख रुपया मिलता है, पर सिफारिश की जरूरत नहीं। अगर चयनित है तो डेढ़ लाख रुपये उसको मिलेगा और बीमार होने पर तीस हजार, तीन लाख भामाशाह में भी है। इस योजना में ईश्वर ऐसा नहीं करे, लेकिन अगर परिवार का मुखिया मर जाये तो साढ़े पाँच लाख रुपये का बीमा उसके परिवार को मिलता है। इस तरह की योजना है ...(व्यवधान)... माननीय वसुंधरा जी का जो विजन है कि राजस्थान का आदमी खुशहाल बने, राजस्थान का आदमी तरक्की करे। माननीय मुख्य मंत्रीजी बीमारू राज्य की श्रेणी से प्रदेश को निकाल कर लाईं। जल स्वावलंबन योजना के तहत ...(व्यवधान)... हाथ जोड़ लूं, बोलने दो मुझे, फिर कोई बोलेगा तो मैं बिलकुल नहीं बोलने दूंगा। कांग्रेस और काल की राशि एक ही है। जब यह राज में आते हैं बरसात नहीं होती है। माननीय वसुंधरा जी जब आई तो बीसलपुर का नाम सुना होगा, तीन बार बीसलपुर का बाँध भर गया, 16-16 गेट खोले। जल स्वावलंबन योजना में सारे नदी, नाले, खाले, तालाब भर गये। जिस पर भगवान की कृपा होती है तभी बरसात होती है। यह तो मैंने बता ही दिया कि कांग्रेस और काल की एक ही राशि है। इस जल स्वावलंबन योजना में लोगों को फायदा मिला और जल स्तर बढ़ा, किसानों को फायदा हुआ। उससे आज भले ही कम वर्षा हुई पर आज पानी का स्तर है जिससे किसानों को फायदा हुआ। राजस्थान तो बहुत भाग्यशाली है। कोई भी योजना होती है तो वह राजस्थान से लागू

(श्री हीरालाल)

होती है। अब आप राजस्थान के बाहर के हो तो बात अलग है। मुझे टोकते हो, मैं क्षमा चाहता हूं मुझे टोकें नहीं। माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने परमाणु परीक्षण किया और अमरीका ने उनको कहा, पर वह अपने इरादे की पक्की थीं, अब यह भी नहीं कहूंगा ...(व्यवधान)... इरादे की पक्की थी, अमरीका की परवाह नहीं की और परमाणु परीक्षण पोकरण से हुआ, राजस्थान से ...(व्यवधान)... माननीय अटल जी प्रधान मंत्री बने, उनको अमरीका ने कहा कि हम सहायता देंगे। उन्होंने कहा कि आप अपनी सहायता को अपने पास रख लो, हिन्दुस्तान को किसी की भीख की जरूरत नहीं है। हिन्दुस्तानी नागरिक, हिन्दुस्तान का जवान 10-10 दिन तक भूखे रहकर भी 20-20 आतंकियों का नाश कर देगा। उन्होंने परमाणु परीक्षण पोकरण से किया। उसके बाद अटल जी आये, अटल जी ने भी राजस्थान से ही किया। राजस्थान तो वीरों की भूमि है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट, मैं आया हूं इतनी दूर से, एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें। आप एक बार इनको पूरा सुन लें।

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान)... और विश्व को दिखा दिया और हिन्दुस्तान परमाणु परीक्षण में चौथे नंबर पर आ गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): धारा प्रवाह बोल रहे हैं इसलिए आपके पेट में तकलीफ हो रही है। धारा प्रवाह भाषण सुनो अब। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य आप विराजें। एक बार उनको पूरा सुन लें आप। थोड़ी सुनने की भी क्षमता रखो आप।

श्री हीरालाल (निवाई): ...(व्यवधान)... माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं, यह बीच में नहीं बोलें। माननीय सभापति महोदय, आप आसन पर विराजमान है।

राजस्थान बहुत भाग्यशाली प्रदेश है। माननीय मोदी जी ने मृदा परीक्षण किया, वह भी हमारे राजस्थान के गंगानगर जिले से किया। परमाणु परीक्षण

(श्री हीरालाल)
भी हमारे यहां से होता है, मृदा परीक्षण भी यहां से होता है तो राजस्थान तो बहुत भाग्यशाली है। विश्व में राजस्थान का नाम है। आपके झुंझुनूं, सीकर माथे पर है लेकिन राजस्थान की सीमा पर हमारे भी एक-दो शहीद हुए हैं देश की रक्षा करने के लिये। आपके सीकर-झुंझुनूं वालों को बहुत सलाम करते हैं हम। हमने वहां आपके शहीदों की मूर्तियां देखी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, न्याय आपके द्वार चला, माननीय वसुंधरा जी के राज में जन कल्याण शिविर चले, 16-16 महकमे गये और प्रशासन के मुखिया पंचायत के हैड क्वार्टर पर गये। जनता की सारी समस्याएं सुनी और देखीं, उनका निराकरण भी किया। ...(व्यवधान)... या तो आप बोल लो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, और जनता ने रिजल्ट भी दे दिया।

श्री हीरालाल (निवाई): मुंगेरीलाल के सपने छोडो। अभी तो हम अपने आपे में हैं फिर बतायेंगे हम क्या हैं।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदय, इनको बहुत ज्यादा ग़लतफ़हमी हो गई है, इस ग़लतफ़हमी में ही रहें आप। 17-0, 17-0, आप 21 में सिमट गये हैं। जनता ने हमको भी थोड़ा सावधान होने के लिये और आपका दिमाग खराब करने के लिये यह दिया है। थोड़ी शांति रखो आप।

श्री हीरालाल (निवाई): दोनों जाट भाइयों बैठ जाओ आप। यह भी जाट, आप भी जाट। दोनों जाट भाई क्यों करते हो, बीच में शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है। ...(व्यवधान)... शेरनी है, उधर एक ही शेरनी काफी है। उनका तकिया कलाम है, कल सुना हमने। न्याय आपके द्वार में लोगों के मुकदमे निपटाये। आपको जाना चाहिये, देखना चाहिये क्या हो रहा है। नामांतरण, पोथी नामांतरण और जिनका नाम गलत था उनका शुद्धिकरण, उसी समय वहीं हुआ। पट्टे दिये। वहीं नायब तहसीलदार, तहसीलदार को रजिस्ट्रेशन करने के लिये बैठा दिया। उस पट्टे की कीमत हो गई। आज गांवों में लड़ाई-झगड़े होते हैं तो ऐसे प्रमाण-पत्र, पट्टे पर अगर नायब तहसीलदार का ठप्पा लग गया तो वह प्रमाण पत्र हो गया। यह काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय वसुंधरा जी ने किया। सचेतक साहब सुनिए,

(श्री हीरालाल)

न्याय आपके द्वार में पूरे राजस्थान में पहले नंबर पर निवाई उपखण्ड, दूसरे नंबर पर पीपलू उपखण्ड और तीसरे नंबर पर कामां उपखण्ड जो भरतपुर जिले में है। मैं वहां के कलेक्टर को और वहां के राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वह राजस्थान के नक्शे पर निवाई को लाये। आप लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते हैं, यह आपकी मर्जी है। निवाई तो राजस्थान के नक्शे पर है। समझ गये ना आप? अभी आपको और कोई बात कहनी है तो सुनाऊं आपको, फिर आप बुरा मानोगे।

निवाई नया गांव और गांव रेवडा,

नेहरू जी के बाग़ में केतकी और केवड़ा।

जो निवाई की बुराई करे तो घाल गले में जेवड़ा।

(16.18 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, जब ऐसा ही अभिभाषण पढ़ना हो तो..

श्री हीरालाल (निवाई): कृषि मंत्रीजी प्रभू लाल जी के समय में जयपुर, कोटा और उदयपुर, एक हमारे टोंक जिले का लाल, प्रभू लाल, जिसने किसानों के लिये काम किया और उसमें किसानों का फायदा हुआ तो वह लाल भी यही हैं। इजराइल जाने वाला लाल भी प्रभू लाल है और जैतून की खेती लाने वाला भी प्रभू लाल है। था कोई आपके यहां, आपकी सरकार में गया क्या? सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार बनी, माननीय अटल जी विदेश मंत्री के रहते हुए पाकिस्तान गये। कांग्रेस के राज में किसी की हिम्मत हुई ? मोदी जी अफगानिस्तान से चलते वक्त पाकिस्तान चले गये। ऐसे जाते हैं जैसे हम निवाई-जयपुर आते हैं। जैसे हीरालाल निवाई-जयपुर आता है। क्या आपके यहां कोई जाने वाला है? मोदी जी का तो इतना भय है कि आये दिन गर्दन काट ले। आपके टाइम में गर्दन काटकर फुटबाल खेलते थे। आज वे पाकिस्तानी, वे आतंककारी पता नहीं किस बिल में छिप गये? यह मोदी जी की देन है। सर्जिकल स्ट्राइक, नहीं है तो बता देंगे। आप मुंगेरी लाल के सपने तो छोड़ो। मुझे आपने पर्ची क्यों भेजी है? बोलने के लिए खड़ा किया है। मुख्य सचेतक जी और सचेतक जी ने भेजी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह इसलिए भेजी है कि दो-तीन दिन से जो भी वक्ता आपके यहां से अभिभाषण में भाग ले रहे हैं, वे केवल मोदी जी की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की नहीं कर रहे हैं तो कहीं टिकट नहीं कट जाये, इसलिए आप नाम ले लो मुख्य मंत्रीजी का।

श्री हीरालाल (निवाई): आप बाद में आये। भाई साहब, आप थे ही नहीं। मैंने वसुंधरा जी के लिए कहा कि वे भी शेरनी हैं। अभी शेर सुनाऊंगा।

आप बिजली की बात कहते हो। नागौर के मोलासर में कांग्रेस के मुख्य मंत्री की क्या स्थिति है, अब मैं नाम नहीं लूंगा। चप्पलें कहां रह गयीं? आदमी पीछे भाग रहा है। एसपी, कलेक्टर चप्पल लेकर, मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं अरे चप्पल रहने दे। वह स्थिति नागौर के मोलासर में हुई है। आप बिजली की बात करते हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, सुन लो यदि इतिहास पता नहीं हो तो।

श्री हीरालाल (निवाई): इसलिए मैं कहता हूं कि मत बोलो। मैं बोलूं तो सबके हाथ जोड़ता हूं। मैं साधारण आदमी हूं। एक किसान और मजदूर का बेटा हूं। इसलिए मत बोला करो। आप तो जाट हो। हम किसान हैं। मैं किसान मजदूर हूं। इसलिए आपको समझाता हूं कि हमारे मजदूरों के बिना किसानों का काम नहीं चलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूं। अब सुनो, भारतीय जनता पार्टी के लिए और आप कहते हो, हमारी शेरनी के लिए, माननीय वसुंधरा जी के लिए.।..

फानूस बनकर जिसको रोशन हवा करे,
वो शमा क्या बुझेगी, जिसकी हिफाजत खुदा करे।

जय जय राजस्थान। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।

श्री उपाध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह जी।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वसुंधरा राजे जी के पिछले चार साल के कार्यकाल में जो काम हुए हैं, वे वास्तव में पूरे राजस्थान में इतने काम

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

हुए हैं, वे कांग्रेस के साठ सालों में नहीं हुए हैं। उन कामों में कुछ कमी यह रही कि जितना हाई लाइट करना था, उतना हम नहीं कर पाये। अब जो सात-आठ महीने या एक साल का कार्यकाल बचा है, उसमें उन कार्यकालों को भी हाई लाइट करेंगे। जितने भी हमारे मंत्री महोदय हैं, उन्होंने अपने पूरे प्रयत्न से विकास के काफी काम किये हैं और जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है भले ही शेखावत साहब का कार्यकाल हो, भले ही वसुंधरा राजे जी का पूरा कार्यकाल हो या पिछले चार साल का कार्यकाल हो। लोगों का यह कहना है कि वास्तव में विकास तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भले ही केंद्र में सरकार बने जब, राजस्थान में सरकार बने जब। अटल बिहारी जी के राज में भी काफी विकास हुआ है। इस राज्य में काफी विकास हुआ है।

भामाशाह योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। भामाशाह योजना पिछले कार्यकाल में वसुंधरा जी ने काफी हाई लाइट की और इससे काफी लोग लाभान्वित हुए। कांग्रेस का राज आते ही वापस उस योजना को बंद कर दिया गया। इन चार सालों में वापस इस योजना को चालू किया है। इस योजना से इतना लाभ हुआ। 1 करोड़ 48 लाख परिवारों के 5 करोड़ 47 लाख से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया। अब तक गैर-नकद 30 करोड़ 26 लाख ट्रांजेक्शन के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में 10 हजार 852 करोड़ रुपये स्थानान्तरित किये जा चुके हैं। आज हर महिला, हर आदमी के मन में भामाशाह की योजना है और भामाशाह कार्ड हर आदमी का बना दिया गया है।

इसी योजना के तहत, आज मैं पीडब्ल्यूडी से चालू करूं। पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी ने, यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने जो रोड़ बनाये हैं, नोन पेचेबल रोड हो, मिसिंग लिंक हो, गौरव पथ हो। कांग्रेस के पाँच साल के कार्यकाल के जो गड्ढे थे वे गड्ढे नहीं भर पाये हैं। इन पाँच सालों के कार्यकाल में इतना काम हुआ। पंचायत हैडक्वार्टर पर एक-एक किलोमीटर सी.सी. रोड़ दिया क्योंकि पंचायत हैडक्वार्टर पर ग्राम पंचायत होती है, पटवार सर्किल होता है, जीएनएम कार्यालय सेंटर होता है और वहां पर सभी लोगों का आना-जाना होता है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब ने इसके लिए 60 लाख रुपए के गौरव

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')
पथ का काम दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 70 प्रतिशत गौरव पथ बन चुके हैं और बाकी के गौरव पथ भी आने वाले दिनों में बन जायेंगे। वास्तव में गौरव पथ हो, मिसिंग लिंक हो, या दूसरे जो भी रोड बने हैं, उनके लिए मैं पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी को और वसुंधरा जी को धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में जो काम हुआ है, वह सराहनीय काम हुआ है।

उसके अलावा, सिंचाई विभाग के काम कहूं। सिंचाई विभाग में भी मंत्री महोदय और वसुंधरा जी ने पूरे राजस्थान में और हमारे यहां भी कायाकल्प किया है। वहां बस्सी की नहरों के लिए 11 करोड़ रुपये दिये हैं। इसके अलावा 22 करोड़ रुपये एक अलख बाँध की नहरों के लिये दिये हैं। हमारे वहां साकेड़ा बाँध का काफी वर्षों का काम था। साकेड़ा बाँध के 11 करोड़ रुपये मंत्रीजी ने दिये, वसुंधरा जी ने दिये। उन पैसों से कम से कम 10 से 15 पंचायतें पानी भी पीयेंगी और नहरों का काम भी होगा। वास्तव में इस सिंचाई विभाग में बहुत अच्छे काम हुए हैं, उसके लिए मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दूं और सी.एम. साहिबा को भी धन्यवाद दूं। वास्तव में काफी काम हुए हैं।

इसके अलावा चिकित्सा विभाग में चिकित्सा मंत्री राठौड़ साहब रहे हैं। उन्होंने भी और कालीचरण जी ने भी जितने भी हास्पिटल हैं, वहां बिल्डिंगों के काम हों, सीएचसी, पीएचसी की बिल्डिंगों के काम हों, डॉक्टर की भर्ती हो, जीएनएम, एएनएम की भर्ती हो। वास्तव में काफी भर्तियां की हैं और पिछले पाँच साल के कार्यकाल में डॉक्टरों की भर्ती नहीं की थी, उन भर्तियों को करने से अस्पतालों का कायाकल्प हुआ है। आज चिकित्सा विभाग में वास्तव में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसके लिए सीएम साहिबा और मंत्री महोदय को धन्यवाद दूं। काफी काम हुआ है।

मैं पीएचईडी से शुरुआत करूं। पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर किरण जी माहेश्वरी रही हैं या अभी सुरेन्द्र जी गोयल मंत्री महोदय हैं, उनको भी धन्यवाद दूं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में कम-से-कम 30 से 40 करोड़ रुपये दिये हैं। वहां पर पानी की पाइप लाइन हो, टंकी का काम हो और पी.एच.ई.डी का काम आलऑवर राजस्थान में हुआ है। उसके लिए मंत्री महोदय को, सीएम साहिबा को धन्यवाद।

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

उसके अलावा पूरे राजस्थान में पहली बार किसी सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए काम किया है, वह वास्तव में सराहनीय है। हमारे यहां हो या फिर जितने भी पुराने रजिस्टर्ड मंदिर हैं, उनमें लखावत साहब ने और सीएम साहिबा ने उनके जीर्णोद्धार में करोड़ों रुपये का खर्चा किया है और आज सभी जगह पर यह वातावरण है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जब भी आई है, भारतीय जनता पार्टी की जब भी सरकार बनी है, वर्षों से खण्डर के रूप में जो मंदिर थे, उनका आज जीर्णोद्धार हो गया है। वास्तव में पर्यटन की दृष्टि से भी यह अच्छा हो गया है।

चित्तौड़गढ़ जिले में मातृकुण्डिया का बहुत अच्छा स्थान है। वह राजस्थान का ही नहीं, हमारे वहां का बहुत अच्छा धार्मिक स्थल है। उसका भी कायाकल्प हुआ है। रामदेवरा का हो या जहां-जहां का भी हो, खाटूश्याम जी का हो, कैलादेवी का हो। काफी जीर्णोद्धार हुए हैं। वास्तव में यह जीर्णोद्धार सराहनीय है। काफी काम अच्छे हुए हैं उसके लिए सीएम साहिबा को, मंत्री ओटाराम जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत काम किए हैं।

ऊर्जा की दृष्टि से देखे, चार साल पहले तारों में करंट नहीं आता था, लाइट की काफी समस्या थी, राजस्थान में लाइटों का काफी कर्जा था। आज दिन में 6 घंटे, रात में 7 घंटे लाइट है। 24 घंटे दिन में लाइट आ रही है। लाइट के रूप में जो काम हुआ है उसके लिए राजस्थान की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा कायाकल्प ऊर्जा में किया है, वह वास्तव में सराहनीय काम है। इन कामों को जनता के बीच में गिनाने का काम है। इन कामों को लेकर लोग उत्साहित हैं, उसके लिए भी धन्यवाद।

हमारे वहां मुख्य मंत्रीजी ने पैनोरमा भी काफी बनाए हैं। चित्तौड़गढ़ में काफी महापुरुषों के पैनोरमा बनाए हैं। वेदाज का पैनोरमा हो, मीरा का पैनोरमा हो, राजस्थान में बहुत पैनोरमा बनाए हैं। काफी महापुरुषों के पैनोरमा बनाए हैं उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। इतने पैनोरमा बन नहीं सकते हैं। पैनोरमा के विषय में अच्छा काम हुआ है उसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं, राजस्थान की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, इतने पैनोरमा कभी बन नहीं सकते हैं, इतने पैनोरमा आप लोगों ने बनाए हैं।

शिक्षा जगत में राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने, मंत्री महोदय

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

देवनानी जी ने जो काम किया है वह बहुत सराहनीय काम है। पंचायत हैड क्वार्टर पर आठवीं से दसवीं तक का जो काम किया गया है वह वसुन्धरा जी के पूरे कार्यकाल का काम है। दसवीं से बारहवीं तक का काम भी अभी हुआ है। शिक्षा जगत में टीचर व पीटीआई की कमी थी उनकी भी पूर्ति की गई है। शिक्षा जगत में पंचायत हैड क्वार्टर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों का होना बहुत जरूरी है। वहां स्कूल खुले हैं। हर हैड क्वार्टर पर मॉडल स्कूल बना है। मॉडल स्कूल बहुत अच्छे बने हैं। मॉडल स्कूल की सराहना कर लोग धन्यवाद दे रहे हैं कि वास्तव में ऐसे मॉडल स्कूल कभी नहीं बन सकते। ग्रामीण बच्चों को छात्रावास का फायदा, पढ़ने का फायदा मिला। जो लोग शहर में पढ़ते हैं उनको जो वातावरण मिलता है वैसा ही वातावरण आज गांवों में उन मॉडल स्कूलों के रूप में दिया जा रहा है।

शिक्षा जगत में साइकिल का काम हो या लेपटॉप का काम हो, बच्चों को साइकिल देनी है या लेपटॉप देना है, पहले गिने-चुनों को साइकिल दी जाती थी अब नवीं की सभी बच्चियों को साइकिल दी जा रही है। मंत्री महोदय को भी धन्यवाद, राजस्थान की मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को भी धन्यवाद। शिक्षा जगत में इन्होंने बहुत अच्छा वातावरण बनाया है, बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए भी मंत्री महोदय व सीएम साहिबा को धन्यवाद। वास्तव में ऐसा काम होना चाहिए। बहुत अच्छा काम हुआ है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत, गांवों में शौचालय नहीं थे, वहां के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर, प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर उनको मोटिवेट किया। सभी को शौचालय के लिए 12-12 हजार रुपये दिए गए। आज काफी गांव-शहर ओडीएफ हो चुके हैं। ओडीएफ के रूप में आज अच्छा वातावरण है। जो गंदगी गाँवों में होती थी आज वह गंदगी नहीं हो पा रही है। आज सभी घर-घर में शौचालय बन गए हैं। बहुत अच्छा काम हुआ है। मैं चित्तौड़गढ़ शहर की बात करूं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हो या अमृत योजना का हो, हमारे मंत्री महोदय श्रीचन्द कृपलानी साहब को भी धन्यवाद देता हूं उन्होंने शहर में गौरव पथ दिए। एलईडी लाइटें दीं। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर में काफी काम हुए हैं। अमृत योजना के तहत पूरे शहर में पानी का काम हो, गार्डन का काम हो, रूडिप का काम हो,

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

बहुत काम शहर में हुए हैं। अकेले चित्तौड़गढ़ शहर में 100-200 करोड़ रुपये का काम चल रहा है। मैं मोदी जी और वसुन्धरा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने शहरों को अमृत योजना में लिया और चित्तौड़गढ़ शहर को भी उसमें लिया। उपाध्यक्ष महोदय, स्किल डवलपमेंट में भी काफी काम हुआ है। गांवों में मोटिवेट करके वहां पर काम किया है।

श्री उपाध्यक्ष: सम्माननीय सदस्य, आपने जितने मंत्रियों को धन्यवाद दिया, क्या उन मंत्रियों ने आपका धन्यवाद ध्यान से सुना है क्या?

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): मैंने देखा भी है, इधर-उधर मैंने झांका भी है, वह देख भी रहे हैं कि वास्तव में मैंने काम किया तो चन्द्रभान जी धन्यवाद...

श्री उपाध्यक्ष: एक मंत्री से पूछ लें कि आपने उनको किस-किस बात पर धन्यवाद दिया।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उच्च शिक्षा मंत्री): मंत्री बैठे हैं, सुन रहे हैं ...(व्यवधान)... वह धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपका धन्यवाद, किसी ने धन्यवाद के रूप में तो स्वीकार किया। मंत्रिमण्डल के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि धन्यवाद को तो ध्यान से सुनें।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): उपाध्यक्ष महोदय, आज हर उपखण्ड स्तर पर...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य सचेतक महोदय एकदम सावधान हो रहे हैं, करंट सा लगा। इनको तो कोई धन्यवाद दे ही नहीं रहा फिर भी सावधान हो रहे हैं। आपको काहे का धन्यवाद देंगे। आज तो आपको समय भी नहीं बढ़ाना। आज तो समय से पहले ही पूरा हो जाएगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके धन्यवाद की मुझे जरूरत भी नहीं है और जो देना चाहते हैं वह सब मुझे दे देते हैं। आप क्यों चिंता करते हो, आप तो अपनी चिंता करो कि आपको कोई धन्यवाद नहीं देता।

श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

आज हर उपखण्ड स्तर पर कॉलेज बन गए हैं। कॉलेज की घोषणा हो गई है। ग्रामीणों में आज काफी उत्साह है। पहले चित्तौड़गढ़ जिले में केवल चित्तौड़गढ़ हैड क्वार्टर पर कॉलेज था, आज सभी उपखण्ड स्तर पर कॉलेज खुल गए हैं। कॉलेज खुलने के बाद गांवों में बहुत अच्छा माहौल है। मेरे वहां कॉलेज ही नहीं, नये सैक्शन भी खुले हैं, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। उपखण्ड स्तर पर खुलने के कारण चित्तौड़गढ़ जिले में भी 5-7 नये कॉलेज खुले हैं, उनके लिए भी धन्यवाद।

एग्रीकल्चर के विषय में काफी अच्छे काम हुए हैं। कृषि एग्रोमीट में, एक साल में जयपुर, उदयपुर हो या कोटा हो, कम से कम दो-तीन लाख किसान आए। वहां उच्च क्वालिटी के पशु भी आए। वहां काफी काम हुए हैं, अच्छे एग्रीकल्चर के बारे में भी बताया, उसके लिए मंत्री महोदय व वसुन्धरा जी को भी धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा के माध्यम से भी काफी पक्के काम हुए हैं। नरेगा के माध्यम से श्मशान घाट का काम हो, आंगनबाड़ी का काम हो, पुलिया हो या ग्रेवल रोड हो, नरेगा के माध्यम से इतने काम हुए हैं। पहले कांग्रेस सरकार नरेगा के पैसे का उपयोग नहीं कर पाई। नरेगा का पैसा किस तरह से उपयोग लिया जा सकता है, वह वसुन्धरा जी ने और राजस्थान की सरकार ने लिया है। काफी अच्छे काम हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं। काफी लंबे समय से पंचायती राज में ग्राम पंचायतें नहीं बनी थी, पंचायत समितियां नहीं बनी थी। पंचायती राज मंत्रीजी, पहले गुलाब जी भाई साहब थे उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में 47 पंचायत समितियां और 723 ग्राम पंचायतें नई बनाईं। काफी समय से लंबित थी। कांग्रेस सरकार ने काफी काम किया लेकिन यह इतनी पंचायतें बनाने का काम नहीं कर पाए। अभी नई ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां बनी हैं। कैसे काम किया जा सकता है, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है।

हर ग्राम पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सालय भी खुले हैं। पर्यटन की दृष्टि से पूरे राजस्थान में काम हुआ है। चित्तौड़गढ़ ज़िले में किले के डवलपमेंट का भी काफी काम हुआ है। किले के डवलपमेंट के लिए 100-150

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

करोड़ रुपये भी आए हैं। पर्यटन की दृष्टि से डवलप करने के लिए किले का काम चल रहा है। पर्यटकों को कैसे लुभाया जा सकता है उस दृष्टि से भी राजस्थान में बहुत अच्छे काम हुए हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

गृह मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, राजस्थान में सभी जगह, जहां-जहां थाने की बिल्डिंग नहीं थी, डिप्टी साहब के रहने के लिए क्वार्टर नहीं थे, पुलिस लाइन में क्वार्टर नहीं थे, उनको थाने की बिल्डिंग दी। मेरे यहां भी 3-4 थानों के लिए बिल्डिंग दी, काफी डवलपमेंट का काम हुआ है उसके लिए भी धन्यवाद।

उद्योग जगत में भी काफी नई फैक्ट्रियां आई। नई इण्डस्ट्रीज आई। काफी लोगों को रोजगार मिला है। राजस्थान उद्योग की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ था, पहले कर नहीं पाए, अब उद्योग की दृष्टि से भी काफी काम हुआ है।

सहकारिता की दृष्टि से राजस्थान में काफी काम हुए हैं। राजस्थान में चाहे केन्द्रीय सहकारी बैंक के चुनाव हुए हों, भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए या पढ़ाई के बारे में हो। मैं पढ़ाई के लिए भी कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में सहकारिता में पढ़ाई का काम लागू किया है, उसके लिए भी धन्यवाद। पंचायती राज में पढ़ाई का काम जारी किया है। दसवीं, आठवीं पास का किया है, उससे नये युवाओं को मौका मिला है। जो नये सदस्य आए हैं चाहे सरपंच हो, ग्राम पंचायत सदस्य हो, जिला परिषद हो, वे अच्छे पढ़े-लिखे हैं। वह पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर पाई है। काफी अमूल्य परिवर्तन हुए हैं।

इसके अलावा नोटबंदी, जीएसटी के काम हुए हैं उसमें भी काफी अच्छे काम हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण योजना मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना है। मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना में भी काफी अच्छे काम हुए हैं।

मैं मेरी विधान सभा के भी कहूं, जो पानी वास्तव में बहुत गहराई पर था और काफी लोगों ने जन सहयोग भी दिया, उद्योगों ने भी जन सहयोग दिया। पहले चरण में प्रदेश की 200 पंचायत समितियों में 3529 गांवों का

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

चयन कर 95 हजार से अधिक जल स्वावलम्बन से जुड़े कार्य पूर्ण कर इन कार्यों में 270 करोड़ रुपये व्यय हुए। दूसरे चरण में 28127 जल संरक्षण कार्य पूर्ण किये, जिन पर 1525 करोड़ रुपये की लागत आई। दो चरणों में कुल 90 लाख पौधों का पौधारोपण हुआ।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा में भी काफी अच्छा काम हुआ है। 30 हजार से लगाकर 3 लाख रुपये तक जो इलाज था, उससे लोगों को इलाज में काफी फायदा मिला है और काफी अच्छा काम हो रहा है। मुख्य मंत्री राजश्री योजना, न्याय आपके द्वार के शिविर लगे। न्याय आपके द्वार शिविर का भी मैं कहना चाहता हूं कि लोग भटकते-फिरते थे, लोगों के काम होते नहीं थे।

आज अभियान के तहत अभी तक 55 हजार से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, इनमें से 2015 से अधिक पुराने प्रकरण भी शामिल हैं।

अन्नपूर्णा भण्डार, वास्तव में राजस्थान सरकार ने जो इन चार सालों में काम किया है, वह कांग्रेस सरकार 50-60 सालों में कर नहीं पाई है। इन कामों को लोगों के बीच में गिनाने की जरूरत है, वास्तव में जो विकास हुए हैं, जो काम हुए हैं। आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंहजी रावत।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिये जो आपने समय दिया है, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। महामहिम राज्यपाल ने अभिभाषण दिया, इस सरकार की नीतियों और किये गये कार्यों की जो व्याख्या की है, वह मैं समझता हूं कि हमारे देश, हमारे राज्य के लिये एक बहुत ही सराहनीय सिद्ध होगा।

हमारी मुख्य मंत्री महोदया द्वारा जो विकास के आयाम इन चार सालों में कायम किये, उसमें मैं उल्लिखित करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जो कमियां थीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आवास, ग्रामीण विकास, सामाजिक सुरक्षा, उद्योग, पर्यटन एवं कई क्षेत्रों में हमारे ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिनकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

(श्री हरिसिंह रावत)

उपाध्यक्ष महोदय, एक कहावत है कि शिक्षा, आज अगर चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं, चाहे शहर की करूं, चाहे देश की, चाहे प्रदेश की, सभी के विकास की जननी है तो शिक्षा है। अगर हमारा परिवार, हमारा समाज शिक्षित होगा तो ही मैं समझता हूं कि कोई विकास की बात होगी। वह तभी सर्वमान्य होगी कि हम स्वयं सुशिक्षित हों। साथ में सुशिक्षित होने के साथ में उन योजनाओं से कैसे लाभान्वित हो सकें। इसी का एक अभिप्राय मैं मानता हूं। शिक्षा की दृष्टि से मैं समझता हूं कि क्षेत्र का या समाज का सर्वांगीण विकास, अगर हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने यही सोच और सपना देखा और उन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं को प्राथमिकता दी। इसमें शिक्षा को सर्वप्रथम महत्व दिया। शिक्षा को महत्व देते हुए, हमारी सरकार ने हर गांव-ढाणी में स्कूल खोले। जहां राजकीय महाविद्यालय की जरूरत थी, वहां महाविद्यालय खोले। वैसे कहते हैं, पूर्व में भी जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने भी जाते-जाते रेवड़ी बांटी और कई ऐसी घोषणाएं कर दीं और फिर कागजों में कॉलेज खोल दिये। हकीकत में जब हमारी सरकार आई, जब हमने देखा, जिसमें मैं भी हूं। हमारे देवगढ़ में भी एक घोषणा की थी कि देवगढ़ राजकीय महाविद्यालय होगा, मेरे पड़ोस कुम्भलगढ़ में एक राजकीय महाविद्यालय खुल गया। जब हमारी सरकार आई, हमने धरातल पर देखा कि वहां न अता था, न पता था, न कोई राशि आबंटित हुई, कुछ भी नहीं था, केवल थोथी घोषणा थी लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि जैसे प्रथम वर्ष में उन्होंने बजट घोषणा की और जो-जो भी कॉलेज हैं, जो मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाये थे पूर्ववर्ती सरकार ने, उनको हमारी सरकार ने साकार किया और जहां-जहां घोषणा की वहां तत्काल प्रथम वर्ष में ही कॉलेज प्रारम्भ किये।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से, किसी जमाने में कहा करते थे कि हम विश्व गुरु थे। 'विश्व गुरु थे' को 'विश्व गुरु हैं' में परिवर्तित करने के लिये, जब-जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने उसी को पुन: कैसे विश्व गुरु बने, वह सपना संजोया है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी यह सपना देखा था। लेकिन क्या सपना देखा। उन्होंने कहा कि राइट टू

(श्री हरिसिंह रावत)

एजुकेशन हम लगाएंगे। सबको शिक्षा देंगे, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, उन्होंने राइट टू एजुकेशन लगाकर क्या किया कि बच्चा पढ़े या न पढ़े, स्वत: उसको आठवीं पास कर दो। अब बच्चा क्या जाने कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है। गुरु ने देखा, क्या करना है। शिक्षक ने देखा कि बच्चा पढ़े न पढ़े, मुझे ऐसे ही पास करना है तो वह भी एकदम निरंकुश हो गया। बच्चे ने भी देखा कि क्या करना है, मुझे वैसे ही पास कर देंगे। लेकिन यह पता नहीं कि जब वह बच्चा आठवीं पास करके नवीं में जाएगा और फेल होगा तो आगे उसका भविष्य क्या होगा, उस वक्त उस माता-पिता का क्या होगा कि जिसने बेटे का एक सपना देखा कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इन्होंने गर्त में बैठा दिया राइट टू एजुकेशन लगाकर, फिर साथ ही साथ इन्होंने, जो हमने पहले लागू किया था पांचवीं बोर्ड होगा, आठवीं बोर्ड होगा, दसवीं बोर्ड होगा, इन्होंने खतम कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी भारत वर्ष की जनता और राज्य की जनता को, उन्होंने पुन: हमें सेवा करने का मौका दिया और प्रथम वर्ष में ही हमने इस चीज का आकलन किया कि हम शिक्षा में कैसे आमूलचूल परिवर्तन करें। उसी के अनुरूप पुन: हमारी सरकार ने पांचवीं बोर्ड, आठवीं बोर्ड, दसवीं बोर्ड, बारहवीं बोर्ड प्रारम्भ किये, जिनके लिये मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसी के साथ-साथ शिक्षा को कैसे हम आगे लाएं, इसके अन्तर्गत ग्रामीण परिवेश के जो हमारे भाई लोग रहते हैं, उनके दिल में यह होता था कि अंग्रेजी शिक्षा तो केवल पैसे वाले ही ग्रहण कर सकते हैं। हम गरीबों के साथ यह हमारे नसीब में नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी को, हमारी मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने मॉडल स्कूल के रूप में हर पंचायत समिति हैड-क्वार्टर में एक मॉडल स्कूल का श्रीगणेश किया जिसकी वजह से, जो हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे थे, जिनके परिवार के दिल में यह था कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची भी इंग्लिश स्कूल में पढ़े और हाई-क्वालीफाइड होकर कोई आई.ए.एस., आई.पी.एस. बने, कोई बड़े काम्पीटीशन में भाग ले सके। इसी के अनुरूप हमारी सरकार ने हर पंचायत समिति हैड क्वार्टर पर एक मॉडल स्कूल खोला, जिसके लिये मैं समझता हूं

(श्री हरिसिंह रावत)

कि हमें सबको धन्यवाद देना चाहिए। इसी के साथ-साथ शिक्षा की दृष्टि से हमारे कई ऐसे आमूलचूल परिवर्तन हुए। मैं समझता हूं कि नारी शिक्षा को भी हमें महत्व देना होगा। जब तक हमारे परिवार में हमारी बेटियां नहीं पढ़ेंगी, मैं समझता हूं कि हमारे सर्वांगीण विकास की बात करना थोथापन साबित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसी अनुरूप कि हमारे बच्चे-बच्चियों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा के माध्यम से हमारी बेटी कैसे पढ़कर आगे आये, इसमें हमारी मुख्य मंत्रीजी ने राजश्री योजना प्रारम्भ की है, प्रथम वर्ष में, आज हमारे घर में बेटी पैदा होती है और वह बेटी जिस दिन पैदा होगी, उसी दिन उसके खाते में ढाई हजार रुपये जमा हो जाएंगे। वह बेटी प्रथम वर्षगांठ मनाएगी, पुन: उसके खाते में ढाई हजार जमा हो जाएंगे। वह बेटी पाँच साल बाद स्कूल में जाने लगेगी, पुन: उस बेटी के खाते में चार हजार रुपये जमा हो जाएंगे। इसी प्रकार बेटी पैदा होने से लेकर 12वीं तक पढ़ते-पढ़ते उस बेटी के खाते में 50 हजार जमा हो जाते हैं तो मां-बाप को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान भी, मैं समझता हूं, इसी में सम्मिलित हो गया। इसी के साथ-साथ, हमारी सरकार यहीं नहीं रुकी है। बेटी के पैदा होने से लेकर 12वीं तक और 12वीं के बाद कॉलेज तक भी हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, जिनसे हमारी बेटी पढ़ सके।

बेटी के पढ़ने के साथ-साथ श्रम कल्याण के माध्यम से जो बेटी 18 साल की उम्र के बाद शादी के लायक हो जाती है, उस एक बेटी की शादी के लिये 55 हजार और एक परिवार में जो श्रमिक कार्डधारी है, उसकी दो बेटियों का सरकार ने बीड़ा उठाया है, दो बेटियों की शादी के एक लाख दस हजार रुपया। उपाध्यक्ष महोदय, जब बेटी पैदा हुई, पली-बढ़ी, शिक्षा ग्रहण की और शादी तक सरकार ने खर्चा उठाया है तो इससे बड़ा और क्या हमारे देश के लिये एक सपना हो सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा की दृष्टि से हमारी बेटियों को आगे लाने के लिए हमारी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं के अंतर्गत हमारी बेटियां जो गांव में पाँच किलोमीटर की परिधि में रहती हैं,

(श्री हरिसिंह रावत)

दूर रहती हैं, उनको साइकिल वितरित कर रहे हैं और इससे अगर दूर है तो उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर्स दिये जाते हैं और उसी प्रकार जब कॉलेज में हमारी बेटी पढ़ती है, 70 परसेंट से अगर ऊपर मार्क्स लेकर आती है तो उसको स्कूटी प्रदान की जाती है। हमारी सरकार की यह योजना है कि हमारी बेटी कैसे पढ़-लिखकर आगे आये तो मैं समझता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं है।

दूसरी, शिक्षा के बाद में एक और बात करना चाहता हूं। पूर्ववर्ती सरकारों के पास में अगर हमें कोई स्कूल क्रमोन्नत करने होते थे तो हमारे गांव के भाई पूरे जीप में भरकर, गाड़ी भर के आते थे, उनके जूते घिस जाया करते थे, कोई स्कूल क्रमोन्नत नहीं होती थी लेकिन मैं हमारी मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिना किसी के जूते घिसे, बिना किसी के कहे, हर पंचायत हैड-क्वार्टर में 12वीं की स्कूल खोल दी और उसके साथ-साथ ही यहां पर ही नहीं रुके, जहां-जहां भी शिक्षकों की कमी थी, वह शिक्षकों की कमी पूर्ण हुई। डोटासराजी, थोड़ा बैठ जाइये। ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट। एक ही बात, ज्ञानवर्धन के लिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने राजस्थान में कितनी तो ग्राम पंचायतें हैं और अब तक कितने 12वीं के विद्यालय खोल दिये आपकी सरकार ने, बता दो तो हमारा ज्ञानवर्धन हो जाएगा।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): डोटासराजी, हर पंचायत हैडक्वार्टर में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुल चुकी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं है। यह इसीलिए तो हो गया आपका हाल।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): हमारे यहां पर नहीं खुले। मेरे यहां पर ऐसे उदाहरण हैं, टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में हमारे यहां पर नहीं खुले हैं। ....(व्यवधान)....

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): आप बता दो, पांच साल में आप लोगों ने कांग्रेस के राज में कितनी स्कूल खोली हैं? ....(व्यवधान)....

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पंचायतें कितनी हैं? पंचायतें कितनी हैं? पूरे राजस्थान में पंचायतें कितनी हैं?

श्री जयराम जाटव (अलवर ग्रामीण): आप बता दो कि आपने पांच साल में कितनी 12वीं की स्कूलें खोलीं?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): सभी जगह पर नहीं खोले हैं। प्राइवेट स्कूलों के नाम पर आपने यह कह दिया ....(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आप इंटरप्ट न करें, प्लीज बैठ जाइये। ....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय सदस्य, आप सभी ग्राम पंचायतों का न बोलें, सब जगह नहीं खोले गये हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आपने 60 साल में किया क्या? वह सब हमें उठाना पड़ा है, और भी हम उठाएंगे, आप चिंता मत करो। कोई बाकी रह गयी तो वह भी हम खोल देंगे और कोई बाकी रह गयी तो हम खोल देंगे, चिंता मत करो। अब शिक्षा के साथ-साथ ....(व्यवधान)....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का समय आज की कार्यसूची पूर्ण होने तक बढ़ाया जाए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आज आपको पूरे में से पूरे नम्बर हैं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक बढ़ाया जाए?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कार्यसूची का क्या तात्पर्य है?

श्री उपाध्यक्ष: कार्यसूची का तात्पर्य है कि जितने बोलने वालों की सूचियां माननीय सदस्यों की आई हुई हैं, उस सूची के सम्पूर्ण होने तक, इस सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कार्यसूची नहीं, सूची पूरी होने तक।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हुआ क्या माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि हम तो विपक्ष में थे ही और इनके हाल विपक्ष जैसे हो गये इसलिए सब एक जैसे हो गये, मतलब यह बात है।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नरेगा की बात करना चाहूंगा। नरेगा प्रारंभ हुई और यह सोच कर हुई कि नरेगा के माध्यम से 100 में से 70 परसेंट जो जनता हमारी गांवों में रहती है, उस ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों का कैसे सर्वांगीण विकास किया जाए, यह योजना प्रारंभ हुई। इस योजना में हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बड़ा नाजायज फायदा उठाया और उन्होंने जिस प्रकार राइट टू एजुकेशन लगाया उसी प्रकार उन्होंने नरेगा प्रारंभ की और उसमें ऐसे आयाम प्रारंभ किये कि तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। नरेगा के अंदर जब प्रथम बार 2005, 2006, 2007 में स्टार्ट हुई थी उस वक्त इन्होंने मिट्टी खोदने का काम प्रारंभ किया। मिट्टी खोदना कैसे? कि इस महीने मिट्टी इधर से खोदो और उधर डाल दो। दूसरे महीने इधर से खोद कर उधर डाल दो और बारिश आए तो कहीं भी पत्थर फैलने वाला काम हो जाएगा और बिल बन जाएगा, एम.बी. भर दी जाएगी और पैसे उठ जाएंगे।

मैं सोचता हूं कि यह नरेगा योजना प्रारंभ करके हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों को ऐसे निठल्ले बनाने का इन्होंने कार्यक्रम किया था कि धीरे-धीरे यह स्थिति हो जाए कि यह लोग घर पर बैठे-बैठे, इनको मुंह में रोटी देने की स्थिति आ जाए, ऐसे हाल इन कांग्रेसियों ने किया था।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नरेगा में स्थिति यह हो गयी कि आज किसी मजदूर को, किसी को घर बनाना है, किसी को खेत में अगर मजदूर बुलाना है तो कोई जाएगा नहीं, चाहे आप 300 रुपये दो या 500 रुपये दो तो भी कोई नहीं जाएगा लेकिन नरेगा में 100 रुपये दे या 50 रुपये दे तो भी वहां पर पांच किलोमीटर पैदल चले जाएंगे। यह हालत इन कांग्रेस के भाइयों ने की लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मुख्य मंत्रीजी को, हमारे प्रधान मंत्रीजी को कि इन्होंने आकर, जो प्रधान मंत्रीजी की हमारी केन्द्र की

(श्री हरिसिंह रावत)

योजना है, इन्होंने कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा और जो पैसा लगेगा विकास का, मैं सम्पूर्ण पैसा गांव की जनता को दूंगा।

इसी में हमारे देश के प्रधान मंत्रीजी ने आमूल-चूल परिवर्तन करके नरेगा में ऐसे आयाम कायम किये जो हर ग्राम के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की परमानेंट असैट कैसे बने। उसके अंतर्गत इन्होंने योजना बनाई कि हर ग्राम पंचायत में हर वर्ष 3 किलोमीटर सी.सी. रोड, ब्लॉक रोड बनें, हर ग्राम पंचायत में स्कूल की बाउंड्री बनें, हर ग्राम क्षेत्र के स्कूल में खेल मैदान बनें और इसके साथ-साथ ही जहां पर कम पूंजी में, हमारी जो छोटी जोत है, छोटी जोत में कैसे कम पानी से, कैसे हम लोग ज्यादा उपज ले सकें, उसको भी नरेगा के अन्तर्गत जोड़ा।

फव्वारा सिंचाई से खेती करो, कम पानी से कैसे नई-नई उपज ले सकते हैं, इजरायली स्टाइल से, इजरायल में भी...., हमारे कृषि मंत्रीजी कहां गये? वह भी कहते हैं। कई ऐसे-ऐसे उपयोग वहां पर देखकर आये और इन्होंने हमारे यहां पर चालू किये। कम खेती में, कम जमीन में कैसे ज्यादा उपज ले सकते हैं, कम पानी से कैसे ज्यादा उपज ले सकते हैं, यह भी प्रयोग हमारे राजस्थान में प्रारंभ किया जिसकी वजह से हमारे छोटे-छोटे किसान भाई भी आज खुद आत्म-स्वावलंबन हो गये तो मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यही निवेदन है कि हमारी सरकार ने इसी नरेगा के अंतर्गत, आज हमारे किसी गांव में यदि श्मशान घाट नहीं है तो मुक्ति धाम के नाम से वहां पर श्मशान घाट भी बन रहा है, वहां पर हैण्डपम्प भी लग रहा है और इसके साथ-साथ ही आपकी कई ऐसी योजना नरेगा के अंतर्गत है, जिसमें जंगली जानवरों से निजात पाने के लिए बाड़ाबंदी के लिए भी सरकार पैसे दे रही है इस नरेगा में। उसमें 50 परसेंट तो जो उपयोग करेगा वह देगा और 50 परसेंट सरकार दे रही है। इसके बाद छोटे-छोटे कोई पुलिया निर्माण है, छोटी कोई बावड़ी, कोई एनीकट बनाने हैं, वह भी हमारे इसमें जुड़ गये।

इसके साथ-साथ कैटल शेड, जानवरों के रहने के लिए भी कैटल शेड की योजना भी जोड़ी है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने नरेगा के अंतर्गत कई आमूल-चूल परिवर्तन करके, हमारे ग्राम के जो भाई हैं, जो किसान हैं उनको आत्म-स्वावलंबी बनाया है।

(श्री हरिसिंह रावत)

इसके साथ-साथ, जैसे ही नरेगा के 90 दिन पूर्ण होते हैं और एक नई योजना आ गयी- श्रमिक कार्ड के माध्यम से पुन: हम उनको कैसे लाभ दे सकें, उसकी भी हमारी सरकार ने कई ऐसी योजना बनाई। श्रमिक कार्ड का जब कार्ड धारी बन जाता है तो उसके बाद में उसको कितने बेनिफिट मिलते हैं, उसका मैं आपको थोड़ा विश्लेषण करना चाहूंगा। उस कार्ड धारी परिवार का एक व्यक्ति अगर कही बाहर जा रहा है और अनायास एक्सीडेंट से मौत हो जाती है तो 9 लाख 75 हजार रुपये उसको बीमा के मिलते हैं। उसी परिवार में अगर नोर्मल मौत से, साधारण मौत से अगर घर पर कोई बीमार होकर मरता है तो भी उसको 2 लाख रुपये मिलते हैं।

इसमें स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 30 हजार से लेकर 3 लाख रुपये तक का इनका बीमा क्लेम इलाज के लिए मिलता है और इसके साथ-साथ ही इसी के अंतर्गत किसी भाई के अगर घर नहीं है तो कहीं मुख्य मंत्री आवास योजना या प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत जाने की जरूरत है, उसमें 75 हजार रुपये मिलते हैं। यह तो इसका बाप है, इसमें डेढ़ लाख रुपया घर बनाने का मिलता है। कितनी अच्छी योजना हमारी सरकार की है।

इन योजनाओं के साथ-साथ, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था कि बेटियों की शादी के लिए, दो बेटियों का 1 लाख 10 हजार रुपये शादी के लिए मिलते हैं और शिक्षा की दृष्टि से भी, इसमें भी स्लेब-बाई-स्लेब प्रथम क्लास से 12वीं तक इसमें पचास हजार रुपये, प्रथम क्लास से पांचवीं तक 1500 रुपये, यह पूरा स्लेब-बाई-स्लेब अगर मान लीजिए 12वीं तक बेटी पढ़ती है तो उसके बाद में उसको पूरा 50 हजार रुपया मिलता है और बेटियों को पढ़ने के लिए, आज जैसे कस्तूरबा विद्यालय में आठवीं तक बच्चियां हमारी पढ़ती हैं। आठवीं के बाद 12वीं तक भी बच्चियों के पढ़ने के लिए हमारी सरकार ने हॉस्टल बनाये हैं तो इस प्रकार की योजनाओं से हमारी हर आम जनता को कितना फायदा मिल रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ ही मैं चिकित्सा की बात करूं तो चिकित्सा के अंतर्गत भी हमारा आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। आज हमारे क्षेत्र में सात जिलों में चिकित्सा महाविद्यालय खुल रहे हैं। वे भी

(श्री हरिसिंह रावत)

अति-शीघ्र अगले साल तक प्रारंभ हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि चिकित्सा की दृष्टि से भी हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे।

इसके साथ-साथ ही मैं उज्ज्वला योजना के बारे में बात करना चाहूंगा। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी हमारी सरकार ने कई ऐसी योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत कोई भी घर हमारा बिजली से वंचित नहीं रहेगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से हर ग्राम-ढाणी में बिजली पहुंचे, यह भी हमारी सरकार की एक योजना है, हर गांव-ढाणी में आज घर-घर में बिजली पहुंच गयी है।

(17.00 बजे)

इसके साथ मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग की बात करूं कि पीडब्ल्यूडी के माध्यम से भी हमारी सरकार ने ऐसे गौरवमयी काम किए हैं, जिनसे आज हर एक ग्राम पंचायत का व्यक्ति गौरव महसूस करता है। हर पंचायत हैडक्वार्टर में 1 किलोमीटर तक जो मेन नाली से निर्माण होता है, जिस किसी गांव में जाते थे, पहले गंदगी नजर आती थी, पूरा कूड़ा-करकट नजर आता था, गौरव पथ के माध्यम से आज फर्स्ट क्लास रोड बन गए हैं। हर गांव-ढाणी में आज नरेगा के माध्यम से सीसी रोड बन रहे हैं, ब्लॉक रोड बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी जमाने में हम सपना देखते थे कि हमारा गांव भी शहर जैसा हो। आज मैं समझता हूं कि अगर यही नीति रही तो हमारा ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति कभी शहर में जाना पसंद नहीं करेगा। इस प्रकार की योजना हमारी सरकार ने बनाई है। हमारी सरकार की नीति सही है। मैं समझता हूं कि इसको हमारे लोगों ने बाजार में भुनाया नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से जो भी हमारे विधायक महोदय या जनप्रतिनिधि हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी हमारी योजनाएं हैं, उन्हें धरातल तक ले जाएं ताकि हर गांव के नागरिक को पता चले कि हमारी सरकार क्या-क्या योजनाएं ला रही हैं। अगर इन योजनाओं का लाभ मिलेगा तो मैं समझता हूं कि वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा करते थे, विश्व गुरु कहा करते थे, वह सपना पूर्ण होगा। इसी आशा के साथ में- जय हिंद, जय भारत, जय, जय राजस्थान।

श्री उपाध्यक्ष: श्री रामनारायण गुर्जर।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बीसलपुर योजना का यह हाल है कि गांवों को जोड़ना बता दिया है, परंतु जाति विशेष की कुछ पंचायतें आज तक भी नहीं जुड़ी हैं। इनमें लाइन डाल दी गई। लाइन डालने के बाद यह हाल हुआ है कि वापस उखाड़ ली गई। ठेकेदारों को पेमेंट हो गया। इसी तरह गांवों में यहाँ तक हाल है कि पंचायतों को बीसलपुर से जोड़ दिया गया, परंतु आज तक पानी नहीं मिला है उन गांवों को। पीसांगन पंचायत समिति इतनी बड़ी है। ठेकेदारों को जोड़ना बता दिया गया। हाउसिंग बोर्ड ही नहीं ठेकेदारों की प्राइवेट कॉलोनियों में लाइनें डाल दी हैं, पर आबादी में लाइन नहीं डली है, आबादी के बाहर लाइन डाल दी है जहां दो-दो घर भी नहीं हैं। माननीय मंत्रीजी चाहें तो जांच करा लें। यह सच्चाई है। यहां तक कि कुछ पंचायतें ऐसी हैं, जिनका मैं नाम बता दूं- झड़वासा पंचायत, भैरूखेड़ा, जसवंतपुरा, अखेपुरा में लाइन आज तक नहीं डली है, क्योंकि कुछ जाति विशेष के गांव हैं। इसी तरह भगवानपुरा में मात्र एक टूंटी लगाकर जोड़ दी है, उन ढाणियों में आज तक लाइन नहीं पहुंची। बीसलपुर का पानी है नहीं, फ्लोराइडयुक्त पानी है। लोग पानी पी-पीकर बीमार हो रहे हैं। आप जांच कराएं। ये हमारे माननीय प्रभारी कालूलाल जी गुर्जर साहब वोट लेने गए थे। वहां देखा गया है कि बिड़कचावास में पानी है, उन ढाणियों को तीन-तीन साल पहले जोड़ दिया है। ठेकेदार पैसा उठाकर खा गए हैं। आज भी आप चैक करा लें, उन ढाणियों में पानी नहीं है। यह हाल है बीसलपुर योजना का। ठेकेदारों ने लाखों का बिल उठा लिया है। जांच करवा लें मंत्रीजी चाहें तो। इसमें अगर एक भी गलती हो तो आप जो चाहे जुर्माना भुगतने के लिए तैयार हूं।

साथ ही माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हैं। उनको मैं अरु-भरु होकर नसीराबाद में जिस सर्जन ने एक ऑपरेशन नहीं किया था, उसने ऑपरेशन किया। एक 32 साल के लड़के की टेबल पर ही डैथ हो गयी। वहां से अजमेर रेफर कर दिया गया। उसके बाद आज भी वहां पर डॉक्टर बैठा हुआ है और मंत्रीजी ने खुद भी सीएमएचओ, जोइंट डायरेक्टर को कहा था कि इसको हाथोंहाथ सस्पैंड करो, इसका ट्रांसफर करो, इसको एपीओ करो, पर

(श्री रामनारायण)
वह आज तक बैठा हुआ है, क्योंकि वहां तो चिकित्सा का यह हाल है कि पैसा बोलता है। आपके पैसे में कितना दम है, उसमें कितनी पॉवर है? यहां तक हाल है कि ..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ..(व्यवधान)...) मंत्रीजी रोग लगा है।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): पीसांगन में आज तक महिला डॉक्टर नहीं है। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' की बात कर रहे हैं। आप बताइये कि महिलाए कहां जायेंगी? रामसर गांव है, वहाँ पर भी नहीं है। तिहारी गांव में कम्पाउंडर ऑपरेशन कर रहे हैं। महिलाएं ऑपरेशन कराने को तैयार नहीं है। आप छोटे-मोटे छोड़िये, बडे-बड़े हास्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। डेढ़ सौ बैड का हास्पिटल है। मैंने मंत्रीजी को बताया कि आई.सी.यू. नहीं है। बस अजमेर रेफर-टू करते हैं। यह हाल चिकित्सा का है। दवाइयां नहीं मिल रही हैं। एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है। बस यह है कि हास्पिटल में जैसे काम चल रहा है, वैसे चलाये जाओ। इस तरह से हमारे यहां जो भी डॉक्टर लगे हैं, बिड़कचावास, लीड़ी, इनमें डॉक्टर जाते ही नहीं हैं। जाते हैं तो अपना काम पूरा किया, घंटा-आधा घंटा बैठे, रवाना हो जाते हैं। सीएमएचओ एक रात गांवों में न सोते हैं, न बैठते हैं और यह कह रहे हैं कि कलक्टर साहब भी गांवों में घूम रहे हैं, रात्रि विश्राम कर रहे हैं। चिकित्सा मंत्रीजी आदेश दे देते हैं कि आप जायेंगे, गांवों में रहेंगे, देखेंगे। मेरे हिसाब से सीएमएचओ ने एक दिन मीटिंग नहीं ली होगी। जोइंट डाइरेक्टर साहब को छह महीने हो गये होंगे। एक दिन मीटिंग नहीं ली है। यह हाल तो चिकित्सा का है।

साथ ही आप जहां उठाकर देखेंगे, गृह मंत्रालय देख लीजिए। गृह मंत्रालय का यह हाल है कि हमारे एसपी साहब निकलते हैं कि टाइगर जा रहा है, अखबारों में आता है कि टाइगर चुपचाप रवाना हो गया। कहां जाएगा, पता नहीं। टाइगर जाते हैं और थानों का निरीक्षण करते हैं। थानों में डोडा चूरा, शराब आज भी आप देख लो जाकर, निरीक्षण कर लो, बहुत पाई जाएंगी। थानेदार, सिपाही ये खुद बेच रहे हैं वहां पर। निरीक्षण करके आते हैं कि हमने बहुत अच्छा निरीक्षण किया। हमें सब कुछ वहाँ यथास्थिति मिली। माल गोदाम को कभी खोलकर नहीं देखते हैं। नसीराबाद

(श्री रामनारायण)

सिटी का यह हाल है। चिटफंड की एक कंपनी थी। उन आदमियों को अरैस्ट किया। उसका माल जब्त किया। सोफा-सैट, टीवी, कूलर, स्कूटर सब जब्त किए। आज आप उस सिटी थाने के माल गोदाम में देखेंगे तो एक चीज नहीं मिलेगी। अब पता नहीं सीआई साहब ले गए हैं, पता नहीं कौन ले गया है? उस माल गोदाम में आज एक भी चीज नहीं हैं। इसकी भी जांच करा सकते हैं। वहां पोपाबाई का राज हो रहा है तीन साल से तो।

आप देखेंगे कि कृषि का हाल यह है कि बीज फ्री दे रहे हैं, खाद फ्री दे रहे हैं। बीजों का यह हाल है कि वहां बुला-बुलाकर नसीराबाद में जो आसपास के गांव हैं उनमें दो-दो, चार-चार थैलियां दे देंगे, बाकी का पता नहीं। इसी तरह खाद थानों में बांट रहे हैं। थानों में किसानों को मारा जा रहा है। मूंगों का यह हाल है कि आज भी किसानों को एक-एक महीने की डेट मिल रही थी, जब चुनाव नहीं थे। अब भी यह हाल है कि मूंग खरीददार नहीं हैं। किसान चक्कर लगा रहे हैं। लेते हैं तो बस ये काला है, ये पीला है, इसका ये भाव मिलेगा, इसका वो भाव मिलेगा और जब किसान बातचीत करके वापस आता है तो सारा मूंग तुल जाता है। काला-पीला सब एक जगह हो जाता है। कभी कहते हैं गोदाम में जगह नहीं है। कभी कहते हैं कि हमारे यहां के जो गोदाम हैं, वहां से गाड़ियां लौट गई हैं। इस तरह बहाने करते हैं। किसानों को इस तरह परेशान कर रखा है। न बिजली टाइम पर है, न पानी टाइम पर है। यहां तक कि बिजली में ट्रांसफार्मर खराब होने पर बताते हैं कि हम 72 घंटे में ट्रांसफार्मर बदलेंगे। यहां तो 72 घंटे के अलावा 36 घंटे में बदली कर देंगे। बात तो ऐसी करेंगे। पर 7 दिन, 8 दिन 10 दिन बगैर होता नहीं है। ठेकेदारों की मनमर्जी चलती है। ट्रांसफार्मर नहीं है साहब, यह नहीं है, वह नहीं है। किसान परेशान होते हैं। आज भी कई किसान ऐसे हैं जिनके ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते। अभी दो घंटे पहले फोन आया कि धोला पंचायत में एक गांव है अमृतपुरा। आधा गांव तीन दिन से अंधेरे में है।

ट्रांसफार्मर आज नहीं भेजेंगे, कल भेजेंगे, परसों भेजेंगे। यह लेटेस्ट आज की खबर है, आप इस बात को मालूम करवाइये। इसी तरह कौनसा विषय ऐसा है, जिस पर यह असत्य नहीं बोल रहे। मैं तो यहां तक कहूंगा कि यह

(श्री रामनारायण)

कृषि में फेल हैं, दवाओं में यह फेल हैं, डॉक्टर नहीं हैं।

जहां तक शिक्षा की बात कर रहे हैं, अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि स्कूलें खुल गयीं। प्राइमरी-मिडल स्कूलों में एक-एक टीचर है, कहीं दो-दो टीचर हैं। एक टीचर प्राइमरी स्कूल में क्या तो काम करेगा, क्या इनके डी.एल.ओ. बनेगा? वह स्कूलों के ताले लगाकर घूमते रहते है, बच्चे बाहर घूमते रहते है।

गांव के लोग यह कहते हैं कि हम ताला लगायेंगे, एक ही टीचर है। सरकार ने डेपुटेशन बंद कर रखे हैं, उसके बाद भी डेपुटेशन पर टीचर लगे हुए हैं आज भी। सरकार के आदेश की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं और जैसे ही गांव वाले ताला लगाने की बात करेंगे या गांव के लोग ताला लगा देंगे तो दूसरे दिन वहां टीचर लग जाएगा। अब दूसरे दिन टीचर कहां से आ जाएगा? अल्टीमेटम देते हैं छह-छह, सात-सात दिन, पन्द्रह दिन जब तक टीचर नहीं लगता है, दूसरे दिन टीचर लगा देते हैं। यह हाल सरकार का है और अभी आपने देखा ही होगा कि सारी जगह से सरकार को जनता ने नकार दिया है। नसीराबाद विधान सभा क्षेत्र में कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जहां पर जनता ने सरकार को नहीं नकारा हो। बिजली नहीं, पानी नहीं, सब कार्यों में फेल है। यह सरकार का हाल है और बड़े-बड़े गीत गा रहे हैं सरकार के।

इसी का हाल अभी बताऊं। हमारे कार्यकर्ताओं को मारा। हमने आपके यहां पर 15 मिनट का धरना दिया। माननीय अध्यक्षजी ने कहा कि मैं अभी सरकार को अवगत करा देता हूं। उसका हाल यह हुआ कि आज तक भी कुछ नहीं हुआ है। मारा भी, हमारे कार्यकर्ता पिटे भी, एफ.आई.आर. भी नहीं हुई और यहां तक हुआ कि उनको घर से बुलाकर एफ.आई.आर. दर्ज कर ली है। अब बताइये बूथ से उनका घर एक किलोमीटर दूर है, झगड़ा बूथ पर बता रहे हैं, कन्नौज बूथ पंचायत में बता रहे हैं और उसमें मेनिपुलेट करके यह कह रहे हैं कि साहब, घर में घुसे थे, मारपीट की और महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। यह हाल सरकार का है, गृह मंत्रीजी की बात कोई मानने के लिये तैयार नहीं हैं। गृह मंत्रीजी ऐसे हो रहे हैं जैसे गाय हो रही है, कुछ बोले ही नहीं। इससे तो अच्छा है, मैं कह रहा हूं शर्म

(श्री रामनारायण)

आनी चाहिये, उन गृह मंत्रीजी को इस्तीफा दे देना चाहिये। इसलिये कि, उनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। थानेदार का ट्रांसफर नहीं कर सकते, सी.ओ. का नहीं कर सकते, एस.पी. का नहीं कर सकते तो फिर करेंगे किसका? ....(व्यवधान)... आप आराम कर लो, थक गये होंगे। एक महीने से आप नसीराबाद में घूम रहे थे, आराम कर लो।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आप एक मिनट बिराजें।

श्री उपाध्यक्ष: आदरणीय सदस्य, आप विराजो। मुख्य सचेतक हैं यह।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा कि गृह मंत्रीजी गाय बन गये हैं। इस तरह गाय बनाना ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): गृह मंत्रीजी नहीं है तो आप बन जाओ।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): मैं गृह मंत्रीजी का शुभचिन्तक हूं। मैं तो आपका भी शुभचिन्तक हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): यह बनेंगे तो सांड बनेंगे।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): पर उनको गाय कहना, यह तो वाजिब नहीं है। गाय से आपका क्या मतलब है? वह तो दूध देती है। इसलिये या तो इस शब्द को निकाला जाये या फिर माननीय सदस्य से यह पूछा जाये कि उनको गाय क्यों कहा?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपको भी तो गाय बना दिया, आप क्यों कह रहे हो? यादवों को बैठाओ, सबको गाय बनाकर छोड़ दिया।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): गाय जानवर होता है, इसलिये इस शब्द को निकालो।

श्री उपाध्यक्ष: और किसी के भी विचार हो मन में, तो वह भी कह दे। हम पशु धन की बात कर रहे हैं, मानव धन की बात नहीं कर रहे।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप अनुमति प्रदान करें तो उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: जब मुख्य सचेतक ने कहा तो प्रतिपक्ष के सचेतक का बोलना तो अनिवार्य-सा लगता है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मेहरबानी है, आप इतने दयालु हैं कि सत्य बात को कहने में समय देते हैं। गांधीजी के जमाने में, इस भारत देश में 70 साल का एक वृद्ध व्यक्ति क्या असत्य बोल सकता है? आप उस पर शंका कर रहे हो। जो कहा, सत्य कहा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मंत्रीजी गाय है या नहीं, इस पर तो हम एक्सपर्ट नहीं हैं, हमारे गोपालन मंत्रीजी राय दे सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आप अपने श्रीमुख से कुछ फरमाना चाहेंगे?

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): गाय तो हमारी राष्ट्रीय गौ-माता है। अब अगर अपन मानव को भी गाय कहें तो अच्छा नहीं है क्योंकि यह गृह मंत्रीजी की बात थी और गृह मंत्रीजी को गाय कहना उचित नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): गाय में कितने देवी-देवताओं का वास है, यह तो बताओ जरा।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): 33 करोड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): गाय में 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है। हमारे गृह मंत्रीजी में भी 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास है, यह तो महा मानव है। अब यह गाय की संज्ञा से यह महा मानव की संज्ञा में आ गये, यह क्या बात कर रहे हो आप?

श्री घनश्याम (टोडाभीम): नहीं, 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास तो है, पर गाय की जो हालत इस समय में हो रही है न, इसलिये ऐसा माननीय सदस्य ने कहा है। जो पोजीशन गायों की इस वक्त हो रही है देश में और प्रदेश में, इसलिये इन्होंने ऐसा कहा है कि गाय जैसी पोजीशन हो रही है।

श्री कालू लाल गुर्जर (सरकारी मुख्य सचेतक): आपके राज में तो इससे भी ज्यादा खराब थी।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, मंत्री महोदय कुछ फरमा रहे हैं।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन था कि यह गाय के बारे में बार-बार बात करते हैं। पहले तो यह रिकार्ड देख लें

(श्री ओटाराम)

कि इन्होंने गाय के लिये क्या किया है? 2014 के बाद में 2018 तक 325 करोड़ सेस से पैसे हमने दिये और इन्होंने 2012-13 में ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मंत्री महोदय, खर्च कितने किये, वह भी बता दो। अभी वैसे मंत्रालय का चार्ज तो आपको नहीं मिला सवा चार साल से, लेकिन फिर भी बता दो नॉलेज हो तो।

श्री उपाध्यक्ष: सचेतक महोदय, थोड़ा धैर्य भी रखें, अनुशासित भी रहें।

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): आपने 2012-13 में सिर्फ 51 लाख रुपये दिये थे, उसके बाद में आपने 84 करोड़ रुपये जाते-जाते पांच साल में दिये। उसके बाद में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, तब से लगाकर आज दिन तक 325 करोड़ रुपये दिये गायों के लिये। यह आपका भी पांच साल का रिकार्ड है।

अभी परसों मेरा एक क्वेश्चन लगा था गाय के ऊपर, राजकुमार जी का प्रश्न था। मेरा क्वेश्चन हाउस में आया नहीं, परन्तु मैं उसका जवाब देने वाला ही था कि जिस तरह से आज की तारीख में गायों के लिये आपके उस समय मेरे हिसाब से 3 लाख पशु गौशालाओं में थे, आज साढ़े सात लाख पशुधन है गौशालाओं में। मेरी बात सुनिये। ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हिंगोनिया गौशाला में क्या हो गया था?

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): हिंगोनिया गौशाला में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आपके टाइम का भी रिकार्ड देख लो, और अभी का रिकार्ड भी देख लो। उस समय भी गायें मरी थीं और उसके बाद में हमने अक्षय पात्र को इसकी जिम्मेदारी दी और जिस दिन से अक्षय पात्र को जिम्मेदारी दी, आज दिन तक आपके सामने ऐसी कोई घटना नहीं आयी होगी। जिस तरह से पूरे राजस्थान में, मैं समझता हूं कि आज यहां की जनसंख्या है साढ़े 6 करोड़ और गौ-वंश है एक करोड़ 33 लाख, अगर अपन सभी एक साथ में बीड़ा उठा लें और एक-एक गाय भी अगर रखना चालू करें तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। गाय पर बात बहुत करते हैं, मैं भी देखता हूं, गाय पर बार-बार वाट्स-अप पर लिखते रहते हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, गायों को तो रख लेंगे, जो सांड घूम रहे हैं उनका क्या करेंगे?

श्री ओटाराम (राज्य मंत्री, गोपालन): जिस तरह से गायें घूम रही हैं...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मंत्रीजी से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, 325 करोड़ में से आपने करौली में कितना पैसा खर्च किया?

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय, एक मिनट आप बिराजें। आप भी विराजो। यह विषय गौ-माता से संबंधित था इसलिये आसन ने भी मंत्री महोदय को निवेदन किया और इजाजत दी कि वह बात करें। मैं इसको वाद-विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। गौ-माता हमारे लिये पूजनीय है और हम सब उसकी आराधना करते हैं। इस बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। सदस्य महोदय, आप अपना वक्तव्य जारी रखें। अब इसको कन्क्लूड कर दें, आपको काफी टाइम हो गया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गृह मंत्रीजी के लिये आदर सूचक हो गया साहब। आपका जो रिमार्क है, वह गृह मंत्रीजी के लिये आदर सूचक हो गया।

श्री उपाध्यक्ष: उसका क्या तात्पर्य है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): तात्पर्य तो सब समझ जाएंगे साहब, इसमें क्या है।

श्री उपाध्यक्ष: इसका विश्लेषण कर दीजिये जरा, सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह असामान्य लोगों के लिये है साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आप कुछ कहना पसंद करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके श्रीमुख से अगर यह बात निकलती है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अगर उस संदर्भ में गृह मंत्रीजी के लिये इस रूप में सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य की दिव्य दृष्टि ऐसी टिक रही है उनकी तरफ भी, तो अच्छी बात है। गृह मंत्रीजी को मानव से ऊपर महा मानव की तरफ आप ले जा रहे हो, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जब तक वह हमारे साथ थे तो मानव थे, आपके साथ आते ही महा मानव हो गये।

श्री उपाध्यक्ष: आप सब महानुभावों का यही अर्थ है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही है साहब।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक कृषि का सवाल है, मैं बता रहा था ...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष: आप अपने विवेक से बोलिए। आपके सचेतक महोदय आपको पथ भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): इस सरकार पर हंसी आती है। पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी नहीं हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी बता रहे हैं कि इतने बढ़िया हर पंचायत में एक-एक गौरव पथ बने हैं, उनका हाल यह है, माननीय मंत्रीजी अभी नहीं हैं, आप नोट करके बता देना, मैं बता रहा हूं, जांच करवा लें उनकी। कितना घटिया स्तर का वहां मसाला लगा है। नीचे जो 6 इंच की गिट्टी लगी होती है, वह गायब है। तिलाना पंचायत में एक बना हुआ है गौरव पथ, एक धाल पंचायत में बना हुआ है गौरव पथ। वहां आप जांच करवा लें।

साथ ही, नसीराबाद में शहरी गौरव पथ बन रहा है, काम अभी चालू है। वहां यह हाल है कि 33 परसेंट बिलो है। सरकारी खर्चे अलग हैं। सरकारी खर्चे का मतलब है जीएसटी है, रायल्टी है। सुविधा शुल्क अलग है। 50 परसेंट में शहरी गौरव पथ कैसे बन जायेगा? आप खुद ही इस बात का ध्यान कर लें।

साथ ही, अभी ताबड़-तोड़ में, जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, उससे पहले ही, आचार संहिता लग जायेगी, कुछ ठेकेदारों को काम दे दिया गया और वह काम चालू हो गया। इस ताबड़-तोड़ में और भी घटिया सड़कें बन रही हैं। कोई देखने वाला नहीं है और यह हाल हुआ है कि हमारे एईएन, जेईएन को तो पहले ही वहां से हटा दिया ताकि कोई कहने वाला ही नहीं मिले। आप तो काम पूरा करवा दो। यह हाल था। पंचायती राज मंत्री बैठे हैं, ग्रामीण गौरव पथ में इतने घटिया ब्लॉक लगाये हैं, मंत्रीजी, जांच करवानी तो एक तो लच्चावास ले लो, एक मांगलियावास ले लो, जो ब्लॉक लगे हैं, वह ऐसे हैं कि पंचायतों में गलियों में भी नहीं लगे होंगे। वहां

(श्री रामनारायण)

गाड़ियां जा नहीं सकती हैं, बड़े ट्रक जा नहीं सकते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा उनको मिलेगा। 60-60 करोड़ रुपये की एक-एक सड़क है वह, तो जांच तो करवा लो, नोट तो कर लो माननीय मंत्रीजी। लच्चावास में ग्रामीण गौरव पथ बना है। इसी तरह मांगलियावास में भी चालू है अभी। दोनों की जांच करवा लेना, इतने घटिया स्तर के ब्लॉक लगे हुए हैं।

इसी तरह एक जांच और करवा लेना। ...(व्यवधान)... आप शांत बैठें आराम से। सुनने को तैयार रहें थोड़ा-सा।

इसी तरह लोहरवाड़ा सरपंच को तो जेल भेज दिया था झूठी शिकायत करके। अब उसने शिकायत की है पंचायत समिति श्रीनगर की, कि घटिया पाइप लगे हैं। यहां तक कि हैण्डपम्प खुदाई नहीं हुई और पेमेन्ट हो गया है, एमबी भर दी है बीडीओ ने, जेईएन और एईएन ने एमबी भर कर पैसा भी उठा लिया है। लोहरवाड़ा की शिकायत है, आज तक जांच नहीं हो रही है। वह बेचारा जांच करवाने के लिए घूम रहा है।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप प्रधान थे, तब के ये सब हैं काम किये हुए। ये घोटाले आपके किये हुए हैं, जब आप प्रधान थे।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): अभी-अभी हुए हैं।

श्री मदन राठौड़ (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अभी-अभी नहीं हुआ है। कहां हुआ है अभी।

श्री रामनारायण (नसीराबाद): आप ठहरो। ठहरो। सुनते जाओ थोड़ा-सा। मैं तो कह रहा हूं न, जांच करवा लो। अभी तो रोड बन ही रहे हैं, बन कर तैयार ही हुए हैं। आपके पत्थर लगे ही हैं अभी। रोड तैयार नहीं होता है और पत्थर लग गये आपके।

इसी तरह आगे आप देखो, तिलाना का तो हो ही गया है। बाकी दूसरे भी ग्रामीण गौरव पथ बन रहे हैं, उनकी भी जांच करवा लेना। नसीराबाद में मैं गलत बोल रहा हूं तो दूसरी जगह की जांच करवा लेना। यह हाल है ग्रामीण गौरव पथों का।

माननीय मंत्रीजी, बेचारे ईमानदारी से जो काम कर रहे हैं, वह मर रहे हैं। जो ठेकेदार आपके चहेते हैं, आपके विभागों को पैसा दे रहे हैं खुल्ला,

(श्री रामनारायण)

वह एमबी भरवा कर लाखों रुपये उठा रहे हैं।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, ऐसे डाक्टर का ट्रांसफर तो कर दो, जिसने बैड पर ही मरीज को मार दिया। उसके पहले उसने एक फोड़े का ऑपरेशन नहीं किया था। ऐसा सर्जन बैठा रखा है अभी भी नसीराबाद में। आपके पैट्रोल के दाम तो बढ़ते-घटते रहते हैं, पर इसमें तो दाम घटाओ, बढ़ाओ मत न, हटाने करने में तो। आपने खुद ने कहा था कि इस डाक्टर को मैं इमिजियेट हटा दूंगा। इससे क्या साबित होता है? इसलिए अब सरकार जाने वाली है। पांच-चार महीनों में कुछ काम करो तो कर दो, पर जाना तो निश्चित है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्रीमती शिमला बाबरी।

श्रीमती शिमला बावरी (अनूपगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया। आज पूरे भारत के अन्दर हमारे नरेन्द्र मोदीजी की सरकार है। हमारे स्टेट के अन्दर भारतीय जनता पार्टी की मुख्य मंत्रीजी की सरकार है वसुन्धराजी की। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो भी जन कल्याणकारी योजना चलाकर जो हमारी जनता को लाभ देने का काम किया है, वह वास्तव में ऐतिहासिक है।

मैं आपको कहना चाहूंगी, हमारे राजस्थान के अन्दर पीएचईडी के जो वाटर वर्क्स थे, प्रत्येक वाटर वर्क्स के अन्दर दो-दो करोड़ रुपये देकर उनका सुधार किया है, मैं कहना चाहती हूं कि उनका पूरा का पूरा फिल्टर सही और सारी की सारी डिग्गियां सही और सारी की सारी मोटरों को सही करके जो स्वच्छ जल पिलाने का काम हमारी मुख्य मंत्रीजी ने किया है और मंत्रीजी ने किया है, वह बहुत ही सराहनीय है।

सिंचाई विभाग के अन्दर पूरे राजस्थान के अन्दर जो भी काम हुआ है, मैं कहना चाहती हूं, अभी डाक्टर राम प्रतापजी नहीं हैं, पंजाब से आने वाली नहर आईजीएनपी नहर बहुत बड़ी नहर है। उस नहर से करीब आधा राजस्थान पानी पीता है और सिंचाई भी करता है। जिसमें गंगानगर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, रामगढ़, ये पूरे के पूरे जिले हमारे आईजीएनपी से जुड़ते हैं और इसके अन्दर मरम्मत करने का कोई काम किया है तो हमारी मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी ने किया है।

(श्रीमती शिमला बावरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहती हूं कि हमारी मुख्य मंत्रीजी ने इस नहर के ऊपर जो डेम है हरिके, वहां से यह आईजीएनपी नहर निकलती है और आज तक कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार ने आज तक वहां जाकर न तो उस डेम को देखा और न ही उसकी कभी मरम्मत करवायी। मैं समझती हूं कि वहां पर पिछले पाँच साल के अन्दर कांग्रेस की सरकार थी तब वहां पर गहलोतजी गये थे और उस हरिके बैराज को देखकर वह इतने डर गये, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उस सिस्टम को छेड़ सकें, उसको सही करवा सकें क्योंकि वह इतना बड़ा सिस्टम है कि छोटा-मोटा मुख्य मंत्री तो उसका काम भी नहीं करवा सकते। यह तो हमारी शेरनी, हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी थीं और हमारे डाक्टर राम प्रतापजी थे, उन्होंने वहां जाकर हालात को देखा और तीन महीनों के अन्दर बराबर हमारे लोगों को पेयजल के लिए पानी भी दिया और पूरे सिस्टम को सही करके सही ढंग से लागू किया और उसके अन्दर 32 गेट जो पाकिस्तान की ओर जाने वाले गेट हैं, उनको भी सही करवाया और गंग नहर के जो गेट हैं, उनको भी सही करवाया। आईजीएनपी के गेटों को भी सही करवा कर किसानों को पूरा पानी देने का काम किया है।

यही नहीं, हमारी अनूपगढ़ शाखा भी उसी आईजीएनपी से निकलती है और उसके अन्दर भी हमारी मुख्य मंत्रीजी ने बिरधवाली हैड से लेकर 77 आर.डी. तक, उन्होंने 132 करोड़ रुपये देकर पूरा का पूरा सी.सी. करके किसानों को पूरा पानी दिया है और उसके साथ-साथ में, उसकी जो निकलने वाली छोटी माइनरें, उसके अन्दर मेरी 10 माइनरें ऐसी हैं, जिनसें बिलकुल बॉर्डर के आस-पास के सभी किसानों से सिंचाई करते हैं, उसमें 7-7 करोड़ रुपये, 8-8 करोड़ रुपये देकर उसका भी बैड लेवल सही किया है और उसका पूरा का पूरा सी.सी. बनाकर उस नहर को दिया है और उसके साथ-साथ में छोटे लेवल पर, जो किसान हमारे खाल से सिंचाई करते हैं, उन खालों को भी हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पक्का करने का काम किया है। आज तक पक्के खाले के बारे में कांग्रेस ने नहीं सोचा, सोचा क्या, बता दो कभी सोचा हो तो। कभी नहर में एक ईंट लगाई हो तो बता दो। वैसे बड़ी-बड़ी बातें करने का और जो अलवर वाली और जो अजमेर वाली सीट जीतकर आप कह रहे

(श्रीमती शिमला बावरी)

हो कि हम राजस्थान के अन्दर फिर से सरकार बना लेंगे, नहीं। मैं आप सबको यह कहना चाहती हूं कि जो हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, किसानों के लिए हितैषी काम किये हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं और पूरे प्रदेश की जनता इसको जानती भी है।

उसके बाद हमारे ग्राम पंचायत के अंदर, आज जो ग्राम पंचायत के अंदर आप देखिए, आप कहते हो कि इंदिरा आवास योजना जो मिलती थी, पहले देखिए, आप, एक कमरा मिलता था गरीब को, कोई भी गरीब परिवार को एक कमरा मिलता था जिसमें पचास हजार का पैसा आता था। उसके अंदर कभी वो नीचे उसकी नींव रखते हैं तो दूसरी किश्त नहीं आती थी, अगर छत पर चला गया तो छत लगाने के लिए किश्त नहीं आती थी। उसी स्कीम में हमारे नरेन्द्र मोदी जी ने डेढ़ लाख रुपये की उनको सहायता देकर बहुत ही अच्छा और बढ़िया हाउस बनाकर गरीब लोगों को दे रहे हैं और उसके साथ-साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत लेट और बाथरूम की भी उनको साथ-साथ में मदद मिल रही है और उसके बाद में यहीं नहीं, हम उस गरीब महिला को उज्ज्वला योजना के तहत आज सब गरीब बहन जो चाहे भट्टे पर काम करती हैं, चाहे मजदूरी करती हैं, कोई चूड़ी बिंदिया बेचने जाती हैं चाहे कोई भी मजदूरी करती है, उस बहन को आज उज्ज्वला योजना के तहत हमारे नरेन्द्र जी मोदी जी ने गैस चूल्हा देकर के बहुत ही सौगातें दी हैं और सभी गरीब जो महिला हैं, वे शहर आती हैं कि किसी ने महिला के बारे में काम किया है तो हमारे नरेन्द्र जी मोदी जी ने किया है और उसके बाद में पंडित दीनदयाल शिविर चला करके, हमारी ग्राम पंचायत के अन्दर छोटे-छोटे काम के लिए जो हमारे बी.डी.ओ. के पास में हमारी गरीब जनता जाया करती थी, चक्कर लगाया करती थी, वो हमने ग्राम पंचायत पर जाकर शिविर लगाकर के बी.डी.ओ. वहां, सैक्रेटरी वहां, तहसीलदार वहां, पटवारी वहां और उनका कोई भी पेंशन का काम, चाहे उनकी बुढ़ापा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे किसी तरीके का छोटा-छोटा कोई काम हो, वहीं पर बैठकर शिविर के अन्दर उसको सुलटाया गया और वहीं पर उनका समाधान किया गया और उसके बाद नरेगा के अन्दर, अपना काम-अपना खेत के अन्दर हमारे ऐसे बहुत सारे किसान हैं, जो लघु

(श्रीमती शिमला बावरी)

सीमान्त के अन्दर आते हैं और एस.सी. वर्ग को जो अपना काम-अपना खेत के तहत, जो लोगों को शैड का और पक्के खाले का और डिग्गी का काम दिया गया, वह बहुत ही सराहनीय है और जनता ने बहुत ही इसका फायदा लिया है और जो हमारे राजस्थान के अन्दर हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने जो नई ग्राम पंचायतें बनाने का काम किया है, वो वास्तव में ऐतिहासिक काम है। हमारी ग्राम पंचायत के अन्दर, नई ग्राम पंचायतों के अन्दर बहुत ही अच्छी शानदार बिल्डिंग्स भी बनी हैं और बड़ी ग्राम पंचायतें थी, उनको छोटी ग्राम पंचायत में करके और उन लोगों को लाभ देने का काम किया।

उसके बाद में हमारी मुख्य मंत्री जल स्वावलम्बन योजना, यह तो बहुत ही पूरे राजस्थान के अन्दर इतनी अच्छी तरीके से और इतने बढ़िया तरीके से लोगों ने सराहा है कि इसके अन्दर बहुत ही बढ़िया काम हुआ है चाहे पक्के खाले का निर्माण हो, चाहे पक्के जोहड़ का निर्माण हो, चाहे पेयजल डिग्गियों का निर्माण हो, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से इसमें काम हुआ है और सबने इसके अन्दर सहयोग भी दिया है और सराहा भी है। मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

उसके बाद पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर ये लोग कह रहे हैं कि गौरव पथ क्या है। मैं इनको बताना चाहती हूं कि गौरव पथ वो चीज है कि जो ग्राम पंचायत के अन्दर आने वाले सभी सरकारी मुख्यालय और सभी लोगों ने इसको सराहा है। एक किलोमीटर तक जो गौरव पथ बना है वास्तव में गांव के अन्दर गौरव बढ़ाने का काम किया है और सी.सी. सड़क जो इतनी अच्छी और इतनी बढ़िया क्वालिटी की बनकर तैयार हुई है, कहने को, आरोप लगाने को तो चाहे कुछ भी कहें, लेकिन इतना बढ़िया गौरव पथ बना है कि वास्तव में सभी गांव के लोग यह सराहते हैं कि हमारे गांव के अन्दर भी इसी तरीके का गौरव पथ बनना चाहिए। उसके बाद हमारे पी.डब्ल्यू.डी. के अन्दर मैं आप सबको यह कहना चाहती हूं कि हमारे अनूपगढ़ से लेकर हमारे सूरतगढ़ तक एक 70 किलोमीटर तक की ऐसी सड़क थी जिस पर आने-जाने में बहुत परेशानी हुआ करती है और साथ में वह ग्रेफ के अन्दर भी थी, लेकिन आज हजारों ये लोग बैठे हैं, ये पीछे 5 साल बैठे ही रहे, बातें ही करते रहे लेकिन उस सड़क को नहीं बना पाये,

(श्रीमती शिमला बावरी)

उन्होंने पेचवर्क भी नहीं किया और हमारी मुख्य मंत्री को ध्यान आते ही और हमारी पी.डब्ल्यू.डी. के मंत्री के ध्यान आते ही और उस सड़क के अन्दर 282 करोड़ रुपये देकर के उसको सी.सी., एकदम सी.सी. बनाने का काम किया है जिसको पूरा गंगानगर जिला सराहता है और मैं समझती हूं कि पूरे राजस्थान के अन्दर पहली सड़क होगी जो इतनी लम्बी और चौड़ी और हम उस सड़क पर जब चलते हैं तो वास्तव में एहसास होता है कि या तो हम पंजाब में आ गये या हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से हमें महसूस होता है। यह कभी बना पाये क्या आप? बात करते हो बड़ी-बडी और उसके बाद के अन्दर गौरव पथ जो हमारा शहर में गौरव पथ बना है। मैं कहना चाहती हूं कि शहर के अन्दर गौरव पथ बना है वो वास्तव में बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर है। मैं आपको कहना चाहती हूं कि जो गौरव पथ है एक किलोमीटर का, इसके अन्दर जो शहरी नगरपालिका के अन्दर जो बना है उसके अन्दर साथ में ही लाइटें, साथ में डिवाइडर, साथ में पौधे इस तरीके से गौरव पथ बनकर हमारे नगरपालिका के अन्दर तैयार हुआ है और वो वास्तव में सराहनीय है। यहां पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री नहीं हैं, मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं। हमारे मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं और जो मिसिंग सड़कें है वो भी शानदार सड़कें बनी हैं। मिसिंग सड़कें जो हमारे गांव टू गांव जोड़ने वाली सड़कें थीं, लोगों की डिमांड्स थी कि हमारी ये सड़क जुड़नी चाहिए, उन सड़क को 2-2 किलोमीटर की जो सड़कें हैं, 3-3 किलोमीटर की जो सड़कें हैं, उनको हमने मिसिंग लिंक के अन्दर डालकर उनको भी डामर बनाने का काम किया है और उसके बाद में कृषि मण्डी के अन्दर भी, उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने कृषि मण्डी के अन्दर जो किसानों का पैसा बेचकर जो कुछ परसेंट कटता था पैसा, वह मण्डी के अंदर जमा हो जाता था, उन पैसों से हम सड़कें बनाते थे। जो किसान अपने खेत के अंदर से होकर, अपने घरों से अंदर से होकर, जो बाजार के अंदर बेचने आते थे, जो अपना फल है, सब्जी है जो भी अपनी फसल है, वो बेचने आते तो टूटी-फूटी सड़कों से आते थे, लेकिन उन सड़कों को पहली बार हमारी मुख्य मंत्रीजी ने, हमारे मंत्रीजी ने उन गांव के अंदर सड़कें बनाने का काम किया है, वह बहुत ही सराहनीय काम है

(श्रीमती शिमला बावरी)

और हमारे प्रभू लाल जी सैनी जी बैठे हैं, मैं प्रभू लाल जी, सैनी जी को धन्यवाद देती हूं कि इन्होंने हमारी घड़साना जो ग्राम पंचायत है, उसमें एक किलोमीटर की बड़े शानदार उसके अंदर पौधे लिये हैं और डिवाइडर भी लिया है। सारे एक किलोमीटर की फल-सब्जी मंडी को जोड़ती वह सड़क है, वह आपने दी है। मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

उसके बाद मैं आपको कहना चाहती हूं हमारे डेयरी, हमारे चिलिंग प्लांट के अंदर मैं आपको कहना चाहती हूं हमारे मंत्रीजी यहां बैठे हैं कि उन्होंने तीन करोड़ रुपये देकर मेरी विधान सभा के अंदर बिल्डिंग बनाने का काम किया है और उसके अंदर.., अभी कल-परसों मैं अधिकारी के पास में गई तो सामान भी आ गया है, उसके लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं।

अंत में, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे मंत्रीजी ने काम किया है वो भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूं कि मेरी बोर्डर की विधान सभा है और पूरे राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायतों के अंदर जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल बनाने का जो काम किया है, जो क्रमोन्नत करने का काम किया है, वह वास्तव में सराहनीय है और आज देखो आप जो गरीब दूर-दराज ग्राम पंचायतों में बैठी हुई बच्चियां हैं, जो अक्सर आठवीं पढ़कर के, दसवीं पढ़कर के घर में बैठ जाया करती थी, आज बड़े आराम से उनके मां-बाप अपनी ग्राम पंचायत के अंदर सीनियर सैकण्डरी तक बच्ची को स्कूल में भेजकर के वो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रही है और उसके बाद में पिछले दिनों मैंने मुख्य मंत्रीजी से कॉलेज भी मांगा था और राजकीय महाविद्यालय खोलकर बहुत बड़ी सौगातें दी हैं तो मैं मंत्रीजी को और हमारे मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

उसके अन्दर हमारे विवेकानन्द मॉडल स्कूल, जो गरीब परिवार होता है, वह गरीब परिवार हमेशा यह सोच रखता है कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। आज हमारे अनूपगढ़ के अन्दर जो विवेकानन्द मॉडल स्कूल खुला है उसके अन्दर शानदार बिल्डिंग, ऐसी कोई भी जिले के अन्दर भी नहीं होगी, इस तरीके से हमारे अनूपगढ़ में बिल्डिंग बनी हुई है और उसके अन्दर मॉडल स्कूल चल रहा है। आज पूरी फैसेलिटी के साथ में हमारे गरीब बच्चे वहां पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय काम है। मैं मुख्य

(श्रीमती शिमला बावरी)
मंत्रीजी को, हमारे मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी 2018 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.40 बजे, गुरुवार, दिनांक 08 फरवरी 2018 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता के लम्बित आवेदन

29. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में गत दो वर्षों में किस-किस जिले के किन-किन कॉलेज संचालकों ने कब-कब नर्सिंग कॉलेज की मान्यता के लिए आवेदन किया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त में से किन-किन को कब-कब नर्सिंग कॉलेज की मान्यता प्रदत्त की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किन-किन कॉलेजों के मान्यता के आवेदन पत्र वर्तमान में किन कारणों से लंबित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान करने के क्या नियम एवं शर्तें हैं तथा कितने दिनों में मान्यता देने अथवा आवेदन पत्र खारिज करने का नियमों में प्रावधान है? संबंधित आदेशों/ नियमों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या गत दो वर्षों में नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने के मामलों में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत दो वर्षों में विभाग द्वारा मान्यता देने के लिये कोई भी आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किये गये।

(2) उपरोक्तानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित नही किये जाने के कारण संस्थाओं को मान्यता प्रदत्त नही की गई।

(3) पिछले दो वर्षों में मान्यता हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नही हुआ है। अत: इस अवधि का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(4) भारतीय नर्सिंग परिषद, नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नर्सिंग कॉलेज खोलने हेतु मान्यता प्रदान की जाती है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(प्रतिलिपि परिशिष्ट-अ पर संलग्न)

(5) जी हां। प्राप्त शिकायतों पर राजस्थान नर्सिंग कौंसिल/राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर से जांच करवाई जाती है। उक्त शिकायतें लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त हुई थी जिनका जवाब लोकायुक्त को भिजवा दिया गया है। (प्रतिलिपि परिशिष्ट-ब पर संलग्न)

(प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गयी)

टोडारायसिंह उपखण्ड में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

30. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह उपखण्ड में रीको औद्योगिक क्षेत्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) औद्योगिक क्षेत्र खोलने हेतु संपूर्ण दस्तावेज भिजवाये जाने के उपरान्त भी उक्त उपखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं व अब कब तक रीको औद्योगिक क्षेत्र खोल दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के टोडारायसिंह उपखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र खोलने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। इस हेतु ग्राम श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह में भूमि चिन्हित की जाकर जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिये प्रस्तावित उक्त भूमि का आवंटन होने पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही किया जाना संभव होगा।

(2) टोडारायसिंह उपखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र खोलने हेतु सम्पूर्ण दस्तावेज संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर को कार्यालय जिला कलक्टर, टोंक के पत्र दिनांक 21.02.17 को प्रस्तावित औद्योगिक भूमि में पहुंच मार्ग के विवरण सहित आवश्यक स्वीकृति हेतु भिजवाये जा चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि प्राप्त होने के

(उद्योग मंत्री)

उपरान्त ही टोडारायसिंह उपखण्ड में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

ब्यावर में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

31. श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के सभी संकायों में सीटें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उचित माहौल के अभाव में कई छात्राएं भी इस महाविद्यालय में अपनी महाविद्यालय स्तर की पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं?

(3) क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में ब्यावर में एक कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय महाविद्यालयों में सीटें बढ़ानें का निर्णय प्राप्त आवेदनों की आवश्यकता को देखते हुए औचित्य के आधार पर लिया जाता है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 में स्नातक प्रथम वर्ष में 20 प्रतिशत सीटों में वृद्धि की गई है (संलग्न परिशिष्ट-1)।

(2) जी नहीं।

(3) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर ब्यावर में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुरवाटी तहसील (झुंझुनूं) में श्रमिक सहायता के लम्बित आवेदन

32. श्री शुभकरण चौधरी (उदयपुरवाटी): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील में अब तक कितने श्रामिक

(श्री शुभकरण चौधरी)

कार्ड किन-किन व्यक्तियों के बनाये गये व किन-किनके श्रमिक कार्ड के आवेदन किस-किस कारण से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील के किन-किन श्रमिकों के सहायता राशि के आवेदन लम्बित हैं तथा सरकार द्वारा पात्र लाभार्थियों का भुगतान कब तक करने का विचार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी तहसील में कुल 16251 निर्माण श्रमिकों का हिताधिकारी के रूप में पंजीयन किया गया है। पंजीयन व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण हिताधिकारी के पंजीयन आवेदन स्वीकृत होने तथा निर्धारित शुल्क एवं अंशदान राशि जमा होने के उपरान्त स्वतः ही पोर्टल पर आवेदनकर्ता श्रमिक का कार्ड तैयार हो जाता है। अतः सभी पंजीकृत श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये जा चुके हैं।

निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु श्रम निरीक्षक तथा पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी अधिकृत है। वर्तमान में विभाग के स्तर पर कोई आवेदन लंबित नहीं है। विकास अधिकारी, उदयपुरवाटी के स्तर पर कुल 623 पंजीयन आवेदन लम्बित हैं। उदयपुरवाटी तहसील में पंजीकृत हिताधिकारियों की सूची तथा लम्बित पंजीयन आवेदनों की सूची क्रमशः परिशिष्ट-1 एवं 2 पर संलग्न है।

(2) झुंझुनूं जिले की उदयपुरवाटी तहसील के कुल 4612 आवेदन (2280 आवेदन श्रम विभाग के स्तर पर तथा 2332 आवेदन विकास अधिकारी, उदयपुरवाटी के स्तर पर) लम्बित हैं। इन आवेदनों के निस्तारण हेतु विभाग के श्रम निरीक्षक को उदयपुरवाटी क्षेत्र हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त पंजीयन की लागू ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदनों का निस्तारण क्रमवार (फर्स्ट कम फर्स्ट आउट) आधार पर करना सुनिश्चित किया गया है।

जिला श्रम कार्यालय, झुन्झुनूं में पूर्णकालिक श्रम अधिकारी तथा निरीक्षकों के रिक्त पदो पर नियुक्ति कर दी गई है। अतः यथाशीघ्र समस्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा। लम्बित आवेदनों की सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

बाड़ी में न्यायालयों के नवीन भवनों का निर्माण

33. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि बाड़ी में एस.डी.एम. कार्यालय एवं समस्त न्यायालय पुराने एवं जर्जर स्थिति वाले भवन में संचालित हैं? क्या सरकार उक्त के लिये नवीन भवनों का निर्माण कराये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

उपखण्ड बाड़ी, जिला धौलपुर के पुराने किले मे एस. डी. एम. कार्यालय व समस्त न्यायालय संचालित हैं।

उपरोक्त कार्यालयों एवं न्यायालय भवनों का निर्माण भूमि एवं बजट उपलब्धता के अनुरूप किया जा सकेगा।

प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र से प्राप्त सहायता

34. डॉ. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई व प्राप्त राशि में से कहां-कहां कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई व प्राप्त राशि में से कहां-कहां कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में किन-किन विद्यालयों में पेयजल के लिए हैण्डपम्प/ सिंगलफेज/पानी की टंकी व शौचालय की सुविधा का अभाव है? क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

द्वारा राशि मदवार उपलब्ध नहीं कराई जाकर एकमुश्त उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वर्षवार निम्नानुसार राशि उपलब्ध कराई गई है:-

(राशि लाखों में)

वित्तीय वर्ष	प्राप्त राशि		
	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	13वें वित्त आयोग के तहत प्राप्त राशि
2008-09	108326.84	62058.30	0.00
2009-10	127124.00	67000.00	0.00
2010-11	146182.29	86113.00	28700.00
2011-12	148580.86	133966.00	32000.00
2012-13	153520.11	145523.95	35600.00
2013-14	242488.70	112899.97	39400.00
2014-15	248041.55	123023.59	40900.00
2015-16	193462.09	213209.12	0.00
2016-17	182578.48	263676.12	0.00
2017-18 (31.12.17 तक)	193973.00	193214.38	0.00

सर्व शिक्षा अभियान द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2017-2018 तक व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक प्राप्त राशि रुपये 31950012.00 एवं व्यय राशि 32407101.61 रुपये व्यय की गई जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" पर एवं राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उक्त अवधि में कराये गये निर्माण कार्यों/ गतिविधियों में प्राप्त राशि एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट "ग" पर संलग्न हैं।

(3) विराटनगर विधान सभा क्षेत्र के सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

माध्यमिक विद्यालय में पेयजल के लिए हैण्डपम्प/ सिंगलफेज/पानी की टंकी एवं शौचालय की सुविधा उपलब्ध है तथा राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। पेयजल के लिए हैण्डपम्प/ सिंगलफेज/पानी की टंकी की सुविधा के अभाव वाले राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है।

जी हां। 14वें केन्द्रीय वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग तथा शहरी क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पी.एच.ई.डी. द्वारा भी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है, लेकिन वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत पेयजल व्यवस्था हेतु बजट का आवंटन नहीं किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

वीर हनुमान मंदिर, सामोद में पर्यटन विकास के कार्य

35. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की वीर हनुमान मंदिर, सामोद को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना है? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत क्या-क्या कार्य करवाये जायेंगे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान पर पर्यटन विकास के कार्य अप्रेल तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत स्वदेश दर्शन योजनान्तर्गत श्री सामोद बालाजी के विकास हेतु राशि रु. 188.87 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। योजना में स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट- "अ" पर उपलब्ध है।

(2) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार की उक्त स्वीकृति के अनुसार कार्य को पूर्ण करने की अवधि माह सितम्बर, 2018 निर्धारित है।

परिशिष्ट- अ

पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 30.03.2017 को स्वदेश दर्शन योजनार्न्तत स्वीकृत आध्यात्मिक सर्किट प्रोजेक्ट में श्री सामोद बालाजी के विकास हेतु राशि रु. 188.87 लाख के निम्न कार्य स्वीकृत किये गये हैं-

क्र.सं.	श्री सामोद बालाजी	राशि रु.
1.	पर्यटक सुविधा केन्द्र का विकास कार्य	4,604,700
2.	आपातकालीन चिकित्सा सेन्टर	2,587,230
3.	सूचनात्मक साइनेजेज	115,000
4.	आधारभूत सुविधाओं का विकास (पेयजल, बैनचेज, लॉकर इत्यादि)	6,355,420
5.	हाईमास्क लाईट (1 पार्किंग पर एवं 1 मंदिर के ऊपरी भाग पर)	531,000
6.	मंदिर की सीढ़ियों के दोंनों तरफ जल निकास (ड्रेनेज) कार्य	1,723,000
7.	वाई-फाई सिस्टम	667,500
8.	सीसीटीवी सिस्टम	401,400
9.	मंदिर पहाड़ी के ऊपर, 1100 सीढ़ियों व पार्किंग क्षेत्र पर सोलर लाइट	1,902,000
	कुल योग	18,887,250

बड़ी सादड़ी के गांवों का विद्युतीकरण

36. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण

(श्री गोतम कुमार)

ज्योति योजना के तहत कुल कितने गांव विद्‌युतीकरण हुए एवं कितने बिजली कनेक्शन किये गए? वर्षवार, ग्रामवार, नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बी.पी.एल. के अलावा स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को बिजली कनेक्शन देने तथा बिजली रहित गांवों का विद्‌युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़) में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत अविद्‌युतीकृत गांव पीपलापानी (01 ग्राम) को विद्‌युतीकृत किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत कुल 5015 (1638 बीपीएल एवं 3377 एपीएल) घरेलू विद्‌युत कनेक्शन जारी किये गये हैं। जिनका वर्षवार, ग्रामवार, नाम सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अर्न्तगत बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवारों को जो घरेलू विद्‌युत कनेक्शन से वंचित थे, उनको उक्त योजना के तहत विद्‌युतीकृत कर विद्‌युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं एवं माह जून, 2018 तक कार्य को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा रेंज के पुलिस थानों में महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति

37. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटा रेंज के पुलिस थानों में से अधिकांश ग्रामीण थानों में पर्याप्त महिला पुलिसकर्मी नहीं होने के कारण महिला डेस्क भी पुरुष कर्मचारी संभाल रहे हैं? यदि हां, तो नियमानुसार प्रत्येक थाने में कितनी महिला कर्मचारी होनी चाहिए और वर्तमान में उक्त रेंज के ग्रामीण थानों में कितनी महिला कर्मचारी कार्यरत हैं? थानेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल नागर)

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त में से कुछ थानों में एक भी महिला कर्मचारी कार्यरत नहीं है? यदि हां, तो ऐसे थानों में दुष्कर्म, छेड़छाड़ व अन्य महिला अत्याचार की पीड़िता के बयान लेने की क्या व्यवस्था की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्र के थानों में महिला कर्मचारियों के लिए अलग से आवास की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां महिला कर्मचारियों को नियुक्ति देने में समस्या आ रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रेंज के सभी थानों में महिला कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा रेंज के ग्रामीण थानों में जिला बारां में ग्रामीण थाना मोठपुर, बापचा, कस्बा थाना, शाहबाद, हरनावदा में महिला कांस्टेबल पदस्थापित नही हैं। महिला कांस्टेबल प्रशिक्षण में है, प्रशिक्षण से आने पर पदस्थापित की जाएगी। इसी प्रकार जिला बूंदी में दबलाना एवं जिला झालावाड़ के दांगीपुरा थाने पर महिलाकर्मी तैनात नहीं हैं जहां पर शीघ्र ही पदस्थापन करवा दिया जाएगा। इन थानों पर आवश्यकता पड़ने पर नजदीकी वृत के थानों से महिला कांस्टेबल कार्यवाही हेतु बुलायी जाती है। नियमानुसार प्रत्येक थाने में महिला कांस्टेबल के पदों की अलग से नफरी स्वीकृत नहीं है। कार्य संचालन हेतु आवश्कतानुसार महिला कांस्टेबल थानों में पदस्थापित है। रेंज के ग्रामीण 70 थाने हैं जिनमें 143 महिला कांस्टेबल कार्यरत हैं जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। कोटा रेंज के बूंदी जिला के थाना दबलाना व जिला बारां में ग्रामीण थाना मोठपुर, बापचा, कस्बा थाना, शाहबाद, हरनावदा एवं जिला झालावाड के दांगीपुरा में कोई महिला कांस्टेबल पदस्थापित नहीं होने के कारण इन थानों में दुष्कर्म, छेड़छाड़ तथा अन्य महिला अत्याचार की पीड़िता के बयान लेने के लिए नजदीकी वृत थाने एवं पुलिस लाइन से कार्यवाही हेतु महिला कांस्टेबल की व्यवस्था की जाती है।

(3) जी नहीं। कोटा रेंज के सभी ग्रामीण थानों पर कर्मचारियों के

(गृह मंत्री)

आवास की सुविधा है। महिलाकर्मी द्वारा आवेदन करने पर उन्हें आवास उपलब्ध करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

हनुमानगढ़ जिले में चयनित कनिष्ठ लिपिकों को नियुक्ति

38. श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विभाग में कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में चयनितों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है? यदि हां, तो हनुमानगढ़ जिले में कितने पद भरे गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति घड़साना में उक्त चयनितों में से कितनों को नियुक्ति दी गई है? क्या पात्र व्यक्ति भी नियुक्ति से वंचित रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) श्रीगंगानगर जिला परिषद में उक्त भर्ती परीक्षा में चयनित नियुक्ति से वंचित लोगों को कब तक नियुक्ति प्रदान कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में जिला परिषद हनुमानगढ़ में कुल 250 अभ्यार्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है।

(2) पंचायत समिति घड़साना में कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 में 48 पदों पर नियुक्तियां दी गई हैं। वरीयतानुसार सूची अनुसार काई भी पात्र अभ्यर्थी भर्ती से वंचित नहीं रहा है।

(3) जिला परिषद, श्रीगंगानगर में कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती परीक्षा 2013 की संशोधित वरीयतानुसार कोई भी पात्र अभ्यर्थी नियक्ति से वंचित नहीं रहा है।

प्रदेश में पी.पी.पी. मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थान

39. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(1) प्रदेश में पी.पी.पी. मोड पर कितने सरकारी चिकित्सा संस्थान किस-किस कंपनी व संस्था के माध्यम से संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पी.पी.पी. मोड पर संचालन करने वाली कंपनी या संस्था को सरकार द्वारा अब तक कितना भुगतान कर दिया एवं इसके लिए क्या-क्या मानदंड व नियम निर्धारित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश के हित में उक्त पी.पी.पी. मोड पर संचालित सरकारी चिकित्सा संस्थानों को पुनः सरकारी स्तर से संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज रखें।

(4) प्रदेश के नागौर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनूं, बाड़मेर व जैसलमेर जिले में पी.पी.पी. मोड पर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत स्टॉफ की नाम व पदनाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में पी.पी.पी मोड पर संचालित 99 ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उनका संचालन करने वाली संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी.पी.पी मोड पर संचालित 38 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर के माध्यम से पी.पी.पी मोड पर मेट्रो मास अस्पताल जयपुर का संचालन किया जा रहा है।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों को पी.पी.पी मोड पर संचालित करने वाली संस्थाओं को किए गये भुगतान का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पी.पी.पी मोड पर संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन करने वाली संस्थाओं को किये गये भुगतान का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित मैट्रो मास अस्पताल को अनुबंध में किए प्रावधान अनुसार भुगतान नही किया जाना है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पीपीपी मोड पर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मापदण्ड व नियमों का विवरण परिशिष्ट- क एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत पीपीपी मोड पर संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुबंध का विवरण परिशिष्ट- ख पर संलग्न है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा मैट्रो मास अस्पताल के साथ किए गये अनुबंध का विवरण परिशिष्ट- ग पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थानों को सरकारी स्तर से संचालित किए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रथम चरण में जून 2016 में पीपीपी मोड पर दिये गये ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के मूल्यांकन अनुसार इन संस्थाओं पर उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, विवरण परिशिष्ट-घ पर संलग्न है।

एक वर्ष से कम अवधि में संचालित संस्थानों का अभी मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(4) प्रदेश के नागौर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, झुन्झुनूं, बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में पीपीपी मोड पर संचालित ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत स्टाफ का नाम एवं पदनाम परिशिष्ट-य पर संलग्न है। सीकर में कोई भी ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपीपी मोड पर संचालित नहीं है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नागौर, जोधपुर, चूरू, बीकानेर एवं सीकर जिले में पीपीपी मोड पर संचालित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत स्टाफ की सूची मय नाम, पदनाम परिशिष्ट-य पर संलग्न है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में झुन्झुनूं, बाड़मेर, जैसलमेर जिले में कोई भी शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पीपीपी मोड पर संचालित नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

तिजारा के उद्योगों द्वारा सी.एस.आर. से कराये गये सामाजिक कार्य

40. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, चौपानकी, कहरानी, खुशखेड़ा, करौली और टपूकड़ा में स्थापित उद्योग अपने लाभ में से सी.एस.आर. के रूप में सरकार के नियमानुसार सामाजिक कार्य में लगाते हैं? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य क्षेत्रीय विधायक की अभिशंसा से कराये जाते हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार नियमानुसार उक्त कार्य क्षेत्रीय विधायक की अभिशंसा से कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2013 से 15 जनवरी, 2018 तक उक्त औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगों द्वारा सी.एस.आर. के रूप में सामाजिक कार्यों पर कितनी राशि व्यय करनी थी व कितनी व्यय की गई तथा कितनी व्यय किया जाना शेष है? औद्योगिक क्षेत्र व उद्योगवार दूरभाष नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र तिजारा में औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी, चौपानकी, कहरानी, खुशखेड़ा, करौली और टपूकड़ा में स्थापित कम्पनियां अपने लाभ का कुछ प्रतिशत कम्पनी में गठित सीएसआर समिति के निर्णयानुसार सामाजिक कार्य में लगाते हैं। भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अन्तर्गत सीएसआर हेतु बनाये गये नियमों व अधिसूचनाओं के आधार पर कम्पनियों की सीएसआर राशि के उपयोग हेतु विधिक रूप से क्षेत्रीय विधायक से अभिशंसा लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं हैं।

(2) कम्पनियों द्वारा व्यय किये जाने वाले सीएसआर फण्ड की मोनिटरिंग करने का राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नही है। इकाइयों द्वारा व्यय की जाने वाली एवं व्यय की गयी सीएसआर राशि की सूचना को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाता है। यद्यपि राज्य

(उद्योग मंत्री)

सरकारों द्वारा इस राशि की मोनिटरिंग करने का कोई प्रावधान नहीं है किन्तु फिर भी इकाइयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अलवर जिले में स्थापित कम्पनियों की सूची एवं उनके द्वारा की गयी व्यय की सूची परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

कोटा में आई.आई.आई.टी. संस्थान का भवन निर्माण

41. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा में स्वीकृत आई.आई.आई.टी. संस्थान में शिक्षण कार्य आरम्भ हो चुका है? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त संस्थान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं?

(2) उक्त संस्थान में वर्तमान में कितना स्टॉफ कर्यरत है तथा उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त संस्थान के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो भवन निर्माण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

(4) उक्त भवन के निर्माण एवं संसाधनों के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आई.आई.आई.टी. कोटा में वर्तमान में 299 विद्यार्थी अध्ययनरत है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) आई.आई.आई.टी. कोटा में 22 नियमित संकाय सदस्यों के (एंट्री लेवल) पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में समस्त पद रिक्त हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। आई.आई.आई.टी. कोटा हेतु भूमि आवंटन के पश्चात चारदीवारी एवं सिक्योरिटी ऑफिस, साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्य भवन का निर्माण कार्य करवाया जाना शेष है। भवन निर्माण के लिए अपेक्षित राशि उपलब्ध होने पर निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा।

(तकनीकी शिक्षा मंत्री)

(4) उक्त संस्थान के भवन निर्माण एवं संसाधनों के लिए राज्य सरकार द्वारा समुचित राशि स्वीकृत किया जाना विचाराधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में स्टाफ का पदस्थापन

42. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा बांदीकुई में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्मित करवाया गया है? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त संस्थान में वर्तमान में कुल कितने छात्र अध्ययनरत हैं? क्या उनके अनुपात में पर्याप्त स्टॉफ/संकाय उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में बांदीकुई में कोई राजकीय आईटीआई स्वीकृत नहीं है। अतः सरकार द्वारा कोई संस्थान भवन का निर्माण नहीं करवाया गया।

(2) बांदीकुई में कोई राजकीय आईटीआई स्वीकृत नहीं है। अतः प्रश्न लागू नहीं होता है।

प्रदेश में सिवायचक भूमि के पट्टे देने की योजना

43. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में सिवायचक भूमि पर लम्बे समय से खेती कर रहे काश्तकारों को उक्त भूमि का पट्टा देने के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उदयपुर जिले में सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में कितनी सिवाय चक भूमि पर खेती कर रहे काश्तकारों को पट्टे दिए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री फूलसिंह मीणा)

(3) क्या सरकार सिवायचक भूमि पर लम्बे समय से खेती कर रहे काश्तकारों को पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सिवायचक भूमि पर लम्बे समय से खेती कर रहे/ भूमिहीन पात्र काश्तकारों को भूमि आवंटन/नियमन किये जाने का प्रावधान राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम-1970 के अन्तर्गत किया हुआ है। नियम की प्रति परिशिष्ट- "अ" पर संलग्न है।

(2) उदयपुर जिले में गत पांच वर्षों में राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम-1970 के नियमों के तहत अब तक किये गये आवंटन/नियमन की सूचना परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) राजस्थान भू-राजस्व (कृषि हेतु भूमि का आवंटन) नियम-1970 के तहत आवंटन सलाहकार समिति द्वारा समय-समय पर आवंटन/नियमन की कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के सरकारी विद्यालयों का पी.पी.पी. मोड पर संचालन

44. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश के कौन-कौनसे विद्यालयों को पी.पी.पी. मोड पर दिया जा रहा है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश के सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मोड पर देने के क्या कारण हैं व पीपीपी मोड पर देने के पश्चात् उक्त विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का समायोजन किस प्रकार किया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के राजकीय विद्यालयों को पीपीपी मोड पर दिये जाने के क्या-क्या नियम व शर्तें हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में जनवरी, 2013 के पश्चात् विभिन्न स्तर के कितने नये सरकारी विद्यालय खोले गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(5) प्रदेश में 01 जनवरी, 2013 एवं 01 जनवरी, 2018 को कितने-कितने सरकारी विद्यालय संचालित थे? उक्त दोनों वर्षों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। 300 विद्यालयों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) प्रदेश के सरकारी सरकारी विद्यालयों को पीपीपी मोड पर देने का उद्देश्य Policy For Private Partnership In School Education, 2017 के बिन्दु संख्या 01 एवं 02 में उल्लेखित है।

पॉलिसी के बिन्दु संख्या 06 के उपबिन्दु (X) के अनुसार इनमें कार्यरत कार्मिकों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा अन्य राजकीय विद्यालयों के रिक्त पदों पर स्थानान्तरित किया जाएगा।

(3) पॉलिसी के बिन्दु संख्या 5.1.2 के अन्तर्गत पीपीपी पार्टनर का चयन खुली प्रतिस्पर्धात्मक निविदा द्वारा किया जाना है। पॉलिसी में वर्णित नियम/शर्तों के अनुसार ई-निविदा दिनांक 21.12.2017 को जारी कर E-Proc वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

(4) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में जनवरी, 2013 के बाद 1962 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले गये जिनका जिलेवार संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 01 जनवरी, 2013 से अब तक 2044 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तथा 6386 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया है, जिनका जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है।

(5) स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 01 जनवरी, 2013 एवं 01 जनवरी, 2018 को निम्नानुसार राजकीय विद्यालय संचालित थे:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या 1 जनवरी, 2013	विद्यालयों की संख्या 1 जनवरी, 2018
1.	प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 1 से 5) वाले राजकीय विद्यालयों	70659	62996
2.	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 7) वाले राजकीय विद्यालय	34092	32585
3.	माध्यमिक (कक्षा 9 से 10) वाले राजकीय विद्यालय	13288	13685
4.	उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 से 12) वाले राजकीय विद्यालय	4404	9909
	योग	122443	119175

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश के होटलों को पी.पी.पी. मोड पर देने की योजना

45. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार का खासाकोठी होटल और आनंद भवन को पीपीपी मोड पर देने का विचार है? यदि हां, तो क्यों एवं किन शर्तों पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि खासा कोठी होटल और आनन्द भवन को पीपीपी मोड पर देने के संबंध मे निजी क्षेत्र की सहभागिता प्राप्त करना प्रक्रियाधीन है।

होटल व्यवसाय करना सरकार के मुख्य दायित्वों में शामिल नहीं है। इस व्यवसाय को निजी क्षेत्र द्वारा बेहतर तरीके से सम्पादित किया जा सकता है। होटल व्यवसाय में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के चलते सरकारी सैक्टर में होटलों का संचालन घाटे का सौदा बन गया है। ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य होटल्स निगम लि. की इकाई होटल खासा कोठी, जयपुर एवं होटल आनन्द भवन, उदयपुर की वित्तीय स्थिति भी असंतोषजनक बनी हुई है।

होटल खासा कोठी, जयपुर एवं होटल आनन्द भवन, उदयपुर को पीपीपी मोड पर देने हेतु शर्तें निर्धारित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में डोडा पोस्त/भांग के ठेकों का निरीक्षण

46. श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में डोडा पोस्त/भांग समूह की निविदा आमंत्रित की जाती है? यदि हां, तो निविदा की शर्तें, नियम व मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि डोडा पोस्त/भांग को खुदरा दुकानों पर माप से विक्रय किया जाता है? यदि हां, तो भांग किस माप से विक्रय की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या गत चार वर्षों में भांग विक्रेताओं द्वारा तय माप से नहीं बेचने तथा इसमें अन्य पत्तियों को मिलाकर बेचने की शिकायतें प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग द्वारा समय-समय पर खुदरा भांग की दुकानों का निरीक्षण किया जाता है? यदि हां, तो गत चार वर्षों में कितनी खुदरा दुकानों पर कार्यवाही की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि प्रदेश के भांग के ठेकेदारों ने तय नियमों व शर्तों के अनुसार भांग के प्लान्ट लगा रखे हैं? यदि नहीं, तो ठेके किस आधार पर दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य में दिनांक 01.04.2016 से डोडा पोस्त मानव उपयोग एवं विक्रय हेतु प्रतिबंधित है।

भांग समूह की निविदा आबकारी विभाग द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) निविदा प्रपत्र में उल्लेखित निविदा के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं शर्तों के बिन्दु संख्या 04 के अनुसार भांग पत्ती/भांग घोटा (माजुम, बुकनी, गुलकन्द आदि सहित) खुदरा विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं।

भांग खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र (लाइसेंस) की शर्त संख्या 6.7 अनुसार एक व्यक्ति को एक बार में 100 ग्राम से अधिक भांग का विक्रय नहीं किया जा सकता है।

(आबकारी मंत्री)

(3) भांग विक्रेताओं के विरुद्ध भांग में किसी प्रकार की पत्तियां मिलाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) नियमानुसार खुदरा भांग दुकानों का निरीक्षण किया जाता है। राज्य में भांग दुकानों के निरीक्षण के दौरान अनुज्ञापत्र की शर्तों के उल्लंघन के कारण कुल 07 अभियोग पंजिकृत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है-

क्रम संख्या	नाम जिला	अभियोग संख्या व दिनांक
1.	जयपुर	01/2017-18 दिनांक 03.05.2017
2.	जयपुर	03/2017-18 दिनांक 03.05.2017
3.	भीलवाड़ा	21/2017-18 दिनांक 10.08.2018
4.	बून्दी	38/2017-18 दिनांक 26.10.2017
5.	बून्दी	39/2017-18 दिनांक 26.10.2017
6.	बून्दी	40/2017-18 दिनांक 26.10.2017
7.	बून्दी	28/2017-18 दिनांक 23.01.2018

(5) राज्य में भांग के अनुज्ञाधारियों द्धारा भांग का कोई प्लान्ट स्थापित नहीं है। राज्य में भांग का उत्पादन नहीं होने के कारण अनुज्ञाधारियों द्धारा राज्य के बाहर से संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा जारी आयात परमिट के आधार पर भांग आयात की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगंज में नवीन पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

47. श्री ललित कुमार (किशनगंज): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार किशनगंज तहसील में नया पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार मध्यप्रदेश सीमा से लगे राजपुर, बिलखेड़ा, डांग व खण्डेला में चैक पोस्ट पर जवानों को 24 घण्टे तैनात रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार किशनगंज-शाहाबाद में नया थाना खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(श्री ललित कुमार)

(4) क्या सरकार को रामगढ़ चौकी को थाना बनाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) किशनगंज में नया सी.ओ कार्यालय खोलने का प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक बारां से पत्रांक 576-77 दिनांक 21-01-2016 द्वारा प्राप्त होने पर डॉ.परमेश चन्द्र आई.ए.एस. (सेवानिवृत) की अध्यक्षता में गठित कमेटी को प्रेषित किए गए।

कमेटी की अनुशंषाओं के आलोक में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध व कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस की नफरी की उपलब्धता के आधार पर किशनगंज तहसील में नया पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) मध्यप्रदेश की सीमा से लगे राजपुर, बिलखेडा, डांग व खण्डेला आदि में जाप्ते की कमी होने से स्थाई पोस्ट तैनात नही की जाकर ए.डी.एफ. एरिये में आने व डकैतों का मूवमेन्ट होने पर समय-समय पर आर.ए.सी. की पोस्ट तैनात की जाती है तथा रात्रि गश्त व नाकाबंदी की जाती है।

(3) किशनगंज-शाहबाद में नया थाना खोलने का प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(4) रामगढ़ चौकी को थाना बनाने संबंधी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

पाली जिले में कैटल शेड्स का निर्माण

48. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पाली जिले में वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किस-किस पंचायत समिति की किस-किस ग्राम पंचायत में किस-किस जाति के एवं किस-किस चयनित परिवार के कैटल शैड निर्माण के प्रस्ताव पंचायत समितियों द्वारा किस-किस तारीख को जिला परिषद पाली में भिजवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावों में से कौन-कौन से प्रकरणों को किस-किस तारीख को स्वीकृत किया गया एवं कौन-कौन से प्रकरण कितनी-कितनी अवधि से

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

किन-किन कारणों से लंबित हैं एवं कौन-कौन से प्रकरण किन-किन कारणों से अपात्र मान खारिज किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में लंबित प्रकरणों में से कौन-कौन से प्रकरण पात्रता रखते हैं एवं इनमें से किन-किन प्रकरणों में कितनी-कितनी अवधि में स्वीकृतियां जारी कर दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों में स्वीकृतियां जारी होने में अत्यधिक विलंब होता है? यदि हां, तो क्या सरकार समय पर स्वीकृतियां जारी होने के लिये समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी अवधि में व नहीं, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पाली जिले में कैटल शैड/पशुधन निर्माण की स्वीकृति के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए समस्त पंचायत समितियों से प्राप्त प्रस्ताव तथा स्वीकृत प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	पंचायत समिति	प्राप्त कुल प्रस्तावों की संख्या		स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या		लम्बित प्रस्तावों की संख्या	
		16-17	17-18	16-17	17-18	16-17	17-18
1	बाली	774	0	767	2	0	28
2	देसूरी	373	0	373	0	19	19
3	जैतारण	665	168	624	1	36	27
4	मारवाड़ जं.	255	11	240	2	0	18
5	पाली	1180	39	1176	11	4	28
6	रायपुर	759	34	598	0	8	11
7	रानी	499	2	184	2	306	0
8	रोहट	296	49	292	0	4	49
9	सोजत	554	0	544	0	43	19
10	सुमेरपुर	492	109	492	22	0	106
	योग	5847	412	5290	40	420	302

ग्राम पंचायत एवं लाभार्थीवार सूचना प्रपत्र-अ पर संलग्न है।

(ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी) मंत्री)

(2) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पाली जिले में कैटल शैड/पशुधन निर्माण की स्वीकृति के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रक्रिया से संबन्धित सूचना प्रपत्र-ब पर संलग्न है।

(3) महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पाली जिले में कैटल शैड/पशुधन निर्माण की स्वीकृति के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए प्राप्त प्रस्तावों में से लम्बित प्रस्तावों की संख्या 722 हैं, जिन्हें आक्षेप उपरांत स्वीकृति के लिए विभागीय कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत पंचायत समितियों से विभिन्न स्वीकृतियों हेतु प्राप्त तकमीनों की "तकनीकी परीक्षण" उपरांत नियमानुसार स्वीकृति जारी कर दी जाती है परन्तु तकनीकी परीक्षण के दौरान आक्षेप पाए जाने पर संबन्धित पंचायत समिति द्वारा आक्षेप आपूर्ति किए जाने के उपरांत स्वीकृति जारी कर दी जाती है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले में भवनविहीन आयुर्वेद चिकित्सालय

49. श्री विजय सिंह (नावां): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने आयुर्वेद चिकित्सालय भवनविहीन हैं एवं कितने किराये के भवनों में संचालित हैं? क्या नागौर जिले में भी उक्त चिकित्सालय किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार भवनविहीन चिकित्सालयों के भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार कुचामन सिटी में संचालित 'अ' श्रेणी के आयुर्वेद चिकित्सालय का भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार कुचामन के 'अ' श्रेणी चिकित्सालय का भवन PMO कार्यालय कुचामन के प्रथम तल पर ही बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो, क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्तमान में 25 आयुर्वेद चिकित्सालय/औषद्यालय

(आयुर्वेद मंत्री)

किराये के भवन में संचालित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न हैं।

वर्तमान में नागौर जिलान्तर्गत केवल मात्र एक राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय मकराना (नागौर) किराये के भवन में संचालित है। इस हेतु विभागीय भवन निर्माण के लिए जिला कलक्टर नागौर को भूमि आवंटन हेतु लिखा गया है। भूमि आवंटन होने के उपरान्त आवश्यक बजट प्रावधान उपलब्ध करवाया जाकर निर्माण कार्य करवाया जा सकेगा।

(2) राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय कुचामन सिटी-नागौर वर्तमान में जिस भवन में संचालित है वह भवन विभाग को दान में प्राप्त है जिसमें 23 कमरे व बरामदा/शौचालय निर्मित है जो चिकित्सालय संचालन हेतु पर्याप्त है।

(3) राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय कुचामन का भवन चिकित्सालय संचालन हेतु पर्याप्त है। अत: भवन बनाने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट- अ

	किरायें के भवनों में संचालित औषद्यालय/ चिकित्सालयों का विवरण		
क्रम संख्या	संभाग का नाम	नाम जिला	नाम औषद्यालय/चिकित्सालय
1	अजमेर	अजमेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय चन्दननिवास
2		अजमेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय गौतमनगर
3		अजमेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय नागबाई
4		भीलवाड़ा	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय सांगानेर
5		भीलवाड़ा	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय पुर
6		नागौर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय मकराना
7		टोंक	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय टोंक
8	बीकानेर	बीकानेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय नत्थूसर बास बीकानेर
9		बीकानेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय सोनगिरि कुआं बीकानेर
10		बीकानेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय गोगागेट हरिजन बस्ती बीकानेर
11		बीकानेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय शीतलगेट बीकानेर
12		बीकानेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय बारह गुवाड़ का चौक बीकानेर

(आयुर्वेद मंत्री)

13	बीकानेर	बीकानेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय बीकानेर शहर
14		बीकानेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय कोलायत
15		बीकानेर	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय श्री डूंगरगढ़
16		चूरू	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय राणासर
17	जयपुर	जयपुर 'अ'	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय झोटवाड़ा
18		जयपुर 'अ'	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय पुरानी बस्ती
19		जयपुर 'अ'	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय सिरसी
20		जयपुर 'अ'	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय ढेहर का बालाजी
21		जयपुर 'अ'	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय खातीपुरा
22		जयपुर 'ब'	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय आर्दशनगर
23		जयपुर 'ब'	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय जगतपुरा
24		झुंझुनूं	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय झुंझुनूं
25	जोधपुर	पाली	राजकीय आयुर्वेद औषद्यालय शुभाष नगर पाली

रिसर्जेंट राजस्थान के तहत जयपुर एवं भरतपुर संभाग में स्थापित उद्योग

50. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) रिसर्जेंट राजस्थान के तहत जयपुर एवं भरतपुर संभाग के जिलों में नये उद्योग लगाने के लिए कितने व कौन-कौन से एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एम.ओ.यू. के आधार पर जयपुर व भरतपुर संभाग के जिलों में कितने व कौन-कौन से उद्योग लगाये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत कितने युवा उद्यमियों को किस-किस प्रकृति के उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा अब तक कितने युवा उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रिसर्जेंट राजस्थान के तहत जयपुर एवं भरतपुर संभाग के जिलों में नये उद्योगो के लिए 38 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये है जिनका विवरण अनुसंलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(2) रिसर्जेंट राजस्थान के तहत किये गये एम.ओ.यू. में से जयपुर एवं भरतपुर संभाग में 12 परियोजनाएं औद्योगिक सैक्टर में क्रियान्वित हो गयी है, का विवरण अनुसंलग्नक-2 उपलब्ध है।

(3) राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के तहत राज्य के सभी प्रकार के स्टार्टअप को राजस्थान सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। अब तक कुल 15 स्टार्टअप/उद्यमियों को वित्त सहायता उपलब्ध करवाई गयी है, का विवरण अनुसंलग्नक-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नवलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय की स्थापना

51. डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश के प्रत्येक उपखण्ड मुख्यालय पर राजकीय कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नवलगढ़ उपखण्ड मुख्यालय पर कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर जिस उपखण्ड मुख्यालय पर छात्र/छात्राओं हेतु राजकीय महाविद्यालय नहीं है, वहां चरणबद्ध रूप से महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर नवलगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

रायपुर (भीलवाड़ा) में तहसीलदार का पदस्थापन

52. श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील रायपुर में तहसीलदार का पद गत 18 माह से रिक्त है? यदि हां, तो उक्त रिक्त पद पर कब तक पदस्थापन कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र की उप तहसील कारोही में भी नायब तहसीलदार एवं अन्य स्टॉफ के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर कब तक पदस्थापन कर दिया जाएगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की तहसील रायपुर में तहसीलदार का पद माह नवम्बर 2016 से रिक्त रहा है।

आदेश दिनांक 31-01-2018 द्वारा तहसीलदार, रायपुर (भीलवाड़ा) के पद पर पदस्थापन कर दिया गया है।

(2) जी नहीं। उप तहसील कारोई में पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1	नायब तहसीलदार	01	श्री कृष्णागोपाल त्रिपाठी	01
2	लिपिक ग्रेड-I	01	(स्थानान्तरणाधीन)	01
3	लिपिक ग्रेड-II	02	1. श्री निजामुदीन नीलगार 2. श्री धन्नालाल धोबी सेवानिवृत्त संविदा कार्मिक	00
4	सहायक ऑफिस कानूनंगो	01	-	01
5	च.श्रे.क.	02	श्री रामगोपाल शर्मा	01

कार्मिकों की उपलब्धता के अनुरूप रिक्त पदों पर पदस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

रमसा में अधिकारियों की प्रफोर्मा पदोन्नति

53. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में गत चार वर्षों में कुल कितने अधिकारियों को प्रफोर्मा पदोन्नति दी गई है? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा उसके अन्तर्गत संचालित विवेकानन्द मॉडल स्कूलों में विभिन्न वर्षों की डीपीसी में चयनित अधिकारियों में से 55 अधिकारियों को प्रफोर्मा पदोन्नति प्रदान की गई, जिनकी सूची परिशिष्ट-'क' पर तथा आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-'ख' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

डिग्गी (मालपुरा) में विद्युत सब-डिवीजन कार्यालय की स्थापना

22. श्री कन्हैयालाल (मालपुरा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा में लगभग 42000 बिजली के उपभोक्ता हैं? क्या सरकार उक्त उपखण्ड के ग्राम डिग्गी में एक अतिरिक्त सब डिवीजन कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कलमण्डा में एक ग्रिड सब स्टेशन खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा में 36696 नियमित तथा 5581 पी.डी.सी. एवं कुल 42277 उपभोक्ता हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट घोषणा में माननीया मुख्य मंत्री महोदया द्वारा विद्युत वितरण निगमों में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि के मद्देनजर संगठनात्मक ढांचे का पुनर्गठन कर आवश्यकतानुसार नये उपखण्ड और वृत कार्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। इसकी अनुपालना में स्थापित कार्यालयों का पुनर्गठन किया जाना प्रक्रियाधीन है। उक्तानुसार उपखण्ड मालपुरा के ग्राम डिग्गी में एक अतिरिक्त सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में भी उचित निर्णय लिया जाएगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ग्राम पंचायत कलमण्डा में 33/11 के.वी सब स्टेशन बनाना तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य नहीं है। वर्तमान में ग्राम कलमण्डा में विद्युत आपूर्ति निर्बाध/सुचारु रूप से चालू है। ग्राम कलमण्डा में विद्युत आपूर्ति 33/11 के.वी. विद्युत उप केन्द्र तिलाजूं के 11 के.वी. कलमण्डा फीडर से की जा रही है, जिसके तकनीकी मापदण्ड तय सीमा में है। अत: नये विद्युत उप केन्द्र की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्र सरकार से प्रदेश को जी.एस.टी. के नुकसान की भरपाई

23. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जी.एस.टी. से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो कब और क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जी.एस.टी. से हुए नुकसान की कुल कितनी राशि केन्द्र सरकार से प्रदेश को प्राप्त होगी व अब तक कितनी राशि प्राप्त हो गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जीएसटी से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को जीएसटी में शामिल वस्तुओं से प्राप्त राजस्व की सूचना प्रेषित की है। माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा-5 (1) के प्रावधानों के तहत जीएसटी में समाहित होने वाले करों से प्राप्त होने वाले आश्वासित राजस्व की गणना वर्ष 2015-16 के राजस्व में 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को आधार मानते हुए की जाती है। इन प्रावधानों के तहत, प्राप्त जीएसटी राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति केन्द्र द्वारा आगामी 5 वर्षों तक की जायेगी। जीएसटी लागू होने के उपरान्त माह जुलाई व अगस्त, 2017 के लिये जीएसटी में समाहित होने वाले करों से प्राप्त राजस्व की सूचना दिनांक 12.09.2017 (परिशिष्ट-"अ") को, माह सितम्बर व अक्टूबर के लिये दिनांक 14.11.2017 (परिशिष्ट-"ब") को तथा माह नवम्बर व दिसम्बर, 2017 के लिये दिनांक 04.01.2018 (परिशिष्ट-"स") को विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को प्रेषित की गई है।

(2) माह जुलाई से दिसम्बर, 2017 तक की अवधि के लिए राज्य को क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 2776.31 करोड़ प्राप्त होने थे, जिनमें से माह जुलाई से अक्टूबर, 2017 तक की अवधि के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में रुपये 1911 करोड़ अब तक प्राप्त हो चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

24. श्री रमेश (सपोटरा): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 तक कितने अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये? श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार सरकार द्वारा उक्त अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है? यदि हां, तो जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2017 के मध्य इनमें से कितने अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में सरकार को कार्यवाही हेतु निदेश प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी 2014 से दिसम्बर, 2017 तक की अवधि में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के विरुद्ध 501 प्रकरण दर्ज किये गये है। प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'क' पर अवलोकनीय है।

(2) भ्रष्टाचार में लिप्त पाये जाने पर राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के संबंध में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अथवा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आरोप पत्र कार्मिक विभाग में प्राप्त होने पर परीक्षण उपरांत कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 09.08.2001 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रकरणों में समान आरोपों के संबंध में द्विस्तरीय (न्यायिक/अनुशासनिक) कार्यवाही स्थगित रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। अब कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.17 के जारी होने के उपरांत भ्रष्टाचार में लिप्त पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध समानान्तर रूप से विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से प्राप्त उक्त सूची के अनुसार कार्मिक विभाग में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध वर्तमान में लंबित 12

(कार्मिक मंत्री)

अनुशासनात्मक कार्यवाही, कार्यवाही प्रकरणों की सूची, परिपत्र दिनांक 09.08.2001 एवं परिपत्र दिनांक 30.08.17 परिशिष्ट 'ख' पर अवलोकनीय है।

(3) जी हां। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच द्वारा एस.बी.क्रिमिनल मिस. बेल सं. 9441/2017 अरविन्द सिंह राजावत बनाम राज्य में दिनांक 30.08.17 को दिये गये निर्णय एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 30.08.17 द्वारा राज्य सरकार के समस्त राजकीय कार्यालयों को ऐसे प्रकरणों का परीक्षण किये जाने एवं यदि परीक्षण से किसी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने योग्य तथ्य पाये जाएं तो संबंधित कार्मिक के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया के साथ-साथ विभागीय कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

उल्लेखित न्यायिक निर्णय एवं परिपत्र के क्रम में इस विभाग के पत्र दिनांक 27.10.17 स्मरण पत्र दिनांक 23 .11.17 एवं अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 31.01.18 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में आरोपित अधिकारियों के विरुद्ध आचरण नियमों का उल्लंघन का प्रकरण बनना पाया जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र एंव आरोप विवरण पत्र मय अ,ब,स,द एवं संबंधित अभिलेख कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया गया है ताकि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकें।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में महिला अपराधों की रोकथाम की कार्ययोजना

25. श्री नन्दकिशोर महरिया (फतेहपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में दलालों के मार्फत दूसरे प्रदेशों से लड़कियां लाकर शादियों का चलन बढ़ रहा है व उक्त लड़कियां कुछ दिनों के बाद सामान, गहने, नकदी लेकर फरार हो जाती हैं? यदि हां, तो प्रदेश में गत चार वर्षों में ऐसे कितने प्रकरण सामने आए हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में लड़कियों/दुल्हनों द्वारा कितनी राशि व जेवरात ले जाने के प्रकरण सामने आये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नन्दकिशोर महरिया)

(3) उक्त अवधि में दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों पर कार्यवाही हुई? कितना माल वापस बरामद किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में दलालों के मार्फत दूसरे प्रदेशों से लड़कियां लाकर शादी किये जाने तथा कुछ दिनों बाद इन लड़कियों द्वारा सामान गहने नकदी लेकर पार हो जाने के प्रकरण दर्ज हुए हैं। प्रदेश में गत चार वर्षों में ऐसे कुल 103 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट अ पर अंकित है।

(2) उक्त मामलों में लड़कियों/दुल्हनों द्वारा ले जाई जाने वाले राशि व जेवरात का विवरण परिशिष्ट अ पर अंकित है।

(3) गत चार वर्षों में दर्ज प्रकरणों में कुल 57 प्रकरणों में कार्यवाही हुई है एवं बरामद किये गये माल/नकदी का विवरण परिशिष्ट अ पर अंकित है।

(4) इस प्रकार का प्रकरण ज्ञात होने पर अविलम्ब कानून सम्मत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में अभय कमाण्ड सेंटर की स्थापना

26. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर पुलिस के अभय कमाण्ड सेंटर स्थापित करने की योजना है? यदि हां, तो अब तक कितने स्थानों पर ऐसे सेंटर स्थापित किये गये व उन पर कितनी लागत आई तथा स्थापना का कार्य किस फर्म द्वारा किया गया और इनमें स्थापित तकनीकी उपकरणों का संधारण किसके द्वारा किया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अभय कमाण्ड सेंटर का स्वरूप क्या है व इन्हें कौन-कौनसे आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाये गये हैं तथा इससे कानून व्यवस्था

(श्री भवानी सिंह राजावत)

स्थापित करने में किस प्रकार मदद मिलेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कोटा में अभय कमाण्ड सेंटर प्रारंभ कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व स्थापना से अब तक इसकी सहायता से कितने अपराध रोके गये तथा कितने अपराधी पकड़े गये? घटनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कोटा के कमाण्ड सेंटर में कम्प्यूटर, कैमरे व अन्य तकनीकी उपकरणों के संचालन के लिए पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस पुलिस कर्मी को कितनी अवधि का प्रशिक्षण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों पर पुलिस के अभय कमाण्ड सेंटर स्थापित करने की योजना है। अब तक सभी 07 सम्भागों पर अभय कमाण्ड सेंटर स्थापित किये जा चुके हैं। 07 अभय कमाण्ड सेन्टर की स्थापना में कुल खर्चा 247 करोड़ रुपये है। अभय कमाण्ड सेन्टर के निर्माण से संबंधित कार्य निम्न फर्मों के द्वारा किया गया है-

1. M/s Eminent Colonizers Pvt. Ltd.
2. M/s Kardam construction Pvt. Ltd.

अभय कमाण्ड सेन्टर के तकनीकी उपकरण निम्न फर्मों के द्वारा सप्लाई किये गये हैं-

1. M/s Tech Mahindra Ltd. & M/s Mahindra Defense Systems Ltd. (for Jaipur, Ajmer, Kota and Udaipur)
2. L & T Ltd. (for Bikaner, Bharatpur and Jodhpur)

इनका संधारण महिन्द्रा डिफेन्स सिस्टम लिमिटेड, मैसर्स एल. एण्ड टी. कंट्रेक्शन प्राइवेट लि. राजस्थान क्रेन सर्विसेज, ऑप्टीकल फाइबर, मैसर्स ओरियन प्रो, सोल्यूसन लिमिटेड द्वारा किया जावेगा।

(2) अभय कमाण्ड सेंटर की संरचना निम्न प्रकार है-

1. वीडियो सर्विलेन्स रूम, 2. डायल 100 कंट्रोल रूम 3. कम्प्यूटर

(गृह मंत्री)

एडिड डिस्पेचर रूम 4. ट्रैफिक मैनेजमेन्ट रूम 5. साइबर फोरेन्सिक रूम 6. वायरलैस रूम 7. इन्चार्ज रूम 8. यूपीएस एण्ड कन्ट्रोल पैनल रूम 9. डाटा सेन्टर।

अभय कमाण्ड सेन्टर से यातायात व्यवस्था, धरना प्रदर्शन में निगरानी एवं नि:शुल्क 100 नम्बर पर सूचना देने वाले की सम्पूर्ण जानकारी/लोकेशन स्वत: प्राप्त होगी जिससे उचित पुलिस सहायता हेतु फील्ड रेसपोन्स वाहन द्वारा तुरन्त घटनास्थल पर दी जा सकेगी। सीसीटीवी कैमरे से संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी एवं डेटा सेंटर पर स्टोर भी की जा सकेगी। आईटीएमएस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखी जा सकेगी।

(3) जिला कोटा शहर में अभय कमाण्ड सेंटर शहीद हेमू कालानी सामुदायिक भवन में स्थापित कर दिनांक 18.08.2017 को औपचारिक रूप से प्रारम्भ किया गया है। किन्तु वर्तमान में कोटा शहर में अभय कमाण्ड सेंटर स्थापित करने की दिशा में चिन्हित स्थानों पर कैमरे व अन्य उपकरण स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर होने के कारण अपराध रोकने में पूर्ण उपयोग नही हो पाया है। इसके पूर्ण संचालन पर अपराध नियंत्रण में इसका उपयोग किया जा सकेगा।

(4) हां। अधिकारी/कर्मचारियों को सूचना तकनीकी एवं संचार विभाग प्रशिक्षण केन्द्र, तृतीय तल योजना भवन तिलक मार्ग सी. स्कीम, जयपुर पर 03 दिवसीय प्रशिक्षण दिलवाया गया। जिनकी सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या 27

(स्थगित)

प्रदेश में गौ तस्करी के दर्ज प्रकरण

28. श्री हीरालाल नागर (सांगोद): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में प्रदेश में गौ तस्करी के कितने प्रकरण दर्ज किये गये व इनमें कितने गौवंश बरामद हुए एवं कितने वाहनों को जब्त किया तथा कितने तस्करों को पकड़ा गया और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही

(श्री हीरालाल नागर)

की गयी? वर्षवार व जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त अवधि में गौ तस्करों द्वारा कई बार पुलिस पर फायरिंग भी की गई है? यदि हां, तो पुलिस और गौ तस्करों में फायरिंग की कितनी घटनाएं हुई, इनमें कितने पुलिसकर्मी शहीद हुए, कितने घायल हुए, कितने गौ तस्कर मारे गये व कितने घायल हुए? जिलेवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गौ तस्करी पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए कठोर कानून बनाने एवं विशेष अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों (2015,2016,2017) में प्रदेश में गौ तस्करी के कुल 1113 प्रकरण दर्ज किये गये जिनमें 16428 गौ-वंश बरामद किये गये, 1051 वाहन जप्त किये गये एवं 2198 गौ तस्करों को पकड़ा गया। इनमें से 931 प्रकरणों में चालान पेश किया गया, 122 प्रकरणों में एफ.आर दी गई एवं शेष 60 प्रकरण पैंण्डिग पुलिस हैं, जिनका अनुसंधान जारी है। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट अ पर अंकित है।

(2) हां। यह सही है कि विगत तीन वर्षों (2015,2016,2017) में गौ-तस्करों एवं पुलिस में कुल 33 बार फायरिंग की घटनाएँ हुई, जिनमें 07 पुलिसकर्मी घायल हुए, 01 गौ तस्कर मारा गया एवं 03 गौ तस्कर घायल हुए, जिनका जिलेवार एवं वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट ब पर अंकित है।

(3) गौ तस्करी पर प्रभावी रोकथाम लगाने के लिए समय-समय पर गश्त निगरानी एवं नाकाबंदी की जा रही है। गौ तस्करी के खिलाफ वर्तमान कानूनों/ अधिनियमों के तहत प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में वर्तमान में राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1995 एवं नियम, 1995 प्रचलित है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों को आबकारी अधिनियम के प्रावधानों की तर्ज अनुरूप अधिक प्रभावी बनाने हेतु अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बांदीकुई में सांसद/विधायक कोष से स्वीकृत कार्य

29. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्ष 2013 से जनवरी, 2018 तक एम.पी./एम.एल.ए./ स्थानीय निकायों से किन-किन ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी मद के क्या-क्या कार्य, कब-कब स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्यों में से कितनी-कितनी राशि के कौन-कौनसे कार्य अभी लंबित हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में वर्ष 2013 से जनवरी, 2018 तक एम.पी./एम.एल.ए. स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में स्वीकृत कार्यों का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है। ग्राम पंचायतों में स्थानीय निकाय विभाग द्वारा कोई कार्यं नहीं करवाये गये हैं।

(2)

योजना का नाम	स्वीकृत कार्य	पूर्ण कार्य
एम.पी.लैड	49	37
एम.एल.ए.लैड	310	260

कार्यो का विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(3)

योजना का नाम	स्वीकृत कार्य
एम.पी.लैड	12
एम.एल.ए.लैड	50

कार्यो का विवरण परिशिष्ट - 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोधपुर जिले में शौचालयों का निर्माण

30. श्री जोगाराम पटेल (लूणी): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत प्रदेश को वर्ष 2018 तक खुले में 'शौच से मुक्त' (ओ.डी.एफ.) करने का लक्ष्य तय किया गया है? यदि हां, तो दिसम्बर, 2017 तक प्रदेश की कुल कितनी ग्राम पंचायतें व पंचायत समितियां खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं?

(2) क्या जो ग्राम पंचायत या पंचायत समितियां खुले में शौच मुक्त हो चुकी हैं, उनको नियमानुसार प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई गई है? यदि हां, तो कितनी-कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जोधपुर जिले में 'स्वच्छ भारत मिशन' के तहत कितने मकान शौचालयविहीन पाये गए? क्या सरकार द्वारा शौचालयविहीन मकानों को शौचालय बनाने हेतु देय प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त जिले में कितनी राशि का भुगतान किया गया व कितनी राशि दिया जाना शेष है? शेष राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत राजस्थान राज्य को वर्ष 2018 तक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करने का लक्ष्य तय कर रखा है। राजस्थान में अब तक कुल 9048 ग्राम पंचायत व 229 पंचायत समितियां खुले में शौच से मुक्त हो चुकी हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि रु 12000/- प्रति शौचालय भुगतान उपलब्ध करवाया गया है। वर्ष 2017-18 में रु 1410 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का भुगतान हो चुका है। जिसका विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) जोधपुर जिले में 2012 के बेस लाइन सर्वे अनुसार कुल 484794

(पंचायती राज मंत्री)

परिवार में से 292909 शौचालय विहीन परिवार थे। वर्तमान में 51990 शौचालय विहीन परिवार हैं। जोधपुर जिले में शौचालय विहीन परिवारों द्वारा शौचालय निर्माण के पश्चात प्रोत्साहन राशि अदा की जा रही है तथा जोधपुर जिले की कुल 274.91 करोड़ राशि बनती है, जिसमें से 148.03 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया गया है तथा शेष राशि के भुगतान लाभार्थियों द्वारा शौचालय निर्माण एवं संबंधित ग्राम पंचायतों से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त कर दिया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइटें लगाने की योजना

31. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में लगाई गयी उक्त कितनी स्ट्रीट लाइटें चालू स्थिति में हैं व कितनी बंद हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बंद लाइटों को पुन: चालू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नगर परिषद, नगरपालिका एवं नगर निगम की तर्ज पर ग्राम पंचायतों में भी सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइटें लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में 230 सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। जिनका विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में लगाई गयी उक्त स्ट्रीट लाइटों में से 37 लाइटें चालू एवं 193 लाइटें बन्द हैं। बन्द पड़ी लाइटो के कारणों की जांच करवाई जाएगी एवं संबंधित के उत्तरदायित्व का निर्धारण कर, राशि

(पंचायती राज मंत्री)

वसूल किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

इस क्रम में विभागीय पत्र क्रमांक 408 दि. 05.02.2018 के द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर को निर्देशित कर दिया गया है।

(3) बन्द पड़ी लाइटो को पुन: चालू करने के लिये सर्वे कराकर व्यय राशि की गणना कराई जाकर, चालू कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) गत वर्षों में राज्य की ग्राम पंचायतो द्वारा क्रय की गई सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइट के क्रय में अनियमिततायें पाये जाने के फलस्वरूप दिनांक 17.06.2014 अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई थी। जिसमें दिनांक 31.08.2015 को आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए सांसद आदर्श ग्राम योजना एवं मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजनान्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों में सौलर लाइट लगाने की छूट प्रदान की गई है। विभाग द्वारा दिनांक 15.12.2017 के द्वारा ग्राम पंचायतों में विद्युत वितरण निगम के खम्भों पर एल.ई.डी. लगाने के आदेश जारी किये गये।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में लगाई गयी सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइटों का विवरण

क्र. सं.	**पंचायत समिति का नाम**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइटों की संख्या**	**सौर ऊर्जा चलित स्ट्रीट लाइटों**		**विशेष वितरण**
				चालू लाइटों की संख्या	**बन्द लाइटों की संख्या**	
1	गिर्वा	बारापाल	45	7	38	
2		बुझडा	15	2	13	
3		कलडवास	61	6	55	
4		नाई	15	3	12	
5		पई	35	8	27	
6	कुराबड	गुडली	20	3	17	
7		कोंट	16	3	13	
8	बडगांव	ढीकली	13	3	10	
9		बडी	10	2	8	
कुल योग			230	37	193	

बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय को 100 शैयाओं का करने की योजना

32. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के बाडी़ मुख्यालय पर वर्ष 2013 से सामान्य चिकित्सालय संचालित है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय हेतु अब तक केवल 30 शैया के अनुसार ही बजट आंवटित किया जा रहा है?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय को 100 शैयाओं का कर उसी आधार पर बजट आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राज्य सरकार के आदेश दिनांक 19.06.2012 द्वारा राजकीय चिकित्सालय, बाड़ी (धौलपुर) में शैयाओं को 75 से 100 किया गया था। तद्नुसार आदेश दिनांक 10.09.2013 द्वारा उक्त चिकित्सालय का पदनाम परिवर्तित कर सामान्य चिकित्सालय तथा प्रभारी अधिकारी का पदनाम परिवर्तित कर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी किया गया था। उक्त चिकित्सालय को 100 शैयाओं के अनुसार सामान्य चिकित्सालय मद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में में बजट आवंटित किया जा रहा है।

(3) जी हां। भविष्य में बाड़ी में 100 शैयाओं के अनुसार प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को सीधे सामान्य चिकित्सालय मद में बजट हस्तान्तरित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पद

33. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कितने मेडिकल कॉलेज संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(2) उक्त कॉलेजों में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी में स्वीकृत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के पद बड़ी संख्या में रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 8 सरकारी एवं 8 निजी मेडिकल कॉलेज वर्तमान में संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) चिकित्सा महाविधालयों में स्वीकृत पदों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में राजकीय मेडिकल कॉलेजो में विभिन्न श्रेणियों के काफी पद रिक्त है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014 में कुल 753 पदों हेतु आरपीएससी को अर्थनाएं प्रेषित की गई थी जिनके विरुद्ध 548 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। वर्ष 2017 में 8 विशिष्टताओं के 39 पदों पर सीधी भर्ती हेतु आरपीएससी को अर्थनाएं भेजी गई हैं।

आरपीएससी से चयनित अभ्यर्थियों की सूची देरी से उपलब्ध होने, चयनित अभ्यर्थियों के देरी से कार्यग्रहण करने / नहीं करने /अध्ययन अवकाश / उच्च अध्ययन अवकाश पर जाने के कारण काफी पद रिक्त रह जाते हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय ब्यावर में रिक्त पद

34. श्री शंकर सिंह (ब्यावर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में चार जिलों के मरीज ईलाज कराने आते हैं?

(2) उक्त चिकित्सालय में विभिन्न श्रेणियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने कार्यरत हैं एवं कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में मरीजों की संख्या को देखते हुए

(श्री शंकर सिंह)

ब्यावर में मेडिकल कॉलेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर में चिकित्सकों के 69 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 35 पदों पर चिकित्सक पदस्थापित हैं एवं 34 पद रिक्त हैं, जिनकी रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

अराजपत्रित संवर्ग के 255 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 181 पदो पर कार्मिक पदस्थापित हैं एवं 74 पद रिक्त हैं, जिनकी रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। 300 शैयाओं व इससे अधिक क्षमता वाले जिला चिकित्सालयों को चरणबद्ध रूप से मेडिकल कॉलेज में विकसित करने की राज्य सरकार की दीर्घकालिक योजना है। प्रथम चरण में केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोला जाना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रिसर्जेंट राजस्थान के तहत स्थापित उद्योगों में उत्पादन

35. श्री घनश्याम (टोडाभीम): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जनवरी, 2014 से जनवरी, 2018 तक रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान हुए एम.ओ.यू. में से अब तक कितनी राशि के एम.ओ.यू. क्रियान्वित हो चुके हैं व कितनी राशि के प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं? उक्त प्रोजेक्ट किन-किन जिलों में क्रियान्वित हो चुके हैं व कौन-कौनसे जिलों में किस-किस क्षेत्र में एम.ओ.यू. के तहत प्रोजेक्ट विचाराधीन हैं? एम.ओ.यू. सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) रिसर्जेंट राजस्थान में हुए एम.ओ.यू. में से कितनी राशि के प्रोजेक्ट क्लियरेंस के किन-किन चरणों में लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त में से क्रियान्विति के उपरान्त कार्यरूप ले चुके एम.ओ.यू. से

(श्री घनश्याम)

संबंधित इकाइयों में माहवार औसत उत्पादन कितनी राशि का हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जनवरी, 2014 से जनवरी, 2018 तक रिसर्जेन्ट राजस्थान के दौरान 470 एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये जिनमें से रुपये 11845.76 करोड़ के 62 निवेश प्रस्ताव क्रियान्वित हो चुके हैं एवं रुपये 190754.24 करोड़ के 119 प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

क्रियान्वित हो चुके प्रस्तावों की जिलेवार सूचना अनुसंलग्नक-1 पर उपलब्ध है एवं विचाराधीन परियोजनाओं की जिलेवार एवं क्षेत्रवार सूचना अनुसंलग्नक-2 पर उपलबध है।

एमओयूज की सूची अनुसंलग्नक-3 पर संलग्न है।

(2) रिसर्जेन्ट राजस्थान में हुये एम.ओ.यू. में से रुपये 6016.82 करोड़ की 19 परियोजनाए क्लीयरेन्स के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी सूचना अनुसंलग्नक-4 पर उपलब्ध है।

(3) इस प्रकार की सूचना संधारित नहीं की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मूंडवा (नागौर) में अंबूजा सीमेंट लिमिटेड को आवंटित भूमि

36. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले के मूंडवा में दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 को सरकार द्वारा निर्देश देने के पश्चात् अंबूजा सीमेंट लिमिटेड द्वारा उक्त जिले में माइनिंग व सीमेंट प्लांट स्थापित करने हेतु अवाप्त की गई जमीन के संबंध में स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा उठाए गये बिंदु के समाधान के लिए जिला कलेक्टर नागौर व अन्य प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 7 अप्रैल, 2016 को आयोजित हुई बैठक में क्षेत्रीय प्रबंधक रीको के नागौर कार्यालय से जारी बैठक कार्यवाही बिंदु संख्या 7 में जिला कलेक्टर नागौर द्वारा तहसीलदार मूंडवा को दिए गये निर्देशों की पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा अब तक की गई कार्यवाही व जिला कलेक्टर नागौर को 14 जनवरी, 2018 तक

(श्री हनुमान बेनीवाल)

समय-समय पर प्रस्तुत पालना रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त बैठक के बिंदु संख्या 5 में जिला कलेक्ट्रेट नागौर ने कंपनी को आवंटित सिवायचक भूमि में से काफी भूमि चारागाह/अगोर/तालाब पेटा किस्म की आवंटित होना दर्शाया गया है? यदि हां, तो उक्त श्रेणी की जमीन किस-किस राजस्व कार्मिक व अधिकारी ने आवंटित की? नाम व पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर नागौर व अन्य जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 7 अप्रैल, 2016 को आयोजित हुई बैठक के कार्यवाही विवरण के बिंदु संख्या 7 के अनुसरण में यथा अपेक्षित सर्वे हेतु एक कमेटी का गठन किया गया और कमेटी के पर्यवेक्षण में वांछित सर्वे कार्य पूर्ण किया गया, की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर के आवंटन निरस्त करने के आदेश के विरुद्ध मैसर्स अंबूजा सीमेन्ट लि. द्वारा माननीय उच्च जोधपुर न्यायालय में निम्न याचिकाए प्रस्तुत की गईः-

क्र. सं.	याचिका सं.	अनवान	याचिका में पारित आदेश
1	एसबी सिविल पिटीशन नं. 9621/11	अम्बूजा बनाम स्टेट	11.12.2013
2	डीबी सिविल पिटीशन नं. 329/14	अम्बूजा बनाम स्टेट	13.04.2016
3	एसबी सिविल पिटीशन नं. 1038/14	अम्बूजा बनाम स्टेट	02.11.2016

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उक्त याचिकाओं में राज्य की ओर से प्रभावी पैरवी हेतु तहसीलदार मूंडवा को प्रभारी अधिकारी बनाया गया। माननीय न्यायालय में प्रभावी पक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त याचिकाए निर्णीत कर दी गयीं।

(2) बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 07.04.2016 के बिन्दु संख्या 5 में

(उद्योग मंत्री)

कम्पनी को आवंटित सिवायचक भूमि में से चारागाह/अगोर/तलाबी पेटा की होकर उच्चतम न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये विभिन्न निर्णयों से प्रतिबन्धित होकर ऐसी किस्म की भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया।

उद्योग विभाग द्वारा कम्पनी को आवंटित 1001 बीघा भूमि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। आवंटित भूमि में से 504.02 बीघा भूमि किस्म अंगोर होने के कारण दिनांक 17.03.2011 को निरस्त कर दी गई। ग्राम खेण में खसरा नं. 486 में से कम्पनी को आवंटित 132 बीघा भूमि गोचर होने के कारण दिनांक 04.10.2013 को राजस्व (ग्रुप-3) विभाग के आदेश की पालना में जिला कलेक्टर नागौर के आदेश दिनांक 13.04.2011 एवं 17.10.2013 को निरस्त कर दिया गया, की प्रति परिशिष्ट-3 व 4 पर संलग्न है।

जिला कलेक्टर, नागौर के प्रस्ताव क्रमांक एफ. 12 (14)राज/86 दिनांक 02.04.86 के आधार पर शासन उप सचिव, उद्योग विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प. 4 (54)उद्योग/1/86, जयपुर दिनांक 21.03.88 से हस्तगत भूमि आवंटित की गई।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

गंगापुर उपखण्ड में राजकीय महाविद्यालय

37. **श्री बालू राम चौधरी** (सहाड़ा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उपखण्ड गंगापुर में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के निजी महाविद्यालय को अधिग्रहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के उपखण्ड गंगापुर में एक निजी महाविद्यालय संचालित है। निर्धारित मानदण्डों के पूर्ण होने और

(उच्च शिक्षा मंत्री)

संसाधनों की उपलब्धता व गुणावगुण के आधार पर सहाड़ा के उपखण्ड गंगापुर में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

राजकीय कला महाविद्यालय दौसा के नवीन भवन का निर्माण

38. श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय कला महाविद्यालय दौसा के पृथक् नवीन भवन निर्माण के लिए वित्तीय राशि स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब एवं कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत की गई राशि उक्त महाविद्यालय के नवीन भवन निर्माण हेतु पर्याप्त है? यदि हां, तो निर्माण कार्य एवं स्वीकृत राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि आवंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय कला महाविद्यालय, दौसा के पृथक नवीन भवन निर्माण के लिए राशि 600.00 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18.05.2017 को जारी की गई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि रुपये 600.00 लाख से दो मंजिल का निर्माण होगा, भूतल पर 06 कमरे एवं प्रथम तल पर 03 (कुल 09 कमरे), प्राचार्य कक्ष, उपाचार्य कक्ष, कार्यालय कक्ष, सुविधाए छात्र-छात्राए, व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय, एनएसएस कक्ष, एनसीसी कक्ष, टैरेस, बरामदा, कम्प्यूटर कक्ष एवं कान्फ्रेंस कक्ष का निर्माण होगा।

(3) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बड़ी सादड़ी में श्रमिक कार्ड के लाभार्थी

39. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा बड़ी सादड़ी में कुल कितने श्रमिक कार्ड बनाये गए हैं? नामवार गांव व ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कितने श्रमिक कार्डधारियों को उक्त कार्ड का लाभ मिल चुका है तथा किस-किसका बकाया है? ग्राम पंचायत, नाम एवं गांव सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़-प्रतापगढ़) में कुल 19096 श्रमिक कार्ड तैयार किये गये हैं। श्रमिक कार्ड का ग्राम पंचायत, गांव एवं नाम सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त श्रमिक कार्ड से अब तक 1020 कार्डधारियों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिनका ग्राम पंचायत, नाम एवं गांव सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है तथा 1800 कार्डधारियों के आवेदन लम्बित हैं, जिनका ग्राम पंचायत, नाम एवं गांव सहित विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धोद में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह की लम्बित सहायता राशि

40. श्री गोरधन (धोद): क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों की पुत्रियों के 18 वर्ष पूर्ण करने पर विवाह के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र धोद में उक्त योजना के अंतर्गत गत चार वर्षों में कितने आवेदकों को सहायता राशि उपलब्ध करा दी गई है व शेष को किन कारणों से राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है? लाभान्वित एवं शेष आवेदकों के नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डल द्वारा "हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता योजना" का संचालन दिनांक 31.12.2015 को प्रत्याहरित कर दिनांक 01.01.2016 से "शुभशक्ति योजना" लागू की गई है। उक्त विवाह हेतु सहायता योजना में हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी को 18 वर्ष पूर्ण करने पर 51 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती थी। योजना के प्रावधान तथा शर्तों आदि का उल्लेख परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विवाह सहायता योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र धोद में सीकर जिले से प्राप्त सूचना अनुसार 572 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 535 आवेदनों को सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। 37 आवेदनों का निस्तारण किया जाना शेष है, जिनकी कारण सहित सूचना परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम रामपुरा तहसील किशनगढ़ रेनवाल (जयपुर) में मन्दिर माफी की भूमि

41. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम रामपुरा, पंचायत डूंगरीखुर्द तह. किशनगढ़ रेनवाल जिला जयपुर में मन्दिर माफी की कुल कितनी बीघा भूमि स्थित है तथा उक्त मन्दिर माफी की भूमि में किस-किस पुजारी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा किस-किस पुजारी का कितना-कितना हिस्सा है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मन्दिर माफी की भूमि की वर्ष 1980 से वर्ष 2017 तक की जमाबन्दी की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा मन्दिर माफी की भूमि में कब-कब पुजारियों के नाम जोड़ने एवं कब-कब हटाने के आदेश जारी किये गये? आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार मन्दिर माफी की भूमि में पुन: पुजारियों के नाम जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत डूंगरीखुर्द के ग्राम डूंगरीखुर्द में 52 बीघा 4 बिस्वा, ग्राम अभयपुरा में 9 बीघा 3 बिस्वा तथा ग्राम रामपुरा में 16 बीघा 7 बिस्वा भूमि मन्दिर माफी की है। इस प्रकार ग्राम पंचायत क्षेत्र में मंदिर माफी की कुल 77 बीघा 14 बिस्वा भूमि है। जिसमें भू-प्रबन्ध खतोनी सम्वत 2011 में ग्राम डूंगरीखुर्द में 20 बीघा 3 बिस्वा में सुवा वल्द बालु हि. 1/2 बोदु वल्द रामनारायण हि. 1/2 कौम ब्राह्मण तथा रकबा 18बीघा 7 बिस्वा में कन्हैया वल्द शिवचन्द हि. 1/4 देवी सहाय वल्द बल्लू हि. 1/4 मगना वल्द लादू हि. 1/4 छिगना वल्द बोदू हि. 1/4 कौम ब्राह्मण तथा रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा पर हीरा वल्द मान्या कौम बलाई तथा 9 बीघा 16 बिस्वा पर बालू वल्द सोनारायण कौम ब्राह्मण का नाम पुजारी में दर्ज है। ग्राम अभयपुरा में 9 बीघा 3 बिस्वा फूल्या वल्द बलदेवा कौम मीना सा.देह का नाम पुजारी मे दर्ज है तथा ग्राम रामपुरा में 16 बीघा 7 बिस्वा पर महादेव वल्द बल्भाराम कौम ब्राह्मण पुजारी का नाम दर्ज है।

(2) उपरोक्त वर्णित मंदिर की भूमि की वर्ष 1980 से वर्ष 2017 तक की जमाबंदी की छाया प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) सरकार द्वारा मंदिर माफी की भूमि के संबंध में जारी आदेश दिनांक 13.12.1991, 06.03.2003, 24.05.2007 एवं 25.11.11 की प्रतियां संलग्न हैं।

(4) वर्तमान में मन्दिर माफी जमीनों और पुजारियों की मांगों के संबंध में एक कमेटी का गठन किया जा चुका है, जो इस संबंध में विचार कर रिपोर्ट देगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आमेर महल में पर्यटकों को लाने-ले जाने हेतु नर हाथियों पर रोक

42. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): क्या कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा नर हाथियों को आमेर महल में पर्यटकों को लाने-ले-जाने पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा हाथी पालकों पर हाथी पोलो खिलाने पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो कब से व किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तत्कालीन पर्यटन सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 06.01.2001 को हाथी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति की आयोजित बैठक में आमेर में पर्यटक सवारी में लगे नर हाथियों को रोटेशन से हटाने का निर्णय लिया गया था। उक्त निर्णय नर हाथियों द्वारा दुर्घटना अधिक होने के कारण लिया गया है।

(2) जी हां। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 22 के अन्तर्गत पशुओं को बिना पंजीयन के प्रशिक्षण देना एवं प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है। इस प्रयोजन हेतु पंजीयन की प्रक्रिया अधिनियम की धारा 23 में दी गई है। बिना पंजीयन के पशुओं को प्रशिक्षित करना एवं प्रदर्शित करना अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्ष 2011 तक हाथी पोलो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किये जाने वाले हाथी महोत्सव, जयपुर का हिस्सा था। "पेटा" सोसायटी के अनुरोध तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2012 से पर्यटन विभाग द्वारा हाथी महोत्सव का आयोजन बन्द कर दिया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश के प्रतिबन्धित जिलों से अध्यापकों के स्थानान्तरण

43. श्रीमती कामिनी जिन्दल (गंगानगर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में स्थानान्तरण हेतु कितने जिले कब से प्रतिबंधित जिलों की श्रेणी में रखे गए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रतिबंधित जिलों से अध्यापकों के स्थानान्तरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती कामिनी जिन्दल)

(3) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ जिलों के कई अध्यापक प्रतिबंधित जिलों बाड़मेर एवं जैसलमेर में कार्यरत हैं? क्या सरकार उक्त अध्यापकों का स्थानान्तरण मूल जिलों में करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में शिक्षकों के स्थानान्तरण हेतु निम्नांकित 10 जिलों को प्रतिबन्धित किया हुआ है:- जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जालौर, झालावाड़, सिरोही एवं बीकानेर को वर्ष 2006 में, जिला बारां को वर्ष 2008 में तथा जिला प्रतापगढ़ को वर्ष 2010 में स्थानान्तरण हेतु प्रतिबंधित जिलों की श्रेणी में रखा गया है। उक्त प्रतिबंध शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े एवं शिक्षकों की कमी को देखते हुए लगाया गया है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।